Fourth Series, Vol. XVI No. 50

Thursday April 25, 1968
Vaisakha 5, 1890 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

Fourth Session

LOK SABHA SECRETARIAT
New Delhi

CONTENTS

No. 50—Thursday, April 25, 1968/Vaisakha 5, 1890 (Saka)

	Columns
Oral Answers to Questions—	
*Starred Questions Nos. 1442, 1445, 1451, to 1453, 1455 and 1456	2889—2922
Short Notice Question No. 25 ...	2922—28
Written Answers to Questions—	
Starred Questions Nos. 1437, to 1441, 1443, 1444, 1446 to 1450, 1454, 1457 to 1466 ...	2929—44
Unstarred Questions Nos. 8422 to 8537	2944—3023
Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—Reported statement by the Agriculture Minister of Andhra against Harijans ...	3023—32
Papers Laid on the Table ...	3032—33
Estimates Committee—.	
Fifty-Fourth Report	3033
Committee on Public Undertakings—.	
Sixteenth, Seventeenth and Eighteenth Reports	3034
Questions on Statement made by Food Minister on 22nd April. *Re*-Apeejay Shipping Company—	3034—50
Shri Madhu Limaye	3034—38
Shri Jagjiwan Ram	3038—50
Business of the House	3050—51
Demands for Grants, 1968-69—	
Ministry of Industrial Development and Company Affairs	3051—3177
Shri N. K. Somani. ...	3053—58
Shri Hardayal Devgun	3058—61
Shri Rajaram	3061—64
Shri P. K. Ghosh	3065—68
Dr. Ranen Sen ...	3068—69

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

	Columns
Shri Rabi Ray	3069—74
Shri Bhola Nath	3074—78
Shri J. Ahmed	3078—80
Shri Ganpat Sahai	3080—82
Shri Umanath	3382—86
Shri F. A. Ahmed	3087—3100
Department of Social Welfare	3100
Shri D. R. Parmer	3101—06
Dr. S. K. Saha	3106—07
Shri Muthu Gounder ...	3107—11
Shri Z. M. Kahandole ...	3113—15
Shri Shiv Charan Lal ...	3115—20
Shri R. D. Bhandare	3120—25
Shri A. K. Kisku	3125—29
Shri Kamble	3129—35
Shrimati Suseela Gopalan	3135—38
Shrimati Ganga Devi	3138—44
Shri K. Haldar	3144—46
Shri Kartik Oraon ...	3146—51
Shri Baidhar Behera	3151—54
Kumari Kamala Kumari ...	3154—58
Shri Onkar Lal Berwa ...	3158—63
Shri Sunder Lal	3163—66
Shri Ramji Ram	3166—73
Shri Asoka Mehta	3173—76
Ministries of Finance, Health, Law etc. and other Departments	3177—84
Appropriation (No. 2) Bill, 1968— Introduced and Passed	3184—86

LOK SABHA

Thursday, April 25, 1968/Vaisakha 5, 1890 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[Mr. Speaker *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

मोटे अनाज का बिना रोक-टोक लाना व ले जाना

+

*1442. **श्री बृज भूषण लाल :**
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री टी० पी० शाह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चने, जौ तथा अन्य मोटे अनाजों के लाने ले जाने पर से प्रतिबन्धों के हटा देने तथा दिल्ली को भी शामिल करके उत्तरी जोन को बड़ा बना देने का क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या इससे किसानों को तथा उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार खाद्य जोनों को पूर्णतया समाप्त करने के प्रश्न पर विचार करने का है ?

THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI JAGJIWAN RAM) : (a) and (b). The decision to make movement of gram and barley free in the country and to form larger Northern Zone was given effect to only on 28.3.1968. It is too early to assess the effect of the relaxations on movement particularly as the Rabi crop has just started coming into the market.

(c) There is no proposal at present for abolition of Food Zones altogether. The question of continuance or otherwise of the zonal restrictions may be considered in the conference of Chief Ministers before the Kharif harvest.

श्री बृज भूषण लाल : आज उत्तर प्रदेश एक डेफिसिट प्रान्त है। उसने 1967-68 में अनाज के बारे में केन्द्रीय सरकार से जो मांग की थी, उसकी 75 परसेंट भी केन्द्रीय सरकार ने नहीं दिया। क्या मंत्री महोदय उत्तर प्रदेश को भी दिल्ली, हिमांचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के जोन में शामिल करने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री जगजीवन राम : विचार करने के बाद ही अभी यह फैसला हुआ है कि अभी जोन यहीं तक सीमित रहें। लेकिन मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि यह खुशी की बात है कि इस साल उत्तर प्रदेश में रबी की फसल बहुत अच्छी हुई है और गेहूँ के दाम पंजाब के दामों के मुकाबले में हैं।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : अभी समाचार पत्रों में आया है कि सुरक्षित भंडार के लिए पंजाब सरकार का जो कोटा नियत किया गया था, वह उससे लगभग दुगुना कोटा देने के लिए तैयार है। वैसे सभी देश के प्रायः सभी भागों में फ़सल अच्छी हुई है। इस स्थिति में सरकार क्यों नहीं इन जोन्स की दीवारों को हटा देती है, ताकि देश में खाद्यान्नों का उन्मुक्त आवागमन हो और सबको समान रूप से गेहूँ उपलब्ध हो सके ?

श्री जगजीवन राम : इन सभी पहलुओं पर विचार करके मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में

यह फैसला लिया गया था और चूंकि यह फैसला अभी लिया गया है, इस लिए तुरन्त ही उस में कोई रद्दो-बदल करने की आवश्यकता दिखाई नहीं देती है ।

श्री क० ना० निवारी : अभी एक माननीय सदस्य ने उत्तर प्रदेश को उत्तरी जोन में शामिल करने के बारे में पूछा है । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह बिहार की स्थिति को दृष्टि में रखते हुए उसको भी उस जोन में शामिल करने की कृपा करेंगे ?

श्री जगजीवन राम : जैसा कि मैंने कहा है, रबी के लिये जोन के मामले पर फिर से विचार करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है ।

SHRI RANGA : I am glad that the Minister concerned was favourable to extending the area of the zone in spite of the protest from some of the local Governments and, in the end, he succeeded in getting Delhi also included. What steps are being taken to ensure that the producers' interested are properly protected and, secondly, why is it that Government has expressed the fear that they may not be able to procure right upto the target of 3½ million or 7 million tonnes in view of the fact that there is a bumper crop and the peasants are too anxious to sell and the Food Corporation should be capable of taking in what all surpluses the peasants are willing to hand over ?

SHRI JAGJIWAN RAM : I will first explain the point about the procurement figures. The figure of 7 million tonnes was for the Kharif crop. It was not the total procurement and what the apprehension was expressed, taking into consideration the political situation and other factors that the target of Kharif procurement may not reach 7 million tonnes. We have fixed the target of Rabi procurement as 2 million tonnes, the total being 9 million tonnes. So far as Rabi crop is concerned, I have no doubt that the target may even be exceeded.

So far as the farmers' interest is concerned, we have fixed the procurement price of Rabi, which is regarded as a good incentive price and the efforts are being made to see that by procurement, through the public agencies, whatever stock is offered is purchased at the procurement price and that the price are not permitted to fall below that.

श्री शिव नारायण : सरकार की पालिसी स्टेट ट्रेडिंग और प्रोक्युरमेंट की है । जोन के झगड़े को छोड़ दीजिये, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार इस पालिसी को कब तक कार्यान्वित कर सकेगी, ताकि सारा गल्ला उस के हाथ में रहे ।

श्री जगजीवन राम : जैसे-जैसे गल्ला बाजार में आता रहेगा, वैसे-वैसे हम खरीदते जायेंगे ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : दक्षिण के चार राज्यों का एक चावल क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव बहुत पुराना है । क्या मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में उस प्रस्ताव पर भी विचार किया गया और क्या खाद्य मंत्री महोदय उन कारणों पर प्रकाश डालने का कष्ट करेंगे, जिनके आधार पर वह प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया ।

श्री जगजीवन राम : जैसा कि मूल प्रश्न के उत्तर में बताया गया है, जहां तक और जोन्ज का प्रश्न है, जिनका सम्बन्ध खरीफ की उपज से है, जब खरीफ की फसल तैयार होगी, उस वक्त उस पर विचार किया जायेगा । अभी मुख्य मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ था, उसमें सिर्फ रबी पर विचार किया गया था ।

SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHARY: In spite of the removal of restriction in the movement of gram and barley, the State of Madhya Pradesh is not allowing the movement of these grains. The Railways are also not booking these goods. May I know what steps the Central Government is taking to get this decision implemented ?

SHRI JAGJIWAN RAM : As we have informed the House earlier, any restriction placed by any State Government, in contravention of the Central direction, will be illegal and *ultra vires*. If any

party has any grievance, he can seek the requisite remedy.

SHRI HEM BARUA : Is it not a fact that the question of abolition of zonal restriction on food was discussed in the last meeting of the Chief Ministers of Rabi crop areas and that they were in general agreement so far as the abolition of zonal restrictions is concerned and, if so, may I know why is it that the Government have not acted on the advice of the Chief Ministers?

SHRI JAGJIWAN RAM : The Government has acted on the advice and the consensus that emerged in the Chief Ministers' Conference.

श्री अमृत नाहाटा : यह सही है कि जब तक देश खाद्यान्न के मामले में पूरी तरह से आत्म-निर्भर नहीं हो जायेगा, जब तक सरकार के पास बहुत बड़ा वफर स्टाक नहीं हो जायेगा, तब तक इन जोन्ज को रखना आवश्यक है, चाहे देश का व्यापारी वर्ग उनके एबालिशन की मांग करे। हमारे देश में जो राज्य हैं, वे भाषा के आधार पर बने थे; वे खाद्यान्न के उत्पादन के आधार पर नहीं बने थे। इस का नतीजा यह है कि जो स्टेट सरप्लस है, उसके साथ डेफ़िसिट स्टेट्स ऐसा बर्ताव करती हैं, जैसे कि सरप्लस होना कोई अपराध है; सब उन पर टूट पड़ते हैं। क्या सरकार एक दो डेफिसिट स्टेट्स और एक दो सरप्लस स्टेट्स को मिलाकर देश में चार पांच मल्टी-स्टेट जोन्ज बनाने के प्रश्न पर विचार करेगी, ताकि देश भर में खाद्यान्न का उचित वितरण हो सके ?

श्री जगजीवन राम : जैसा कि मैंने कई दफा सदन में बताया है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-काश्मीर का जो ज़ोन बनाया गया है, वह तो मल्टी-स्टेट ज़ोन ही है।

श्री अब्दुल गनी डार : वजीर साहब ने श्री प्रकाशवीर शास्त्री के सवाल के जवाब में फरमाया चूंकि जोन्ज के बारे में अभी हमने फैसला किया है, इस लिए इस पर दोबारा गौर करने की जरूरत नहीं है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप इस बात का भरोसा दिलायंगे कि पंजाब में जहां बहुत ज्यादा गेहूं पैदा हुआ है, वहां के किसानों को जो मुनासिब निर्ख है, उस से कम निर्ख नहीं मिलेगा और सरकार इस मामले में पूरी मदद करेगी जिससे कि निर्ख गिरने न पायें, ताकि किसानों को पिछले दो सालों में जिस तबाही का सामना करना पड़ा है, अब थोड़ी सी सहूलियत उन को मिल सकेगी ?

وزیر صاحب نے شری پرکاش ویر شاستری کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ چونکہ زونز کے بارے میں ابھی ہم نے فیصلہ کیا ہے۔ اسلئے اس پر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ اس بات کا بھروسہ دلائینگے کہ پنجاب میں جہاں بہت زیادہ گیہوں پیدا ہوا ہے وہاں کے کسانوں کو جو مناسب نرخ ہے اس سے کم نرخ نہیں ملے گا۔ اور سرکار اس معاملے میں پوری مدد کریگی۔ جس سے کہ نرخ گرنے نہ پائیں۔ تاکہ کسانوں کو پچھلے دو سالوں میں جس تباہی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اب تھوڑی سی سہولیت انکو مل سکے۔

श्री जगजीवन राम : मैंने इस सवाल का जवाब दिया है, पंजाब का किसान तो पिछले साल भी अच्छा ही रहा है। जितना भी अनाज मिलेगा, जो दाम हमने उपलब्धि के निश्चित किये हैं, उस पर खरीद लेंगे।

SHRI SRADHAKAR SUPAKAR : So far as the procurement is concerned, the season for procurement of rice is not yet over. But we hear from newspaper reports that a huge quantity of rice is going to be imported from abroad. How far is this news correct ?

SHRI JAGJIWAN RAM : Does it arise out of this question ?

SHRI SRADHAKAR SUPAKAR : Yes, because procurement was discussed ; answer for procurement was given earlier during this Question. That is why I put this question- Is there a scheme for procuring a large quantity of rice from abroad, although the period of procurement is not yet over ?

SHRI JAGJIWAN RAM : Yes, Sir. It is proposed, from the very beginning,

to import some rice because we are still deficit in rice.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, जहां तक चने का सवाल है, उसको बिना रोक लाने तथा ले जाने के बारे में मध्य प्रदेश की गैर कांग्रेसी सरकार और केन्द्र की कांग्रेसी सरकार के बीच में बड़ी अखबारी लड़ाई चल रही है। आपने कहा है कि उन को ऐसा अधिकार नहीं है और मध्य प्रदेश की सरकार ने कहा है कि हमने रोक नहीं लगाई है। इसके बारे में वास्तविक स्थिति क्या है और मध्य प्रदेश से इन दिनों में कितना चना बाहर गया है क्या सरकार के पास इसकी सूचना है ?

श्री जगजीवन राम : जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, मैंने यहां सदन में एक वक्तव्य दिया था और उस में मामला साफ कर दिया गया था। जब परमिट और लाइसेंस नहीं रहता है तब, जैसा कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का कहना है, उस का कोई हिसाब रखना कि कितना बाहर गया सम्भव नहीं है।

SHRI ANANTRAO PATIL: After the formation of a larger Northern Zone, the concerned States have been benefited to a larger extent. In view of that, may I know from the Government whether they propose to form a larger Southern Zone comprising the States of Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Mysore, Andhra Pradesh, etc. ?

SARI JAGJIWAN RAM: I have already answered that.

श्री झारखण्डे राय : मान्यवर, मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में बराबर इस बात की आवाज उठाई गई कि खाद्य जोन अलग-अलग सूबों का समाप्त कर दिया जाय, इसके साथ ही भारत सरकार राज्य सरकारों की राय से अलग अलग स्टेट में लैवी भी दोनों फसलों में इकट्ठा कर रही है। ऐसी हालत में कौन सा ऐसा मजबूत आधार है कि अलग-अलग सूबों का अलग-अलग जोन कायम रखा जाय-यही मैं जानना चाहता हूं ?

श्री जगजीवन राम : यह तो मैंने बार'बार दोहराया है कि मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में इन प्रश्नों पर विचार होता है और वहां जो प्रायः सहमति होती है, उस के ऊपर अमल किया जा रहा है। जहां तक लैवी का प्रश्न आपने उठाया हमने किसी भी सरकार को किस तरह से लैवी लगाई जाय, यह नहीं कहा है। हमने उन से इतना ही कहा है कि इतना अनाज आपको उपलब्ध कर लेना चाहिए। कैसे करेंगे यह उनके ऊपर निर्भर करता है।

श्री विभूति मिश्र : यह सरकार कहती है कि अगर हम जोन नहीं बनायें, तो प्राइवेट ट्रेडर्स बीच में चले आयेंगे। प्राइवेट ट्रेडर्स के नाम से यह सरकार किसानों को मारती है। सरकार जो प्रोक्योरमेंट प्राइस रखती है, फ्री-मार्केट से उसकी आधी कीमत होती है। मैं चाहता हूं कि किसानों के हित में सरकार प्राईवेट ट्रेड को बन्द कर दे और किसानों को कहे कि फ्री-मूवमेंट खुला रहेगा, जो चाहे ले जाय। सरकार किसानों पर लेवी लगाती है, लेकिन फैक्टरी वालों पर कोई लेवी लागू नहीं करती, कपड़ा और दूसरे सामान हमको सही दामों पर सप्लाई नहीं करती है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार किसानों के हित में कौन सा उपाय सोच रही है कि जिससे किसानों को उचित कीमत मिल सके ?

श्री जगजीवन राम : मैंने बार-बार बताया है कि इस वर्ष जो रबी का दाम निश्चित किया गया है, वह बिल्कुल मुनासिब और लाभकारी दाम है। इसको अगर कोई यह समझता है कि यह कम दाम है, तो मैं समझता हूं कि वह मुनासिब नहीं समझता है। जहां तक उद्योगों का सम्बन्ध है, बहुत से उद्योग ऐसे हैं जिनकी सारे उत्पादन के ऊपर दाम का नियन्त्रण है इस पहलू को नहीं भूलना चाहिए। यहां पर

यदि लेवी है तो उत्पादन के एक छोटे से अंश पर है, बाकी अंश किसान के लिए स्वतंत्र रहता है चाहे जिस दाम पर बेचे। लेकिन जहां तक रबी का सवाल है गेहूं का दाम जो निर्धारित किया गया है, मैं मानता हूं कि काफी मुनासिब और प्रोत्साहित करने वाला दाम है।

श्री कंवर लाल गुप्त : दिल्ली में सरकार की इस नीति से यह असर हुआ है कि करीब करीब 15-20 रु० क्विंटल दाम गिर गये हैं। नतीजा यह हुआ है कि राशनिंग में जो 12-13 हजार क्विंटल अनाज था, उसको कोई लेता नहीं था और अब सरकार ने उसकी कीमत नीचे गिराकर बेचा है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली की राशनिंग व्यवस्था के बारे में आगे उनका क्या रुख है- आया इन्फ़ार्नल राशनिंग रहेगा या फेअर प्राइस शाप्स रहेंगी क्या व्यवस्था सरकार सोच रही है ? क्या यह सही है कि हरियाणा और पंजाब में सरकार प्रोक्योरमेंट नहीं कर रही है और वहां पर दाम नीचे गिर रहे हैं। कभी करती है और कभी नहीं करती है। क्या आप फर्म एंशोरेन्स देंगे कि जो भाव आपने निश्चित किये हैं, सरकार उस भाव पर जरूर खरीदेगी ?

MK. SPEAKER : I think he has already assured that the prices will not be allowed to fall down ?

श्री जगजीवन राम : मैं तो बराबर कह रहा हूं लेकिन व्यापारियों का एक अपना लोबी है और वह इसलिए है कि यह सारा मामला खुल जाय। वे कुछ इस प्रकार की लोबी तैयार किया करते हैं कि वहां तो 20 रु० गेहूं बिकने लगा, वहां पर 22 रु० बिकने लगा, जब मैं छानबीन करता हूं तो हमको उस दाम में मिलता ही नहीं। अगर गुप्ता जी गिरे हुए दामों पर दिलवा दें तो हम लेने को तैयार हैं, हरियाणा और पंजाब की सरकारें दोनों इस मामले पर तत्पर हैं, खरीदने के लिए तैयार हैं, खरीद भी रही हैं और दाम नहीं गिरने दिया जायेगा, यहां मैंने इस बात को कहा है।

दिल्ली के बारे में फोरमली राशनिंग को खत्म नहीं किया गया है, लेकिन व्यावहारिक तरीके से सभी प्रकार की छूट दे दी गई है। उसको इसलिए रखा गया है कि आज भी शायद माननीय सदस्य को मालूम होगा हम जो बाहर से आये हुए गेहूं का आटा दिल्ली में देते हैं, उस आटे की खपत काफी हो रही है। इसके मायने यह हैं कि जो सीमित साधन और आय वाले लोग हैं, आज भी इस पर निर्भर करते हैं, अतः उस को बिल्कुल हटा देने की मंशा अभी नहीं है।

SHRI MANUBHAI PATEL : In view of the experience gained by removing the restrictions on the movement of course grains like gram, jowar, etc., and in view of the bumper crop of wheat in wheat area, will the Government consider removing restrictions on the movement of wheat also at the earliest ?

SHRI JAGJIWAN RAM : No ; the Government will not consider that.

SHRI LOBO PRABHU : The statement of the Minister that his Ministry would be very ready to buy grain at a price lower than the statutory price apparently has not been compared by him with the daily prices reported in the papers, for instance, according to the report today, the price of Mexican wheat is Rs. 60 to 66 per quintal. Am I to infer that this information is not available to the procurement agencies and that they have, therefore, refrained from going and buying that wheat and are inflating the price to the level fixed by the Government ?

SHRI JAGJIWAN RAM : I do not know which Market is being quoted, but sometimes...(*Interruptions*) in regard to some markets, their quotations are on the paper and not on the physical quantity of foodgrains.

SHRI LOBO PRABHU : May I inform him that these quotations have been watched by me over a period of time ?

MR. SPEAKER : Next Question.

गेहूं की वसूली

*1445. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में ऐसी कौन-कौन सी एजेंसियां हैं जिनके माध्यम से सरकार गेहूं की वसूली करती है ;

(ख) प्रत्येक एजेंसी के माध्यम से वसूली पर कितना व्यय होता है ; और

(ग) क्या वर्तमान व्यवस्था में कोई परिवर्तन करने का सरकार का विचार है ताकि वसूली व्यय कम किया जा सके ?

THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI JAGJIWAN RAM) : (a) During 1967-68 wheat was procured for the Central Government only in the State of Punjab through the State Co-operative Supply and Marketing Federation. During the coming season i.e. 1968-69, wheat will be procured in Punjab through the Marketing Federation and the Food Corporation, in Haryana and U.P., through the State civil Supplies Departments and in Rajasthan and Madhya Pradesh, through the agency of the Food Corporation.

(b) and (c). For the procurement 1967-68 the cost of procurement, viz. expenses incurred by the Punjab State Co-operative Supply and Marketing Federation from the time of procurement till the grain reached the first storage point (including mandi charges, labour charges, temporary storage and extra handling and establishment charges) was Rs. 4.07 per quintal. The details of the cost of the procurement by the various agencies for the season 1968-69 are being settled in consultation with the State Governments and the agencies concerned. It is, however, the policy of Government to keep the cost of procurement as low as possible.

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : श्रीमान्, अभी माननीय खाद्य मंत्री ने बताया कि कहीं फूड कारपोरेशन के जरिये से खरीद की है, कहीं कोआपरेटिव फेडरेशन के जरिये खरीद की है और कहीं गवर्नमेंन्ट डिपार्टमेंट के जरिये से खरीद की है, तो मैं जानना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ था क्या उसमें कोई ऐसा निर्णय हुआ था कि एक ही एजेन्सी के द्वारा अनाज खदीदा जाये जिससे सारे देश में यूनिफार्म भाव रहें ?

श्री जगजीवन राम : यह सम्भव नहीं है, इसीलिये कई एक संस्थायें काम कर रही हैं । कोआपरेशन, सहकारिता को भी प्रोत्साहित करना है, फूड कारपोरेशन भी मैदान में है और पहले से कुछ तजुर्बा राज्य सरकारों को है । इन सारी एजेन्सीज की मार्फत अनाज खरीदने का काम होता है इसलिये यह निर्णय नहीं लिया गया कि सभी जगह एक ही एजेन्सी हो । अलग अलग एजन्सीज रहेगी ।

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : क्या मन्त्री महोदय को कुछ एजेन्सीज के मुताल्लिक शिकायतें भी मिली हैं और यह प्रार्थना की गई है कि इसपर विचार किया जाये कि इन एजेन्सीज को उस क्षेत्र में रहने दिया जाये या नहीं ?

श्री जगजीवन राम : इस तरह की शिकायतें नहीं मिली हैं कि किसी एजेन्सी को बन्द कर दिया जाये ।

श्री तुलशी दास जाधव : ऐसी कम्प्लेन्ट्स आई हैं कि पंजाब में गेहूं खरीदा नहीं जा रहा है क्योंकि जब मैं वहां गया था तो वहां पर ऐसी कम्प्लेन्ट्स मिलीं कि जो एजेन्सीज खरीद करती हैं वह खरीद नही रही है, किसानों के पास माल पड़ा हुआ है, क्या इसकी इंक्वायरी मन्त्री महोदय करायेंगे ?

दूसरी बात यह है कि जो आप प्रोक्योरमेंट प्राइस निश्चित करते हैं वह किस बेसिस पर निश्चित करते हैं, कास्ट आफ प्रोडक्शन या और किन किन चीजों को ध्यान में रखते हैं ? जिस प्रकार से आप एक वर्कर की वेज निश्चित करते हैं तो उस में बाहर की चीजों की

कीमतों को देखते हैं तो इसमें किस बेसिस पर प्राइस फिक्स करते हैं ?

श्री जगजीवन राम : यह प्रश्न हर वर्ष उठाया जाता है। पंजाब में खरीदने का काम जैसा कि मैंने कहा कोआपरेटिव मार्केटिंग फैडरेशन करती थी, फूड कारपोरेशन की जिम्मेदारी नहीं थी गेहूँ खरीदने की। जैसा मैंने अभी बतलाया कि ट्रेडर्स की एक लाबी बन गई है जो यह चाहते हैं कि सभी चीजों की छूट कर दिया जाये, उनकी तरफ से इसका प्रोपेगैन्डा भी किया जाता है लेकिन जब जब ऐसी बात आई तो हमने पंजाब सरकार को कहा कि वह जल्दी से खरीद करें तो मालूम हुआ कि ऐसी कोई बात नहीं है ।

जहाँ तक दाम निर्धारित करने की बात, है यह बराबर सवाल आता है कि कास्ट आफ प्रोडक्शन लिया या नहीं और मैंने बराबर जवाब दिया है कि जिस प्रकार से उद्योग में उत्पादन का खर्चा और हिसाब किताब लगाया जाता है, कृषि के सम्बन्ध में भी हम वैसा ही कर सकने का दावा करें तो वह मुनासिब नहीं है और वह सही नहीं होगा—अभी वह सम्भव नहीं है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैं यह जानना चाहता हूँ कि जितनी आपकी एजेन्सीज हैं अनाज खरीदने की ओर जो दाम आपने बांधे हैं अनाज के, क्या उन बांध हुये दामों से भाव नीचे गिरेगा तब एजेन्सीज खरीदेंगी और यदि भाव उससे ऊपर जायेगा तो व्यापारी खरीदेंगे, क्या इस प्रकार का आपने आदेश दे रखा है ?

दूसरी बात यह है कि काश्तकार मंडी में जो अपना गल्ला लाते हैं उनके लिये कोई ऐसा नियम नहीं है कि उनका गल्ला लेने के कितने समय बाद उनको पैसे का भुगतान किया जायेगा, क्या यह बात सही है ? इस प्रकार के उदाहरण हैं कि काश्तकारों का माल लेने के महीने दो महीने बाद भुगतान किया जाता है ? क्या आप इस प्रकार की व्यवस्था करने जा रहे हैं कि तत्काल काश्तकारों का भुगतान हो जाये, इधर माल तौला और उधर पैसे दे दिये ?

श्री जगजीवन राम : मंशा तो यही है कि ज माल लिया जाय तो जल्द भुगतान कर दिया जाए। अगर कहीं दो महीने लगे हैं तो वह मुनासिब नहीं हुआ है, इतना समय नहीं लगना चाहिये। तीन चार दिन में भुगतान हो जाना चाहिये और यदि सम्भव हो तो वहीं पर हो जाये। माननीय सदस्य ने जो बताया कि दो महीने लग गये, अगर वह विवरण देंगे तो उसकी जांच हो जायेगी।

श्री हुकम चन्द कछवाय : अगर दाम नीचे गिरेंगे तो आपकी एजेन्सी खरीदेगी और अगर दाम उपर जायेंगे तो व्यापारी खरीदेंगे, इसका उत्तर आपने नहीं दिया।

श्री जगजीवन राम :यही प्रयास हो रहा है कि दामों को नीचे न गिरने दिया जाय इसलिये मैंने जवाब दिया कि जहां दाम नीचे गिरेंगे, वहां पर जितना भी मिलेगा, हम खरीद लेंगे—दाम ऊपर जाते हैं, यह प्रश्न आता नहीं – लेकिन यह भी नहीं है कि जितने दाम हैं उसी पर खरीदेंगे, कहीं एक दो रुपया ज्यादा भी होगा तो उस पर भी खरीद लेंगे, कितनी जरूरत है उस पर निर्भर करता है। अगर दाम गिरने लगेंगे तब जितना भी मिलेगा वह खरीद लेंगे।

श्री कमलनयन बजाज : इस वर्ष पंजाब में गेहूं कीं पैदवार ईश्वर की दया से इतनी अच्छी हुई है.....

श्री देवराव पाटिल : किसानों के प्रयत्न से।

श्री कमलनयन बजाज : हां, हां, किसानों के प्रयत्न से और गवर्नमेंट ने भी मदद की है। तो इस वर्ष पंजाब में जितनी अच्छी क्राप हुई है, उसको किसानों से खरीदने के लिये जो एजेन्सीज बनाई गई हैं वह पूरी तौर से खरीद

नहीं पा रही है, किसान जितना बेचना चाहता है वह बेच नहीं पा रहा है और उस गल्ले को किसान के लिये अपने पास रखने की गुंजायश भी नहीं है गोदामों वगैरह की और उसको यह डर हो रहा है कि अगर कहीं बरसात आ गई तो उसका माल किस प्रकार सुरक्षित रह पायेगा। यह भी खबरें आ रही हैं कि वहां पर ढोरों को अनाज खिलाया जा रहा है।

श्री जगजीवन राम : मैं समझता था कि माननीय सदस्य को थोड़ा सा व्याहारिक ज्ञान है। अभी से इस तरह की बातें करना जबकि पंजाब में अभी कुछ गेहूँ खेतों में ही है.....

श्री कमलनयन बजाज : किसान के पास है।

श्री जगजीवन राम : अभी तो कुछ खेतों में ही है और बहुत सा खलिहानों में है, और अभी से इनके यहां यह प्रश्न पैदा हो गया कि गल्ला बिक नहीं रहा है। इसी को हम कहते हैं कि ट्रेडर्स की लाबी है। पंजाब में तो अभी नयी फसल का गेहूं बाजार में आया ही नहीं है मैं समझता था कि माननीय सदस्य को शायद यह भी ज्ञान हो कि पंजाब में जितना अनाज बेचा जाता है उसका वहां पर सबसे सुन्दर प्रबन्ध है। पंजाब में सारा का रैगुलेटेड मार्केट से बेचा जाता है और अभी तक हमारे पास ऐसी खबर नहीं आई है कि किसान रैगुलेटेड मार्केट में अपना गल्ला लाये और फिर वापिस ले गये। अगर माननीय सदस्य के पास ऐसी कोई खबर हो तो वह विस्तार से हमें दे दें।

SHRI TENNETI VISWANATHAM : While talking about the procurement agencies, the hon. Minister said that he had not received complaints about co-operative societies. Does he know that when one man wants to eat away the other man's property, it is called misappropriation, and when two do it, it is called conspiracy and when more than ten combine, it is called co-operation ?

SHRI JAGJIWAN RAM : I cannot challenge any statement from my hon. friend because whatever he says here is out of the experience that he has gained.

SHRI HEM BARUA : Was it a kick or a compliment ?

MR. SPEAKER : Why does he want to create trouble now ? Shri Shivaji Rao S. Deshmukh.

SHRI SHIVAJI RAO S. DESHMUKH: In States like U. P. and Punjab, possibly because the Opposition Chief Ministers could succeed in pressurising our Government at the Centre, the procurement prices were raised by about 100 per cent. But in the case of jowar in Maharashtra, the procurement prices were raised from Rs. 37 to Rs. 43 which works out to about 10 to 15 per cent only. Further, this jowar is procured at a sub-centre, and the cost of transport working to about 5 to 10 per cent is reduced from that ; added to that is the dryage calculated at 5 per cent. Would the hon. Minister explain how there is so much disparity in the procurement prices in the case of wheat and jowar, how in the case of wheat it has increased by 100 per cent but in the case of jowar, the actual cost in the pocket of the farmer has come down and that too in monopoly conditions in Maharashtra State ?

SHRI JAGJIWAN RAM : In the first place, I may inform the hon. Member for his enlightenment that wheat prices this year have not been increased over the last year's prices. Therefore, the question of increase does not arise. As a matter of fact, in some areas like U. P., it has been rather reduced, not increased.

As for the question of pressurisation, it does not arise. Whatever prices are fixed are in consultation with State Governments. In the case of Maharashtra, I may inform him that we have not resisted the State Government increasing the price.

SHRI SHIVAJI RAO S. DESHMUKH: He should have asked them to increase it ?

SHRI JAGJIWAN RAM : Why should I ask them to increase it ?

श्री शिवचरण लाल : अध्यक्ष महोदय, जब किसानों ने खेत में बोने के लिए गेहूं लिया तो वह 50-60 रुपये मन के हिसाब से लिया लेकिन अब उसे अपने पैदा किये हुए गेहूँ को 20-25 रुपये मन के अन्दर बेचना पड़ रहा है। में मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि वह जुलाई, अगस्त के महीने में जबकि किसान को बोने के लिए गेहूँ के बीज की आवश्यकता पड़ेगी तो उसे किस भाव से आप देने जा रहे हैं ? क्या 16 प्रतिशत के अन्दर उस के भाव चढ़ें या गिरें ऐसी कोई व्यवस्था करने का विचार है ? इस समय आप किसानों से 75 रुपये क्विंटल के हिसाब से गेहूँ ले रहे हैं और जुलाई, अगस्त में किसानों को आप वही गेहूँ का बीज 150 रुपये क्विंटल देंगे तो ऐसा करना उचित नहीं होगा और मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि जुलाई, अगस्त में किसानों को आप गेहूँ का बीज किस भाव पर देना चाहते हैं ?

श्री जगजीवन राम : माननीय सदस्य को यह मालूम होगा कि खेत में जो एक मन गेहूँ का बीज लगाया जाता है तो वहां पर सिर्फ एक मन गेहूँ ही पैदा नहीं होता है बल्कि उससे ज्यादा गेहूँ पैदा होता है लेकिन शहर में रहने वालों को तो यह चीज मालूम नहीं हैं इसलिए बराबर कह दिया जाता है कि सरकार ने 150 रुपये क्विंटल के भाव से तो गेहूँ का बीज दिया है ऐसी हालत में हम 75 रुपये क्विंटल गेहूं कैसे बेच सकते हैं ? एक मन लगा कर एक मन गेहूँ पैदा नहीं होता है बल्कि उस से कई गुना गेहूँ पैदा होता है।

श्री प्रेम चन्द वर्मा : मन्त्री महोदय ने अभी यह कहा है कि यह पंजाब में 4 रुपया 7 पैसे क्विंटल ओवरहैड चार्जेज प्रोक्योरमैंट के लिए लगाये जाते हैं लेकिन मन्त्री महोदय को शायद मालूम होगा कि हिमाचल प्रदेश में जो भाव वहां से गेहूँ खरीदा जाता है उस से 20-25 रुपया क्विंटल फालतू लिया जाता है। मैं यह जानना चाहूंगा कि इस सिलसिले में क्या वह कोई कार्यवाही करेंगे कि अगर गेहूँ पर चार रुपया क्विंटल खर्चा पड़ता है तो उस के अनुसार पैसे लगा कर किसान से पैसे वसूल किये जायं ?

श्री जगजीवन राम : माननीय सदस्य कृपया पुनः प्रश्न करें क्योंकि मैं समझ नहीं पाया हूं।

श्री प्रेम चन्द वर्मा : हिमाचल प्रदेश में 105 रुपये और 110 रुपये क्विंटल गेहूं बिक रहा है जबकि कोआपरेटिव सोसाइटियों ने वहां पंजाब में गेहूँ 75 रुपये और 80 रुपये क्विंटल खरीदा है। 4 रुपये क्विंटल खर्चा लगता है तो फिर यह 105 रुपये और 110 रुपये क्विंटल के भाव पर हिमाचल प्रदेश में क्यों दिया जाता है ? यह 25-30 रुपये क्विंटल का फर्क क्यों सरकार डालती है ? मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री महोदय कोई ऐसा इंतजाम करेंगे जिससे मुनासिब खर्चा जोड़ कर रीजनेबुल दाम पर हिमाचल प्रदेश के लोगों को गेहूँ मिल जाये ?

श्री जगजीवन राम : माननीय सदस्य को समझना चाहिए कि मैंने जो दर बनाया है वह सिर्फ प्रोक्योरमैंट का है लेकिन यह पंजाब से गेहूँ हिमाचल प्रदेश में ले जाने का, उसे स्टोर करके रखने के स्टोरेज चार्जेज और उस में उन का जो कैपिटल लगेगा उस का इंटरैस्ट और फिर डिस्ट्रिब्यूशन का भी इंतजाम होना है तो वह डिस्ट्रिब्यूशन चार्जेज भी लगेंगे, यह सब खर्चे मिला कर उस हिसाब से वहां कंज्यूमर्स को मिलेगा। इसका विस्तृत ब्यौरा हमारे पास नहीं है। बाकी यह सारा खर्चा जो मैंने बतलाया और साथ ही 4 रुपये यह सब खर्चा कंज्यूमर्स के ऊपर ही चढ़ेगा।

श्री ओ० प्र० त्यागी : क्या यह सच है कि रबी में अन्न संग्रह करने का जो लक्ष्य बनाया गया था उस लक्ष्य की पूर्ति नहीं हुई और अब खरीफ में अन्न संग्रह का जो आप ने लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य की पूर्ति करने में भी कुछ संदेह आ गया है। समाचार पत्रों में इस तरह

का संकेत प्रकाशित भी हो गया है कि अगर आणविक संधि पर भारत सरकार ने हस्ताक्षर नहीं किये तो अमरीका गेहूं की सप्लाई रोक देगा और उससे हमें अन्न मिलने की आशा नहीं रहेगी। क्या सरकार अपने अन्न संग्रह के कार्य को और तेज करेगी और जो लक्ष्य उसका है उस को भी कुछ बढ़ा कर रखने का विचार करेगी ?

श्री जगजीवन राम : अभी कुछ देर पहले प्रोफेसर रंगा के प्रश्न के उत्तर में मैंने इन दोनों प्रश्नों का जवाब दे दिया है।

श्री बसराज मधोक : पंजाब के अन्दर कीमतें प्रोक्योरमैंट प्राइस से नीचे नहीं होने दी जायेंगी यह ठीक बात है लेकिन पंजाब के अन्दर इस बार बम्पर क्रौप है और लगभग 8 लाख टन प्रोक्योरमैंट करने वाले हैं। अब के फसल इतनी अच्छी नये बीजों के कारण हुई है तो मैं जानना चाहता हूं कि यह नये किस्म के बीजों के कारण अधिक अन्न पैदा हुआ है उन अच्छे बीजों की वेराइटीज को अलग स्टोर करने की व्यवस्था की जायगी ताकि किसानों को फसल बोने के समय मुनासिब दामों पर यह अच्छे किस्म के बीज मिल सकें और उन्हें वह बीज 5-5 रुपये किलो पर न खरीदने पड़ें मुनासिब दामों पर किसानों को यह उन्नत किस्म के बीज पर्याप्त मात्रा में मिल सकें ?

श्री जगजीवन राम : कई एक वैराइटीज बीजों की ऐसी हैं जिनके कि मिलने के बारे में कोई कठिनाई नहीं है और जरूरत से ज्यादा बीज सुलभ रहते हैं। सिर्फ उन बीजों के बारे में कठिनाई होती है जिनके बारे में हमारे वैज्ञानिक कुछ प्रयोग करते होते हैं और वह इस स्टेज पर नहीं पहुँचे हैं कि हम उन को किसानों के लिए छोड़ सकें लेकिन किसानों को चूंकि वह इंटरैस्टैड होते है इसलिए उन्हें पता चल जाता है कि कुछ चमत्कारिक बीजों के ऊपर प्रयोग हो रहा है और उन बीजों को प्राप्त करने की उन में एक उतावली रहती है और वह ऐसे उन्नत बीज 100 रुपये और 150 रु० क्विंटल तक खरीद कर उसे बोना चाहते हैं और ऐसी स्थिति में इस की दिक्कत आती है। अलबत्ता इस तरह के बीज जिनके बारे में हमारे वैज्ञानिकों ने कह दिया है कि किसान उन का इस्तेमाल कर सकते हैं उन के बारे में हमने आवश्यक कार्यवाही कर ली है और वह किसानों को आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे ?

Land under Rabi Crops in Bihar and West Bengal

*1451. SHRI BENI SHANKER SHARMA : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the acreage of land brought under wheat and other rabi crops cultivation during this rabi season as well as in the last rabi season in West Bengal and Bihar ;

(b) the portion of it which had proper irrigation facilities and the portion which depended on chance rains ; and

(c) the arrangements which Government are making to provide irrigation facilities to those areas which get good harvest depending only on rain water ?

THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI JAGJIWAN RAM) : (a) to (c). A statement is placed on the Table of the Sabha. [*Placed in Library. See* No. LT 1025/68].

श्री बेणीशंकर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जानते हैं कि जहां तक बिहार और पश्चिम बंगाल का प्रश्न है वे चावल खाने वाले प्रदेश थे किन्तु सरकार की भिक्षा वृत्ति की नीति के कारण और अन्न ऋण लेने की नीति के कारण उन की कृपा से पश्चिम बंगाल और बिहार के लोगों ने भी गेहूँ और चना खाना सीख लिया है। अब जिस जमीन में धान पैदा होता है उस जमीन में अगर गेहूं भी पूरा पैदा किया जा सके तो हमारे यहां बंगाल और बिहार में अन्न की समस्या का

पूरा समाधान हो जायगा। लेकिन उन्होंने जो वक्तव्य दिया है उस से मालूम होता है कि अभी तक बिहार में सिंचाई की गई जमीन केवल 19 प्रतिशत थी और पश्चिम बंगाल में 16 प्रतिशत थी, इतनी ही जमीन पर सिंचाई का बंदोबस्त किया जा सका है। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि चूंकि बंगाल और बिहार में लोगों ने गेहूं और चना खाना सीख लिया है तो वहां की सम्पूर्ण खेती लायक जमीन में गेहूं व चना पैदा करने के लिए क्या वे पर्याप्त सिंचाई की व्यवस्था करने की कृपा करेंगे।

श्री जगजीवन राम : माननीय सदस्य को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि बिहार के कितने ऐसे क्षेत्र में जिसको आमतौर से समझा जाता था कि वह धान पैदा करने वाले क्षेत्र हैं वहां पर इस साल बहुत अच्छी गेहूं की फसल हुई है। जहां तक चने का सवाल है बिहार बहुत जमाने से चने की बहुत अच्छी फसल पैदा करता रहा है। और भी अधिक स्थानों में और क्षेत्रों में एक ही फसल नहीं बल्कि एक से अधिक फसल पैदा की जा सके इस के लिए तेजी से प्रबन्ध हो रहा है। बिहार सरकार जितनी तेजी से काम करेगी हम उतनी उनको उस में सहायता करेंगे।

श्री वेणीशंकर शर्मा : यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज हमारे किसान साल में दो, दो और तीन, तीन फसलें पैदा करने लगे हैं। अभी जब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र (बांका) में गया था तो मैंने देखा कि वहां हमारे किसान जगह-जगह जहां पानी की व्यवस्था है ताइचून धान लगा रहे हैं। आज तक मैंने इन दिनों खेतों में कहीं धान नहीं देखा था और मुझे यह देख कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि वहां आज कल ताइचून धान रोपा जाने के कारण जो खेतों में हरियाली देखने को नसीब हो रही है जोकि इस से पहले कभी देखने में नहीं आई थी तो क्या माननीय मन्त्री वहां सिंचाई के लिए किसानों को और भी अधिक मात्रा में पानी मुहैया किये जाने की व्यवस्था करेंगे क्योंकि वैसा करने से हमारे किसान बहुत आसानी से साल में तीन फसल पैदा कर सकेंगे। प्रश्न केवल पानी का है। मैंने बराबर मन्त्री महोदय से प्रार्थना की है, और आज भी फिर उन से प्रार्थना करूंगा कि कम से कम वे अपनी कैबिनेट से लड़ झगड़ कर पानी की व्यवस्था के लिए काफी रुपयों का इन्तजाम करें। चूंकि वे स्वयं भी बिहार से आते हैं इस लिये हमें उन पर बड़ा फख्र है। किन्तु अभी-अभी 1440 नं० के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया है कि बिहार में प्राइवेट ट्यूबवेल 8,000 और स्टेट ट्यूबवेल 70 लगाये जा रहे हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है वहां 570 स्टेट ट्यूबवेल लगाये जा रहे हैं और वेस्ट बंगाल में 450 लगाये जा रहे हैं। आखिर बिहार के साथ क्यों सौतेली मां का सा व्यवहार किया जा रहा है कि वहां सिर्फ 70 ट्यूबवेल ही लगाये जा रहे हैं?

श्री जगजीवन राम : पता नहीं कैसे माननीय सदस्य को सौतेली मां की याद हो आई। बराबर यह बात रही है कि बिहार की जितनी क्षमता खर्च करने की होगी और किसान कितना उतावलापन दिखलायेंगे उतना लैंड डेवेलपमेंट बैंक से उन्हें कर्जा मिल जायेगा?

Incentive Wages in Public Undertakings

*1452. **SHRI RABI RAY** : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the preliminary studies conducted by the Labour Bureau have shown that where incentive wages have been introduced in the public sector undertakings, labour productivity has gone up ;

(b) if so, whether it is a fact that this problem was considered at a Conference of the Heads of public sector undertakings held on the 19th April, 1968 ; and

(c) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI HATHI) : (a) to (c). The question was discussed at

the Meeting of Heads of Public Sector Undertakings held on 19.4.1968 with a view to obtaining their consent to certain data being made available to the Director Labour Bureau who has been asked to collect the necessary information. The Heads of Public Sector Undertakings have agreed to this proposal. I may add that in April information was collected but it was not very scientific.

श्री रवि राय : मैं पूछना चाहता हूं कि जब मन्त्री महोदय मानते हैं कि इस तरह का इन्सेन्टिव देने से पब्लिक सेक्टर अन्डरटेकिन्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तब जो पिछली इंडियन लेवर कांफरेंस हुई थी उस में इस पर बहस हुई थी ? यदि हुई थी तो क्या फैसला हुआ ?

श्री हाथी : इस पर तो बहस नहीं हुई है, लेकिन हर एक इंडस्ट्री में प्रोडक्टिविटी का समीकरण करने के बारे में तय किया गया है ।

श्री रवि राय : कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स जो तैयार किया गया है वह प्रोडक्शन पर किया गया है, तो कौन कौन साल की कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स को बेसिस माना गया है ?

SHRI HATHI : This is connected with productivity and if incentive schemes are given to the worker, if he produces more then he gets more. The idea is to have the wage fixed first—the basic wage, and then a portion is to be added as cost of living and third, according to the greater production, an incentive. These three combined should form the wage, and for that purpose, we want to find out where this incentive can be worked and for what. Certain data have to be collected, and therefore, we said at this meeting of the heads of public sector undertakings that where scientific data have been collected they may be supplied to the Labour Board. They have agreed.

श्री रवि राय : डेटा जो कलेक्ट है क्या आप टेबल पर रक्खेंगे ?

श्री हाथी : अभी उस को कलेक्ट करना है ।

श्री जार्ज फरनेन्डीज : जब अभी इन्सेन्टिव स्कीम अमल में लानी है तो क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि सभी मजदूर संगठनों के साथ बात चीत कर के और उन की सहमति से यह स्कीम अमल में लाई जायेगी, यूनियन को मान्यता है या नहीं है, इस किस्म के झंझट में न जाते हुए सिर्फ पैदावार बढ़ाने की बात ही दृष्टि के सामने रक्खी जायेगी ?

SHRI HATHI : In fact that is what I said before, and certainly the unions will be taken into confidence before this scheme is discussed ; definitely.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : मेरे प्रश्न का दूसरा भाग है मान्यता है या नहीं इस झंझट में न जाते हुए...

SHRI HATHI : Whatever is the plan, the workers will be taken into confidence.

SHRI K. NARAYANA RAO : Mr. Speaker, Sir, the public sector undertakings have been the subject of criticism all these years. In view of this, and also in view of the fact that they have not registered much improvement in spite of the criticisms, may I know from the hon. Minister whether they would consider that the workers' participation in profit-sharing can be a better solution out of this malaise in the public sector undertakings ?

SHRI HATHI : Not this actually, but in the last Indian Labour Conference, this question was considered as to how best the industrial relations in the public sector undertakings can be improved, and a bi-partite team might go into it.

श्री मुहम्मद इस्माइल : हैवी इंजीनिअरिंग कारपोरेशन रांची में मशीनें तैयार होती हैं। मैंने सुना है वहां पर कोई स्टडी टीम बनाई गई है प्रोडक्शन के लिये । मैं जानना चाहता हूँ कि यह ठीक है या नहीं । अगर नहीं बनाई गई है तो क्या किसी इन्सेंटिव स्कीम को बनाने की प्लैन आप कर रहे हैं जिस से प्रोडक्शन ज्यादा हो ? आप ने कोई इंस्ट्रक्शन इस सम्बन्ध में दिया है या नहीं ?

श्री हाथी : अभी तो सिर्फ कलेक्शन आफ डेटा का सवाल है । इस के लिये हमने वहां से भी डेटा मंगाया है उस के आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है ।

SHRI SHANTILAL SHAH : Will the Government see that in framing the incentive schemes they are not utilised to depress the wage for the workers and that these schemes are not utilised to get rid of someone else ?

SHRI HATHI : There is no question of getting rid of any workers. The question was that the more they produce, the more they get : they get the basic wage plus the cost of living allowance plus something by way of incentive if they produce more. That is the whole idea.

SHRI RANGA : It is quite clear that the Minister has tried to make us understand what is meant by the incentive scheme and what are its limitations. From ancient time—of Nandaji and Pandit Nehru—they have been talking of this workers' participation or partnership in the so-called profits which do not exist and also the incentive schemes. Why is it that Government are taking so many years to study this matter, sort out all the facts that they have at their disposal and then there after alone to come to a decision as to where, to what extent and in what manner this incentive scheme should be introduced in the public sector undertakings which are expected to set an example to all other entrepreneurs as ideal entrepreneurs ?

SHRI HATHI : The different industries will have to be looked into. It is not that one incentive scheme could apply to all. It will have to depend upon each particular industry because the conditions differ and the methods of production differ and that takes time.

SHRI D. C. SHARMA : We have very intimate relations with Yugoslavia and I think the incentive scheme has been worked much better in Yugoslavia, so far as I know, than in many of the democratic and other types of countries. May I, therefore, ask the hon. Minister whether he will be prepared to consider and try the Yugoslavian experiment so far as the public sector undertakings are concerned, so that the so-called Managers and Chairmen who know nothing about the public undertakings have as much of stake in those undertakings as the workers have ?

SHRI HATHI : I have not studied that scheme. So, I cannot say.

श्री देवेन सेन : मैं जानना चाहता हूं कि जो इन्सेंटिव स्कीम तैयार हुई है वह सभी मजदूरों की कटेगरीज पर लागू होगी या कुछ मजदूरों की कटेगरीज पर ही लागू होगी ।

श्री हाथी : अभी लागू करने की कोई बात तो है नहीं । कैसे कलेक्शन आफ डेटा हो इस के लिये प्रश्न है । सब पर लागू करना है या नहीं, यह बात नहीं है ।

उत्तर प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों का वितरण

*1453. **श्री मोलहू प्रसाद** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को उर्वरकों के वितरण के लिए दी जाने वाली अनुदान की राशि 1966-67 में 57 करोड़ रुपये से घटाकर 1967-68 में 19 करोड़ रुपये कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस कटौती के परिणामस्वरूप रासायनिक उर्वरकों की कीमत में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि अमोनियम सल्फेट की कीमत प्रति क्विन्टल 405 रुपये से बढ़कर 492 रुपये हो गई है; और

(घ) इस मूल्य वृद्धि को कम करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ताकि किसान अधिक अनाज का उत्पादन कर सके ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (घ). केन्द्रीय सरकार रासायनिक उर्वरकों के वितरण के लिये राज्य सरकारों को कोई अनुदान नहीं देती है । फिर भी, केन्द्रीय सरकार उन्हें उर्वरकों के विपणन व वितरण के लिये भी अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है ।

1967-68 की अवधि में उत्तर प्रदेश सरकार को अल्पकालीन ऋण के रूप में जो धनराशि दी गई वह 1966-67 की मंजूर की गई धनराशि से कहीं अधिक थी। 1967-68 की अवधि में उर्वरकों के विपणन या उर्वरकों के वितरण की तकाबी के लिये जो अल्पकालीन ऋण स्वीकार किया गया था वह क्रमशः 11.99 करोड़ रुपये व 9 करोड़ रुपये था जबकि 1966-67 में इनके लिये क्रमशः 1.95 करोड़ रुपये और 2.00 करोड़ रुपये मंजूर किये गये थे।

यह सच है कि 1 अप्रैल 1967 से अमोनियम सल्फेट का प्रति मीटरी टन (न कि प्रति क्विन्टल, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है) (अधिकतम) खुदरा विक्रय मूल्य 405 रुपये से बढ़ाकर 492 रुपये कर दिया गया था और 1 अप्रैल 1968 से मूल्य में और वृद्धि करके उसे 502 रुपये प्रति मीटरी टन कर दिया गया है। 1967-68 में मूल्यों में संशोधन करने के पश्चात भी, केन्द्रीय उर्वरक भण्डार उर्वरकों के विक्रय के लिये आंशिक रूप से सहायता दे रहा था और उसे उस वर्ष घाटा होने की सम्भावना है। परन्तु ठीक ठीक स्थिति का ज्ञान नहीं है क्योंकि उस वर्ष के लेखे को अन्तिम रूप देकर अभी उसकी लेखा-परीक्षा नहीं हुई। 1968-69 की अवधि में अमोनियम सल्फेट, यूरिया तथा म्यूरेट आफ पोटास के खुदरा मूल्यों में मामूली वृद्धि की गई है जिस से कि भण्डार को अपने कार्यकलापों में हानि न उठानी पड़े।

हाल ही के वर्षों में अपनाये गये विदेशी व संकर किस्मों के बीजों से होने वाली प्रति एकड़ अधिक उपज को दृष्टि में रखते हुए, कृषक लोग अब तक वर्तमान मूल्यों के होते भी उर्वरकों का उपयोग करना लाभप्रद अनुभव करते हैं। देश के विभिन्न भागों में उर्वरकों के कई बड़े कारखानों की स्थापना हो रही है जिससे उर्वरकों की उपलब्धि बढ़ेगी। आशा है कि ये कारखाने कम लागत पर उर्वरक तैयार कर सकेंगे। अतः ज्यों ही कुछ नये कारखाने उत्पादन शुरू कर देंगे इनके मूल्य नीचे गिर सकते हैं।

श्री मोलहू प्रसाद : जो विवरण रक्खा गया है उस में सरकार ने बतलाया है कि खुदरा बिक्री मूल्य 405 रु० से बढ़ा कर 492 रु० कर दिया था और 1 अप्रैल, 1968 से मूल्य में वृद्धि कर के उसे 502 रुपये प्रति मीटरी टन कर दिया गया है। इसी सन्दर्भ में मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि अपने देश में जितना उर्वरक पैदा होता है, चाहे निजी क्षेत्र में हो चाहे सार्वजनिक क्षेत्र में, उस पर कितने मीट्रिक टन लागत खर्च आता है और कितना बिक्री मूल्य आता है। जरा इस का ब्यौरा बतला दिया जाये।

श्री जगजीवन राम : अभी जो बतलाया है उससे ज्यादा बताने के लिये मेरे पास कुछ नहीं है।

श्री मोलहू प्रसाद : मैंने खाद के लागत खर्च के बारे में पूछा है। मैंने पूछा है कि निजी क्षेत्र में जो खाद पैदा होती है और सार्वजनिक क्षेत्र में जो पैदा होती है उसका लागत खर्च कितना होता है और बिक्री मूल्य कितना होता है। इसके बारे में मुझे पता नहीं कि मंत्री महोदय ने कब बताया था। यह जानकारी तो मिलनी ही चाहिये।

श्री जगजीवन राम : मैंने अनाज के बारे में बताया है। खाद के बारे में अगर माननीय सदस्य जानना चाहें तो यह इस प्रश्न में नहीं आता है। अगर माननीय सदस्य सूचना दें तो इसका जवाब भी उनको दिया जा सकता है।

श्री मोलहू प्रसाद : वक्तव्य में मंत्री महोदय ने कहा है : "हाल ही के वर्षों में अपनाये गये विदेशी व संकर किस्मों के बीजों से होने वाली प्रति एकड़ अधिक उपज को दृष्टि में रखते हुए, कृषक लोग अब तक वर्तमान मूल्यों के होते

हुये भी उर्वरकों का उपयोग करना लाभप्रद अनुभव करते हैं" ।

इसी संदर्भ में मैं पूछना चाहता हूँ कि नए किस्म के बीज हैं इनको ले कर केवल एक प्रतिशत किसान ही बो सकते हैं या जिन के पास भरपूर सिंचाई का प्रबन्ध है वही बो सकते हैं क्या यह सही नहीं है ? यदि यह सही है तो सामान्य किसान को क्या सरकार सस्ते उर्वरक देने का प्रयास कर रही है ।

श्री जगजीवन राम : अभी तक सिंचाई के क्षेत्र में और अच्छे बीज लगाने वाले जो किसान हैं उनको जितने की जरूरत होती है वह भी देश में पैदा होने वाले और बाहर से मंगाये जाने वाले खाद से पूरी नहीं होती है, उनको भी पर्याप्त मात्रा में वह नहीं मिल पाती है। यह सही है कि उसके बाहर के किसानों को कोई अच्छी मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं ।

SHRI VIRENDRAKUMAR SHAH : The distribution of fertilisers is done by the State, but the Centre is concerned with higher foodgrain production. May I know whether Government is aware that the distribution, particularly of nitrogenous fertilisers, in various States and in Gujarat in particular, being made through the co-operative societies is not reaching the farmers and whether he would consider advising the State Governments to supply nitrogenous fertilisers not only through co-operative societies...

MR. SPEAKER : From U.P., the hon. member is going to other States.

SHRI VIRENDRAKUMAR SHAH : It is a general question about all States.

MR. SPEAKER : Unfortunately the main question relates to U. P.

श्री महाराज सिंह भारती : मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है कि आगे चल कर जब उत्पादन बढ़ जाएगा तब कीमतें नीचे आ जायेंगी । जहां तक पोटाश की खाद का सम्बन्ध है इसको आप हमेशा इम्पोर्ट करेंगे । इस वास्ते उसकी कीमत नीचे आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है । जितनी आगे आपकी फैक्ट्रियों में खाद का उत्पादन होगा । उस उत्पादन के सत्तर प्रतिशत पर कोई मूल्यों पर आपका नियन्त्रण नहीं होगा । आपने जो यह कहा है स्टेटमेंट में कि आगे पैदावार बढ़ेगी तो इससे क्या कीमत आप समझते हैं कि कम हो जाएगी ? क्या आप यह समझते हैं कि जितनी मांग होगी उससे ज्यादा पैदावार आप करने जा रहे हैं ?

श्री जगजीवन राम : जितनी मांग होगी उससे ज्यादा पैदा करने हम जा रहे हैं यह दावा तो मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मांग तो बराबर बढ़ने वाली है और जैसे-जैसे किसानों में इस चीज की पहुँच होती जाएगी, नए बीजों की, पानी की तो खाद की बहुत ज्यादा मांग होगी । इस में भी शक नहीं है कि दुनिया में हम सब से कम खाद इस्तेमाल करते हैं पर कैपिटा, लेकिन अभी जो कुछ हम देख रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि जितनी हमारी फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के हाथ में स्कीमें है कारखाने खड़े करने की वे अगर खड़े हो जायेगें तो दाम अभी जो हैं उसके मुकाबले में नीचे आ जायेगे ।

Commercialisation of Indian Agriculture

\+

*1455. **SHRI SHIVA CHANDRA JHA :**
SHRI KASHI NATH PANDEY :

Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Indian agriculture has been more Commercialised since the First Plan period ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the present percentage of commercial crops *vis-a-vis* thai of the foodgrains production relative to what it was at the beginning of the First Plan ?

THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI JAGJIWAN RAM) : (a) to (c). A statement is pleased on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT—1026/68].

श्री शिव चन्द्र झा : मैं जानना चाहता हूँ कि कमर्शियल क्राप्स की जो पैदावार बढ़ी है यह एट दी कास्ट आफ फूडग्रेंज बढ़ी है या नई जमीन को तोड़ा गया है और वहां पर कमर्शियल क्राप्स की पैदावार की गई है इस वजह से पैदावार बढ़ी है ?

श्री जगजीवन राम : कुछ जगह ऐसा भी हुआ है। कुछ इलाके में थोड़ा अनाज वाला क्षेत्र कम हुआ है। कुछ नए तरीके से बढ़ी है। थोड़ा सा इसका असर अनाज पर पड़ा है।

श्री शिव चन्द्र झा : कमर्शिलाइजेशन की एक लहर सी चल पड़ी है और इसकी वजह से जैसे रशिया में कुलाक्स पैदा हो गये थे इसी तरह से यहां भी कुलकाइजेशन की एक लहर चल गई है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह बात सही नहीं है ?

श्री जगजीवन राम : यह बिल्कुल सही है कि देहातों में जो बड़े किसान हैं वे नए तरीके से ज्यादा लाभ उठा रहे हैं और जो छोटे किसान है वे उससे लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। यह भी ठीक है कि जो नये बीज हुए हैं या रासायनिक खाद हुई है इसका फायदा उनको अधिक पहुँचा है जिन के पास साधन है। यह तो वस्तुस्थिति है।

SHRI SHIVAJIRAO S. DESHMUKH : Is the Government aware that even in the case of commercial crops, the economy is so deficient that there is large scope not only for increase in production of commercial crops in competition with foodgrains, but along with foodgrains ? To achieve this end, does the Government propose to encourage, not commercialisation, but acceptance of the basic commercial principle of recognising agriculture as an industry and treating it as such ?

SHRI JAGJIWAN RAM : That is the whole trend. With the new strategy in agriculture, we are lifting it from the subsistance stage to commercial or paying stage.

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैं जानना चाहता हूँ कि इन फसलों के बारे में भी मंत्री महोदय वही नीति अपनाने जा रहे है जो कि उन्होंने अनाज के बारे में अपनाई है ? होता यह है कि ये फसलें जब आती हैं तो जो बड़े व्यापारी हैं वे इनको बहुत सस्ते दामों पर ले कर इन्हें बहुत ऊंचें दामों पर बेचते हैं और ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। इस मुनाफे में कमी हो सके और काश्तकार को उचित और अधिक दाम मिले सके, इसके लिए क्या कोई विशेष नीति अपनाने जा रहे हैं ?

श्री जगजीवन राम : इस पर तो बराबर विचार होता रहता है कि ऐसा कोई इंतजाम रहे कोओप्रेटिव्ज के जरिये या कमोडिटी कारपोरेशन के जरिये कि किसान को निर्धारित मूल्य मिल सके और फसल के वक्त पर व्यापारी सस्ते दामों पर खरीद कर बेमुनासिब मुनाफा न उठा सकें।

SHRIMATI TARKESHWARI SINHA: In view of the large imbalance between the price ratio of commercial crops *vis-a-vis* foodgrains, there is likerihood of diversion taking place, as it happened recently in sugarcane. Has the Government devised any scheme by which the relative stability of commercial crops and foodgrains may be maintained to avoid this diversion, which affects our total production capacity ?

SHRI JAGJIWAN RAM : Constant exercises are done on that question so that we can have something like a price parity between various agricultural commodities. But I will not claim that any very satisfactory solution has been yet found.

Food Corporation of India

*1456. SHRI PREM CHAND VERMA: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the quantity of foodgrains which has been handled by the Food Corporation

of India during 1967-68 from indigenous and imported sources separately ;

(b) the expenditure incurred on the Organisation during the above period ; and

(c) the over-head charges incurred by the Corporation on the handling of foodgrains till their distribution and charges realised from the consumers ?

THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI JAGJIWAN RAM) : (a) The Food Corporation of India handled the following quantities of foodgrains during the financial year 1967-68 :—

(Figures in lakh tonnes)

(i) Indigenous	...	30.6
(ii) Imported	...	25.0

(b) About Rs. 541 lakhs on the basis of provisional figures of expenditure for 1967-68.

(c) The estimated expenditure on overhead charges (*i.e.* administrative charges, interest, milling, handling charges, and freight) of the Corporation works out to about Rs. 5/- per quintal for the year 1967-68 upto the stage of issue of foodgrains to the nominees of the State Governments. The Corporation does not sell foodgrains in retail to consumers. The retail prices to be charged from the consumers are fixed by the respective State Governments and are based on the cost of foodgrains received from all sources including internal purchases and also after taking into account the State's administrative charge, margin allowed to the retailer and local taxes if any.

श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या यह सही है कि फूड कारपोरेशन का जो प्रशासनिक खर्चा है, उस सब को इस में जोड़ लिया जाता है; यदि हां, तो इस खर्चे को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ? फूड कारपोरेशन के प्रशासनिक खर्चे का जिक्र अखबारों में और कुछ रिपोर्टस में भी किया गया है और कहा गया है कि वह खर्चा बहुत ज्यादा है, जब कि उस का काम जितना अच्छा होना चाहिये, वह उतना अच्छा नहीं है । क्या मन्त्री महोदय इस बारे में कुछ कार्यवाही करेंगे ?

श्री जगजीवन राम : इस को बराबर देखा जाता है और जहां तक मालूम है, उसका प्रशासनिक खर्चा बहुत ज्यादा नहीं है । कभी यह होता है कि अगर अनाज ही कम मिले, तो ज्यादा खर्चा पड़ता है । लेकिन, जैसा कि मैंने बताया है, कई एक मदों को मिला कर जो खर्चा है, उस को ज्यादा नहीं कहा जा सकता है ।

श्री महन्त दिग्विजय नाथ : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न पूछने से पहले यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस प्रश्न की सूचना मैं ने दी थी, उस में परिवर्तन कर दिया गया है । उस को तोड़-मरोड़ देने से उस के मूल अर्थ का उद्देश्य ही निकल गया है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप प्रश्न पूछना चाहते हैं या नहीं ?

श्री महन्त दिग्विजय नाथ : मेरा निवेदन यह है कि मूल प्रश्न के आधार पर यह मेरा प्रश्न नहीं है, यह दूसरा प्रश्न है ।

MR. SPEAKER : Normally they club them. If the hon. Member does not want to put the question I will call the next name on the list. There are five names.

श्री महन्त दिग्विजय नाथ : मैं इस प्रश्न में संशोधन करना चाहता हूं । लेकिन मंत्री महोदय छपे हुए प्रश्न का ही उत्तर दें ।

SHORT NOTICE QUESTION

"ताजिया" के कारण लखनऊ-दिल्ली डाकगाड़ी का रोका जाना

SNQ. 25. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री राम चरण :
श्री बशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लखनऊ-दिल्ली डाकगाड़ी, जिसका दिल्ली स्टेशन पर पहुँचने

का निर्धारित समय प्रातः 9 बजे था, 10 अप्रेल, 1968 को दोपहर बाद लगभग साढ़े तीन बजे वहां पहुँची;

(ख) क्या रेल की पटरी पर एक 'ताजिया' रखे जाने के कारण गाड़ी को रुकना पड़ा था;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है, और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री रोहन लाल चतुर्वेदी) (क) जी हां।

(ख) से (घ). 9 अप्रैल, 1968 की रात को लगभग 10.00 बजे मुहर्रम के जुलूस में शामिल कुछ लोग जो ताजिये ले जा रहे थे, मुरादाबाद में एक समपार से रेलवे लाइन को पार करना चाहते थे। चूंकि उन में से एक ताजिया इतना ऊंचा था कि वह रेलवे की ऊपरी संचार तारों के नीचे से नहीं गुजर सकता था, इसलिए जुलूस के लोगों ने आग्रह किया कि जुलूस ले जाने के लिए तार काट दिये जायें और उन्होंने गाड़ियों को समपार से गुजरने नहीं दिया। चूंकि कानून और व्यवस्था बनाये रखना स्थानीय सिविल प्राधिकारियों की जिम्मेदारी है, इसलिए इस मामले की सूचना विधिवत् उत्तर प्रदेश सरकार के जिला प्राधिकारियों को दे दी गई। जिला प्राधिकारियों ने लाइन के ऊपर लगे तारों को काटने का आदेश दिया और 10.4.68 को सवेरे 5 बजकर 20 मिनट पर उन तारों को काट देना पड़ा। इसकी वजह से 10.4.68 के सवेरे तक गाड़ियों का आना-जाना बन्द रहा और परिणामस्वरूप कई गाड़ियां आधे घन्टे से लेकर लगभग सात घन्टे तक रुकी रहीं।

श्री महन्त दिग्विजय नाथ : मैं जिस गाड़ी से सफर कर रहा था और मेरे साथ उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व खाद्य मंत्री और अब इस सदन के माननीय सदस्य, श्री झारखंडे राय भी थे। हमारी गाड़ी जिस वक्त रामपुर में रुकी रही, तो कारण पूछने पर पता चला कि लाइन पर ताजिया रख दिया गया है। उस वक्त हरिद्वार अर्द्धकुम्भ का अवसर था। जहां तक मुझे सूचना मिली है, इस कारण से वहां पर 18 गाड़ियां, जिसमें मालगाड़ी, मेल और पैसेन्जर रोक दी गयी। जब तक ये तार नहीं काटे गये, तब तक उन गाड़ियों को जाने की आज्ञा प्रदान नहीं की गयी। इस प्रश्न के पूछने का मेरा अभिप्राय यह है कि ये जो घटनायें आज देश में साम्प्रदायिक दंगों के नाम पर हो रही हैं, वे एक चेन हैं, जिसकी यह एक कड़ी है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि मुरादाबाद में कटघर के पास जिस जगह पर ट्रेन पर यह ताजिया रख दिया गया था, क्या उस जगह पर पहले भी कभी ताजिया रखा गया था; यदि रखा गया था, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इतना ही बड़ा ताजिया या इस से छोटा ताजिया हमेशा जाया करता था। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि रेलवे ट्रेक पर टेलीफोन के तार नये लगाये गए थे या पुराने लगे हुए थे; यदि पुराने लगे थे, तो प्रतिवर्ष यह ताजिया कैसे ले जाया जाता था और इस स्थिति में ये तार काटने का आदेश क्यों दिया गया। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि ये तार काटने की जिम्मेदारी रेलवे अधिकारियों पर है, अथवा केन्द्रीय गृह मंत्रालय के आदेश से ये तार काटे गए ?

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : माननीय सदस्य का पहला प्रश्न यह है कि क्या यह ताजिया रेलवे लाइन पर पहली दफा रखा गया। उस सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना है कि वह पहली दफा वहां रखा गया था। उनका दूसरा प्रश्न यह है कि क्या ये तार हमेशा वैसे ही लगे थे और क्या वे पहले इतने ही ऊंचे थे। उस सम्बन्ध में मैं सिर्फ इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि शायद दिसम्बर, 1967 में वायर्ज का कुछ रीएलाइनमेंट हुआ था और उस सिलसिले

में शायद कुछ ऊंच-नीच हो गई हो। मैं उसके बारे में ठीक से नहीं बता सकता हूं।

श्री महन्त दिग्विजय नाथ : यात्री गाड़ियों और माल-गाड़ियों के घंटों लेट होने के कारण हजारों यात्रियों को जो असुविधा हुई और आवश्यक कार्यों में विलम्ब होने से उन्हें जो मानसिक तथा आर्थिक क्षति उठानी पड़ी, उस की जिम्मेदारी किस पर है ?

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : जब इस किस्म की कोई घटना होती है, तो परेशानी सब को सहनी पड़ती है, माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि चूंकि वह अर्द्ध-कुम्भ का समय था, इसलिए काफी यात्री जा रहे थे। सिवाये इसके कि इसके लिए मैं खेद प्रकट करूं कि उन को तकलीफ हुई, मैं इस वक्त इसका और क्या उत्तर दे सकता हूं ?

श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या यह सही है कि यह जो ताजिया पटरी पर रखा गया, वह जान-बूझ कर, योजनाबद्ध तरीके से, झगड़ा और शरारत करने के लिए रखा गया था ? क्या रेलवे प्रशासन ने इस के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही की है; यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ? इस कारण जो गाड़ियां लेट हुई, उससे यात्रियों को जो परेशानी हुई और जो तार काटे गये, इससे कितनी धन-हानि हुई है, क्या सरकार ने इसका हिसाब लगाया है ?

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : माननीय सदस्य ने यह संकेत किया है और पूछा है कि क्या यह ताजिया आर्गनाइज्ड वे में और किसी योजना के अनुसार वहां पर रखा गया था। इस सिलसिले में मैं कुछ बताने की स्थिति में नहीं हूं। इसके बारे में स्थानीय प्राधिकारियों, अफसरों, को ज्यादा मालूम होगा। जो सूचना मेरे पास है, वह मैंने दे दी है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : इस सवाल की सूचना 11 अप्रैल को दी गई थी। क्या अब तक मंत्री महोदय को इस बारे में जानकारी नहीं मिली है ? यह बड़े दुख की बात है।

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : इस के बारे में मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि हमने स्थानीय प्राधिकारियों, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सुपरिटेडेंट पुलिस को इनफर्मेशन, इत्तिला दे दी और उन्होंने जरूरी कार्यवाही की। इसमें रेलवे मंत्रालय क्या कर सकता है ?

श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या उन लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई ? क्या इस मामले की कोई छानबीन की गई कि किन लोगों ने इसमें भाग लिया ?

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : माननीय सदस्य थोड़ा समझने की कोशिश करें, यह मेरा निवेदन है। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों का, रेलवे मंत्रालय का, पहला फर्ज यह है कि स्थानीय प्राधिकारियों को, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सुपरिटेडेंट आफ पुलिस को, खबर करें। वे ला एंड आर्डर के लिए रेसपांसीबल हैं। जब ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है, तो जैसे वे आदेश देंगे, वह करेंगे। रेलवे मंत्रालय अपने आप कुछ नहीं कर सकता है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। क्या रेलवे प्रशासन ने कोई कानूनी कार्यवाही की, क्या पुलिस में रिपोर्ट कराई ?

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : हम लोगों को इतनी ही कानूनी कार्यवाही करना है कि डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज को खबर कर दी जाये। जो कार्यवाही करना उनका फर्ज है.....

MR. SPEAKER : What he wants to know is whether anybody has been arrested and what action has been taken. If the Minister has that information he may give it.

SHRI R. L. CHATURVEDI : About arrests and all that I have no information.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह उत्तर पूरा नहीं है। रेलवे की पटरियों पर ताजिये रखना या कोई चीज रखना, जिससे रेलों के आने जाने में कठिनाई पैदा हो—यह रेलवे एक्ट के अन्तर्गत जुर्म है.....

MR. SPEAKER : He has said, "We reported to the Superintendent of Police and to the district authorities."

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इसके खिलाफ रेलवे पुलिस स्वयं कार्यवाही कर सकती है। मैं जानना चाहता हूं कि रेलवे पुलिस ने कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : इस चीज को माननीय सदस्य जरा समझने की कोशिश करें.....

श्री हुकम चन्द कछवाय : आप ने ही समझने का ठेका लिया है।

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे मामले में डिस्ट्रिक्ट अथोरिटीज को खबर करना पड़ता है, हम लोगों ने.....

श्री हुकम चन्द कछवाय : अगर कोई पटरी उखाड़ दे तो क्या आप कुछ नहीं करेंगे, आपको इस में करने का कोई अधिकार नहीं है ? अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का कोई उत्तर नहीं आया मैं जानना चाहता हूं कि इस में कितनी धन हानि हुई है ?

MR. SPEAKER : I am not allowing you. There must be a stop at some stage. There must be some limit.

श्री भारखंडे राव : मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह ताजिया या बहुत से ताजिये—चूंकि यह मामला रेलवे क्रासिंग पर हुआ था क्या लाइन पर रखे गये थे या लाइन के किनारे जो रोड थी, उस पर रखे गये थे ?

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : इनको लेबल क्रासिंग के गेट्स के पास जो सड़क एक तरफ बरेली को जाती है और दूसरी तरफ चन्दौसी को जाती है—जो कि गेट से 20-25 फुट की दूरी पर है, रखा गया था। लेकिन इस दरमियान जलूस के लोग काफी तादाद में वहां पर मौजूद थे। उन्होंने एक्जेक्टली लाइन के ऊपर या जरा हट कर रखा, इस सिलसिले में मैं बिलकुल ठीक तो नहीं बता सकता, लेकिन यह निश्चित है कि रेलवे किसी तरह से चल नहीं सकती थी, क्योंकि हमारा रास्ता ब्लाक था।

MR. SPEAKER : Calling-attention notice. Shri Rabi Ray.

SHRI BAL RAJ MADHOK : Sir, I want to put a question.

MR. SPEAKER : I have called him now.

SHRI BAL RAJ MADHOK : Sir, I protest. It is such an important question and you do not allow supplementaries.

MR. SPEAKER : I know it but you did not get up earlier.

SHRI BAL RAJ MADHOK : I stood up in the very beginning.

MR. SPEAKER : Shri Rabi Ray.

SHRI BAL RAJ MADHOK : I protest against this communal approach of the Government of India and those people who did it. Such a thing never happened any. where in the world, not even in the western countries. This must stop. I strongly protest against the policy that the Government of India is pursuing.

SHRI R. L. CHATURVEDI : This is a matter of opinion.

MR. SPEAKER : Do not add to my trouble. The moment you look at them and get up, you add to my trouble. Shri Rabi Ray.

———

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Indo-West German Agreement

*1437. SHRI C. CHITTYBABU : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that India and West Germany signed an agreement on the 26th March, 1968 on Bonn's assistance for the setting up of Training and Research Institute at Calcutta;

(b) If so, the form in which the assistance will be provided;

(c) what will be the expenditure on the whole scheme; and

(d) the object of the institute ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION (SHRI S. C. JAMIR) : (a) Yes.

(b) The West German Government will provide assistance in the form of Advisers, Fellowships and equipment.

(c) About Rupees eighty-one lakhs.

(d) The Institute will conduct research in trade training, prepare material for the performance of trade training, provide supplementary training to Central and State Officers concerned with Craftsmen training and extend advice to Indian industry on all matters relating to industrial training.

Bharat Sewak Samaj

*1438. SHRI JYOTIRMOY BASU : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the recent statement of Shri S. S. Singh, Joint Secretary Bharat Sewak Samaj stating that "till 1965-66 Government had not demanded the consolidated accounts"; and

(b) if so, the reasons for violating the provisions of G. F. R. ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI M. S. GURUPADASWAMY) : (a) :Yes, Sir.

(b) The issue that General Financial Rule 149 (3) required annual consolidated statement of accounts of the grantee institutions, came to the fore in the context of the Thirty-Fourth report of the Public Accounts Committee (Third Lok Sabha), It was duly examined and accepted, with retrospective effect, both by the Government and Bharat Sewak Samaj.

रामकृष्णपुरम में सार्वजनिक टेलीफोनों का लगाना

*1439. श्री यशपाल सिंह :
श्री बलराज मधोक :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली के कुछ दुकानदारों ने सार्वजनिक टेलीफोन लगाने के लिये आवेदन-पत्र भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने आवेदन-पत्र मिले हैं और किस-किस तारीख को मिले हैं; और

(ग) उन पर कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) 37 इनमें से 17 आवेदन-पत्र मार्च 1967 तक मिले और 20 आवेदन-पत्र 1967-68 में प्राप्त हुए।

(ग) टेलीफोन केन्द्र की अक्षमता और सिक्के डाले जाने वाले टेलीफोन बक्सों के उपलब्ध न होने के कारण।

वर्ष 1968 में देश में निर्मित किये जाने वाले नलकूप

*1440. श्री ओ० प्र० त्यागी : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 में देश में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कुल कितने नलकूपों का निर्माण करने का विचार है;

(ख) नलकूपों के निर्माण के लिये प्रत्येक राज्य को कितनी वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है; और

(ग) इन से कितने एकड़ भूमि में सिंचाई होने की सम्भावना है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या** LT 1027/68]

टेलीफोन दिये जाने की प्रक्रिया

*1441. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन देने के संबंध में सरकार ने कोई नई प्रक्रिया अपनाई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस नई प्रक्रिया के अन्तर्गत सामान्य आय वाले लोगों के लिये कोई सुविधा दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) टेलीफोन देने सम्बन्धी मौजूदा नियमों में कुछ सीमा तक संशोधन किया गया है।

(ख) टेलीफोन देने सम्बन्धी संशोधित नियमों के अनुसार 1 जनवरी, 1968 से 'अपना टेलीफोन योजना' का आगे ऐसे सभी स्थानों के लिए विस्तार किया गया है जहां की संस्थापित क्षमता 1000 लाइनों या इससे अधिक की है। आगे जब कभी किसी स्थान की संस्थापित क्षमता 1000 लाइनों तक पहुँचेगी, उस स्थान पर 'अपना टेलीफोन योजना' चालू कर दी जायेगी। ऐसे स्थान जहां प्रचलित 'अपना टेलीफोन योजना' में कुछ ढील बरती जाती जाती थी, उसे 1 जनवरी, 1968 से खत्म कर दिया गया है। टेलीफोन देने के लिए एक्सचेंज की क्षमता का इस प्रकार विभाजन किया गया है –

वर्ग	ऐसे स्थान जहां 1 जनवरी 1968 से पूर्व 'अपना टेलीफोन योजना' चालू थी	ऐसे स्थान जहां 1 जनवरी, 1968 से 'अपना टेलीफोन योजना' लागू की गई
अपना टेलीफोन योजना	70 प्रतिशत	50 प्रतिशत
विशेष	15 प्रतिशत	20 प्रतिशत
सामान्य	15 प्रतिशत	30 प्रतिशत

जिन स्थानों पर 'अपना टेलीफोन योजना' लागू नहीं है, यह विभाजन इस प्रकार होगा—

सामान्य 80 प्रतिशत

विशेष —20 प्रतिशत

(ग) जी हां।

(घ) टेलीफोन देने के इससे पहले के नियमों में 'सामान्य' वर्ग के अन्तर्गत टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी। अब जिन स्थानों पर 1 जनवरी, 1968 से पूर्व 'अपना टेलीफोन योजना' लागू थी, 15 प्रतिशत आरक्षण और जिन स्थानों पर 'अपना टेलीफोन योजना' 1 जनवरी, 1968 से लागू की गई है, 30 प्रतिशत आरक्षण किया गया है। जिन स्थानों पर 'अपना टेलीफोन योजना' लागू नहीं है, इससे पहले के 'सामान्य' वर्ग के 70 प्रतिशत के नियतन को बढ़ा कर 80 प्रतिशत कर दिया गया है।

Smuggling of Sugar from Nepal

*1443. SHRI SITARAM KESRI : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that large quantities of sugar are being smuggled into India from Nepal across the border in Bihar and U. P.;

(b) whether it is also a fact that the smuggled sugar is being sold at a price lower than the ex-mill rate for sugar released to the open market; and

(c) if so, the steps taken to check the smuggling ?

THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI JAGJIWAN RAM): (a) to (c). The State Governments of U. P. and Bihar have reported that they have no authentic information of the movement across the border of sugar other than Indian or Nepalese Sugars from Nepal into India or the price at which it is sold. They have however alerted the district authorities to prevent any movement across the border of sugar not of Indian or Nepalese origin.

खाद्य तेलों का आयात

*1444. **श्री शशि भूषण वाजपेयी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों से खाद्य तेलों के आयात का देश में तेल के उत्पादन तथा कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या इस प्रकार के आयात के कारण कृषकों को मूंगफली तथा अन्य वस्तुओं के, जिन से तेल निकाला जाता है, कम दाम मिलेंगे; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 1965 – 67 के दौरान खाद्य तेलों के आयात ने देसी तेलों की कमी जोकि उन वर्षों में सूखे की स्थिति होने के कारण उत्पादन कम होने से हुई थी, को पूरा ही किया था।

(ख) उपर्युक्त वर्षों में मूंगफली और अन्य तिलहनों के मूल्य बहुत ही अधिक चढ़ गये थे। 1967 के उत्तरार्द्ध में मूंगफली तथा अन्य तिलहनों की अच्छी फसल होने की प्रत्याशा में मूल्य गिरने लग गये थे।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Agricultural Commission

* 1446. SHRI BHOGENDRA JHA : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to refer to the reply given to starred Question No. 914 on the 28th March, 1968 and state :

(a) whether consideration of the proposal to set up the Agricultural Commission has since been completed;

(b) If so, whether the Commission has been set up and if so, its personel and terms of reference; and

(c) if not, the resaons for the delay ?

THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI JAGJIWAN RAM): (a) to (c). The matter is still under consideration.

National Labour Commission

*1447. SHRI S. M. BANERJEE : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) when the National Commission on Labour is likely to submit its report;

(b) whether the Commission will submit some interim Report shortly; and

(c) if so, when ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI HATHI) : (a) The National Commission on Labour is likely to submit its report by end of December 1968.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Machinery lying idle in Monghyr Post Office

*1448. SHRI MADHU LIMAYE : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have received a complaint about machinery worth lakhs of rupees lying idle in Monghyr Post Office, Bihar ;

(b) whether the letter also contains complaints about the trunk call arrangements, etc. ;

(c) whether any enquiry has been held in the matter ; and

(d) if so. the result thereof and the action taken by Government on the complaint ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND COMMUNICATIONS (SHRI I. K. GUJRAL) : (a) Yes, Sir. A camplaint dated 2-4-68 has been received It related to delay in utilisation of automatic exchange equipment.

(b) Yes, Sir.

(c) Yes, Sir.

(d) Regarding automatic exchange equipment, Government were aware of the posltion of its being unutilised due to delay in building construction. Keeping it in view, diversion of equipment to Deogarh was approved in January, 1968. The equipment is now under installation there. As far as Monghyr is concerned, the building construction will be expedited and Deogarh equipment which is expected to be delivered later will be utilised for its automatisation.

Regarding trunk working, the trunk line between Patna and Monghyr which carries the bulk of Monghyr traffic, has been subject to very frequent copper wire thefts, disrupting the trunk working. The replacement of this line by Aluminium Conductor Steel Reinforced (ACSR) wire is under examination.

दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश में सब्जियों के बीजों पर बिक्री कर

*1449. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में सब्जियों के बीजों पर बिक्री कर बढ़ाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या इस कर को हटाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि 1 अप्रैल 1968 से उत्तर प्रदेश में भी कुछ बीजों पर बिक्री कर बढ़ाया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). सम्बन्धित राज्यों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Coastal Fish Reserves

*1450. SHRI S. K. TAPURIAH : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the schemes which will exploit the coastal fish reserves in the different regions during the year 1968-69 ;

(b) the likely fish yield to be exported from these reserves during the above period; and

(c) whether certain vested interests in the fishing industry in any way stand in the way of fuller exploitation of the coastal fish food reserves which possess termendous potential of fish food ?

THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI JAGJIWAN RAM) : (a) The major schemes designed to increase fish landings from the coastal areas may be classified as follows :—

(i) mechanisation of small fishing craft.

(ii) expansion of off-shore fishing with larger fishing craft.

(iii) assistance for improvement of wooden boats.

(iv) supply of fishery requisites such as nets.

(v) assistance to fisheries Co-operative Societies and fishermen.

(vi) provision of landing and berthing facilities, refrigeration and transport.

(b) The above schemes are expected to yield an additional annual fish production of approximately 45,000 tonnes of fish of which approximately 1500 tonnes will be the additional quantity of processed fish exported during the last three years is 19,000 tonnes.

(c) No Sir. The fishing industry and its ancillaries cover a wide field and the interests of one sector may not always concide with those of other sectors. All steps are directed towards securing the

maximum concerted effort in the interests of over-all development.

Government Industrial Schools in Haryana

*1454. SHRI R. S. VIDYARTHI : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the Haryana Government are closing down the 3 Government Industrial Schools located at Rohtak, Hissar and Panipat ; and

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION (SHRI S. C. JAMIR) : (a) On an enquiry made by the Labour Department, the Government of Haryana have intimated that they intend to close down the Government Industrial Schools at Rohtak, Hissar and Panipat this year.

(b) The reasons given are :—

(i) The admissions in schools have not been encouraging to justify their continuance.

(ii) Similar trade courses as are being run in these schools, are also being run at the Industrial Training Institutes at these places. There is, therefore, no need for duplication of these training facilities.

(iii) There will be an economy in expenditure with the closing of the Schools.

Sale of Milk by D.M.S.

*1457. SHRI M. L. SONDHI : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government are receiving complaints against the D. M. S. Depot Staff for selling milk to the nearby shops or disposing it to cash customers while card-holders go blank ;

(b) whether depots are closed ahead of the scheduled time and unless card-holders reach much ahead of opening time they have to go disappointed ; and

(c) whether the working of the depots is proposed to be streamlined ?

THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI JAGJIWAN RAM) : (a) Yes, Sir ; some complaints are received against the D. M. S. depot staff for selling milk to nearby shops or to others instead of supplying to the card-holders.

(b) These complaints are also received.

(c) Yes.

(i) Immediate enquiries are made into complaints against depot staff and disciplinary action is taken as soon as it is found that major complaints such as non-delivery of milk to token-holders or irregular early closing of milk depots are established.

(ii) The inspecting staff are regularly visiting milk depots, at least twice a week. Attempts are being made to tighten up supervision of the depots. The Manager (Distribution) holds regular staff meetings, every week, of the entire inspecting staff to review the position and improve the functioning of the depots.

(iii) The Complaint Cell works from 6 A.M. to 6 P.M. and deals with the complaints received on the telephone.

(iv) Tokens are periodically verified with ration cards to detect bogus tokens.

(v) The depot staff maintains 'tickler form' to guard against use of a milk token more than once.

Non-payment of Telephone Bills in Delhi

*1458. SHRI D. N. PATODIA : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that nearly 60 per cent of defaulters who do not pay the telephone bills, constitute Government offices in Delhi ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) the stops which are usually taken against such defaulters ; and

(d) the reasons for not devising so far better payment procedure to bring down this percentage ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND COMMUNICATIONS (SHRI I. K. GUJRAL): (a) No, Sir. Based on sample survey, about 55% subscribers do not pay in time. Of these, about 35% are Government subscribers.

(b) The reasons are not known to the P. and T. Department.

(c) A telephonic reminder is issued and if default persists, the telephone is disconnected. Efforts at recovery are, however, continued.

(d) The existing procedure of disconnection is already yielding results. Rebate has also been introduced, as an experimental measure, in Delhi as an inducement for prompt payment.

Advance of Rann of Kutch

*1459. SHRI VIRENDRAKUMAR SHAH: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether there is a scheme to create a 'Defence Strip of Trees' along the entire border of the Rann of Kutch with a view to restricting the advance of the Rann to other fertile areas;

(b) if so, the progress so far made in the implementation of the scheme;

(c) the Central aid which is being given for the implementation of the scheme, in view of its strategic importance;

(d) whether the scheme has been reviewed and revised in the context of the Award given by the Kutch Tribunal relating to the boundary between the Rann of Kutch and Sind and if so, what is the revised thickness of the forest belt to be created; and

(e) when the scheme is likely to be completed?

THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI JAGJIWAN RAM): (a) to (e). The required information is being collected from the State Government and will be placed on the Table of the Sabha.

Minimum Wages Advisory Committee's Report

*1460. SHRI K. R. GANESH: Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether Report of the Minimum Wages Advisory Committee for Andaman and Nicobar Islands has been submitted to the Andaman Administration;

(b) if so, when;

(c) whether Government have taken any decision on it; and

(d) if not, when the decision is proposed to be taken thereon?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI HATHI): (a) Yes.

(b) On 4th December 1967.

(c) and (d). The matter is under examination.

East Pakistan Refugees in Tripura

*1461. SHRI MANIKYA BAHADUR: Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) the total number of East Pakistan migrants who have entered Tripura since 1963;

(b) how many of them have since been rehabilitated and at what cost and the Central assistance given for the purpose so far;

(c) whether the Chief Minister of Tripura has lately been demanding rehabilitation benefits for new migrants from East Pakistan in Tripura; and

(d) if so, Government's reaction thereto?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION (SHRI D. R. CHAVAN): (a) 1,55,213 persons upto 15th April, 1968.

(b) The position about their rehabilitation is as under:—

(i) Of the 1,55,213 migrants, 70,535 came on the basis of exchange of properties. A sum of Rs. 10,51,983 has been paid as rehabilitation

loan so far for the purchase of bullocks to them ;

(ii) 22,129 migrants were dispersed to places outside Tripura for rehabilitation. As the schemes of rehabilitation in their case are continuing, it is not possible to estimate the cost of their rehabilitation at this stage ;

(iii) 3,169 migrants are at present in camps awaiting rehabilitation ;

(iv) The remaining migrants have dispersed on their own.

(c) No such reference has lately been received from the Chief Minister of Tripura.

(d) Does not arise.

Accident at Fertilizer Factory, Kotah

*1462. SHRI S. S. KOTHARI : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an accident recently occurred at the site of the Fertilizer Factory at Kotah, resulting in the death and injury to a number of workers and engineers ;

(b) if so, the steps Government have taken to determine responsibility for the accident ;

(c) whether any compensation has been given to the families of the deceased persons on an equitable basis ; and

(d) the precautionary steps taken to avoid recurrence of such accidents ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI HATHI) : (a) to (d). The matter falls in the State sphere.

टेलीफोन ग्राहकों के मकानों में टेलीफोन मीटर लगाना

*1463. श्री हरदयाल देवगुण : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पानी तथा बिजली के मीटरों की भांति टेलीफोन ग्राहकों के घरों में भी टेलीफोन मीटर लगाने की सरकार ने एक योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Revolving Fund for Minor Irrigation Schemes

*1464. SHRI INDER J. MALHOTRA: SHRI K. LAKKAPPA :

Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government have any proposal to organise a "Revolving Fund" to implement minor irrigation schemes in order to boost agriculture in the country ; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI JAGJIWAN RAM): (a) and (b). There is no proposal to set up a revolving fund for financing minor irrigation programmes.

Rural Labour Enquiry

*1465. SHRI LOBO PRABHU : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) the reasons for the delay in the publication of the findings of the Rural Labour Enquiry including the 19th and the first round of the 20th Sample Survey (July, 1964—July, 1965) ;

(b) the latest information about the number, wages, days of employment of agricultural labour ;

(c) whether Government have made any efforts to relate agricultural labour wages with factory labour wages and benefits ; and

(d) the staff, if any, which is maintained in his Ministry to study and progress the interests of agricultural labour ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI HATHI) : (a) In view of the volume of work involved

and the limited tabulating facilities the publication of reports such as these usually takes time.

(b) (i) According to the 1961 Census the total number of agricultural labourers was 31.48 million.

(ii) A Statement showing the minimum rates of wages fixed for unskilled adult male workers in various States under the Minimum Wages Act, 1948, is laid on the Table of the Sabha. [*Placed in Library. See* No. LT-1028/68].

(iii) According to the Second Agricultural Labour Enquiry (1956-57) the All-India average employment for wages of adult male agricultural labourers in the year was 197 days.

(c) Wages for agricultural labour under the Minimum Wages Act are fixed by State Governments who take all relevant factors into account.

(d) A special Agricultural Cell has been set up within the Ministry.

Sale of Weevilled Wheat to Flour Mills in Haryana

*1466. SHRI S. C. SAMANTA: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6423 on the 4th April, 1968 regarding free sale of weevilled wheat to the Roller Flour Mills in Haryana and state :

(a) whether Government have since taken any decision in this matter as the new crop has already started coming in the *madis* in huge quantities ;

(b) if not, the reasons therefor ; and

(c) the difficulties which lie in Government's way in coming to a decision and how long it would take to do so ?

THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI JAGJIWAN RAM) : (a) No, Sir.

(b) and (c). If the flour mills in Haryana are permitted to purchase indigenous wheat then it would become necessary to give such permission to the mills located in the other surplus States also. In view of this it was felt that this general question should be considered when a better idea about the trend of prices of wheat would be available after the arrival of new crop in the market.

Use of Chemical Fertilizers

8422. SHRI BABURAO PATEL: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether over 5 kilograms of fertilizers being used per hectare these days has made our agriculture a completely fertilizer-oriented occupation without the need of good, old compost ; and

(b) the quantity and value of total fertilizers of various kinds required this year by way of imports and indigenous production ?

THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI JAGJIWAN RAM) : (a) The over-all consumption of chemical fertilizers per unit area of agricultural land in 1967-68 was about 10 kilograms per hectare of arable land in terms of nutrients (N+P+K)—Nitrogen, Phosphate and Potass.

It is the policy of the Government to encourage the use of chemical fertilisers in combination with organic manures to obtain maximum agricultural production.

(b) The estimated requirement of various fertilisers during the year 1968-69 is given below :

(Quantity in million tonnes)
(Value : Rupees in crores)

	Nitrogenous (in 'N')		Phosphatic (in 'P_2O_5')		Potassic (in K_2O)	
	Qty.	Value	Qty.	Value	Qty.	Value
Target Indigenous production	1.700	357.0	0.650	156.00	0.450	36.0
	0.650	136.5	0.330	79.20	—	—
*Deficit to be met by imports	1.050	220.5	0.320	76.80	0.450	36.0

*Actual imports may be of lesser quantities, depending on the extent of availability from carry-over stock and off-take.

Fish Oil Industry

8423. SHRI M. L. SONDHI : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the present condition of fish oil industry in the country ;

(b) the total export of all types of fish oil from this country both in terms of value and quantity during the last five years ;

(c) the work which is being done at present to develop this industry further to earn foreign exchange ; and

(d) whether any new factory for the extraction of fish oil is being set up in the country ?

THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI JAGJIWAN RAM) : (a) The present production of fish oil is 1230 metric tons.

(b) The export during the last 5 years has been :—

Year	Fish Body Oil		Shark Liver Oil	
	Qty. in tonnes	Value (in Rs.)	Qty. in tonnes	Value (in Rs.)
1962-63	75	72,959	—	—
1963-64		583	—	—
1964-65	419	3,13,628	10	13,069
1965-66	115	95,118	—	—
1966-67	50	59,128	—	—

(c) Fish body oil is mainly from the oil sardines which appear in the West Coast seasonally, and the fishery fluctuates considerably from year to year. In order to increase the production of sardines, steps have been initiated to study the resources, take up experimental fishing with larger vessels and establish fish meal plants which yield body oil as a by-product.

The scope for export of Shark Liver Oil is restricted. Although landings of sharks show an upward trend the introduction of synthetic vitamin 'A' has reduced the export potential of Shark Liver Oil.

(d) The State Fisheries Corporation of Kerala is proposing to put up a 10 ton fish meal plant at Ernakulam which incidentally will extract fish oil from sardines.

The Department of Fisheries, Gujarat is setting up a Shark Liver Oil Refinery at Veraval with an annual capacity of 50,000 litres and this is expected to go into production in September, 1968.

The Fisheries Department of Pondicherry is also setting up a factory at Mahe.

हनुमानगढ़ नगर (राजस्थान) में टेलीफोन केन्द्र

8424. **श्री मीठालाल मीना** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हनुमानगढ़ नगर टेलीफोन केन्द्र में व्यवस्था तथा ग्राहकों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले टेलीफोन उपकरणों की दशा निरन्तर असन्तोष जनक रहती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस बारे में हनुमानगढ़ नगर वाणिज्य मण्डल द्वारा उन्हें तथा सम्बन्धित अधिकारियों को बहुत सी शिकायतें भेजी गई हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि उन्होंने या संबंधित अधिकारियों ने उन शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं की है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कृ० गुजराल) : (क) यह सच नहीं है कि हनुमानगढ़ नगर में टेलीफोन सेवा लगातार असंतोषजनक रहती है। फिर भी कुछ सुधार करने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

(ख) खाद्यान्न व्यापारी संघ और डा० करणी सिंह, संसद् सदस्य की ओर से एक-एक शिकायत प्राप्त हुई है।

(ग) यह सच नहीं है कि इन शिकायतों पर कोई कारंवाई नहीं की गई। निम्न प्रकार की अतिशीघ्र कार्रवाही की गई है

(i) टेलीफोन केन्द्र के उपस्कार को पूरी तरह से ओवरहाल किया गया है।

(ii) गड़बड़ी के मामलो की चौबीसों घंटे दूर करने के लिए व्यवस्था की गई है ।

(iii) ट्रंक काल बुक करने के काम में सुधार लाने के लिए एक और लाइन की व्यवस्था की गई है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Sugar Quota for Confectioners

8425. SHRI VIRENDRAKUMAR SHAH : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether special quotas of sugar at controlled rates are allotted to confectioners and other manufacturers of sugar products for purposes of exports ;

(b) if so, the quotas allotted to such units in Gujarat during each of the months since the partial decontrol of sugar was enforced ;

(c) the total allotment of sugar to such manufacturers in the whole country in each of these months ;

(d) if the reply to part (a) above be in the negative, the reasons therefor ; and

(e) the other incentives which are offered for production and export of such products ?

THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI JAGJIWAN RAM) : (a) Yes, Sir.

(b) No confectioner in Gujarat made a request for allotment of sugar for manufacture of confectionery for export.

(c) 136 quintals in January, 30 quintals in February and 141 quintals in March, 1968.

(d) Does not arise.

(e) Apart from release of sugar at controlled prices, the confectionery exporters are eligible to the following concessions:—

(1) Entitlement to the extent of 10 percent of the f. o. b. value of exports for import of raw materials, etc.

(2) Cash assistance at the rate of 17 percent of the f. o. b. value of export of confectionery.

(3) Draw back of import duty paid on tinplate used for packing and rebate in excise duty on sugar used in the finished product.

Wage Boards

8426. SHRI VIRENDRAKUMAR SHAH : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the observations made at the All India Conference of the Institute of Personnel Managers in March, 1968 to the effect that wage boards need be set up only where sweated labour conditions existed and where workmen were not well-organised and that when there are well-established trade unions, wage boards became superfluous and became even the cause of further disputes ; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI HATHI) : (a) No, Sir.

(b) The National Commission on Labour is conducting a comprehensive review of the working of Wage Boards in all its aspects. The question whether this or any other view should be accepted can be decided only after the Commission's report has been made available.

Closure of Small Coal Mines and Iron Ore Mines

8427. SHRI VIRENDRAKUMAR SHAH : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether a number of small coal mines and iron ore mines and unfavourably placed mines have represented to Government that they would be forced to close down their units, in case of compulsory enforcement of Wage Board awards without side by side increasing the prices of their products ;

(b) if so, whether any survey has been made about the capability of the industry, particularly of the small units to withstand the burden of the implementation of

the Wage Board awards and if so, with what result ; and

(c) the decision of Government in the light of their representations, with regard to the enforcement of the wage awards ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI HATHI) : (a) Representations have been made on behalf of Iron Ore Mines, expressing difficulties in the implementation of the recommendations of the Wage Board.

(b) These matters were considered by the Wage Board before making their recommendations.

(c) Government do not propose to make any modifications in the recommendations of the Wage Board as this was accepted by Government after careful consideration. Parties have been informed accordingly.

Medical Reimbursement Bills of P. and T. Employees, Madurai

8428. SHRI KIRUTTINAN : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that pending reimbursement, medical bills of P. & T. employees at Madurai were taken away in January, 1968 by the Special Police Establishments for investigation in connection with medical reimbursement scandal ;

(b) whether the investigation has been completed ; and

(c) when the bills are likely to be returned to the P. & T. Officers for making payment to the officials ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND COMMUNICATIONS (SHRI I. K. GUJRAL) : (a) 661 bills of the Posts and Telegraphs employees at Madurai were handed over to Special Police Establishment, Madras.

(b) Investigation is still under progress.

(c) The bills are likely to be returned by end of next month.

Aerial Seeding Experiments

8429. SHRI LOBO PRABHU : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state ;

(a) the results of the experiment of aerial seeding conducted in 1953 ;

(b) the reasons for the failures, if any ; and

(c) the reasons for not conducting further experiments ?

THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI JAGJIWAN RAM) : (a) The Hon'ble Member is perhaps referring to experiment of aerial sowing of seeds of some forest species carried out by Rajasthan Government in 1952. This experiment did not, however, prove to be a success.

(b) The experiment failed because of poor seed bed conditions and unrestricted grazing. It has also been shown by further investigations at the Central Arid Zone Research Institute that by and large direct sowing is hazardous in arid conditions due to uncertainty of climatic conditions.

(c) In view of (b) above, no further experiments in aerial sowing were carried out.

उत्तर प्रदेश में इतखारी छोटी नहर

8430. **श्री जोगेश्वर यादव** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में इतखारी छोटी नहर को पहले चुने हुए स्थान से चार फर्लांग पर बनाने का विचार है ;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं होते ।

दिल्ली क्लाथ तथा बिड़ला मिलों में श्रमिक

8431. **श्री निहाल सिंह** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली क्लाथ मिल तथा बिड़ला क्लाथ मिल श्रमिकों को अधिकतर दैनिक मजूरी पर रखते हैं तथा उन्हें स्थायी नहीं बनाया जाता ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनमें से बहुत से श्रमिकों ने कुल मिलाकर 5 से 6 वर्ष तक का सेवा काल पूरा कर लिया है परन्तु उन्हें अब तक स्थायी नहीं किया गया है ; और

(ग) प्रत्येक मिल में स्थाई तथा अस्थाई कर्मचारियों की संख्या कितनी है तथा उन्हें नियमित रूप से रोजगार न देने के क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं। कपड़ा मिलों में 60 प्रतिशत से अधिक श्रमिक उजरती दरों पर और 30 प्रतिशत से अधिक मासिक दरों पर हैं, परन्तु दैनिक मजूरी पर नियुक्त श्रमिकों की संख्या अपेक्षतया कम है। प्रबन्धक यह दावा करते हैं कि उन्होंने 24-12-64 को समझौता बोर्ड के सामने हुये समझौते को लागू कर दिया है। यह समझौते में यह उल्लिखित है कि विभागों को चलाने के लिए जिन श्रमिकों की आवश्यकता है उनमें से केवल 80 प्रतिशत तक को स्थायी बनाना है।

(ख) भाग (क) के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा है **[पुस्तकालय में रख दिया गया। देखिये संख्या** LT—1029/68]

Missing of Fertilizers from Government Godowns

8432. SHRI K. P. SINGH DEO : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to State :

(a) whether it is a fact that thousands of fertilizers bags were found missing recently from Government godowns at Bachhra, Moradabad, Aurangabad and other places ;

(b) if so, whether the matter has been investigated; and

(c) if so, the result thereof ?

THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI JAGJIWAN RAM): (a) Yes, Sir. Theft of some fertiliser bags at some places in Meerut Region has been reported.

(b) The matter is under investigation by Police.

(c) the result of the investigation is being awaited by the U.P. Government.

Drought Map of Orissa

8433. SHRI SRADHAKAR SUPAKAR: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether the Government of Orissa has been asked to supply a map of Orissa showing the areas invariably affected by drought; and

(b) whether Government propose to give any long term loan or aid to Orissa for the development of irrigation in such areas ?

THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI JAGJIWAN RAM) : (a) The question of implementation of suitable programme of lasting benefit in scarcity frequented areas has been under the active consideration of the Government of India for some time past. The demarcation of the chronically drought affected areas is the first step to be undertaken in respect of each State. The areas are to be classified into 'A', 'B', and 'C' categories based on a total or almost a total failure of crops in the area once every three years, six years or ten years. The State Governments including Orissa have already been requested to classify areas as such.

(b) Due to present financial stringency, it is proposed to make a beginning by taking up pilot projects covering an area not larger than an average district in the "hard core" of the chronically drought affected areas. Schemes relating to investigation of groundwater and mineral resources, minor irrigation, soil and water

conservation works, afforestation and development of pastures are proposed to be taken up.

As regards the pattern of financial assistance, it has been decided that each individual scheme should be eligible for assistance on the same basis as at present. A scheme would qualify for assistance under the proposed Programme only on the basis of expenditure proposed to be incurred over and above the outlay actually achieved in 1967-68.

State Governments have been requested to formulate concrete schemes accordingly.

सरकारी अधिकारियों द्वारा वन नियमों का उल्लंघन

8434. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार की सेवा में भारतीय प्रशासन सेवा और सेना के अधिकारियों ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अरक्षित वन क्षेत्रों में शिकार करके वन नियमों का उल्लंघन किया है जैसा कि 30 दिसम्बर, 1967 के "ब्लिटज" के हिन्दी संस्करण में प्रकाशित हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम): (क) और (ख). राज्य सरकार से अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

R.M.S. Building, Kottayam

8435. SHRI E. K. NAYANAR : will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the Kottayam R. M. S. Building has been leaking ever since its construction ;

(b) whether Government are aware that during the rainy season broken tiles fall down posing threat to the lives of the staff working inside and when it is raining there is pool of water in the varandha also; and

(c) the action Government which propose to take in the matter ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND COMMUNICATIONS (SHRI I. K. GUJRAL) : (a) There have been leakages during heavy rains.

(b) No instances of broken tiles falling after retiling of the roof in November 1967 have come to notice. There are, however, occasional leakages in the varandha.

(c) The entire roof was retiled by Railways during November-December 1967 and further action for repairs is being taken up with Railways.

तार इन्जीनियरी तथा बेतार सेवा श्रेणी 2 परीक्षा

8436. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तार इंजीनियरी तथा बेतार सेवा श्रेणी 2 परीक्षा दिसम्बर, 1966 में हुई थी ;

(ख) 1968 में "डी० पी० सी०" द्वारा किस आधार पर पदोन्नति दी गई है ;

(ग) वरिष्ठता तथा योग्यता के आधार पर तरक्की न देने के क्या कारण हैं जबकि परीक्षा में केवल पास होना ही जरूरी है ; और

(घ) यदि पदोन्नति वेतन के आधार पर की गई थी तो ऐसे नियम कब बनाये गये थे और वे कब लागू किये गये थे ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) (क) जी, हां ।

(ख) विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उत्तीर्ण उम्मीदवारों के गोपनीय रिकार्डों की पूर्ण जांच करके 'चुनाव' द्वारा ।

(ग) भर्ती के नियमों में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले

उम्मीदवारों में से 'चुनाव' करके पदोन्नति करने की व्यवस्था है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रेणी 2 टी० ई० तथा डब्ल्यू० एस० परीक्षाएं

8437. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1964 तथा 1965 में श्रेणी 2 टी० ई० तथा डब्ल्यू० एस० परीक्षाएं ली गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो इन परीक्षाओं के आधार पर किन-किन राज्यों में कर्मचारी पदोन्नत किये गये ; और

(ग) कितने कर्मचारियों की इस प्रकार पदोन्नतियां हुई ; और उसका आधार क्या था ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) टी० ई० तथा डब्ल्यू० एस० श्रेणी-II के लिए जो कि एक अखिल भारतीय सेवा है, पदोन्नतियों राज्य-वार आधार पर नहीं की जातीं।

(ग) 1964 की परीक्षा 303
1965 की परीक्षा 186

उपर्युक्त परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले कर्मचारियों की पदोन्नतियां विभागीय पदोन्नति समितियों द्वारा उनके गोपनीय रिकार्ड को जांच करके 'चुनाव' द्वारा की गई थीं।

हिसार में अनुसंधान प्रयोगशाला

8438. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिट्टी के विश्लेषण और उपयुक्त फसल के लिये हिसार में एक अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने वित्तीय सहायता देने का आश्वासन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि दी जायेगी ;

(ग) इस पर कितनी धन राशि व्यय होगी;

(घ) क्या इसके लिये विदेशी सहायता भी प्राप्त की जायेगी ; और

(ङ) यदि हां, तो किस देश से ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी, नहीं। फिर भी भारत सरकार ने हाल ही में हिसार में भूमि लवणता अनुसंधान संस्थान की स्थापना के लिये स्वीकृति दे दी है। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य देश में लवणीय और क्षारीय मिट्टी, भूमि लवणता, जलनिष्काशन प्रणाली, खराब किस्म के पानी से सिंचाई सम्बन्धी समस्याओं का नया हल निकालना है।

(ख) यह संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन होगा और परिषद इस पर भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों में से धन लगायेगी।

(ग) 31 मार्च 1971 को समाप्त होने वाली 3 वर्ष की अवधि में 52.66 लाख रु०।

(घ) जी, हां।

(ङ) प्राप्ति स्थान के सम्बन्ध में अभी निर्णय किया जाएगा।

T.V. Sets in Delhi

8439. SHRI C. CHITTYBABU :
SHRI DEIVEEKAN :
SHRI MAYAVAN :
SHRI SUBRAVELU :
SHRI KAMALANATHAN :

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) the number of television sets manufactured in the country; and

(b) the number of television sets licensed in Delhi during the years 1966 and 1967 ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND COMMUNICATIONS (SHRI I. K. GUJRAL) : (a) The information is being collected and will be placed on the table of the Sabha.

(b) 1966 ··· 4,162
1967 ··· 6,161

I.C.I. Fertilizer Factory, Kanpur

8440. SHRI BHAGABAN DAS :
SHRI UMANATH :
SHRI VISWANATHA MENON :
SHRI A. K. GOPALAN :

Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the staff of the I. C. I. Fertilizer Factory at Kanpur on the 26th January, 1968 ;

(b) if so, whether the management had taken permissions for the same;

(c) if not, the action taken against the management ; and

(d) whether the staff have been paid extra wages for that day ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI HATHI) : (a) A factory of the name of M/s. Indian Explosives Ltd. (Fertilizer Project) is being erected by the I. C. I. at Panki, Kanpur. It remained closed on the 26th January, 1968.

(b) to (d). Do not arise.

Import of Rambouillet Sheep

8441. SHRI D. N. PATODIA :
SHRI DEIVEEKAN :

Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether the programme of importing Rambouillet sheep from U.S.A. is being financed by the U. S. AID ;

(b) the target of import of sheep to improve the breed during the Fourth Plan period ; and

(c) how many of them will be made available to Rajasthan State which is the main wool producing State ?

THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI JAGJIWAN RAM) : (a) and (b). The import of Rambouillet sheep from USA in March-April, 1968 has been financed from USA. AID non-project loan funds. No specific target for import of sheep during the 4th Five Year Plan has been laid down. It is, however, proposed to import about 10,000 fine wool sheep for improving the indigenous breeds of sheep in the country. The Ministry is processing a scheme to establish a large Central Sheep Breeding Farm with imported fine wool sheep at Hissar in Haryana State with Australian assistance under the Colombo Plan.

(c) These sheep are proposed to be imported on behalf of the State Governments after taking into consideration their requirements. Statewise allocation has not yet been finalized. The Government of Rajasthan has already been addressed to indicate their requirements of fine-wool sheep, if any, for the year 1968-69.

Subsidy on Rice and Wheat

8442. SHRI D. N. PATODIA : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the total amount saved as a result of the withdrawal of subsidy on wheat ; and

(b) how long the subsidy on rice will continue ?

THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE, (SHRI JAGJIWAN RAM) : (a) There as been no saving on account of withdrawal of subsidy in case of imported wheat during the financial year 1967-68 as the issues of imported wheat prior to the revision in its issue price *i.e.* from 1.4.67 to 31.12.67 had been larger than those anticipated earlier in the Budget Estimates of 1967-68.

(b) There is at present no proposal to withdraw the subsidy in the distribution of imported rice.

Survey of Asian Agriculture by Asian Development Bank

8443. SHRI D. N. PATODIA : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Asian Development Bank has completed a survey of Asian agriculture ;

(b) whether the conditions in India have also been taken into account by the survey ;

(c) if so, the findings of the survey so far as it relates to India ; and

(d) the assistance which India is getting at present from the Asian Bank for the development of agriculture ?

THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI JAGJIWAN RAM) : (a) The Technical and Economic Survey Team, sponsored by the Asian Development Bank, has completed its survey. The Team has submitted its Report to the Bank. The Report is under consideration by the Board of Directors of the Bank and may be published by the Bank after completion of its consideration by the Board.

(b) and (c). The final contents of the Report will be known only after the Bank officially issues it incorporating its own comments if any.

(d) The Government of India has not yet sought any assistance from the Asian Development Bank for development of Agriculture.

Wage Board for Electricity Undertakings

8444. SHRI UMANATH :
SHRI MOHAMMAD ISMAIL :
SHRI K. RAMANI :
SHRI K. ANIRUDHAN :

Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5593 on the 28th March, 1968 regarding Wage Board for Electricity Undertakings and state :

(a) whether Government have since taken a decision on the recommendations of the Wage Board ; and

(b) if not, when the decision is likely to be taken and the reasons for the delay ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI HATHI) : (a) No, Sir.

(b) The recommendations are under consideration in consultation with the Ministry of Irrigation and Power. The matter is expected to be finalised shortly.

Special Programme of Wells in Maharashtra

8445. SHRI DEORAO PATIL : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government have approved a special programme of constructing wells, boring and setting up of pump-sets in Maharashtra State as recommended by the Central Study Team ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the amount sanctioned and spent for the programme during the years 1965-66 and 1967-68 ?

THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI JAGJIWAN RAM) : (a) No such programme was recommended by the Central Teams which visited Maharashtra in the years 1965, 1966 and 1967, nor was any such programme approved by the Government of India.

(b) and (c). Do not arise.

Reduction in Wheat Price in Delhi

8446. SHRI SHIVAJIRAO S. DESHMUKH : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government have advised the Delhi Administration to lower the prices of maxican and indigenous wheat to the consumers with a view to clear stocks of unsold wheat ;

(b) whether Government have offered to subsidise such sale at lower rate ; and

(c) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI JAGJIWAN RAM) : (a) The issue price of indigenous Mexican wheat only has been reduced by the Government with a view to dispose of the small stocks of this wheat at present lying with the ration shops in Delhi.

(b) Yes, Sir.

(c) Small stocks of about 300 tonnes of indigenous Maxican wheat got accumulated with the Authorised ration dealers in the rationed area of Delhi due to the consumer preference for other varieties of wheat and the falling trends in the market prices. As it was not administratively feasible to take back the stocks from a large number of authorised ration dealers scattered over the rationed area in Delhi, it was decided to reduce its issue price from Rs. 98.00 to Rs. 75.00 per quintal which was considered to be acceptable to the consumers for the disposal of these stocks.

पटना में टेलीफ़ोन ग्राहकों द्वारा देय टेलीफोन बिलों की बकाया राशि

8447. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना में टेलीफोन ग्राहकों की ओर टेलीफोन बिलों की कोई राशि बकाया है ;

(ख) यदि हां, तो टेलीफोन बिलों की कुल कितनी राशि बकाया है तथा उन ग्राहकों के नाम क्या हैं जिनकी ओर बहुत भारी राशि बकाया है ;

(ग) बकाया राशि को वसूल करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिये कि भविष्य में राशि बकाया न रहे सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० मुंजराल) : (क) जी हां ।

(ख) सितम्बर, 1967 तक जारी किये गये बिलों के लिए 11.87 लाख रुपये । व्यक्तिगत लेखे गोपनीय रखे जाते हैं, अतः जिन प्रयोक्ताओं की ओर राशि बकाया है उनके नाम बताना उचित नहीं होगा ।

(ग) और (घ). वसूली करने और आगे बकाया राशि को इकट्ठा न होने देने की दृष्टि से स्मरण-पत्र जारी करने, टेलीफोन काटने, प्रयोक्ताओं के साथ व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करने और जहां कहीं आवश्यक हो अन्त में कानूनी कार्रवाई तक करने जैसे कदम उठाये जाते हैं ।

हड्डी से बना उर्वरक

8448. **श्री महाराज सिंह भारती** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुमानतः हड्डी से बने कितने उर्वरक की इस वर्ष खपत हुई है तथा यह कुल वार्षिक उत्पादन का कितना प्रतिशत है ; और

(ख) बोन मील को जिस का इस समय निर्यात किया जाता है उर्वरक के रूप में प्रयोग करने में क्या कठिनाई उठानी पड़ रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) ऐसा अनुमान है कि भारत में बोन क्रशिंग मिलों द्वारा उप-उत्पाद के रूप में लगभग 35,000 मैट्रिक टन हड्डी का चूर्ण प्रति वर्ष तैयार किया जाता है । हड्डी चूर्ण अधिकतर देश से बाहर निर्यात की जाती है । चालू वर्ष में देश में हड्डी से बने उर्वरक को अनुमानित खपत के बारे में जानकारी नहीं है । फिर भी, हड्डी का चूरा, बहुत थोड़ी मात्रा में किये जाने वाले निर्यात को छोड़ कर, देश में ही खाद के रूप में प्रयोग में लाया जाता है ।

(ख) हड्डी का चूरा अन्य फासफेटिक उर्वरकों की तुलना में अधिक मूल्य वाला होने के कारण और उसमें सिट्रिक सोलूबल पी$_2$ ओ$_5$ की कम उपलब्धता के कारण उर्वरक के रूप में अधिक लोकप्रिय नहीं हुआ है ।

खली का खाद के रूप में उपयोग

8449. **श्री महाराज सिंह भारती** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष खाद के रूप में प्रत्येक किस्म की खली का कितना प्रयोग किया गया ;

(ख) क्या सरकार तेल निकालने के पश्चात जो खली बाकी रह जाती है उसके निर्यात पर नियन्त्रण करने की सोच रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके कारण एक वर्ष में खाद के लिये कितनी अधिक खली उपलब्ध होगी ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) प्रत्येक प्रकार की खली के आंकड़े, जिसका गत वर्ष खाद के रूप में प्रयोग किया गया या उपलब्ध नहीं है ।

(ख) खाद के रूप में खली का सीमित मूल्य होते और रसायनिक उर्वरकों की तुलना में एक ही पौद पोषक क्षमता के लिये खली का प्रयोग महंगा होने के कारण खली के निर्यात की नीति में किस प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

गाय और भैंसों की संख्या

8450. **श्री महाराज सिंह भारती :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीनतम अनुमान के अनुसार देश में इस समय गाय और भैंसों की संख्या कितनी-कितनी है ;

(ख) क्या यह सच है कि भैंसों की संख्या गायों की संख्या से बहुत बढ़ रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 1961 की गणना के अनुसार, देश में गायों की कुल संख्या 17 करोड़ 55 लाख 60 हजार थी जिसमें से 5 करोड़ 42 लाख प्रौढ मादायें थीं । भैंसों की कुल संख्या 5 करोड़ 12 लाख 10 हजार थी जिनमें से 2 करोड़ 50 लाख 20 हजार प्रौढ़ मादायें थी । 1966 की गणना के अन्तिम अखिल भारतीय आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं है ।

(ख) जी हां, 5 वर्ष की अवधि के लिये अर्थात 1956 से 1961 तक कुल भैंसों की वृद्धि 13.9 प्रतिशत हुई और उसी अवधि के लिये प्रौढ़ मादायों के लिये यह वृद्धि 11.9 प्रतिशत थी । गायों के विषय में कुल गायों की आबादी की वृद्धि 10.6 प्रतिशत रही हैं और प्रौढ़ मादाओं के विषय में, उसी अवधि के लिये 8.6 प्रतिशत रही है ।

(ग) गायों की वृद्धि की अपेक्षा भैंसों की की द्रुततर दर पर वृद्धि के कारणों को मालूम करने के लिये अभी तक कोई क्रमबद्ध अध्ययन नहीं किया गया है कि नगरीकरण एवं औद्योगीकरण के फलस्वरूप दूध के लिए परिवर्धित मांग की दृष्टि से भैंसों की अधिक मांग है, क्योंकि तुलनात्मक दृष्टि से यह अधिक मक्खन वाला दूध अधिक मात्रा में देती है । अतः भैंसों को अधिक संख्या में पाला जा रहा है ।

विधि मन्त्रालय द्वारा दी गई कानूनी राय

8451. **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री रणजीत सिंह :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री टी० पी० शाह :

क्या **विधि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965 तथा 1966 में उनके मन्त्रालय से कितने मामलों में कानूनी राय ली गई थी ; और

(ख) उनमें से कितने मामले न्यायालय में दायर किए गए और उनमें से कितने मामलों में न्यायालय ने उनके मन्त्रालय द्वारा व्यक्त राय के अनुसार निर्णय दिया था ?

विधि मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) 1965 और 1966 के दौरान विधि मन्त्रालय को विधिक राय के लिए निर्दिष्ट मामलों की संख्या इस प्रकार है :

वर्ष	निर्दिष्ट मामलों की संख्या
1965	22,817
1966	23,533

(ख) इस मंत्रालय में कोई ब्यौरा प्राप्त नहीं है ।

कारखानों के पास कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि

8452. **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री रणजीत सिंह :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री बृज भूषण लाल :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष में सारे देश में कर्मचारी

भविष्य निधि की कुल कितनी राशि कारखानों के प्रबन्धकों की ओर बकाया थी ;

(ख) उन कारखाना-मालिकों के नाम तथा पते क्या हैं जिनकी ओर भविष्य निधि की 5 लाख अथवा इससे अधिक रुपये की राशि बकाया है और यह राशि उनकी ओर कितने वर्षों से बकाया है ; और

(ग) उनमें से कितनों पर मुकदमा चलाया गया तथा कितनों को दण्ड दिया गया ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) छूट न प्राप्त कारखानों की ओर 7.63 करोड़ रुपये (31-12-1967 को) ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा है। [**पुस्तकालय में रख दिया गया। देखिये संख्या** LT-1030/68]

(ग) जिन पर मुकदमे चलाए गए—22
जिनको दण्ड दिया गया 8

Import of Sugar from Mauritius

8453. SHRI SITARAM KESRI : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that India is importing sugar from Mauritius ;

(b) if so, the quantity imported during 1966-67 and 1967-68 and the amount of foreign exchange involved ; and

(c) the mode of payment to Mauritius ?

THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI JAGJIWAN RAM) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

Import of Sugar

8454. SHRI SITARAM KESRI : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state the countries from which sugar is imported to meet the deficit in the annual requirement of the country ?

THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI JAGJIWAN RAM) : No sugar has been imported into India since 1957.

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय बीज निगम का विस्तार

8455. **श्री शशी भूषण वाजपेयी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय बीज निगम के विस्तार के लिये सरकार ने कितनी राशि नियत की है और उसके लिये कितने अधिकारी नियुक्त किये गये हैं और उसके क्रियाकलापों का विस्तार करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं;

(ख) क्या इन्दौर डिवीजन के लिये कोई विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया है; और

(ग) बीजों को विकसित करने के लिये पश्चिम निमाड़ में हाल में खोले गये आधुनिक फार्म का और आगे विकास करने के लिये सरकार ने क्या योजना तैयार की है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटिड एक स्वायत्त अन्डरटेकिंग है, अतः अलग अलग राज्य में उसके क्रियाकलापों के विस्तार करने के लिए सरकार द्वारा धन नियत किए जाने का प्रश्न ही नहीं होता ।

फिर भी निगम ने संकर किस्मों तथा अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों के उत्पादन तथा प्रमाणीकरण के लिए क्षेत्रीय कार्यालय खोल दिए हैं। मध्य प्रदेश के लिए क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में स्थित है। 39 अधिकारी यूनिट में नियुक्त किए गए हैं।

(ख) निगम ने इन्दौर प्रभाग के लिए कोई विशेष अधिकारी नियुक्त नहीं किया है, परन्तु भोपाल स्थित क्षेत्री कार्यालय के अधीन वहां एक सब-यूनिट स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार हो रहा है ।

(ग) भारत सरकार ने बीजों के विकास के लिए पश्चिम निमार जिले में किसी आधुनिक फार्म की स्थापना नहीं की है ।

उर्वरकों तथा बीजों में मिलावट

8456. **श्री शशि भूषण वाजपेयी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये कि उर्वरकों में मिलावट न हो तथा बीज इत्यादी अवांछनीय तत्वों के हाथों में न न जाकर सीधे किसानों के पास पहुँचे, कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). उर्वरकों का वितरण करना राज्य सरकारों का काम है और उनका वितरण अधिकांशतः सहकारी समितियों द्वारा किया जाता है। उर्वरकों की बिक्री उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1957 के अन्तर्गत नियमित की जाती है जिसके द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ किस्म के निर्धारित स्तरों पर भी ध्यान दिया जाता है। मिलावट वाले उर्वरक की बिक्री पर डीलर का लायसैन्स रद्द कर दिया जाता है और अनिवार्य जिसे अधिनियम, 1955 (1955 का 10) के अन्तर्गत यह एक दण्डनीय अपराध है।

जहां तक बीजों का सम्बन्ध है, अपने क्षेत्रों में वितरण के लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। केवल अभाव के समय ही केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा विशेष बीज उत्पादन कार्यक्रम आयोजित करा के या फालतू बीजों वाले राज्यों से बीज भिजवा कर अभाव को दूर करने का प्रबन्ध करती है। हर हालत में वास्तविक वितरण तो राज्य सरकारों द्वारा ही किया जाता है।

"सर्च लाइट" तथा "प्रदीप" समाचारपत्र कार्यालयों में हड़ताल

8457. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23 मार्च, 1968 से पटना के "सर्च लाइट" तथा "प्रदीप" नाम के समाचार-पत्र कार्यालयों के कर्मचारियों ने हड़ताल की हुई है;

(ख) क्या उन्होंने सरकार को अपनी मांगों का कोई ज्ञापन भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) इस सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई है।

(ख) जी नहीं। परन्तु यह पता चला है कि यह हड़ताल श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-पत्रकारों के मंजूरी बोर्ड की शिफारिशों को लागू न करने के कारण हुई है।

(ग) बिहार के मुख्य मंत्री से प्रार्थना की गई है कि श्रमजीवी पत्रकारों के मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को लागू कराने के लिए श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1955 में निर्दिष्ट प्रक्रिया द्वारा आवश्यक कार्यवाही करें और संबंधित पक्षों से गैर-पत्रकारों के मजूरी बोर्ड की सिफारिशें लागू करने के लिए अनुनय करें।

सूरतगढ़ फार्म

8458. **श्री निहाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च 1968 में आये भीषण तूफान के कारण सूरतगढ़ फार्म में 30 प्रतिशत खेती को क्षति पहुँची है;

(ख) यदि हां, तो कितनी हानि हुई है; और

(ग) इस बारे में और हानि को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). पता चला है कि काटी जा रही सरसों की फसलों को मार्च 1968 में आयी आंधी द्वारा 5 प्रतिशत की क्षति हुई थी। हानि के बारे में और ब्यौरा तथा आगे हानि को रोकने के लिये जो कदम उठाये गये, आदि

तारघर

उक्त क्षेत्रों में भूमि पर लाइनों के निर्माण और उनका अनुरक्षण करने में कठिनाईयां होने के कारण तार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा सकी हैं। फिर भी नुबड़ा और न्योमा को लेह से जोड़ने के लिए 1968-69 में वेतार सम्बन्ध की व्यवस्था किये जाने की संभावना है बशर्ते कि राज्य सरकार द्वारा स्थान उपलब्ध करा दिया जाए।

Gram Panchayats

8465. SHRI BHOGENDRA JHA : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the criminal and civil jurisdiction and power of the Gram Katcheries under the Gram Panchayats in various States ;

(b) whether Government propose to enhance and make the jurisdication and power uniform throughout the country and advise the States accordingly ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION (SHRI M. S. GURUPADASWAMY) : (a) The jurisdiction of Nyaya Panchayats, civil as well as criminal, is as defined in the respective State enactments. On the civil side the jurisdiction covers simple suits involving money, moveable property and such other transactions ; the criminal jurisdiction is usually confined to petty cases imposition of fine would suffice as punishment ; some State enactments also authorise Nyaya Panchayats to award short term imprisonment in default of payment of find.

(b) and (c). Nyaya Panchayats are a State subject, and it is for the State Governments to determine their jurisdiction and powers. There is no proposal before the Government of India for anouncement of such jurisdiction or powers or making them uniform throughout the country.

Rajhara Mines

8466. SHRI S. M. BANERJEE : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether there is a discontentment among the mine workers in Rajhara ;

(b) if so, the reasons for the discontentment ; and

(c) whether any steps have been taken to settle the demands ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI HATHI) : (a) Yes, among the contract labour in the mines.

(b) On account of fall in iron ore consumption at the Bhilai Steel Plant, raising contractors are retrenching workers.

(c) Officers of the Central Industrial Relations Machinery are in touch with the workers and the management for arriving at an amicable settlement.

हरियाणा और पंजाब में गेहूं के दामों का गिरना

8467. **श्री मधु लिमये** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हरियाणा तथा पंजाब में गेहूँ के घटते दामों की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार निम्नतम मूल्य को बढ़ाने के प्रश्न पर पुनर्विचार करने का है; और

(ग) क्या सरकार ने इन गिरते मूल्यों का आगामी वर्ष की फसल पर जो प्रभाव पड़ सकता है, उस पर विचार किया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) पंजाब में गत कुछ महीनों में गेहूं के भाव सामान्यतः स्थिर रहे हैं। हरियाणा में फरवरी मार्च, 1968 में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई थी लेकिन तब से स्थिति में सुधार हो चुका है।

(ख) और (ग). न्यूनतम साहाय्य मूल्यों में वृद्धि करने के लिए फिर से विचार करने

हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है। अधिप्राप्ति मूल्य जो कि न्यूनतम खाद्यान्न मूल्यों से अपेक्षाकृत ऊंचे हैं, घोषित कर दिये गये हैं। राज्य सरकारों और भारतीय खाद्य निगम को भी कहा गया है कि मंडियों में जब कभी और जहां कहीं सरकार द्वारा घोषित अधिप्राप्ति मूल्यों से मूल्य नीचे आ जाते हैं, उन्हें स्वीकृति किस्म की गेहूं की जितनी मात्राएं बिक्री के लिए पेश की जाती है, घोषित अधिप्राप्ति मूल्य पर खरीद लेनी चाहिये। अतः इससे वह सुनिश्चित हो जायेगा कि मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित अधिप्राप्ति मूल्य के स्तर से नीचे नहीं गिरने दिये जाते हैं। इसलिए अगले फसल वर्ष में गिरते हुए भावों के प्रभाव पर विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्य प्रदेश को गेहूं की सप्लाई

8468. **श्री गं० च० दीक्षित :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फ़रवरी, 1968 में मध्य प्रदेश के लिए कितना गेहूं नियत किया गया था ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : 15,400 मीटरी टन।

मध्य प्रदेश में सुपर बाजार

8469. **श्री गं० च० दीक्षित :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1967-68 में मध्य प्रदेश में सुपर बाजार खोलने के लिए कोई ऋण मंजूर किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि मंजूर की गई है; और

(ग) उसकी अदायगी की शर्तें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) जी हां; तीन सुपर बाजारों के लिए।

(ख) रु० 5,62,500

(ग) ऋण की वापसी—अदायगी की शर्तें सभा पटल पर रखे गये विवरण में दी गई हैं। [पुस्तकालय में रख दिया गया। देखिये संख्या LT-1031/68]।

मध्य प्रदेश में केन्द्रीय सरकार का फार्म

8470. **श्री गं० च० दीक्षित :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्य राज्यों की भांति मध्य प्रदेश में कोई केन्द्रीय सरकारी फार्म स्थापित किया है अथवा स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो यह फार्म किस स्थान पर स्थापित किया गया है अथवा स्थापित करने का विचार है; और

(ग) उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) . मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय राज्य फार्म स्थापित करने के लिए सागर जिले में एक स्थान प्रस्तुत किया है। राज्य फार्म के लिए स्थान की उपयुक्तता की जांच करने के लिए केन्द्रीय बीज फार्म समिति उसे देखने शीघ्र जायेगी। यदि स्थान उपयुक्त समझा गया तो फार्म स्थापित करने के लिए ब्यौरे सहित एक परियोजना रिपोर्ट बनाई जायेगी।

चीनी उद्योग पर नियंत्रण

8471. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय चीनी मिल एसोसियेशन ने चीनी उद्योग पर नियंत्रण शिथिल करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका आधार क्या है और उनकी मांगें क्या हैं ?

जानकारी फार्म के अधिकारियों से प्राप्त की जा रही है और जब यह प्राप्त हो जायेगी तो सभा पटल पर रख दी जायेगी।

ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त की गई भूमि

8459. **श्री निहाल सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटिश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में जिन लोगों की भूमि जब्त की गई थी उनके नाम क्या हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति की कितनी एकड़ भूमि जब्त की गई थी;

(ख) क्या सरकार ने सम्बद्ध व्यक्तियों को वह भूमि लौटाने का निर्णय कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). उत्तर प्रदेश सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

संचार विभाग में कमियां

8460. **श्री ओ० प्र० त्यागी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 मार्च, 1968 के "हिन्दुस्तान" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली नागरिक परिषद् के महा सचिव श्री तारा चन्द खंडेलवाल ने उनके विभाग की अनेक त्रुटियां बताई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके द्वारा बताये गये इन तथ्यों के बारे में सरकार ने जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). इस समाचार के प्रकाशित होने के बाद दिल्ली नागरिक परिषद्, के कुछ सदस्य 26 मार्च, 1968 को संचार मंत्री से मिले और विभिन्न पहलुओं पर बातचीत की प्रत्येक मद के सम्बन्ध में स्थिति उन्हें स्पष्ट कर दी गई। बाद में दिल्ली नागरिक परिषद् के अध्यक्ष श्री गुप्त और कुछ सदस्य दिल्ली टेलीफोन मंडल के काम को प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए 5 अप्रैल, 1968 को वहां गए। श्री गुप्त ने सेवा में सुधार करने के लिए किये गए प्रयत्नों की सराहना की। सेवा में आगे और सुधार करने के लिए कुछ सुझाव भी रखे गये जिन पर विचार किया जाएगा।

सामूहिक कृषि फार्म

8461. **श्री ओ० प्र० त्यागी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान सामूहिक कृषि फार्मों की राज्यवार संख्या कितनी कितनी हैं; और

(ख) वर्ष 1968-69 में राज्यवार कितने कितने नये सामूहिक कृषि फार्म स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

गेहूं के बीज की नई किस्में

8462. **श्री ओ० प्र० त्यागी** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने गेहूं के किस-किस किस्म के नये बीज उगाये हैं और उनमें से प्रत्येक किस्म के बीज की प्रति एकड़ उपज कितनी है;

(ख) क्या चालू फसल में उत्पादित गेहूं के नये किस्म के बीजों को पर्याप्त मात्रा में जमा करने के लिये सरकार ने कोई व्यवस्था की है ताकि भविष्य में समूचे देश में किसानों

को उनकी आवश्यकतानुसार बोने के लिये बीज वितरित किये जा सकें; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक किस्म के बीज अनुमानतः कितनी मात्रा में जमा करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). गेहूं की नई किस्में जो हाल ही में केन्द्रीय किस्म निर्मुक्ति समिति द्वारा निर्मुक्त की गई हैं और अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम में शामिल की गई हैं वे कल्याण-सोना, सोनालिका, शर्वती सोनारा तथा एस—331 हैं। "राज्यों में बीजों का उत्पादन तथा वितरण का प्रबन्ध राज्य सरकारों द्वारा स्वयं किया जाता है"। फिर भी राष्ट्रीय बीज निगम ने गत रबी मौसम के दौरान 531 एकड़ भूमि में कल्याण-सोना, सोनालिका तथा शर्बती सोनारा के मूल बीज उत्पादन का आयोजन किया है। कटाई चालू है और निगम को आशा है कि प्रति एकड़ भूमि में 15 क्विन्टल मूल बीज का औसतन उत्पादन होगा। प्रस्ताव है कि आगामी रबी के दौरान राज्य सरकारों, प्रगतिशील निजी बीज उत्पादकों आदि के द्वारा इस मूल बीज को बीज वृद्धि के लिए उपयोग में लाया जाये।

शराब के लिये गुड़ की खरीद

8463. **श्री ओ० प्र० त्यागी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार शराब बनाने के लिये बहुत मात्रा में गुड़ खरीद रही है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1967 में इस कार्य के लिये कितनी मात्रा में गुड़ खरीदा गया ?

खाद तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) केन्द्रीय सरकार ने शराब बनाने के लिये कोई गुड़ नहीं खरीदा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

लद्दाख में डाकघर तथा तारघर

8464. **श्री कुशोक बाकुला** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि तथा सम्बन्धित क्षेत्रों के लोगों द्वारा बार बार प्रार्थना करने के बावजूद भी लद्दाख के "जोसकर", "नुबड़ा" और "ओमा" क्षेत्रों में अभी तक डाकघरों तथा तारघरों के न खोले जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) इस बात को देखते हुए कि ये सब सीमावर्ती क्षेत्र हैं, सरकार का इन तीनों क्षेत्रों में कब तक डाक तथा तार की सुविधाओं की व्यवस्था करने का विचार है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख). डाक और तार की सुविधाएं निम्नलिखित कारणों से उपलब्ध नहीं कराई जा सकीं।

डाकघर

(1) **जोसकर**—यह क्षेत्र जंसकर नाम से भी प्रसिद्ध है। जंसकर तहसील के मुख्यालय पदम में डाकघर खोलने के प्रस्ताव की जांच करने पर यह पाया गया कि प्रस्तावित डाकघर की अनुमानित हानि एक डाकघर के लिए वार्षिक 2500 रु० की अधिकतम अनुमत्य हानि की सीमा से अधिक होगी जिस की छूट असाधारण मामलों में ही दी जाती है। राज्य सरकार को अनुमत्य हानि की सीमा से अधिक होने वाली हानि की रकम के बराबर गैर-वापसी अंशदान वसूल करने के लिए लिखा गया है जिसके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

(2) **नुबड़ा**—नुबड़ा घाटी के मुख्यालय दिसकिट में डाकघर खोलने के प्रस्ताव की मंजूरी दे दी गई है और वहां शीघ्र ही डाकघर खोल दिया जाएगा।

(3) **ओमा** अभी तक ओमा में डाकघर खोलने के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(c) A note embodying the details is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-1033/68].

Ban on Use of Gur for Industrial Purposes

8477. SHRI RABI RAY : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government have studied the impact of the order banning the use of gur for industrial uses including manufacture of liquor on the price of gur and sugar ; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI JAGJIWAN RAM) : (a) and (b). As a result of the ban imposed on the use of gur for industrial uses and also on account of simultaneous release of additional sugar for free sale and for controlled distribution, the prices of gur and sugar have come down by about Rs. 30 and Rs. 50 per quintal, respectively, in West U.P. where there was an undue rise in prices.

Food and Agriculture Minister's Visit to Calcutta

8478. SHRI RABI RAY : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that he visited Calcutta on the 30th March, 1968 ; and

(b) if so, what was purpose of this visit and the details thereof ?

THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI JAGJIWAN RAM) : (a) Yes, Sir.

(b) The visit was to participate in the Centenary celebrations of the Amrit Bazar Patrika and to discuss current problems in the matter of food with the Governor of West Bengal.

उत्तर प्रदेश कृषक समाज

8479. **श्री मोलहू प्रसाद** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार ने 1965-66 और 1966-67 में उत्तर प्रदेश कृषक समाज नामक संगठन को कितनी वित्तीय सहायता दी ; और

(ख) उक्त संगठन के पदधारियों के जिला बार नाम और पदनाम क्या हैं और उनके कृत्य क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम): (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने 1965-66 और 1966-67 में उत्तर प्रदेश कृषक समाज को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी थी।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा है। [**पुस्तकालय में रख दिया गया। देखिये संख्या** LT—1034/68] ।

गोरखपुर में उचित मूल्य की अनाज की दुकानें

8480. **श्री मोलहू प्रसाद** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966 और 1967 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में जिन-जिन व्यक्तियों को सरकारी उचित मूल्य की अनाज की दुकानें अलाट की गई थी उन के नाम तथा पते क्या है ;

(ख) उन दुकानदारों के नाम क्या हैं जिन के परिवार को एक से अधिक सरकारी उचित मूल्य की अनाज की दुकानें अलाट की गई हैं तथा वर्ष 1967 में जनता और जनता के प्रतिनिधियों से उनके विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ;

(ग) क्या यह भी सच है कि जिला सम्भरण अधिकारी अथवा जिलाधीश द्वारा उन दुकानदारों की दुकानों के आवंटन रद्द नहीं किये गये जिन के विरुद्ध जनता तथा जनता के प्रतिनिधियों से प्राप्त हुई शिकायतें तथ्यों पर आधारित थीं ; अपितु उन दुकानदारों की दुकानों का आवंटन रद्द कर दिया गया, जिन के बिरुद्ध प्राप्त हुई शिकायतें तथ्यों पर आधारित नहीं थीं ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) से (घ) : उत्तर प्रदेश सरकार से एक रिपोर्ट मांगी गयी है और प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दी जावेगी ।

उत्तर प्रदेश का वन विभाग

8481. श्री मौलहू प्रसाद : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के वन विभाग में फोरेस्टर और फारेस्ट गार्ड की वरिष्ठता उनकी नियुक्ति की तारीख से अथवा अन्यथा निर्धारित की जाती है ;

(ख) उन रेंजरों की संख्या क्या है जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1966 में अयोग्य घोषित कर दिया गया था और जिन्हें उनके पूर्व पदों पर अब तक पुर्ननियुक्त किया गया है और प्रत्येक मामले में कितने समय के बाद उनकी इस प्रकार पुर्ननियुक्ति की गई ; और

(ग) उनके बारे में रेंजवार ब्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). उत्तर प्रदेश से अपेक्षित जानकारी भेजने के लिये अनुरोध किया गया है । जानकारी प्राप्त होते ही उसे सभा पट रख दिया जावेगा ।

कानपुर में चमड़ा उद्योग

8482. श्री मौलहू प्रसाद : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर में ऐसे चमड़ा उद्योगों की संख्या क्या है जिन्होंने मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार मजदूरों को अन्तरिम सहायता नहीं दी है ;

(ख) क्या यह सच है कूपर एलन एण्ड नार्थ वैस्ट टैनरी, कानपुर की ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन शाखा छटनी कर रही है और ठेका पद्धति को जारी रखे हुए है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या प्रबन्धकों ने इस काम के लिये श्रम विभाग की अनुमति ले ली थी और यदि नहीं, तो इसे रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) यह बताया गया है कि मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के अन्तर्गत आने वाले कानपुर के 32 प्रतिष्ठान में से केवल एक प्रतिष्ठान ने अन्तरिम सहायता को पूर्णतः लागू नहीं किया है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Import of Seeds

8483. SHRI R. S. VIDYARTHI : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the quantity of Mexican wheat seeds, Asiriya Mwitunde groundnut seeds, Taichung Native I, I.R. 8 paddy seeds imported during the years 1966 and 1967 ;

(b) the quantity of these varieties distributed to each state during the above period ;

(c) the agency through which the distribution was arranged ; and

(d) the number of complaints received for maldistribution of seeds and the action taken by Government thereon ?

THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI JAGJIWAN RAM) : (a) to (c). A statement containing the required information is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT—1035/68].

(d) No complaints regarding any maldistribution were received.

Seed Processing Plants

8484. SHRI R. S. VIDYARTHI : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that bybrid varieties of seeds require a large number of seed processing plants throughout the country ;

(b) whether it is also a fact that due to lack of seed processing equipment, the

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) . दूसरी अप्रैल, 1968 को हुई एसोसिएशन की 35वीं वार्षिक सामान्य बैठक में भारतीय चीनी मील एसोशिएशन के अध्यक्ष ने निम्नलिखित अनुरोध किया था :—

(1) 1966-67 मौसम से बचे माल को ध्यान में रखते हुए खुली बिक्री के लिए चीनी के कोटे की प्रतिशतता बढ़ाई जाय ।

(2) खुले बाजार में बिक्री हेतु प्रतिमास निर्मुक्त चीनी की बिक्री तथा प्रेषण के लिए स्वीकृत अवधि को 30 से बढ़ाकर 45 दिन, जैसा कि लेवी से प्राप्त चीनी के लिए है, कर दिया जाय; और

(3) चीनी की भांति सीरे के उत्पादन का 40 प्रतिशत खुले बाजार में बेचने की अनुमति दी जाय ।

महाराष्ट्र में रोजगार

8472. श्री देवराव पाटिल : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में महाराष्ट्र में कुल कितने व्यक्तियों को रोजगार मिला ;

(ख) वर्ष 1952 से ले कर 1967 तक ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी थी; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित व्यक्तियों में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स० चु० जकीर) : (क) यथा लक्ष्य जानकारी उपलब्ध नहीं है । फिर भी महाराष्ट्र शासन द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना हित तैयार किये ज्ञापन के अनुसार, अनुमान है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में 12.3 लाख नए नियोजन अवसर जुटाये गये ।

(ख) क्योंकि महाराष्ट्र सरकार सन 1960 से कार्य कर रही है अतः इस तारीख के पहिले के अनुमान प्रस्तुत करने का प्रश्न नहीं पैदा होता ।

उक्त हवाले के ही अनुसार, तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में 15·36 लाख व्यक्ति बेरोजगार थे । देहाती क्षेत्र में बेरोजगार व्यक्तियों के सम्बन्ध में स्वतंत्र आंकड़े उपलब्ध नहीं है ।

सभा पटल पर रख दिये गये विवरण में दिखाई है, नियोजन कार्यालयों की सहायता से नियुक्त अवसर खोजने वालों की संख्या है, जैसी कि 1960-67 के बीच प्रत्येक वर्ष के अन्त में दर्ज थी, शहरी क्षेत्र की बेरोजगारी का अनुमान लगाया जा सकता है । [पुस्तकालय में रख दिया गया । देखिये संख्या LT—1032/68]

(ग) आशा है राज्य की वार्षिक योजनाओं में शामिल हुए, ग्राम और लघु उद्योग, सिंचाई और बिजली, यातायात और संचार तथा शिक्षा स्वास्थ्य और समाज कल्याण आदि जैसी सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यक्रमों द्वारा, आने वाले वर्षों में, बेरोजगार लोगों को जिनमें शिक्षित बेरोजगार भी शामिल हैं, बड़े हुए नियोजन अवसर प्राप्त होंगे ।

ग्रामीण ऋणग्रस्तता

8473. श्री देवराव पाटिल : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों की ऋणग्रस्तता की समस्या के अध्ययन के लिए योजना आयोग ने कोई समिति नियुक्त की थी;

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि किसानों की ऋणग्रस्तता लगातार बढ़ती जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए योजना आयोग ने क्या उपाय सुझाए हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ). 1961-62 में भारत के रिजर्व बैंक द्वारा किये गए अखिल भारतीय ग्राम ऋण तथा निवेश सर्वेक्षण के अनुसार सभी काश्तकार परिवारों की ऋणग्रस्तता 2380 करोड़ रुपये आंकी गई थी । बाद के वर्षों के बारे में कोई आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण किसी निष्कर्ष पर पहुँचना कठिन है । तथापि, सुनियोजित आर्थिक विकास के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम सहकारी समितियों के संस्थागत ढांचे को मजबूत बनाना और अन्य उपयुक्त संस्थाएं स्थापित करना है ताकि वे किसानों की उत्पादन ऋण की आवश्यकताओं को ब्याज की उचित दरों पर अधिक से अधिक सम्भव सीमा तक पूरा कर सकें ।

Haringhatta Dairy of West Bengal

8474. SHRI BENI SHANKER SHARMA : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the quantity of milk produced in Haringhatta Dairy of the Government of West Bengal, the cost thereof per litre and the price at which the same is sold to the public ;

(b) how the cost structure of selling and production prices compares with that of the Delhi Milk Scheme ;

(c) whether Government are running the said Dairy at a profit or loss and the figures of profit or loss for the last five years ; and

(d) the steps which Government contemplate to augument the supply of milk in Calcutta ?

THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI JAGJIWAN RAM) : (a) to (d). The required information is not available with us ; we have requested the Government of West Bengal for the details. The answer will be placed on the Table of the Sabha as soon as they are received.

Firestone Tyre and Rubber Company of India (P) Ltd., Bombay

8475. SHRI BENI SHANKER SHARMA : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether the causes of the dispute between the management and the workers in the Firestone Tyre and Rubber Company of India (P) Ltd., Bombay which resulted in the suspension of production since the 4th October, 1967 have been inquired into ;

(b) whether it is a fact that there has been a complete lay-off in all the 16 District Offices of the company in the country; and

(c) if so, the steps taken or proposed to be taken in the matter ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI HATHI) : (a) to (c). The matter falls in the State sphere.

Absorption of Surplus Personnel of Public Sector Undertakings and Construction Labour

8476. SHRI RABI RAY : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the fact that absorption of surplus personnel of public undertakings and construction labour thrown out of employment has assumed acute form on the completion of large projects and the consequent retrenchment of large number of experienced workers of all categories ;

(b) if so, the steps which Government propose to take to solve this problem ; and

(c) the details thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION (SHRI S. C. JAMIR) : (a) Yes, as and when such surpluses have arisen.

(b) A machinery already exists for the development of surplus personnel of public undertakings.

opening of seed processing plants is suffering tremendously ;

(c) whether Government propose to make available such equipment indigenously ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI JAGJIWAN RAM) : (a) Processing of seed, which includes proper drying, cleaning, treating and bagging helps preserve viability. Processing is all the more necessary in case of seeds of hybrid and other high-yielding varieties.

(b) No, Sir.

(c) As a result of the efforts already made to develop indigenous manufacture of seed processing equipments, most of the equipments required for processing plants are now being manufactured within the country.

(d) Does not arise.

Sugar Production in U.P.

8485. SHRI CHENGALRAYA NAIDU : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the sugar out-put in Uttar Pradesh has gone up this year ;

(b) if so, the production in Uttar Pradesh this year ; and

(c) how far the high production of sugar in the State will ease the sugar shortage in the country ?

THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI JAGJIWAN RAM) : (a) and (b). Yes, Sir. The production of sugar in Uttar Pradesh during the current year up to 14th April, 1968, has been 8.11 lakh tonnes as against 7.09 lakh tonnes up to the corresponding date last year.

(c) This has helped in giving additional releases to the extent of 34,000 tonnes per month for the periods March-April and April-May this year.

Agriculture Development Plan

8486. SHRI SHIVA CHANDRA JHA : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an Indicative World Plan for agricultural development is being prepared ;

(b) if so, whether India has agreed to co-operate with it ;

(c) if so, the benefits which India expects out of that Indicative World Plan : and

(d) if not, the total assistance given by the F.A.O. so far in one form or another and the expected assistance, if any, for the Fourth Plan ?

THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI JAGJIWAN RAM) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) and (d). The Indicative World Plan for Agricultural Development being formulated by the F.A.O. is expected to provide *inter alia :*

(i) an international frame of reference which would help Governments to formulate and implement their agricultural policies ;

(ii) a useful basis for attempting to reconcile the conflicts of production and trade policies between countries ; and

(iii) guidance to both recipient and donor countries and organisations with respect to international aid to agriculture.

To the developing countries including India, the Plan is expected to provide a reasoned guide to action by Governments, bringing into focus some of the key policy issues faced by these countries in the planning of their agricultural development.

Modern Bakeries (India) Ltd., Madras

8487. SHRI S. A. AGADI : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Modern Bakeries (India) Limited, Madras is marketing fortified milk bread as advertised in the newspapers ;

(b) if so, the quantity of lysine and milk used in the manufacture of fortified milk bread ;

(c) whether there is any proposal to direct private bakeries to manufacture

fortified bread using lysine in their products ; and

(d) whether lysine is manufactured in India or it is imported ?

THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI JAGJIWAN RAM). (a) The Company is marketing fortified bread under the trade name "Modern Bread". It is not correct to say that this is advertised as "milk bread".

(b) Lysine and milk powder are added at 0.1% and 0.55% respectively of the volume of wheat flour.

(c) No.

(d) Lysine is at present not manufactured commercially in India and is imported.

Shifting of Sub-Post Office from Kadwad Village (Mysore State)

8488. SHRI JAGANNATH RAO JOSHI : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the people from Kadwad Village, District Karwar, Mysore State have protested against shifting of the Sub-Post Office from that place ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND COMMUNICATIONS (SHRI I. K. GUJRAL) : (a) Yes.

(b) The matter was considered, but as the present Post Office building is not sufficiently spacious, not well-ventilated and not easily accesible during the rainy season, the shifting has been approved.

दिल्ली में टेलीफोन बिलों की बकाया राशि

8489. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में टेलीफोन प्रयोक्ताओं पर टेलीफोन बिलों की काफी बड़ी राशि जमा हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो 1965-66, 1966-67 तथा 1967-68 में क्रमशः कितनी राशि बकाया थी ;

(ग) नवम्बर, 1967 से अब तक सरकार ने कितनी बकाया राशि वसूली की है और उन पर अभी कितनी राशि बकाया है ;

(घ) नवम्बर, 1967 से बकाया राशि वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) गत पांच महीनों में बकाया राशि का भुगतान न करने के कारण कितने टेलीफोन कनेक्शन काटे गये ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 30 सितम्बर, 1967 तक जारी किए गये बिलों के लिए 1 जनवरी, 1968 को बकाया राशि 2.25 करोड़ रुपये थी ।

(ख) बकाया राशि में से 0.29 करोड़ रुपये की राशि 1965-66 की थी और 0.39 करोड़ रुपये 1966-67 के थे । 1967-68 (केवल सितम्बर 1967 तक) की बकाया राशि 0.49 करोड़ रुपये थी । बाकी (1.08 करोड़ रुपये) की राशि 1965-66 से पहले की अवधि की है ।

(ग) नवम्बर-दिसम्बर 1967 के दौरान 1.55 करोड़ रुपये की रकम वसूल की जा चुकी थी और जैसा कि पहले बताया गया है अभी 2.25 करोड़ रुपये की बकाया राशि वसूल की जानी है ।

(घ) वसूली करने के लिये स्मरणपत्र जारी करने, टेलीफोन काटने, प्रयोक्ताओं से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करने और जहां-कहीं आवश्यक हो अन्त में टेलीफोन काटने जैसे कदम उठाये जाते हैं ।

(ङ) लगभग 2,575 टेलीफोन कनेक्शन काटे गये हैं ।

उत्तर प्रदेश में कृषि के विकास के लिये योजनायें

8490. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) 1 जनवरी, 1967 से अब तक केन्द्रीय

सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में कृषि विकास के लिए क्रियान्वित की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) कौन-कौन सी योजनायें पूरी हो चुकी हैं तथा अन्य योजनाओं के बारे में कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) सरकार ने कौन-कौन सी योजनाएं स्थगित की तथा उसके क्या कारण हैं; और

(घ) विशेषतः पूर्वी उत्तर प्रदेश में कौन-कौन सी योजनाएं क्रियान्वित की जा रहीं हैं तथा उनके अब तक क्या परिणाम निकले हैं ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) केन्द्रीय सरकार कुछ विशेष पदों को छोड़ कर राज्यों में कृषि विकास के लिए योजनाओं को सीधा कार्यान्वित नहीं करती है। वह कृषि विकास कार्यक्रमों की कार्यान्विति के लिए राज्य सरकारों को केवल वित्तीय सहायता देती है। फिर भी, कुछ योजनायें ऐसी हैं जो कृषि कार्यक्रमों के कुछ पक्षों से सम्बन्ध हैं जैसे मौलिक अनुसन्धान, उच्च शिक्षा, प्रशिक्षण, सर्वेक्षण तथा जांच मार्गदर्शी अध्ययन, विशेष सेवायें तथा कुछ अन्य, जो यद्यपि राज्यों में चालू हैं, तथापि केन्द्रीय सरकार के सीधे प्रशासनिक उत्तरदायित्व में आती हैं।

(ख) से (घ). जानकारी इक्ट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

उत्तर प्रदेश में कृषि का विकास

8491. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1957 से अब तक प्रत्येक वर्ष में केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश को कृषि विकास के लिये कितनी राशि की सहायता दी है ;

(ख) यह सहायता किन-किन योजनाओं की क्रियान्वित के लिए दी गई थी ; और

(ग) विशेषतः पूर्वी उत्तर प्रदेश में किन-किन योजनाओं के लिए सहायता दी गई थी ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को राज्य योजना और केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं के लिये सहायता दी जाती है। वर्तमान विधि के अन्तर्गत, राज्य प्लान योजनाओं के लिये ऐसी सहायता राज्यों को विकास के मुख्य शीर्षकों के अन्तर्गत निर्मुक्त की जाती है और वह किसी विशिष्ट योजना या योजनाओं के वर्ग के लिए नहीं दी जाती है। केन्द्र द्वारा इन परियोजनाओं के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को विकास के मुख्य शीर्षकों के अन्तर्गत 1956-57 से आज तक दी गई सहायता का ब्यौरा सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिया गया है। [पुस्तकालय में रख दिया गया। देखिये संख्या LT—1036/68]

केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश को दी गई सहायता के संबंध में जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक सभा पटल पर रख दी जायेगी।

केन्द्रीय सहायता किसी राज्य के किसी भाग के लिये निर्दिष्ट नहीं की जाती है जैसे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, जब तक कि किसी विशिष्ट परियोजना के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित कोई विशिष्ट योजना किसी विशेष जिले व क्षेत्र में स्थितः न हो।

Sale of Fertilizers outside Priority Areas

8492. SHRI S. K. TAPURIAH :
SHRI MEETHA LAL MEENA :
SHRI BENI SHANKER SHARMA :
SHRI D. C. SHARMA :

Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government have decided to liberalise the sale of fertilizers outside the priority areas ; and

(b) if so, how the prices of fertilizers are likely to be affected as a result thereof ?

THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI JAGJIWAN RAM) : (a) Yes, Sir.

(b) No change in the prices of fertilisers is expected as a result thereof.

Sugar Mills in Cooperative Sector

8493. SHRI PREM CHAND VERMA: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the number of sugar mills in the co-operative sector and their installed capacity ;

(b) how much sugar was produced by mills during 1966-67 season and how much production is likely during the current season ; and

(c) how these figures compare with these of the private sector ?

THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI JAGJIWAN RAM) : (a) At present there are 58 working cooperative sugar factories in India and their installed capacity is 9.4 lakh tonnes of sugar per annum.

(b) and (c). The production of sugar by cooperative and joint stock factories in 1966-67 and 1967-68 (Upto 7th April, 1968) is given below :

Season	Production of sugar in lakh tonnes	
	Cooperatives	Joint Stock
1966-67 (1st Oct. to 30th Sept.)	6.57	14.94
1967-68 (1st Oct. to 7th April)	6.45	14.70

Working Journalists Act

8494. SHRI S. C. SAMANTA : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether legal experts find any contradiction between the sections of the Working Journalists Act and rules framed under that Act regarding earned leave available to Working Journalists employed for less than eleven months ;

(b) whether the Labour Department of Delhi Administration and other Union Territories hold the view that working journalists working for more than eleven months continuously are not eligible for earned leave ; and

(c) whether the opinion of Union Law Ministry has been sought on the flaw in the rules framed under the Act in contradiction with the letter and spirit of the original statute ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI HATHI) : (a) No such contradiction has been brought to the notice of Government.

(b) Government are not aware of any such view.

(c) As no such flaw has been brought to the notice of the Government ; the question of any reference to the Law Ministry does not arise.

Oriental Research and Chemical Laboratory Ltd., Howrah

8495. SHRI JYOTIRMOY BASU : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that owners of Oriental Research and Chemical Laboratory Ltd., Salkia, Howrah, West Bengal have neither deposited employees' share of Provident Fund nor their own share ;

(b) if so, the circumstances under which they have been allowed to do so ; and

(c) the action which Government propose to take in this regard ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI HATHI) : (a) and (b). The employer has defaulted in remitting provident fund contributions.

(c) Legal action by way of recovery proceedings and prosecution has been initiated.

Theft of Copper Wire and Pilferage of P & T Wire

8496. SHRI R. S. VIDYARTHI : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that copper wire thefts and pilferage of P & T wires are frequent ;

(b) if so, the preventive measures pro-

posed to be taken to minimise such thefts ; and

(c) the number of such cases occurred during 1966 and 1967 and the amount involved ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND COMMUNICATIONS (SHRI I. K. GUJRAL) : (a) Yes.

(b) The following action has been taken :

(i) The Chief Ministers of all States have been addressed to direct the I.Gs. Police to take steps to prevent copper wire thefts.

(ii) The Telegraph Wires (Unlawful Possession) Act, 1950 is proposed to be amended to provide for severe punishment to offenders.

(iii) Replacement of copper wire by a copper-weld wire is also proposed depending on the availability of foreign exchange required for the latter.

(c)

1966		1967	
No. of cases	Amount involved in Rupees	No. of cases	Amount involved in Rupees
11,301	25,19,997	16,643	64,17,941

Trilingual Money-Order Forms

8497. SHRI D. N. PATODIA : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5602 on the 28th March, 1968 and state :

(a) whether it is also a fact that the cost of trilingual Money Order forms will be raised from three paise to five paise ;

(b) whether an experiment was made earlier to introduce forms in regional languages ; and

(c) if so, what was the experience of the experiment ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND COMMUNICATIONS (SHRI I. K. GUJRAL) : (a) It is proposed to raise the price of a money-order form from 3 to 5 paise. But the higher price will also be adjusted against the commission when the money order is booked and so the public will not be affected. The increase in the price has no connection with the decision recently taken by Government to print money order forms trilingually in non-Hindi-speaking areas and bilingually in Hindi-speaking areas.

(b) and (c). Money order forms were printed in the past bilingually in English and the regional language in some P & T Circles, but that was not done as an experiment. That policy underwent changes subsequently, and the present decision is as stated in reply to part (a) of the question.

Farm Processing Units

8498. SHRI S. K. TAPURIAH : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether an expert committee appointed by the National Co-operative Development Corporation has recommended the setting up of 1194 farm processing units on the basis of additional production likely to be achieved by 1970-71 ;

(b) if so, the details of the scheme and the State-wise break-up of the units proposed to be set up ; and

(c) Government's reaction thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI M. S. GURUPADASWAMY) : (a) Yes, Sir.

(b) The relevant recommendation of the Expert Committee regarding setting up of 1194 processing units is given in the statement laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-1037/68]. The Expert Committee has not suggested any state-wise break up of these units.

(c) The Government has not taken any decision. The report is still under consideration in the National Cooperative Development Corporation.

Repatriates from Burma

8499. SHRI S. K. TAPURIAH : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether Government's attention has

been drawn to the report in the *Statesman* of the 31st March, 1968 captioned "Pathetic Plight of Burma Repatriates Except at 'Smugglers Bazar' " ;

(b) if so, how far the report about the plight of Burma repatriates as depicted in the said report is correct ; and

(c) the steps envisaged by Government for the rehabilitation of the Burma repatriates ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION (SHRI D. R. CHAVAN) : (a) and (b). Yes. The Government of Madras have been addressed on the subject and their reply is awaited.

(c) A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-1038/68].

Unemployed in Tripura

8500. SHRI MANIKYA BAHADUR : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) the back-log of unemployed in the Union Territory of Tripura at the beginning of the Third Five Year Plan and at its end and what was the number of educated unemployed in that State on these occasions ;

(b) the latest position about the unemployed on the live register of the Employment Exchanges in that State, indicating separately the number of skilled, semi-skilled and unskilled workers and the educated unemployed, including engineers and technicians ; and

(c) the number of employment opportunities likely to created under the 1968-69 plan and under the Fourth Five Year Plan for that State and what will be the likely back-log of the unemployed at the beginning and end of the Fourth Five Year Plan ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION (SHRI S. C. JAMIR) : (a) Precise estimates are not available. The only information available on this subject relates to the work-seekers on the Live Register of Employment Exchange, Agartala (Tripura) which is furnished in Statement-I laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-1039/68]

(b) Information is furnished in Statement-II laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-1039/68]

(c) Estimates in regard to 1968-69 are not available and preparatory work on Fourth Plan is just being initiated.

मधुवनी (बिहार) में डाकघर

8501. **श्री निहाल सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य के सहरसा जिले में छतरपुर पुलिस स्टेशन के अधीन मधुवनी गांव में एक डाकघर खोलने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो यह डाकघर कब खोला जायेगा ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख) . मधुवनी ग्राम में 27 फरवरी, 1968 को एक अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोल दिया गया है ।

टेलीफोन उपकरणों का निर्यात

8502. **श्री निहाल सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले चार वर्षों में कौन-कौन से सरकारी तथा गैर सरकारी फर्मों तथा कम्पनियों ने विदेशों को टेलीफोन उपकरणों का निर्यात किया और किन-किन देशों को किया;

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है; और

(ग) इनमें से प्रत्येक फर्म में कितनी-कितनी पूंजी लगी हुई है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख) . केवल इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड बंगलौर ने, जो कि एक सरकारी कम्पनी है पर-

देशों को टेलीफोन उपस्कर का निर्यात किया। पिछले चार वर्षों में जिन देशों को निर्यात किया गया तथा उससे जो विदेशी मुद्रा अर्जित की गई वह नीचे दी जा रही है :

वर्ष	जिन देशों को निर्यात किया गया	निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा की राशि
1964-65	अफ़गानिस्तान, बेल्जियम, बर्मा, लंका, ईराक, कुवैत, मलयेसिया, पाकिस्तान, पोलैंड, सूडान, सोमाली गणराज्य, दक्षिण-वियतनाम।	6,95,026 रुपये
1965-66	अफगानिस्तान, बेल्जियम, ब्राजील, लंका, ग्रीस, ईरान, कुवैत, मलयेसिया, न्यू-जीलैण्ड, सीरिया, सोमाली- गण-राज्य, दक्षिण-वियतनाम, थाईलैंड, ब्रिटेन और यूगाण्डा।	7,77,663 रुपये
1966-67	अफ़गानिस्तान, बेल्जियम, ब्राजील, बर्मा, लंका, ईराक, आयरलैण्ड, कुवैत, मलयेसिया, न्यू-जीलैण्ड, नाइजीरिया, सूडान, सोमाली-गण-राज्य, सिंगापुर, दक्षिण-वियतनाम, थाईलैण्ड, टर्की, संयुक्त अरब गणराज्य और ब्रिटेन।	79,90,975 रुपये
1967-68	अफ़गनिस्तान, ब्राजील, बेल्जियम, लंका, कीनिया, ईरान, आयरलैण्ड, कुवैत, मोरिशस, मलयेसिया, न्यू-जीलैण्ड, सिंगापुर, दक्षिण-वियतनाम, थाईलैंड, यूगाण्डा, संयुक्त अरब गणराज्य और ब्रिटेन।	50,21,542 रुपये

(ग) इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड बंगलौर की अंशपूंजी में भारत सरकार ने 3,58,74,500 रुपये लगाये हैं।

East Bengal Refugees in Delhi

8503. SHRI DEVEN SEN : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether there is any difference in status between the East Bengal refugees in Delhi and the refugees coming from West Pakistan to Delhi ;

(b) if so, the differences in financial assistance and in the matter of rehabilitation ;

(c) whether it is a fact that the East Bengal refugees in Delhi have not received any financial help or rehabilitation grant from Government whereas refugees coming from East Pakistan to West Bengal have received financial help *e.g.* house-building loans and other rehabilitation grant ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION (SHRI D. R. CHAVAN) : (a) and (b). No. The ordinance issued in 1947 requiring registration of refugees in Delhi did not make any distinction between refugees from East Pakistan and West Pakistan.

(c) and (d). Displaced persons from East Pakistan have migrated mainly to West Bengal and the neighbouring States and have been given rehabilitation assistance, where necessary.

A scheme has, however, been approved for the allotment of a number of housing plots in Delhi on a 'no profit no loss' basis to displaced persons from East Pakistan who are gainfully employed in Delhi.

चुनाव आयुक्त के कार्यालय में हिन्दी का प्रयोग

8504. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या विधि मंत्री 28 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5526 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिवाय कुछ पत्रों केहिन्दी में उत्तर देने के अतिरिक्त चुनाव आयुक्त के कार्यालय में शेष सारा कार्य अंग्रेजी में होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या गृह-कार्य मंत्रालय ने गत वर्ष आयोग को कुछ हिदायतें दी थीं कि वह अपना कार्य हिन्दी में करे और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो हिन्दी-भाषी राज्यों से जो पत्र प्राप्त होते हैं उनके उत्तर हिन्दी में न देने तथा अन्य कार्य हिन्दी में न करने के क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मु० यूनस सलीम): (क) से (ग). निर्वाचन आयोग को अपना काम हिन्दी में करने के लिए गृह मंत्रालय से कोई विशेष अनुदेश प्राप्त नहीं हुए हैं। निर्वाचन आयोग अपना कार्य करने में, हिन्दी के प्रयोग के लिए सरकार द्वारा जारी किए गये साधारण अनुदेशों का यावत्संभव अनुपालन करता है। आयोग के अधिकांश आफिसर जो आयोग की ओर से आदेशों को अधिप्रमाणीकृत करने के लिए प्राधिकृत हैं, या तो अपनी आयु के आधार पर हिन्दी सीखने से छूट प्राप्त हैं या उन्हें हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान नहीं है। इसलिए हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर हिन्दी में नहीं दिया जाता है। किन्तु सम्यक अनुक्रम में जब आयोग के आफिसरों और कर्मचारीवृन्द को हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान हो जाएगा तब आयोग में हिन्दी में कार्य की गति को तेज करना सम्भव हो सकेगा।

निर्वाचन आयोग में कर्मचारियों को हिन्दी सिखाना

8505. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या विधि मंत्री 28 मार्च, 1968 के अतरांकित प्रश्न संख्या 5535 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार निर्वाचन आयुक्त के कार्यालय के सभी कर्मचारियों को हिन्दी सिखाने तथा उक्त कार्यालय में हिन्दी जानने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का है जिससे उक्त कार्यालय में हिन्दी का प्रयोग बढ़ सके; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) हिन्दी प्रशिक्षण स्कीम के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार निर्वाचन आयोग के आफिसरों और कर्मचारीवृन्द को समय-समय पर हिन्दी प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है। इस प्रकार आयोग अपने हिन्दी जानने वाले कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि कर रहा है। आयोग एक पूर्णकालिक हिन्दी आफिसर के भारसाधन में, एक पृथक हिन्दी अनुभाग बनाने के प्रश्न पर भी विचार कर रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सूरतगढ़ कृषि फार्म कर्मचारी संघ द्वारा हड़ताल का नोटिस

8506. **श्री मधु लिमये** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय कृषि यंत्रीकृत फार्म कर्मचारी राष्ट्रीय संघ सूरतगढ़ ने 11 अप्रैल, 1968 से आम हड़ताल करने का नोटिस दिया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों के साथ किये गये अन्याय और 1966 में किए गये विभिन्न करारों के लागू न किये जाने का विरोध करने के लिए हड़ताल की गई है;

(ग) क्या श्रमिकों ने अपनी मांगें सरकार को भेजी हैं तथा उस पर अभी तक विचार नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उनकी मांगों को स्वीकार करने और आम हड़ताल को रोकने के बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (घ). केन्द्रीय यंत्रीकृत फार्म राष्ट्रीय मजदूर संघ, सूरतगढ़ ने 11 अप्रैल, 1968 से हड़ताल करने का नोटिस दिया, क्योंकि उनके द्वारा प्रस्तुत मांगों को स्वीकार न किया गया। नोटिस में मांगें दी गई थीं और यह आरोप भी लगाये गये थे कि फार्म के अधिकारियों ने कर्मचारी संघ के साथ पहले किए करारों को लागू नहीं किया। नोटिस में किसी व्यक्तिगत अधिकारी के अन्याय के बारे में कोई जिक्र नहीं था परन्तु उसमें सामान्य आरोप लगाये गये थे कि फार्म के अधिकारी कर्मचारियों को परेशान करने के लिए अनुशासन सम्बन्धी नियमों का उलंघन कर रहे थे।

संघ की मांगों पर सरकार सक्रिय रूप से विचार करती रही है। सहायक श्रम आयुक्त (समझौता) अजमेर की अध्यक्षता में इन मांगों के सम्बन्ध में समझौता करने पर भी विचार किया गया मांगों पर विचार करने की इन कार्यवाहियों में संघ के और फार्म के निदेशक के प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे। इन समझौता सम्बन्धी कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप, तीन मांगों को छोड़कर शेष सभी बातों पर समझौता हो गया था। समझौता कार्यवाहियों में यह स्वीकार किया था कि इन तीन मांगों को और विचार करने के लिए सरकार के पास भेजा जाये और इस दौरान संघ 11 अप्रैल, 1968 से हड़ताल नहीं करेगा। यह भी निर्णय किया गया कि सहायक श्रम आयुक्त (समझौता) स्थिति हर पुनर्विचार के लिए संघ तथा फार्म के प्रतिनिधियों की एक और बैठक लगभग 25 अप्रैल 1968 के आस-पास बुलायेंगे। सरकार ने तीन में से दो मांगों पर निर्णय कर लिया है। तीसरी मांग पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

संघ के प्रतिनिधियों के सहमत होने के कारण 11 अप्रैल, 1968 से हड़ताल नहीं की गई।

Minor Irrigation Schemes in Mysore

8507. SHRI INDER J. MALHOTRA ; SHRI K. LAKKAPPA :

Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether the Government have asked the Mysore Government to prepare a

phased programme for minor irrigation schemes such as tube-wells and other methods of tapping under-ground water in the State in order to evolve permanent measures to fight famine and scarcity conditions prevailing in certain parts of the State ; and

(b) if so, the action taken in the matter ?

THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI JAGJIWAN RAM) : (a) and (b). The question of the implementation of suitable programmes of lasting benefit in scarcity frequented areas has been under the active consideration of the Government of India for some time past. Due to paucity of funds, it has now been decided to make a beginning by taking up pilot projects covering an area not larger than an average district, in the "hard core" of the chronically drought affected area. Under this approach, it is proposed to take up investigation of ground water and mineral resources, minor irrigation schemes, soil and water conservation works, afforestation and development of pastures. Concrete schemes of these items are to be drawn up by the State Governments under the guidance of a Central team of experts who would visit the areas concerned to make an assessment of the needs in each case. Guidelines for the preparation of such schemes have already been issued to State Governments. The Government of Mysore have identified their 'hard core" areas. A Central team of experts is likely to visit the State shortly.

Central Committee on Employment

8508. SHRI SHIVA CHANDIKA PRASAD : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether there is any Central Committee on Employment ;

(b) if so, what are its functions ;

(c) how many times it has met in 1967 and 1968 so far and the nature of decisions taken ; and

(d) if it has not met, the reasons for the same ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION (SHRI S. C. JAMIR) : (a) Yes.

(b) The functions of the Committee are :—

(i) to review employment information and to assess employment and unemployment trends — urban and rural—and suggest measures for expanding employment opportunities ;

(ii) to advise on the development of the National Employment Service ;

(iii) to advise on development of personnel retrenched on the completion of development projects ;

(iv) to consider special programmes relating to educated unemployed ;

(v) to advise on the development of the Youth Employment Service and Employment Counselling at Employment Exchanges ; and

(vi) to assess the requirements of trained craftsmen and advise the National Council for Training in Vocational Trades.

(c) and (d). The Committee is scheduled to meet on the 21st May, 1968. It could not meet in 1967 or earlier in 1968 due to certain administrative reasons regarding representation on the Committee.

I.C.A.R.

8509. SHRI D. N. DEB :
SHRI GADILINGANA GOWD :
SHRI S. K. TAPURIAH :

Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether some Clerks and Typists have recently been appointed on daily wage basis in the Indian Council of Agricultural Research and other units of his Ministry ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) whether the schemes of employing people on daily wages has been adopted

with the sanction of Government or by the Department itself ; and

(d) the wages paid to those who are employed on daily wages and their conditions of service ?

THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI JAGJIWAN RAM) : (a) to (d). Information is being collected and will be pleased on the Table of the Sabha as soon as compiled.

Sale of Vegetable Ghee in Black-Market in Delhi

8510. SHRI KANWAR LAL GUPTA :
SHRIMATI TARKESHWARI SINHA :

Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to srate :

(a) whether it is a fact that vegetable ghee is being sold in the black-market in Delhi for the last 15 days ; and

(b) if so, the steps which Government propose to take to check it ?

THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI JAGJIWAN RAM) : (a) and (b). Reports indicating a tendency to withhold stocks of vanaspati, particularly in large packs, and overcharging, appeared in the press during the period, but prompt action taken by Government has restored the position to normal. The measures taken in this regard include the following :

(1) The supply of vanaspati to wholesale and retail dealers has been regulated on the basis of supplies received by them during the past three months.

(2) No consumer may be supplied more than 4 kg. of vanaspati loose at a time, or more than one tin of 16.5 kg. per month against production of ration card, priority being given to sale in loose form.

(3) All wholesalers will reserve at least 10% of their monthly quota for effecting supplies for marriage, the supplies being limited to a maximum of 4 tins of 16.5 kg. subject to production of a permit for maida or suji from the Delhi Administration or a certificate from a member of the Municipal Corporation or Delhi Metropolitan Council or a village pradhan (in rural areas).

(4) The retail dealers have been required to maintain a sales register in which the names of customers will have to be entered after obtaining their signatures.

(5) Every wholesale and retail dealer has been required to display a board in his premises showing that Vanaspati is sold at controlled rates.

नेफा, लद्दाख आदि के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये सहायता

8511. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1962 से 1967 तक केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को उन विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये कितनी तथा किस प्रकार की वित्तीय सहायता दी है जो भारत-चीन तथा भारत-पाकिस्तान के 1962 तथा 1965 के क्रमशः युद्धों के कारण नेफा और लद्दाख, काश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात में बेघर हो गये थे ; और

(ख) उक्त राज्यों में केन्द्रीय सरकार ने कितने सरणार्थी शिविर स्थापित किये ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) एक विवरण, जिसमें स्थिति बताई गई है सभा पटल पररखा है। [पुस्कालय में रख दिया गया। देखिये संख्या LT-1040/68]

(ख) प्रभावित राज्यों में केन्द्रीय सरकार ने प्रत्यक्ष रूप में कोई शिविर स्थापित नहीं किये थे, किन्तु जहां कहीं आवश्यक समझा सम्बन्धित राज्य सरकारों को ऐसे शिविर स्थापित करने में सहायता तथा वित्तीय सहायता दी थी। देख

भाल के लिये कर्मचारी वर्ग की संख्या को मजबूत करने में भी सहायता दी थी जैसा कि जम्मू और काश्मीर राज्य में। अगस्त-सितम्बर, 1965 में हुये भारत पाकिस्तान संघर्ष के बाद जम्मू और काश्मीर में 13 शिविर तथा राजस्थान में 5 शिविर राज्य सरकारों द्वारा खोले गये थे। ये सभी शिविर बंद कर दिये गये हैं।

Transportation of Fertilizers

8512. SHRI M. N. REDDY : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the amount paid towards the transport of fertilizers during last 3 years and how much was spent on transportation through railways and road ;

(b) the reasons for spending large amounts by Government on the transport of fertilizers by road ; and

(c) the comparative cost of transport of fertilizers per tonne by road and Railways ?

THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI JAGJIWAN RAM) : (a) The amount paid towards the transport of fertilizers during the last three years and spent on transportation through railways and road is as under :—

	1965-66	1966-67	1967-68
Transport charges (rail and road) :	Rs. 5,58,65,066	5,85,35,850	Accounts not yet ready
Rail :	Separate figures not available.	4,64,04,579	-do-
Road :	-do-	1,21,31,271	-do-

(b) Due to inadequate availability of rail transport and occasional operational restrictions and also to meet the urgent demands of the State Governments, movement by road has been resorted to for supplementing rail capacity. Moreover, this mode of transport helped considerably in the expeditious clearance of imported fertilizers from the ports and speedier supply to the States.

(c) Movement of fertilisers by road is arranged by the State Governments who fix rates with the transporters. These rates are not uniform. Generally, the rates of transport by road range between 16 paise to 20 paise per tonne per Kilometer as against the average rail rate of 5 paise per tonne per k.m.

Agriculture Graduates

8513. SHRI M. N. REDDY : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the number of Graduates in Agriculture (B. Sc. Ag.) who graduated from various Colleges and Universities in the country during last 3 years, year-wise ;

(b) the proportion or percentage of these graduates absorbed in Government jobs during the above period ; and

(c) the measures which Government propose to take for providing employment or other benefits to the unemployed Graduates in future ?

THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI JAGJIWAN RAM) : (a) The number of graduates in agriculture passing out from various Colleges and Universities during 1964—66 is shown below :

	1964	1965	1966
Total output	4,731	5,259	4,232
Number of colleges (for output figures)	56	59	63

(b) The number, proportion or percentage of the Agriculture Graduates who have secured Government jobs within and outside the country is not available with the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation as employment opportunities are offered besides

Central Government, by State Governments and private agencies.

(c) Fourth Plan schemes of Agricultural education, research and development being formulated currently would be expected to provide adequate employment opportunities for trained Agriculture graduates in future, in addition to new openings that would necessarily come up during the course of our developing agriculture in the private sector.

Import of Rice and Wheat

8514. SHRI JUGAL MONDAL : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the quantity of wheat and rice imported from different countries during the last three months ; and

(b) the conditions on which these have been imported ?

THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI JAGJIWAN RAM) : (a) A statement giving the required information is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-1041/68]

(b) Wheat from the U.S.A. has been imported partly under the P.L. 480 Agreement and partly as commercial purchase in U.S.A. Imports of wheat from Australia were out of commercial purchase in that country.

Rice has been imported from Thailand and Burma also by commercial purchase in those countries.

Supply of Ammonium Sulphate and Urea to M/s. Shaw Wallace and Co., Calcutta

8515. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the quantity of ammonium sulphate and urea given to M/s. Shaw Wallace & Co., Calcutta in the year 1966-67 and upto the end of March, 1968 ; and

(b) the purpose for which these materials were given to the said concern ?

THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI JAGJIWAN RAM) : (a) and (b). The following quantities of sulphate of ammonia and urea were allotted in favour of M/s. Shaw Wallace & Co., Calcutta in the year 1966-67 and upto the end of March, 68 for the purpose shown against each :

(Figures in tonnes)

Name of the firm	Kind of fertiliser	Period		Purpose for which allotment was made
		1966-67	1967-68	
M/s. Shaw Wallace & Co., Calcutta	Sulphate of Ammonia	11,000	12,424	For supply to tea gardens in the North East India *i.e.* Assam and West Bengal.
	Urea	44	—	For manufacturing yeast.

Price of Cotton

8516. SHRI BEDABRATA BARUA : SHRI RABI RAY : SHRI RAMACHANDRA VEERAPPA :

Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Gujarat Government have urged the Agricultural Prices Commission to raise the prices of cotton so as to allow certain margin of return to growers ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI JAGJIWAN RAM) : (a) and (b). The Agricultural

Prices Commission visited a number of States during April, 1968, *viz.* Madras, Andhra Pradesh, Maharashtra and Gujarat and held discussions with representatives of growers, traders, industry as well as the State Governments on the Price Policy for cottons and groundnut for the 1968-69 season. During the course of these discussions various viewpoints were presented to the Commission by the concerned interests. The Commission has not yet submitted its Report on the Price Policy for Cotton for 1968-69 season. In the circumstances, Government is not aware of the views expressed before the Agricultural Prices Commission by the Gujarat Government or for that matter by any other party that placed its views before the Commission.

Supply of Ammonium Sulphate and Urea

8517. SHRI KASHI NATH PANDEY : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the names of Distilleries which were given ammonium sulphate and urea during the year 1966-67 and upto the end of March, 1968 by the Central Agriculture Department and the quantity given to each of them ; and

(b) the amount of gain or loss to Government in the purchase and sale of these items ?

THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI JAGJIWAN RAM) : (a) A statement giving the names of distilleries and the quantity of Sulphate of Ammonia and Urea released to each of them during the year 1966-67 and 1967-68 is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-1042/68].

(b) No separate trading and profit and loss accounts are prepared for issue to distilleries. However, the Central Fertiliser Pool, its main task being equitable distribution of fertilisers for agricultural use, incurred a loss of Rs. 40.66 crores in the year 1966-67. The accounts of the Pool for the year 1967-68 have not yet been finalised.

East Pakistan Refugees

8518. SHRI P. R. THAKUR : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 518 on the 12th December, 1967 and state :

(a) whether the information regarding the denial of compensation for the acquired landed properties of East Pakistan displaced persons have since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the reasons and grounds for the Government's refusal to review their policy in regard to the payment of compensation to the East Pakistan displaced persons for their properties left in East Pakistan ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION (SHRI D. R. CHAVAN) : (a) Yes.

(b) It has been reported that the Government of Pakistan have treated the Property left behind by the migrants to India as 'Enemy Property' under the Defence of Pakistan Rules and have not paid compensation for the same. The Government had lodged a protest with the Government of Pakistan.

(c) It has not been found possible for the Government of India to pay compensation to the migrants for their properties left behind for the following amongst other reasons :

(i) The properties of the refugees from East Pakistan are governed by the provisions of Nehru-Liaquat Pact of 1950 according to which their proprietary rights subsist in them.

(ii) There is virtually no evacuee property in the Eastern Zone in India which can form part of any Compensation Pool from which compensation can be paid to the migrants.

(iii) Apart from the financial implications, there will be serious difficulties in verification of claims of the migrants.

Deep Sea Fishing in West Bengal

8519. SHRI BADRUDDUJA :
SHRI JYOTIRMOY BASU :
SHRI DEVEN SEN :
SHRI TRIDIB KUMAR CHAUDHURI :

Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Canadian collaboration has been arranged for deep sea fishing in the West Bengal sea costs ; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI JAGJIWAN RAM) : (a) No, Sir. No Canadian collaboration has been arranged for deep sea fishing on the West Bengal sea coast.

(b) Does not arise.

Educated Unempoyed in India

8520. SHRI M. L. SONDHI : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) the number of educated unemployed in the country as on the 1st January, 1968 on the basis of the figures available with Employment Exchanges in the country ;

(b) whether Government are taking care to make the proposed Fourth Plan as employment oriented in view of the serious unemployment situation in the country ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION (SHRI S. C. JAMIR) : (a) The number of educated employment seekers (Matriculates and above) on the Live Register of Employment Exchanges in India, as on 1.1.1968, was 10,87,371.

(b) and (c). The preparatory work on the Fourth Plan has just been initiated and decisions on the various policy aspects of the Plan including employment Policy are yet to be taken.

Branch Office of Food Corporation of India at Trivandrum

8521. SHRI MANGALATHUMADAM : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether any discontentment has been expressed by the State Government about the functioning of the Branch Office of the Food Corporation of India at Trivandrum ; and

(b) if so, the steps taken by Government to remedy such matters ?

THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI JAGJIWAN RAM) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Soviet Aid for Consumer Co-operative Stores

8522. SHRI K. LAKKAPPA : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government have sought assistance from the U.S.S.R. for Consumer Co-operative Stores in the country ; and

(b) if so, the nature of the assistance sought for and its objects ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI M. S. GURUPADASWAMY) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

नागपुर और बम्बई के बीच सीधी टेलीफोन व्यवस्था

8523. **श्री देवराव पाटिल** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर और बम्बई के बीच सीधी टेलीफोन व्यवस्था चालू करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है और यह सेवा संभवत कब तक आरम्भ की जायगी ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) नागपुर और बम्बई के बीच सहघुरीय केबिल प्रणाली की व्यवस्था की जा रही है। इस काम को हाथ में ले लिया गया है। नागपुर से सम्बन्ध जोड़ने के लिए बम्बई ट्रंक स्वचल एक्सचेंज के विस्तार हेतु उपस्कर के लिए आर्डर भी दे दिये गये हैं। 1971 तक सीधी डायलिंग सुविधा उपलब्ध किये जाने की आशा है।

Rehabilitation of East Pakistan Refugees in Isgoan (A.P.)

8524. SHRI GANGA REDDY : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether Government are aware that an area of more than two thousand acres of forest at Isgoan in Adilabad District in Andhra Pradesh has been cleared to rehabilitate the East Pakistan refugees;

(b) if so, the amount spent per acre for reclamation;

(c) the number of families who have rehabilitated at Isgoan; and

(d) whether it is a fact that this area selected for rehabilitation is not at all fit for cultivation ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION (SHRI D. R. CHAVAN) : (a) About 6,700 acres of forest lands have been reclaimed at Isagaon in Adilabad District of Andhra Pradesh for rehabilitation of new migrants from East Pakistan.

(b) About Rs. 400/-per acre.

(c) Nearly 700 new migrant families were reported to be residing at Isagaon on 31.3.1968; they are in various stages of rehabilitation.

(d) No, Sir. The area selected for rehabilitation has been found favourable for cultivation and is a responsive to good soil management and cropping practices.

Refugees in Neil Island of Andaman Group

8525. SHRI K. R. GANESH : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) how many refugee settlers have been colonised in the Neil island of the Andaman Group and when they were brought there;

(b) the scheme for their settlement and whether land has been allotted to them;

(c) whether land has been found suitable for paddy cultivation and whether there is shortage of water for this land; and

(d) if so, the scheme which Government have formulated to engage the settlers in the meantime ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION (SHRI D. R. CHAVAN) : (a) In April and May, 1967, 86 families of East Pakistan migrants comprising 402 persons were sent to Neil Island.

(b) Land measuring approximately 2,000 acres in the Neil Island is suitable for reclamation. Out of this, nearly 1,000 acres have already been cleared of forest. In the coming season it is proposed to have this area of land sown by the migrants. As more land is cleared of forest, land cleared earlier will be used for planting coconut trees for which there is good scope in this island. Eventually it is expected that three-fifths of the area of land cleared will be brought under plantation and the rest will be used for normal agricultural purposes. Five acres of land comprising three acres of plantation and two of ordinary agricultural land will be allotted to each migrant family.

(c) Land in this island is more suitable for coconut Plantation. However, it has been found that in about two-fifths of the land, which will be clear-felled, paddy can be grown. There is no shortage of water in the island.

(d) The migrants who have been sent to Neil Island are at present working on clear-felling of the forest. In the coming season they will, in addition, grow paddy on land already cleared. thereafter, coconut plantations will be raised on lands which are more suitable for this purpose and the migrants will work on raising such plantations.

Financial Assistance for Soil Conservation in Catchment Areas

8526. SHRI S. A. AGADI : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE

be pleased to state the amount earmarked and utilised for soil conservation in the catchment area of River Valley Projects for the five years period ending the 31st March, 1967 in the Mysore, Andhra Pradesh and Maharashtra, year-wise ?

THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI JAGJIWAN RAM): The amounts earmarked and utilised for Soil Conservation in Catchment areas of River Valley Projects for the five years period ending the 31st March, 1967 in Mysore, Andhra Pradesh and Maharashtra, States, yearwise, are given below :—

(Rs. in lakhs)

year	Amount allocated	Amount utilised
	Mysore	
1962-63	6.90	0.59
1963-64		3.49
1964-65	17.60	4.56
1965-66		3.96
1966-67	10.00	7.76
Total.	34.50	20.36
	Andhra Pradesh	
1962-63		15.39
1963-64	60.00	13.18
1964-65		16 51
1965-66		15.91
1966-67	13.00	15.38
Total.	73.00	76.37
	Maharashtra	
1962-63	—	—
1963-64	—	—
1964-65	10.00	4.01
1965-66		6.00
1966-67	8.00	13.33
Total.	18.00	23.34

दिल्ली दुग्ध योजना

8527. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने दिल्ली दुग्ध योजना पर वित्तीय वर्ष 1964-65, 1965-66 और 1966-67 में कितना धन व्यय किया ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम): सरकार ने दिल्ली दुग्ध योजना पर 1964-65, 1965-66 तथा 1966-67 में निम्नलिखित राशि खर्च की:-

1964-65	4,83,13,854 रु०
1965-66	6,01,17,319 रु०
1966-67	6,94,09,106 रु०

निर्वाचन याचिकाएं

8528. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1967 के आम चुनाव से सम्बन्धित कितनी निर्वाचन याचिकाएं उच्चतम न्यायालय में दायर की गई तथा कितनी याचिकाओं के बारे में निर्णय किया गया कितनी याचिकाओं के बारे में अब तक नहीं दिया गया है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री यु० मुनुस सलीम) : उच्चतम न्यायालय में सीधे कोई निर्वाचन याचिकाएं फाइल नहीं की जातीं ; उच्च न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध अपीलें ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 116 क के अधीन, उच्चतम न्यायालय में फाइल की जाती हैं ।

विभिन्न उच्च न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध 74 अपीलें उच्चतम न्यायालय में फाइल की गई हैं जिनमें से 6 अब तक निपटाई जा चुकी हैं ।

Rehabilitation of Chakma Families

8529. **SHRIMATI JYOTSNA CHANDA:** Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some of the Chakma families, who were taken to N. E. F. A. area for rehabilitation have come back to Cachar recently ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION (SHRI D. R. CHAVAN) : (a) Yes, Sir.

(b) It is reported that these families have been instigated by some interested persons to move to Tripura where other families of the Chakma tribe are already residing in substantial number. It appears that the migrant Chakma families, which in their pioneering efforts for being re-settled in NEFA found life comparatively hard, fell an easy prey to such instigations.

Mail Boxes

8530. SHRI MAHANT DIGVIJAI NATH : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government are introducing new type of mail boxes in the country ;

(b) if so, the size and the cost of the letter boxes ;

(c) the estimated cost thereof ; and

(d) the reasons with details for such a replacement ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND COMMUNICATIONS (SHRI I. K. GUJRAL) ; (a) No. However, the question of improving the traditional design of letter boxes is under consideration,

(b) to (d). Do not arise.

Geologists and Geophysicists

8531. SHRI MAHANT DIGVIJAI NATH : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there are more than 5,000 Geologists and Geophysicists with a Post-graduate degree in the country ;

(b) the total number enrolled in the National Register of Scientific and Technical Personnel the Council of Scientific and Industrial Research ; and

(c) the steps which Government propose to take for absorbing them to avoid further aggravation of the unemployment crisis in the country ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION (SHRI S. C. JAMIR) : (a) Yes.

(b) Over four thousand.

(c) The development programmes in mining and other allied activities included in the annual plans are expected to provide more and more employment opportunities.

East Pakistan Refugees in Andamans

8532. SHRI MAHANT DIGVIJAI NATH : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the displaced persons from East Pakistan are being sent to Andaman Island this year for permanent rehabilitation ;

(b) the total number of such families being sent ;

(c) whether more families are coming from East Pakistan ; and

(d) the estimated expenditure to be incurred on their rehabilitation ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION (SHRI D. R. CHAVAN) : (a) Yes.

(b) It is proposed to send, after the ensuring monsoon, 114 families of East Pakistan migrants to the Andaman and Nicobar Islands.

(c) Yes, The movement of migrants from East Pakistan is still continuing.

(d) The total budget provision proposed for the year 1968-69 for the rehabilitation of displaced persons from East Pakistan and repatriates from Burma and Ceylon is 21 crores approximately.

Postal Division for Mizo Hills District

8533. SHRIMATI JYOTSNA CHANDA: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether Government propose to create a separate Postal Division in the near future in the Mizo Hills District ;

(b) if so, when ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND COMMUNICATIONS (SHRI I. K. GUJRAL) : (a) No,

(b) Does not arise.

(c) The proposal is not justified according to the Departmental standards.

Farm Credit

8534. SHRI KAMESHWAR SINGH : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have allotted funds for farm credit during the year 1968-69 ;

(b) if so, the amount thereof :

(c) the amount allotted to Bihar and the total percentage allotted to Monghyr District out of that ; and

(d) the time by which actual distribution of loan is likely to start in the rural areas ?

THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI JAGJIWAN RAM) : (a) to (d). A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-1043/68].

Proposed Strike by United Chini Mill Mazdoor Sangh

8535. SHRI KAMESHWAR SINGH : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the members of the United Chini Mill Mazdoor Sangh are going to launched a strike in October next ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the steps taken by Government to avert the strike ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI HATHI) : (a) No.

(b) and (c). Do not arise.

Agricultural Graduates

8536. SHRI P. R. THAKUR : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the total number of Agricultural Graduates produced in the country, year-wise, from the beginning of the First Plan period till to-date ;

(b) the number of such Graduates from amongst the Scheduled Castes and Scheduled Tribes separately produced each year during the above period ; and

(c) the corresponding year-wise number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes students who were awarded Government scholarships/stipends for agricultural courses ?

THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI JAGJIWAN RAM) : (a) The number of Agricultural Graduates produced in the country from 1954 to 1966 is given below :

	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960
Total output	792	886	808	994	1,387	1,700	2,090
Number of colleges (for output figures)	20	21	21	24	29	31	34

	1961	1962	1963	1964	1965	1966
Total output	2,612	2,912	4,099	4,731	5,259	4,232
Number of colleges (for output figures)	39	46	53	56	59	63

था, मार डाला गया। महाराष्ट्र के श्री के० पी० पाटिल, जो डिप्टी फूड मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बयान दिया है, क्योंकि वहां भी...

MR. SPEAKER : Do not bring in all those things. This is about the Andhra Minister.

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, दोनों राज्यों में कांग्रेस सरकार चल रही है, इसलिये मैं बहुत सरली से कहना चाहता हूं बल्कि मेरा आरोप है कि गृह मन्त्री क्यों जानबूझ कर उन की रक्षा कर रहे हैं। मेरी मांग है कि क्या वह इस सदन को यह आश्वासन देंगे कि यह मन्त्री जो कि आन्ध्र प्रदेश राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं मैं यह श्री जानकारी के लिए कह सकता हूं कि जब भारत सरकार की सैन्ट्रल कमेटी आन इन्डिकेशन आफ अनटचेबिल्टी आन्ध्र प्रदेश का दौरा कर रही थी, तो उन के सामने जो गवाही दी है...

MR. SPEAKER : I will suggest one thing for your convenience. The Home Minister says that he has no information. So, whatever you may ask, he will say only that.

SHRI MADHU LIMAYE (Monghyr) : Let him collect the information.

MR. SPEAKER : That is exactly what I want to suggest. After all, without information how can he answer what you ask ? When he has information, he will be able to give it.

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar) : Keep it pending.

MR. SPEAKER : That is exactly what I am saying. When he gets information, he will be able to give it.

SHRI SHEO NARAIN (Basti) : He should give us an assurance that he will give us a report.

MR. SPEAKER : Papers to be laid. Shri Shinde.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI D. ERING) : Sir, on behalf of Annasahib Shinde... (*Interruption*).

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, यह क्या हो रहा है ?

MR. SPEAKER : That is postponed.

श्री मधु लिमये : वह तो मैं समझ गया, लेकिन यह हो क्या रहा है ?

श्री जार्ज फरनेन्डीज (बम्बई दक्षिण) : ऐसे नहीं चलेगा। हम इस मन्त्री का इस्तीफा चाहते हैं। गृह मन्त्री हमें आश्वासन दें कि उन को हटायेंगे। इस मन्त्री को हटा देना चाहिये। ऐसे नहीं चल सकता...(व्यवधान...)

श्री रवि राय : उत्तर प्रदेश के एक मन्त्री को हटाया गया था। गृह मन्त्री हम को आश्वासन दें कि वह इन को हटायेंगे।

श्री हुकम चन्द कछवाय (उज्जैन) : इस सरकार के द्वारा हरिजनों को यहां से निकाला जा रहा है।

SHRI P. R. THAKUR : This man would have been dismembered... (*Interruption*). You should know that... (*Interruption*)

श्री जार्ज फरनेन्डीज : आप हम को उन के डिस्मिसल का आश्वासन दें।

श्री रवि राय : आप को पहले से सारी मालूमात ले कर आना चाहिये था।

MR. SPEAKER : I hope, Shri Thakur is tired enough now ; so also, others I think.

SHRI SHEO NARAIN : Only a simple question, Sir.

MR. SPEAKER : It is postponed. Nothing is done till he gets the information.

(b) and (c). The information is being collected from the Agricultural Colleges functioning in the country and the State Governments. It will be laid on the Table of the Sabha when it is received.

East Pakistan Displaced Persons

8537. SHRI P. R. THAKUR : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 576 on the 15th February, 1968 and state :

(a) whether the information regarding the Scheduled Castes displaced persons from East Pakistan settled in the Andamans and Nicobar Islands since 1963-64, has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the number of similar Scheduled Castes families from amongst the total of 2861 families settled there between 1949 and 1963 ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION (SHRI D. R. CHAVAN) : (a) and (b). Yes, Sir. No community has been declared as Scheduled Caste in the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands. However, out of the new migrants who moved to the islands during the years 1955. 1966 and 1967, 382 families declared themselves as belonging to scheduled Castes in East Pakistan.

(c) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

12.13 hrs

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Reported Statement by the Agriculture Minister of Andhra Pradesh against Harijans

श्री रवि राय (पुरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर माननीय गृह कार्य मन्त्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे अपना वक्तव्य दें—

"हरिजनों के विरुद्ध आन्ध्र प्रदेश के कृषि मंत्री का कथित वक्तव्य ।"

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN) : Mr. Speaker, Sir, Government's attention has been drawn to the news item appearing in 'Patriot' of April 24, 1968 in which the Andhra Pradesh Agriculture Minister's informal talk with pressmen has been reported. A report from the State Government is awaited.

I have discussed the matter with the Chief Minister, Andhra Pradesh, who is in Delhi, today. He has assured me that he will personally look into the matter and send me a report.

SHRI NATH PAI (Rajapur) : Meanwhile, suspend him.

SHRI P. R. THAKUR (Nabadwip) : Why do you not ask the press reporters to give you the report ?

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत दुख की बात है । पिछले एक महीने से यह सदन हरिजनों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, उन के बारे में चर्चा कर रहा है, उस के बावजूद "पैट्रियोट" में जो खबर निकली है, यदि वह सत्य है तो यह बड़े आश्चर्य की बात है । मेरे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जवाब में गृह मंत्री जी के जवाब को सुन कर मुझे आश्चर्य हुआ । उन को कहना चाहिये था कि सिम्मारेड्डी ने जो दोष किया है, जो पाप किया है, उन को वहां से निकाला जायेगा । लेकिन वह यहां आ कर कहते हैं कि मैं ब्रह्मानन्द रेड्डी के साथ बात करूंगा । मैं पूछना चाहता हूं...

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बात किया है ।

श्री रवि राय : यदि उन्होंने बात की है तो उन के बात करने का क्या अर्थ है ? आपके सामने आन्ध्र प्रदेश के बारे में अनेकों घटनायें आई हैं - वहां पर एक हरिजन लड़के को जला दिया गया, मानक-गोडा गांव में इन्दु विलसन नाम के एक हरिजन को, जो ईसाई बन गया

SHRI SHEO NARAIN : The Chief Minister is here in Delhi.

MR. SPEAKER : It is perfectly right. You have gone on record. But the point is that the Home Minister has not got information.

SHRI SHEO NARAIN : The Chief Minister should give the decision.

SHRI SONAVANE (Pandharpur) : When will the information be available ?

MR. SPEAKER : I do not know. After all, he must be given some time. I cannot pin him down. Your name is not there.

श्री प्रताप सिंह (शिमला) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल है...

MR. SPEAKER : I am not allowing any *sawal* now.

श्री प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइन्ट आफ़ आर्डर है ।

MR. SPEAKER : There is no point of order as there is no subject before the House. The Speaker is standing and there can be no point of order when the Speaker is standing.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आप का ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूँ...

MR. SPEAKER : Suggest to me what else can be done now, when he has no information.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : उन को मन्त्री मंडल से हटाया जाय, हम यह आश्वासन चाहते हैं । आप उस को हटा दीजिये, वह मंत्री बनने के लायक नहीं है, वह बिलकुल नालायक है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप गृह मन्त्री जी से यह पूछिये कि क्या उन्होंने आन्ध्र के कृषि मन्त्री से सम्पर्क स्थापित करने का प्रयत्न किया था । गृह मंत्री ने कहा है कि वह मुख्य मन्त्री से बात करेंगे । उन्होंने सम्पर्क स्थापित किया, लेकिन वह सम्पर्क स्थापित नहीं कर सके, वह इस के लिये अधिक समय चाहते है - ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा है ।

MR. SPEAKER : Will you kindly sit down ? What he said was that he spoke to the Chief Minister and the Chief Minister also could not have known because he had come here day before yesterday. Both of them will try to contact him and find out the correct version and, perhaps, they will make an enquiry which one is the correct version. *(Interruptions)*

SHRI HEM BARUA (Mangaldai) : May I make a submission ? The Home Minister said that he contacted the Chief Minister and the Chief Minister has no information because he has not succeeded in contacting the Minister concerned. He should have contacted the Minister concerned who wants Harijans to be kicked... *(Interruptions)*

MR. SPEAKER : You are saying what the Home Minister ought to have done and all that... *(Interruptions)*

SHRI HEM BARUA : This Minister from your own State, Sir, who wants Harijans to be kicked can now say that Parliament should be kicked... *(Interruptions)* If he says that the Speaker of the Parliament should be kicked, if he says like that, what will happen to us ? *(Interruptions)*

MR. SPEAKER : Order, order. Will you kindly sit down ? What I have done just now is to postpone it. Do you want the Home Minister to reply saying that he must be given time ? *(Interruptions)* Four or five of you are getting up every minute.

SHRI HEM BARUA : That Minister might say you should be kicked.

श्री मधु लिमये : आप 24 घंटे का समय दीजिये और इसको कल रखिये । यह बहुत गम्भीर मामला है । आप गवर्नर से सम्पर्क स्थापित कीजिये ।

श्री कंवर लाल गुप्त : आप उनको गिरफ्तार करके दिल्ली मंगवाइये और उन पर मुकदमा चलाइये ।

MR. SPEAKER : We will send Mr. Kanwar Lal Gupta to arrest him. When shall we have it ?

SHRI Y. B. CHAVAN : May I say a word ? It is, certainly, a matter of concern to everybody. When all of us read this news, certainly, all of us were rather concerned about it and shocked, as a matter of fact, and I do not think any sensible man can speak in that language. I have no doubt about that.

SHRI P. R. THAKUR : He should be kicked out... *(Interruptions)*

SHRI Y. B. CHAVAN : Why don't you listen to me ?

SHRI S. M. KRISHNA (Mandya) : Has he contradicted the statement ?

श्री मधु लिमये : अभी हम उनका इन्कार नहीं मानेंगे ।

SHRI Y. B. CHAVAN : When such a situation arises, my duty was to find out the facts from the State Government. Somebody made a suggestion that I ought to have contacted him personally. That would not have been enough. Suppose I contact the person concerned on telephone. It is very difficult for me to accept as it is.

श्री रवि राय : वहां पर गवर्नर मौजूद हैं ।

श्री मधु लिमये : किसी गैर कांग्रेसी सरकार को बर्खास्त करना हो तो आप हर समय गवर्नर से बात कर सकते हैं लेकिन हरिजनों और आदिवासियों के मामले में गवर्नर से सम्पर्क नहीं स्थापित कर सकते हैं ।

SHRI Y. B. CHAVAN : Even in the case of non-Congress Governments, I have never contacted Governors. Governors are not expected to do these things.

The only other alternative which was open to me was to discuss the matter with the Chief Minister who happened to be in Delhi. As he was here, he himself did not know about it. He said, he would contact the Minister concerned... *(Interruptions)* He could not get him on the telephone also. Again, I discussed the matter with him before I came to this honourable House. He has assured that he would personally look into the matter and send me a report. What more can I do ?

श्री जार्ज फरनेन्डीज : हमें उनका इस्तीफा चाहिये, रिपोर्ट नहीं चाहिये । उनको रिमूव किया जाये ।

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): He should have been arrested.

SHRI GEORGE FERNANDES : He must be removed.

SHRI P. R. THAKUR : If this sort of thing would have happened in West Bengal, people would have dismembered him.

MR. SPEAKER : Half a dozen times I have warned you. It is not proper. You are an elderly person. Once I can understand, twice I can understand but not like this.

SHRI VASUDEVAN NAIR (Peermade): Our complaint is only this. After hearing the laborious explanation of the Home Minister, we are all the more convinced that he is treating the matter in the most casual manner...

SHRI Y. B. CHAVAN : No.

SHRI VASUDEVAN NAIR : He says, somebody will go, somebody will send a report. After all, Hyderabad is not in the moon, it is not in another Continent. They can immediately get a report. They should treat this matter in the most urgent manner. On behalf of the House, please impress on the Government that they should get us the report tomorrow... *(Interruptions)*

MR. SPEAKER : After two days. We shall give two days' time...

श्री मधु लिमये : दो दिन तो हो गये हैं ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : हमको शाम तक उत्तर मिलना चाहिये ।

SHRI MADHU LIMAYE : Only 24 hours.

MR. SPEAKER : Please try to understand me. The Chief Minister is here. The Chief Minister has to go back.

SHRI MADHU LIMAYE : He need not go back.

यह तो डाइलेट्री टैक्टिक्स हैं। टेलीफोन है और वायरलेस है जिस पर गवर्नर से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।

MR. SPEAKER : What is the use of telephoning ? Suppose, the Home Minister telephones and he denies. Are you satisfied with it ?

SHRI RANGA (Srikakulam) : I join you in expressing the concern from all sections of this House, and the Home Minister has also said it, about the way in which these things have appeared in the papers and these things are said to have been done by the Minister and also his Ministry. We all would like to have it discussed properly in this House. Mere call-attention will not be enough... (*Interruptions*)

MR. SPEAKER : Eliciting information.

SHRI RANGA : Instead of allowing half an hour over eliciting information and thereafter again a separate discussion, it will be much better if you are good enough to give us two hours to discuss this, so that all parties can express their concern in regard to this particular matter ; otherwise, we will be at the mercy of these lots. I find that some of us had also given notice, but none of our party members has found a place in your list. Therefore, you may be pleased to take it up either tomorrow or the day after tomorrow, as soon as possible, and give us two hours so that all parties would have an opportunity to express their concern.

MR. SPEAKER : Now I would like to say this...(*Interruptions*) This is rather an embarrassing situation for me. I happen to come from Andhra Pradesh. Therefore, yesterday itself I admitted it ; the moment I got the notice, I admitted it. Here is the Home Minister who has to reply ; it is not the Speaker who is to reply. On a call-attention notice, I would not have normally allowed this discussion, but if I had not allowed one or two leaders to speak, perhaps they would have misunderstood me. Therefore, I allowed. The Home Minister says that he would expeditiously get the information and tell us .. (*Interruptions*)

एक माननीय सदस्य : कल या परसों ?

MR. SPEAKER : It is the Home Minister who has to say when we can have it, tomorrow or the day after. After all, he will tell me the moment he gets the information. Monday ?

SHRI Y. B. CHAVAN : Yes.

MR. SPEAKER : Yes, Monday. Mr. Ranga's suggestion is also there. The call-attention is also there ; unfortunately, there are lots; what can I do? (*Interruptions*) Therefore, it will be taken up on Monday. Now it is over.

12.29 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Notification under Essential Commodities Act.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION (SHRI D. ERING) : On behalf of Shri Annasahib Shinde, I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications under sub-section (6) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 :—

(1) The Madhya Pradesh Foodgrains (Restriction on Border Transport) Amendment Order, 1968, published in Notification No. G. S. R. 716 in Gazette of India dated the 15th April, 1968.

(2) The West Bengal Rice (Movement Control) Amendment Order, 1968, published in Notification No. G. S. R. 746 in Gazette of India dated the 17th April, 1968.

(3) G. S. R. 747 published in Gazette of India dated the 17th April, 1968 rescinding Bihar Government's Order No. 21807-S. C. dated the 1st November, 1966, prohibiting export of pulses from Bihar. [*Placed in Library. See* No. LT-1021/68]

Notification under Industrial Disputes Act and Employees' State Insurance (Control) Second Amendment Rules

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINSTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION (SHRI S. C. JAMIR) : I beg to lay on the Table :

(1) (i) A copy of Notification No. 30-I.R./IR/IA/1(A)/64-Pt. published in the Calcutta Gazette dated the 25th January, 1968 adding certain industries to the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947, under sub-section (3) of section 40 of the said Act, read with clause (c) (iv) of the Proclamation dated the 20th February, 1968, issued by the President in relation to the State of West Bengal.

(ii) A statement showing reasons for delay in laying the above Notification. [*Placed in Library. See* No. LT-1022/68].

(2) A copy of the Employees' State Insurance (Control) Second Amendment Rules, 1968 published in Notification No. G. S. R. 677 in Gazette of India dated the 6th April, 1968, under sub-section (4) of section 95 of the Employees' State Insurance Act, 1948. [*Placed in Library. See* No. LT-1023/68].

ESTIMATES COMMITTEE

Fifty-fourth Report

SHRI P. VENKATASUBBAIAH (Nandyal) : I beg to present the Fifty-fourth Report of the Estimates Committee on action taken by Government on the recommendations contained in the Hundred and Second Report of the Estimates Committee (Third Lok Sabha) on the Ministry of Education—University Grants Commission.

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

Sixteenth, Seventeenth and Eighteenth Reports

SHRI D. N. TIWARY (Gopalgani) : I beg to present the following Reports of the Committee on Public Undertakings :

(1) Sixteenth Report on action taken by Government on the recommendations contained in the Thirty-ninth Report of the Committee on Public Undertakings (Third Lok Sabha) on Bharat Heavy Electricals Limited, New Delhi.

(2) Seventeenth Report on action taken by Government on the recommendations contained in the Fifteenth Report of the Public Accounts Committee (Third Lok Sabha) regarding Audit Report on the Accounts of Damodar Valley Corporation for the year 1961-62.

(3) Eighteenth Report on action taken by Government on the recommendations contained in the Third Report of the Committee on Public Undertakings (Third Lok Sabha) on the Shipping Corporation of India Limited.

---

12 30 hrs.

QUESTIONS ON STATEMENT MADE BY MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE ON 22ND APRIL 1968 *RE* APEEJAY SHIPPING COMPANY

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, यह जो सवाल अब मैं पूछ रहा हूं यह खाद्य मन्त्री श्री जगजीवन राम के द्वारा टामस साहब को वापिस बुलाने के सम्बन्ध में मेरा जो सवाल था उसमें से उत्पन्न हुआ है। उस का उन्होंने जो उस समय जवाब दिया था, उस जवाब को को वह 22 अप्रैल को दुरुस्त कर रहे हैं। वह इनके उस 22 अप्रैल वाले बयान को लेकर है मैं सवाल पूछना चाहता हूं।

सब से पहले तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय ने अपने उस 22 अप्रैल वाले वक्तव्य में जो अपने पहले उत्तर को शुद्ध किया है लेकिन उसे उन्होंने पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं किया है। इस में और भी दो गल-

[श्री मधु लिमये]

तियां रह गयी हैं। उन की ओर मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

इस के बारे में आप के अध्यक्षीय निर्देश 115 के तहत मैंने अपना बयान दिया, सब से पहले दिया था फिर भी आप ने उस को स्वीकारना उचित नहीं समझा। उस के बारे में मुझे नहीं कहना है लेकिन अब वह शुद्धिकरण जो करना चाहते हैं वह पूरा करें। जैसे कि श्री जगजीवन राम ने उस दिन कहा था। यह 11 अप्रैल की कार्यवाही है। पहले श्री शिन्दे ने कहा :

> "I think the Minister has a right to call for any paper and there was nothing unusual as has been mentioned by the hon. Member."

टामस साहब की जो फ़ाइल मंगवाई तो उस में कोई अनयूजवल या असाधारण बात नहीं है। आगे जगजीवन राम जी उसी दिन कहते हैं :

> 'There is nothing unusual in it."

अब मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन को इस बात का पता नहीं है कि प्रधान मन्त्री जी ने 626 तारांकित प्रश्न का 13 मार्च को मुझे जो उत्तर दिया है उस में यह साफ़ लिखा हुआ है :

> "The normal procedure prescribed is for files and papers coming up for decision to travel from the low to the higher level and reach the Minister through a Joint Secretary/Secretary. In specific cases a Deputy Secretary may also deal direct with the Minister."

इस में नारमल प्रोसीजर दे दिया गया है कि ज्वाएंट सेक्रेटरी या सेक्रेटरी ही फाइल मिनिस्टर के सामने रख सकते हैं। यह साधारण प्रक्रिया है। लेकिन उन्होंने आगे कहा है :

> However instructions provide for level-jumping.

अगर असाधारण हो तो मिनिस्टर सीधे भी मंगा सकते हैं विशेष केसेज में वह ऐसा कर सकते हैं। यह सारी असाधारण प्रक्रिया है इसलिए मन्त्री महोदय का यह भी उत्तर ठीक नहीं था। शायद उनको पता नहीं था कि प्रधान मन्त्री ने क्या जवाब दिया है ? हां यह बात सही है कि साधारण रूप में ज्वाएंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी ही फ़ाइल रखते हैं लेकिन विशेश स्थिति में उसे वह सीधे भी मंगा सकते हैं। अब जब विशेष स्थिति है तो विशेष जिम्मेदारी भी आ जाती है।

दूसरे उन्होंने अपने 22 अप्रैल के स्टेटमैंट में कहा है :

> "These enquiries have now revealed that hon. Member, Shri Madhu Limaye, wrote a letter dated the 16th February, 1968 to the Prime Minister, in which he had *inter alia* asked whether the Prime Minister would consider recalling Shri Thomas from Australia."

अब मेरे पास पत्र तो नहीं है लेकिन मुझे निश्चित रूप से यह याद है कि मैंने उन से यह नहीं पूछा कि क्या आप इस पर विचार कर सकते हैं कि टामस साहब को बुलाया जाय ? मैं ने स्पष्ट मांग की थी कि उन को बुलाया जाय क्योंकि उन्होंने अपनी यह एपीजे शिपिंग कम्पनी की असाधारण तरीके से फ़ाइल देखने के पश्चात भी कोई कुछ नहीं किया है इसलिए उनको रिकौल किया जाय।

अब सब से बड़ी बात जो उस में से निकलती है उस का जवाब माननीय जगजीवन राम नहीं दे सकते हैं उस का जवाब तो इन्दिरा जी को ही देना पड़ेगा। आप सावधानी से उन का बयान पढ़िये। उन्होंने यह लिखा है :

> "An extract from the said letter (*i.e.* my letter) regarding the recall of Shri Thomas was not sent either to the Ministry of External Affairs or the Department of Food as the facts of the case had first to be ascertained from my Department (*i.e.* the Food Department) and only then would the Prime Minister have been in a position to examine whether there was a *prima*

case for considering the suggestion for recall. The Prime Minister's Secretariat accordingly sent on 9th March, 1968 for our comments extracts from the said letter of Shri Madhu Limaye relating to the Department of Food. Our comments were only duly sent to the Prime Minister on the 30th March, 1968."

अब मेरा सवाल 11 अप्रैल को आता है। 30 मार्च को इन को खाद्य मन्त्रालय के सारे कमैंट्स और तथ्य मिल जाते हैं। अब 30 मार्च और 11 अप्रैल के बीच में इन को सारी स्थिति पर विचार करके रिकौल के बारे में अपना निर्णय करना चाहिए था और उस की इत्तिला जगजीवन राम जी को देनी चाहिए थी। लेकिन आप देखिये इन की मिनिस्ट्री पूछती है ऐक्सटरनल एफेयर्स मिनिस्टरी को कि रिकौल के बारे में आप की क्या राय है। ऐक्सटरनल एफेयर्स मिनिस्टरी का जवाब आता है। उस के ऊपर 11 तारीख को वह जवाब देते हैं :

"The External Affairs Ministry advised my Department that they were not aware of any demand for the recall of Shri A. M. Thomas."

अब विदेश मंत्री कौन है ? यह जो बैठी हुई हैं वह विदेश मन्त्री भी है और प्रधान मन्त्री भी है। अध्यक्ष महोदय, यह सरकार ही नहीं रह गयी है। यह बिलकुल खंडित सरकार है।

श्री जगजीत यादव (आजमगढ़) : अदब से बोलिये। "है" की जगह "हैं" कहना सीख लीजिये।

श्री मधु लिमये : हिन्दी को हम ज्यादा सिम्प्लीफ़ाई करना चाहते हैं और पूरी तरह राष्ट्रभाषा बनाना चाहते हैं। जो मैं हिन्दी बोलता हूँ वह राष्ट्रभाषा हिन्दी है। हो सकता है कि वह आप की हिन्दी न हो। लेकिन मैं यह साफ़ कर देना चाहता हूँ कि मैं बिलकुल अदब के साथ बोल रहा हूं। जो प्रधान मन्त्री है वही विदेश मन्त्री है। अब प्रधान मन्त्री का सेक्रेटेरियट विदेश मंत्रालय को नहीं बतलाता है और विदेश मन्त्रालय जगजीवन राम जी को नहीं बतलाता है यह बात सही है कि तारीख को जगजीवन राम जी को नीचा दिखाया गया और इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि मेरे प्रश्न का जवाब प्रधान मन्त्री जी दें कि 16 फरवरी को मेरे पत्र द्वारा नोटिस मिलने के पश्चात् और 30 मार्च को इनका कमैंट आने के पश्चात भी आपने विदेश मन्त्रालय और खाद्य मन्त्रालय को टौमस साहब के रिकौल के बारे में जानकारी आप ने क्यों नहीं दी ? क्या प्रधान मन्त्री जी इस का उत्तर देंगी ?

MR. SPEAKER : Shri George Fernandes.

श्री मधु लिमये : मेरे प्रश्न का उत्तर पहले दिलवाया जाय।

MR. SPEAKER : Whatever the points you have both of you may say. Does the Food Minister want to reply ?

श्री मधु लिमये : पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवा दिया जाय। उस उत्तर में से उन का क्वैश्चन निकल सकता है।

THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI JAGJIWAN RAM) : The first point was this. The hon. Member has said that the manner in which the file was called by the then Deputy Minister was unusual. I have said that there is nothing unusual about it. When a case is put up before a Minister or Deputy Minister it has to pass through certain channels. That is the usual thing. It goes to Deputy Secretary, to Joint Secretary to Secretary and then to the Minister or Deputy Minister, as the case may be. That is the usual channel. But when a Minister or a Deputy Minister wants to see certain papers he calls from wherever the paper is and it is not necessary that it passes through all these channels.

श्री मधु लिमये : यह मेरा सवाल नहीं है। मेरे प्रश्न का उत्तर दिया जाय।

SHRI JAGJIWAN RAM : There is nothing unusual for the Minister or Deputy Minister calling for any paper from any Department under him. That is what he did. What has Mr. Thomas done ? He wanted to see whether certain thing was done with a view to prevent defrauding the Government in case of short supply of rice or short landing of rice. He wanted to know what the Department was doing about it. The file was called for. He found in the file that precautionary action was being taken. There was nothing for him to indicate on the file. He saw the file. He was satisfied with the action that was being taken and then the file was returned. There is no case for calling for any explanation from Mr. Thomas or even enquire from him.

SHRI VASUDEVAN NAIR (Peermade): Is it true that the local representative of Apeejay lines is also another Thomas in Delhi ?

SHRI D. C. SHARMA (Gurdaspur) : All Sharma's are not related to each other!

SHRI JAGJIWAN RAM : So far as the Prime Minister was concerned, as I have stated in the statement and clarification itself...

श्री मधु लिमये : इसी लिये प्रधान मन्त्री से सुनना चाहते हैं, आप से पूछना ही नहीं है।

SHRI JAGJIWAN RAM : I think that clarification is quite satisfactory and nothing further is required.

श्री मधु लिमये : इस तरह से तो मैं नहीं चलने दूंगा।

MR. SPEAKER : Let the hon. Minister complete what he wants to say.

SHRI MADHU LIMAYE : I am satisfied with his explanation. I want an answer from the Prime Minister.

SHRI JAGJIWAN RAM : Therefore, I had said that everything was quite clear and there was nothing to ascertain from Shri A. M. Thomas, and, therefore, it was thought that that clarification was quite satisfactory.

श्री मधु लिमये : क्या मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आयेगा ? मैं ने उन से पूछा ही नहीं था। मैं अपना प्रश्न फिर रिपीट करता हूं।

MR. SPEAKER : I allowed this under the item 'clarification from the Food Minister'. This item had not been admitted for clarification from the Prime Minister.

श्री मधु लिमये : वह तो ट्रांस्फर किया गया है। उस में मेरा क्या बस है ? मेरा प्रश्न तो उन्हीं के नाम से था।

MR. SPEAKER : If the Prime Minister can answer, that is a different matter. But the item in the agenda relates to the Food Minister.

श्री मधु लिमये : प्राइम मिनिस्टर के नाम से बुधवार को प्रश्न प्रकाशित हो चुका है।

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI INDIRA GANDHI) : As my colleague the Food Minister has stated, the demand for the recall of Mr. Thomas was based on the theory that something was wrong. Once I got the explanation from the Food Ministry, the occasion for recall was not their, and I am under no obligation to inform either the External Affairs or anybody else about this matter unless the case had been made for such a recall.

श्री मधु लिमये : माफ कीजिये, अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है और बहुत गम्भीर प्वाइंट आफ आर्डर है। आप जरा मेरे प्रश्न को देख लीजिये। इस तरह से तो उन्होंने सारे सदन का अपमान किया है। वह कहती है कि यह उन का आब्लिगेशन नहीं है। जो आप के द्वारा ऐडमिटेड क्वेश्चन था वह उन के नाम से था। उस का एक हिस्सा था :

> "Whether a demand has been made for his recall in view of the suspicious circumstances, and if so, the reaction of the Government thereto."

यह मेरा प्रश्न ऐडमिटेड है। उन्होंने अपने नाम से ट्रांसफर किया खाद्य मन्त्री के नाम में। अब वह कहती हैं कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : नहीं, नहीं...

श्री मधु लिमये : आप ने यह कहा है। मुझे अपना प्वाइंट आफ आर्डर पूरा करने दीजिये। अध्यक्ष महोदय, यह प्रधान मन्त्री हैं। औरत के नाते मैं उन की बड़ी इज्जत करता हूं। लेकिन आप मेरा प्वाइंट आफ आर्डर सुन लीजिये।

MR. SPEAKER : Let him come to the point of order now. I find that he is reading out something else.

श्री मधु लिमये : यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है। उन्होंने कहा कि कोई आब्लिगेशन नहीं है। प्रधान मन्त्री के नाम से प्रश्न था इन्फार्मेशन सप्लाई करने के लिये और आप ने उसे स्वीकार किया है।

> "It is the duty of the External Affairs Minister or the Prime Minister to supply the information."

यह आप का उस दिन का वाक्य है। खाद्य मन्त्री जी ने कहा है :

> "Our comments were duly sent to the Prime Minister on 30th March, 1968."

और उस के बाद एक्स्टर्नल अफेअर्स मिनिस्ट्री से पूछते हैं।

> "That Ministry advised my Department that they were not aware of any demand for the recall of Shri A. M. Thomas."

MR. SPEAKER : What is the point of order ? Let him state it now.

श्री मधु लिमये : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि 30 मार्च और 11 अप्रैल के बीच में अपना निर्णय, अपना उत्तर और उन के पास जो जानकारी थी उसे खाद्य मन्त्री के जवाब के लिये देना उन का कर्तव्य था। अब वह कह रही हैं कि :

> "I am under no obligation."

मैं जानना चाहता हूं कि इस न में कोई अधिकार है या नहीं ?

SHRI RANGA (Srikakulam) : Is it a point of order ?

श्री मधु लिमये : हमारे कुछ अधिकार हैं या नहीं ? मेरे प्रश्न का उत्तर कौन देगा ?

SHRI RANGA : Before you express your view regarding this point of order, you will have to give some consideration to the way in which we have to deal with this Government and this House has to deal with this Government. Here is the Prime Minister who is above all these various things...

MR. SPEAKER : Does he want a discussion on the point of order now.

SHRI RANGA : This is a very important matter.

MR. SPEAKER : A point of order has been raised, and I have to give my ruling on it.

SHRI RANGA : Excuse me, Sir...

MR. SPEAKER : I do not know what to do ; if the leader of a party says like this, what can I say ? It is a point of order which he has raised. Does he want a discussion on the point of order ?

SHRI RANGA : On the point of order, I want to make my submission.

MR. SPEAKER : If Shri Ranga, the leader of the Swatantra Party here says that every point of order must be discussed, then I cannot resist it. When a point of order is raised, I think the Speaker has to give his ruling on it. There cannot be a discussion on the point of order.

SHRI NATH PAI (Rajapur) : Others can also put in their plea.

SHRI RANGA : I do not wish to argue with you. But what I have understood always in regard to a point of order is that such of the other Members as feel like strengthening or opposing the point of order are entitled to draw your attention to certain points. Thereafter, you may be pleased either to uphold the point of order or to dismiss it.

MR. SPEAKER : That means when a point of order is raised by some Member, we will have to hear everybody else here.

श्री मधु लिमये : यह महत्वपूर्ण बात है। आप सुन लीजिये।

SHRI RANGA : You may exercise your judgment, after you allow two or three members, when you think there has been sufficient clarification of the issue involved.

MR. SPEAKER : I would ask him to consider how he would limit the discussion to two or three members if he were in my position. Otherwise, I do not mind.

SHRI RANGA : Surely two or three of us who are Leaders of the Opposition Parties could be heard.

MR. SPEAKER : Shri D. C. Sharma is already getting up.

SHRI RANGA : That way you can always prevent us from saying anything on the ground that 'other people will also want to speak, so please keep quite.' That is the not way we can carry on here. I do not wish to trouble you. But I would only say this that I would like the Prime Minister to take counsel with her own colleagues and constitutional advisers also later on to realise that what she has said this morning is not the right thing, is not the correct thing, is not within the four corners of constitutional propriety. I do not wish to say anything more.

SHRI MADHU LIMAYE : Under rule 376, Shri Ranga has a right of say.

SHRI D. C. SHARMA : A point of order is essentially between a Member of the House raising it and the Speaker or the hon. Member who sits in your Chair by your permission. I do not know what right any other Member has, even if he be the leader of an Opposition Party, to amplify or magnify it or to put a kind of gloss on it. I think the Food Minister has made the position very clear and the Prime Minister has said that there is no point of order in it. I think we are trying to take out water from something out of which nothing can be got. The point of order deserves to be treated with the utmost contempt and indifference.

SHRI NATH PAI : May I humbly make a submission ? I am not trying to go into the substance of the matter raised by Shri Limaye. In the first place, for future guidance of the House, let us turn to page 113 of *More*, where he says that when there is a point of order, there cannot be a point of order on that point of order, as the learned Professor was trying to raise. Let us now turn to our rule 376(4) :

"...the Speaker may,

SHRI JAGJIWAN RAM : If he wants the assistance of any member

SHRI NATH PAI : I wish his other colleagues know the rules as he knows.

MR. SPEAKER : I thought I had heard the member who raised the point of order. Is he also raising a point of order ?

SHRI NATH PAI : I am supporting Shri Limaye's point of order.

MR. SPEAKER : If we allow this kind of thing, tomorrow it will come in our throat every time.

SHRI NATH PAI : No, Sir.

MR. SPEAKER : I do not mind it. I am only saying that this will be the result.

SHRI RANGA : You can always put a stop somewhere, but you cannot put a stop to the leaders of groups.

SHRI NATH PAI : I am repeating that when there is a point of order, there can not be a second potnt of order. I am

rising in support of the point of order raised by Shri Limaye.

Perhaps the Prime Minister did not intend to say what she said. She has allowed herself to say, she has permitted herself to say, something which is highly derogatory to this House (*Interruptions*).

SHRIMATI INDIRA GANDHI : No, no (*Interruptions*). There is a misunderstanding.

SHRI NATH PAI : She said 'I am under no obligation to give...

SHRIMATI INDIRA GANDHI *rose*—

श्री मधु लिमये : पूरे सदन के सामने कहा है। अब क्लैरिफाई कर रही हैं।

SHRI NATH PAI : I am glad that she wants to clarify. I will continue after her. (*Interruption*).

SHRIMATI INDIRA GANDHI *rose*—

SHRI NATH PAI : A Member who is in possession of the House and is making his point of order must sit down voluntarily and you must ask for his leave.

SHRIMATI INDIRA GANDHI : I am sorry.

SHRI NATH PAI : You may kindly continue.

SHRI MADHU LIMAYE : Now, she will sweetly smile and everything will be over !

SHRIMATI INDIRA GANDHI : I am sorry if there is some misapprehension about What I said. I did use the word "obligation". I am not saying that I did not use it. But I did not use it in connection with the hon. House. (*Interruption*) I was talking about the External Affairs Ministry. The question was whether I had sent that to the External Affairs Ministry. That is what I am saying,...(*Interruption*).

SHRI RANGA : We gave you an opportunity for consulting your advisers before you come to a decision

श्री मधु लिमये : विदेश मन्त्री आप हैं और प्रधान मन्त्री भी आप हैं। प्रधान मन्त्री का कार्यालय विदेश मन्त्रालय को बताता नहीं है। यह अच्छा तमाशा चल रहा है। इसको गवर्नमेंट आफ इंडिया कहते हैं।

SHRI RANGA : From the External Affairs Ministry, they sent it to the Agriculture Ministry. But the Agriculture Ministry says "we do not have the information". But here comes the Prime Minister and says "I am under no obligation to inform the Agriculture Ministry about the External Affairs Ministry."

Then, where is the Prime Minister going to function, in the sky, or in a vacuum or by herself, throwing a thunderbolt on Parliament as well as on the other Ministry ? It is again an extraordinary position to take for the Prime Minister.

SOME HON. MEMBERS *rose*—

MR. SPEAKER : Order, order. Once or twice, I would certainly like to hear the leaders and other Members, but if every minute they get up what should I do ? I can only be helplessly sitting ; that is all. I can understand once or twice, but if every minute this is done, you are not helping the Chair to conduct the proceedings of the House and I will become helpless. I can understand if some Members or some leaders of parties get up ; I can hear them, say Shri Ranga or Shri Vajpayee and others. Whatever the wretched' rule may say, when a leader of a Party gets up, we have to give him a little consideration. But if every minute they get up, what am I to do ? I do not know what I should do. Will you complete now, Mr. Nath Pai ?

SHRI NATH PAI : Mr. Speaker, Sir, I am glad that the hon. Prime Minister made partial amends ; but I expected full amends. Now, Sir, if you are patient with me, I shall finish quickly. I am not in the habit of saying what is irrelevant. It says that "the Ministry advised my department that they were not aware of any demand for the recall of Shri A. M. Thomas." This is quite in contradiction of what para 2 says. It was in this connection that and explanation was required and whether the time allowed to her was insufficient. It was while explaining this that she allowed herself to say something which I hold...(*Interruption*).

MR. SPEAKER : What is the point of order ?

SHRI NATH PAI : I am coming to it. Neither the Prime Minister nor Shri Madhu Limaye nor I have got a right to take a position with regard to Parliament whereby it appears that we do not recognise its authority. When the Prime Minister said "I am not under any obligation", this was nothing short of—not deliberately —inadvertence perhaps. But nonetheless, even so, it was a remark which was unfortunate to say that "I am under no obligation. She is under every obligation to this House to give an explanation when called upon. Since the remark was unwittingly uttered by her, it should be gracefully withdrawn by her. (*Interruption*).

SOME HON. MEMBERS *rose*—

MR. SPEAKER : She explained it later ; she said it is not in connection with the House at all. (*Interruption*).

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मुझे एक पत्र लिखा गया । इसका सम्बन्ध एपीजे की कुछ बातों से था । चूंकि खाद्य मन्त्रालय का संबंध इससे था इसलिए जो उसका रेलेवेंट पैरा था वह उनको भेजा गया । यह जो इन्होंने दूसरी डिमांड की है उसका जिक्र न तो इन से किया गया और न दूसरे मन्त्रालय से किया गया ।

जब मुख्य विषय के बारे में जवाब आया तो मुझे लगा कि इस विषय में और कुछ नहीं करना है । मैंने निर्णय लेने में कोई देर नहीं की । मैंने निर्णय ले लिया कि श्री टामस को वापिस नहीं बुलाना है । इसलिए उसके सम्बन्ध में मैंने कहा है कि यह दूसरी बात मैंने एक्सटर्नल एफेयर्ज से नहीं कही थी ।

जहां तक इस सदन का प्रश्न है इस में कोई दो रायें हो ही नहीं सकती हैं और मैं कभी न तो कह सकती हूं और न ही सोच सकती हूं कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है । जिम्मेदारी तो पूरी है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री फरनेंडीज ।

SHRI MADHU LIMAYE *rose*—

MR. SPEAKER : I have called Mr. Fernandes.

SHRI MADHU LIMAYE : You give a ruling on my point of order.

MR. SPEAKER : I have not accepted the point of order.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : यह जो प्रश्न है यह दस अप्रैल को प्रधान मंत्री के नाम पर था । और प्रधान मन्त्री के नाम पर प्रधान मन्त्री की हैसियत से नहीं बल्कि विदेश मन्त्री की हैसियत से तो था । प्रश्न का उत्तर अन्न मन्त्री ने दे दिया । चूंकि दोनों से इसका सम्बन्ध है, इसलिए मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे रहा हूं । दस अप्रैल को प्रधान मन्त्री को इस प्रश्न का जवाब देना था । लेकिन ग्यारह अप्रैल को यानी एक दिन के बाद अन्न मन्त्री ने इसका जवाब दे दिया । यह जो प्रश्न ट्रांस्फर हुआ मैं समझता हूं कि दस तारीख को ही हुआ चूंकि दस तारीख के नोटिस पेपर में यह आया था । यह दस तारीख को ट्रांस्फर हो गया । मैं समझता हूं कि दस तारीख को इसका उत्तर देने के लिए प्रधान मन्त्री जी ने भी जरूर तैयारी की थी । प्रश्न के दूसरे हिस्से में पूछा गया था और उनके रिकाल की मांग की गई थी । यह कहा गया था :

> "whether he has been sent to Australia as our High Commissioner ; whether an attempt has been made for his recall in view of the suspicious circumstances and if so, the reaction of the Government thereto".

मैं समझता हूं कि दस तारीख तक प्रधान मन्त्री ने इस प्रश्न का उत्तर तैयार करके रख लिया होगा, अगर वह अपना काम करती होतीं तो । ग्यारह तारीख को अन्न मन्त्री जी ने उत्तर दिया । फिर यहां से यह सारा झंझट शुरू हुआ । यह कहते हैं कि एक्सटर्नल मन्त्रालय से हमें कोई इसका पता नहीं चला । अब आप देखें कि दस

तारीख को प्रधान मंत्री की ओर से उत्तर आना था और ग्यारह तारीख को अन्न मंत्री जी इसका जवाब देते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री का तैयार किया उत्तर रिकाल के बारे में क्या अन्न मन्त्री को बतलाने में नहीं आया ?

आपने यह कहा है कि मैंने एक्सटर्नल एफेयर्ज मिनिस्ट्री से पूछताछ की और एक्सटर्नल एफेयर्ज मिनिस्ट्री ने हम से यह कहा कि हमारे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है। हो सकता है कि प्रधान मंत्री के नाम की कुछ गड़बड़ी के कारण यहां मन्त्रालयों में भी गड़बड़ी होती हो। यह मुझे मालूम नहीं है। वर्ना प्रधान मन्त्री एक्सटर्नल एफेयर्ज मंत्री भी हों तो मेरी समझ में नहीं आता है कि किस तरह से वह कह सकती हैं कि मुझे यह मालूम नहीं है कि ऐसी कोई मांग हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि दस तारीख के उत्तर का आपको पता था और आपके द्वारा प्रधान मन्त्री की ओर से एक्सटर्नल एफेयर्ज मिनिस्टर की हैसियत से उस उत्तर को भेजने का काम हुआ था या नहीं हुआ था।

फूड मिनिस्टर की स्टेटमेंट का आखिरी हिस्सा आपने देखा ही होगा।

> "I would like to state that after-full consideration of the matter, the Government are satisfied that no action is necessary on the suggestion made by Mr. Limaye for therecall of Mr. A. M. Thomas."

अन्न मन्त्री विदेश मंत्री की ओर से हमें उत्तर दे कर कह रहे हैं कि उनको वापिस बुलाने की अभी कोई जरूरत नहीं है। यह फैसला हो सकता है कि विदेश विषयक मन्त्री ने लिया हो या प्रधान मन्त्री ने लिया हो लेकिन निश्चित तौर से अन्न मंत्री यह फैसला नहीं ले सकते थे टामस साहब के बारे में। मैं जानना चाहता हूँ कि श्री मधु लिमिये का पत्र जाने के बाद आप लोगों ने कोई पूछताछ की है और की है तो क्या खुलासा उनकी ओर से आया है ?

SHRI JAGJIWAN RAM : So far as the last portion is concerned, I have already answered it. Only the question was transferred to my Ministry. There was no draft reply to that. Therefore, it was necessary to ascertain that portion, as I explained in my statement, whether something was there in the External Affairs Ministry. As explained in my statement and also by the Prime Minister, the reply that was received from External Affairs was given to the House.

As I have already stated, there is no case for ascertaining anything from Shri Thomas. It was quite clear, as I have explained. Shri Thomas might have read in the papers. He was not informed of this because there was no necessity for that.

MR. SPEAKER : Before adjourning the House for lunch.....

श्री जार्ज फरनेन्डीज: अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मेरी बात सुनिये।

13.00 hrs.

BUSINESS OF THE HOUSE

MR. SPEAKER : The hon. Member may resume his seat. I am on my legs. What I want to say is this. The Business Advisory Committee has decided only two hours for discussing the Demands for Grants relating to the Ministry of Industrial Development and Company Affairs. My difficulty is, when only one hour or two hours time is allotted for a particular Ministry I am not able to give half-an-hour to each hon. Member. For the discussion on the Demands for Grants relating to Social Welfare, according to the wishes of many hon. Members of this House, three hours have been allotted—from 4.00 to 7.00 P. M. today. Today is the last day as far as Demands for Grants are concerned. We have to apply guillotine at 7.00 P.M. and from 4.00 to 7.00 we have to discuss Social Welfare. Therefore we have only two hours for Industrial Department and Company Affairs. If all the parties want to speak I cannot deny time to one party and give half-an-hour to another party,

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : Sir, the Business Advisory Committee agreed almost unanimously that the last day for discussion on the Demands for Grants should be 25th April. At that time the Business Advisory Committee never anticipated the fall of U. P. Government and other things. This is not obligatory or mandatory. We can sit for one or two days more discussing the Demands for Grants. Which is the rule that prevents us from doing so ?

MR. SPEAKER : Whenever rule may be there, we are having the guillotine today at 7.00 P. M. and we will be discussing Social Welfare from 4.00 to 7.00 P.M. Today being the last day for discussion on the Demands let us keep up the time schedule.

AN HON. MEMBER : Industrial Development and Company Affairs is an important Ministry.

MR. SPEAKER ; However important it may be I am not going to change it now. We may now adjourn for lunch and meet again at 2.00.

13.03 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

———

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at five minutes past Fourteen of the Clock.

[Mr. **Deputy-Speaker** *in the Chair*]

*DEMANDS FOR GRANTS, 1968-69—*contd.*

Ministry of Industrial Development and Company Affairs

MR. DEPUTY SPEAKER : The House will now take up discussion and voting on Demands Nos. 53 to 56 and 119 relating to the Ministry of Industrial Development and Company Affairs.

Hon. Members present in the House who are desirous of moving their cut motions may send slips to the Table within 15 minutes indicating the serial numbers of the cut motions they would like tomove.

Demand No. 53.—Ministry of Industrial Development and Company Affairs.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :

> "That a sum not exceeding Rs. 66,03,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March 1969, in respect of 'Ministry of Industrial Development and Company Affairs'."

Demand No. 54—Industries.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :

> "That a sum not exceeding Rs. 3,66,20,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Industries'."

Demand No. 55—Salt.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :

> "That a sum not exceeding Rs. 50,09,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Salt'."

Demand No 56—Other Revenue Expenditure of the Ministry of Industrial Development and Company Affairs.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :

> "That a sum not exceeding Rs. 94,85,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Other Revenue Expenditure of the Ministry of Industrial Development and Company Affairs'."

*Moved with the recommendation of the President.

Demand No. 119—Capital Outlay of the Ministry of Industrial Development and Company Affairs.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :

> "That a sum not exceeding Rs. 8,61,57,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March 1969, in respect of 'Capital Outlay of the Ministry of Industrial Development and Company Affairs'."

The discussion on these Demands will be concluded exactly at 4 O'Clock. I will put them to vote exactly at 4 O'Clock. How much time will the Minister require ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) : It depends, half an hour or so.

MR. DEPUTY-SPEAKER : All right. I will not be able to call more than one or two Members from the Congress side.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND COMMUNICATIONS (DR. RAM SUBHAG SINGH) : You finish it exactly at 4 O'Clock.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I will put it to vote exactly at 4 O'Clock. On the Opposition side also, I would request them to stick to the time allotted to them. Shri N. K. Somani. You have got only 10 minutes. Some Members have got only 2 minutes each. I cannot help it. You will have to stick to that. Shri N. K. Somani.

SHRI N. K. SOMANI (Nagaur) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, it is a great pity that an important Ministry like Industrial Development has been so badly devalued that is hardly gets two hours because, I think, we needed much greater time for considering this Ministry and the Minister who presides over nearly half of India's national production and its activities and, I hope, something would be done about it.

Our country is at a critical threshold of industrial development today and what policies and postures we adopt today, the Government of India puts forward, will have a lot to say about our future, whether we shall remain in stagnation, in recession, whether we will continue to be set with unemployment, with low per capita income, with low production and poor exports or whether we shall transform ourselves into a virile take-off which will depend a great deal upon the policies this Ministry has to adopt.

I would like to say, at this stage, that there is something seriously wrong with our decision making processes in this country. When we discuss a country's economic programme and when we know that is beset with high cost economy and low per capita income which is as a result of the drift and ideological consideration, and gruesome taxasion levels and a bogey of sizes and monopolies, then we should be concerned about the performance of this Ministry.

A few months ago, we witnessed the spectacle of this Government being pressurised into a 10-point economic programme nearly under coercion and at the point of gun which, to my mind, is not a sound basis for taking rational decisions on matters which, I think, are extremely complex and which call for a great deal of consideration on all sides. I commented a little while ago that we are beset with a bogey of economic sizes vs. monopolies. Some people are under the mistaken impression and, as far as my Party is concerned, we are definitely against price manipulations, we are definitely against monopolies but we should not forget something at this stage that if we have to compete with the world, if we have to compete with the developing countries, we will have to look after what technology of economic sizes, what instruments of production, what sorts of taxation levels, are operating in this country and if we have to continue to compete with them and export world markets and also to serve our home consumer in a rightful manner, we will have to be concerned about what is not only taking place in India but what is taking place elsewhere.

Therefore, whenever any important policy decision is made, it should not be made under coercion, it should not be made under threat, it should not be made

[Shri N. K. Somani]

under pressure of time. Now we will have to adopt a computor technology, as far as our decisions are concerned. We very well know what parameters, what constrains of limitations, what pricing infra-structure limitations are there in this country. Therefore, when we talk about the operation of any industry, we must assimilate all these decision with a computer and whatever rational, scientific and developing answers that we get from the computer, we should be able to follow them. Commenting on this bogey of size, one must not forget that Tatas manage, they do not own—there is a great difference between owning assets and managing assets—assets of only Rs. 464 crores, Birlas Rs. 447 crores and the third company. Martin Burn & Co., Rs. 154 crores. They manage these assets which, by world standards, by international standards, are nowhere, compared to the world giants. But I am not concerned with size ; there have to be economic sizes and there has to be modern technology in this country.

The second point that I would like to raise is that this Ministry has to act as catalytic agents and the presiding master of a transformation from an industrially orthodox and conservative society where the family deity has been presiding over the company affairs for such a long time and where the bureaucrats have been presiding over industrial management for such a long time, to usher into a modern society where professional managers must come into being, so that the industrial affairs, company expansion and all such decisions are left to the professional managers to be taken in the interest of the country,

I am very sorry to say that we have not—the Government as well as the House —taken any due concern or any lessons from the recession. I understand that there have been tremendous difficulties as far as the recession is concerned both in terms of about Rs. 1,200 crores worth of production loss as well as the adverse effect on over 200,000 workers, but we have not taken any long term study about the recession, nor have we adopted any helpful policies where productivity and progress are possible.

I would like to comment briefly on what happened last year, what we all call, the demon of 'gherao'. It is very convenient for employers as well as this Government to condemn gherao, but none of us has studied the human psychology or the sociological aspect of gherao. I am very sorry to say that a number of employers were responsible for creating these conditions... This Ministry, the Labour Ministry and the Home Ministry should have studied the behaviour aspect of it and should have taken lessons from this. There is a meaningful research study on the subject of mature industrial relations and industrial conflicts by the Indian Institute of Management, Calcutta, and I would urge that the Minister should take lessons from this.

The third point is about optimum coordination. Ours is a country where there are abundant resources but there is very poor coordination between one Ministry and another. So far, the Ministry has only been concerned with creating capacities on paper. We just this morning read about the very sorry state of affairs in the Heavy Engineering Corporation, Ranchi, where it is said that after 1970-71, this huge Corporation is not going to have any orders and it may have to be shut down. Therefore, while we plan any project, whether in the public sector or in the private sector, we have to see that it functions to the optimum size, to the optimum capacity, at the minimum cost to the country, because our economy is in such a state that we cannot afford to have any experimentation. Therefore, if there is a problem about the Railways, if there is a problem about marketing, if there is a problem about planning or finance, I expect that this being a nodal Ministry, the primary Ministry in charge of industrial development, the Minister will forcefully take up the issues with his colleagues on the left and right and see that industrial problems are solved.

In this respect, Sir, as far as controls are concerned. I would like to quote the Congress President, Shri Nijalingappa. who the other day in Bombay, while addressing the All India Manufacturers' Organisation, said that corruption and controls are twin sisters and he also said that all such controls which are thwarting, which are hindering the progress of the

industry, should be removed. In that background I do not know why the paper industry is still being allowed to suffer continuously and there is no imaginative, there is no response coming from the Ministry at all.

I would like to ask the Minister : is there a single industry or commodity which is being forced to sell today its products at just about 10% above the 1947-48 prices? I hope the Minister realises that it takes 5 to 6 years and costs Rs. 12-15 crores on capital for a hundred tonne a day economic paper plant to see the light of the day. I would like this hon. House to realise that if next year or the year after, there is a shortage of paper in this country and if black-marketing then takes place, it will be as a result of the policies of this Government and the hon. Minister will be directly responsible for the shortage.

I give you another instance where optimum considerations do not weigh properly which is the instance of the small car project. I do not know what the necessity is. Have we got enough foreign exchange to play with these ideas ? I am told that the Government is going to set up a new plant for manufacture of small car in the public sector. It is going to cost Rs. 32-35 crores in foreign exchange and even then we will be beset with the uncertainty whether the small car will see the light of the day. As against that, there are 3 or 4 automobile manufacturers and a study has revealed that if only Rs. 5-6 crores of foreign exchange are provided to them, not only the production of cars in this country will go up but the unutilised capacity and the uneconomic production that is going on in the country in the engineering industries will end. Therefore, in matters like this where we are playing with the scarce resources on the one hand of foreign exchange and when we are considering the unutilised capacity of our corporations on the other side, there has to be a rational decision and the Government of India should not stand on prestige and say that there has to be a small car project in the public sector.

About the lack of co-ordination when I mentioned a little while ago, I do not know whether his colleague in the Commerce Ministry consulted him because under the latest import policy, bolts, nuts and screws, steel balls, malleable castings, wire ropes—items like these—for which there is an adequate capacity in this country and for which the engineering workshops are lying idle, are being allowed to be imported.

Lastly, as far as indigenous technology is concerned, very little work has been done by our chain of National Laboratories and it is high time that we pay more attention and put more resources at the disposal of these laboratories and more meaningful projects should be designed so that we get ourselves rid of the foreign imported technology and give encouragement to our own people.

श्री हरदयाल देवगुण (पूर्व दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, यह विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उद्योग देश की अर्थ-व्यवस्था का आधार है। इस पर अधिक वाद-विवाद की आवश्यकता थी। आपने बहुत कम समय दिया है इसलिये मैं समझता हूँ इस पर फिर किसी अन्य दिन विस्तार से विवाद होना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस मंत्रालय को देश के अर्थ से एक पैसा देने को तैयार नहीं हूं क्योंकि इस मन्त्रालय ने पिछले एक वर्ष में कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे कि भविष्य में इसकी उपयोगिता सिद्ध हो सके। इसकी एक वर्ष की कारगुजारी हमारे सामने है। इसमें इसने क्या किया है ? मैं कहना चाहता हूं कि यह मन्त्रालय पूर्ण रूप से असफल रहा है। कृषि और उद्योग इस देश की अर्थ-व्यवस्था का आधार हैं। परन्तु आज उद्योग की क्या हालत है ? मन्दी की लहर उद्योग पर आक्रान्त है। आपको मालूम है कि सन 66 में उद्योगों के उत्पादन में जो कमी हुई उसने भीषण रूप धारण कर लिया है। आज कुछ कारखानों को छोड़ दीजिये जिनकी कैपेसिटी पिछले एक या दो वर्षों में पैदा की गई है जैसे कैमिकल, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम इत्यादि, बाकी सारे उद्योगों में मन्दी की लहर है, उत्पादन घट गया है और उस उत्पादन की कमी को पूरा करने के लिये जो इस मन्त्रालय का कर्तव्य था वह इसने पूरा नहीं किया, इसमें वह बुरी तरह से असफल रहा है।

[श्री हरदयाल देवगुण]

देश के जो मूल उद्योग हैं वह आज इस एक साल में मंदे से निकल पायेंगे इस की कोई योजना आज दिखाई नहीं देती है । पिछले वर्ष में यह जितने असफल रहे हैं उसके रहते भविष्य में आप के पास कोई दिशा नहीं है । यह मन्त्रालय इतना प्राणहीन, निर्जीव और दिशाहीन है कि इस के पास भविष्य के लिए कोई कार्यक्रम नहीं है । खाली जैसे कबरिस्तान का फकीर आते जाते मुर्दों को गिनता रहता है वैसे ही यह विभाग आने जाने वाले मुर्दों को गिनने का काम करता रहता है । मोनोपली कमीशन या लाइसेंस कसे दिये गये या उद्योग को मंदे में से कैसे निकाला जायगा, औद्योगिक विकास कैसे किया जायगा इसके बारे में एक भी शब्द न इन की रिपोर्ट में है और न ही इन के पालिसी रेजोलूशन में है । मैं समझता हूं कि आज सारी पिछली औद्योगिक नीति के परिपूर्ण अवलोकन की जरूरत है । वह इंडिस्ट्रियल पालिसी जो सन् 1949 में हमें दी गई थी या उस के बाद उस में जो संशोधन हुआ था उस से हम को क्या मिला है ? उससे देश को सन् 1962 में और सन् 1965 में मालूम हो गया कि उस उद्योग नीति से हम देश की प्रतिरक्षा नहीं कर सकते । उस से यह मालूम हो गया कि अगर देश में इन्द्र देवता नाराज हो जायं तो हम अपने देश में अपना पेट भरने के लायक अनाज पैदा नहीं कर सकते ।

उद्योग के दो अभिप्रायः अथवा उद्देश्य होते हैं । एक तो यह कि देश की आवश्यकताओं को पूरा किया जाय । अर्थात भारत जैसे कृषि प्रधान देश में उस का उद्देश्य कृषि को बलिष्ठ करना और देश की प्रतिरक्षा को बलिष्ट करना है । यह उद्देश्य इस नीति में नहीं है । दूसरा उद्देश्य उद्योग नीति में यह होता है कि अपने देश में अगर खाने पीने लायक पैदा न हो सकता हो तो उद्योगीकरण करके हम अपने देश में ऐसे सामान बनायें जिनका दूसरे देशों में भेज कर उस के बदले में हम वहां से खाने, पीने का सामान मंगवायें और विदेशी मुद्रा जैसे कि जापान करता है । ऐसे उद्योग को ऐक्सपोर्ट ओरियंटैड इंडस्ट्री कहते हैं अपनी यह कंज्यूमर्स ओरियंटड इंडस्ट्री है लेकिन हम दोनों बातों में असफल रहे हैं । देश की प्रतिरक्षा के लिए कोई साधन नहीं उपजाये और कृषि की कमियों को पूरा करने के लिए उस ने कोई साधन नहीं जुटाये । दोनों बातों में हम असफल रहे हैं । पिछली नीतियों से हमें क्या मिला है ? इनसे काला धन पैदा हुआ है, मंहगाई बढ़ी है । एकाधिकार पैदा हुआ है, मोनोपली पैदा की है और इन सबसे राजनैतिक सत्ता को हाथ में रखने का प्रयत्न किया गया है । आज देश की जितनी अर्थ-व्यवस्था खराब हुई है वह इस नीति के फलस्वरूप है । इसके बारे में देश के अर्थ शास्त्रियों ने साफ तौर पर यह कहा है कि जब तक यह इंडस्ट्रियल पालिसी को नहीं बदलेंगे देश की अर्थ-व्यवस्था नहीं सुधरेगी लेकिन सरकार आज तक इस बारे में कोई निश्चय करने को तैयार नहीं हुई । आज जरूरत इस बात की है कि जिन बातों की वजह से इतनी बुराइयां देश में पैदा हुई हैं उन्हें दूर किया जाय । एक बड़ी नींव बना दी है लेकिन उस पर भवन खड़ा करने के लिए रुपया नहीं, उस के लिए साधन नहीं उस के लिए योजना नहीं । मेरे पास समय नहीं है वरना मैं उसका पोस्टमार्टम एक, एक बात में करता लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि जब तक यह नीति नहीं बदली जायगी और उस के साथ ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऐक्ट में आमूल चूल परिवर्तन नहीं किया जायगा तब तक देश में औद्योगिक विकास ही नहीं हो पायेगा बल्कि जो आज उद्योग है वह भी जिंदा नहीं रह सकेगा । इसलिए उस में तबदीली लाने की जरूरत है और देश की अर्थ व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है । उस के लिए जब तक नीतियों में परिवर्तन नहीं होता है नये सिरे से नीतियां नहीं बनाई जाती तब तक उस में कोई सुधार नहीं होगा और यह मन्त्रालय अपने कार्य में बिलकुल असफल बना रहेगा ।

मैं समझता हूं कि यह जो इनक्वायरी कमीशन बैठाया गया और उस के बाद उन को मुअत्तिल कर दिया गया है इस में एकाधिकार समाप्त करने की इतनी भावना नहीं है जितनी कि ब्लैकमेल करने की भावना है। पहले कसा गया और फिर एलैक्शन के लिए चंदा ले लिया। उस के बाद छोड़ दिया और ढील डाल दी। इस तरह की बातें की जा रही हैं। मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि वह अपने उस वक्फ बोर्ड का काम सम्हालें और यहां के कबरिस्तान का इंतज़ाम करें। यह उद्योग उनके वश का नहीं है। यह देश का उद्योग किसी योग्य आदमी को देना चाहिए। उद्योग मन्त्रालय बहुत बुरी तरह से असफल हुआ है। इसलिए मैं उन की मांगों का विरोध करता हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now, Shri Rajaram.

श्री भोलानाथ (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का चांस मिलना चाहिए।

MR. DEPUTY-SPEAKER : We started these Demands at 2.8 p.m. I have to give 40 minutes to the hon. Minister. So, for the Congress side, I have only 12 minutes left. I can call only two Members from the Congress side.

श्री भोलानाथ : कल भी आपने मुझे समय नहीं दिया था।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I am helpless. He may talk to his Whip. I shall call three Members from the Opposition and then one Member from the Congress, and again three Members from the Opposition and then one from the Congress and then the hon. Minister will be called.

SHRI RAJARAM (Salem) : The report of the Ministry of Industrial Development and Company Affairs begins with the following sentence :

> "The Department of Industrial Development is responsible for the active promotion of industrialisation of the country by encouraging the orderly development of large and small-scale industries both in the private and the public sectors."

I want to ask the hon. Minister whether this Ministry has been promoting orderly development all over the country. Some parts of the country are still backward. Some of the States are being neglected. The requests from some of the States are not at all being looked into. The result is that we have been demanding a decentralisation of power from the Centre.

For instance, even when the Congress Ministry was in power in Madras, the present Planning Commission member, Shri R. Venkataraman, who was then the Industries Minister of Madras had applied for a licence to establish a steel plant a Salem which is my constituency, to this Ministry, with the necessary stamps and other things and with all the paraphernalia. Even now we have not got any reply from the Central Government in regard to the Salem steel plant.

The policy followed by this Government regarding industrial development has also been a policy of vacillation. It has not been a definite and clear policy. Because of this policy our country is now facing a big recession. In fact, it is not only that but we are going to face a big crisis because nearly 40,000 engineers are going to come out of the colleges this year. Besides, from this year we expect 17,400 engineers from 138 engineering colleges and 24,500 diploma-holders from 288 polytechnics. That means that there will be over 83,000 engineers, both graduates and diploma-holders on the rolls looking for jobs. This is the condition of our country. If this Department had done its work properly and in a very gradual and orderly manner, then such things would not have happened. This Department has not developed industry in this country. Rather, they have developed themselves.

We have developed three automobile units in this country, one is the Standard Motors, another is the company manufacturing Fiat cars, and the third is the one manufacturing the Ambassador car. As far as I have seen the Fiat car, if you close one door, the other door opens. That is the condition of the ISI specification laid down by this Department. The automatic system of locking has been lost in this. When I was in Japan, I had seen some taxis which had been fitted with such automatic system. But without any automatic

[Shri Rajaram]

system, in the Fiat car, the door opens in this manner. All these things have been manufactured with tin, perhaps made out of kerosene tins...

SHRI UMANATH (Pudukkottai) : Dalda tins.

SHRI RAJARAM : Besides, take the case of the Ambassador car. My own Chief Minister Shri C. N. Annadurai had purchased an Ambassador car some time back...

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar) : It is not Ambassador car ; but it is embezzlement car.

SHRI RAJARAM : He had taken delivery of the car from the workshop to his house which was hardly two furlongs away from there. On reaching home, he noticed that a sound had developed in the gear-box. He rang up the office of the firm and immediately they told him 'Oh, that part is gone ? Send Rs. 80 to us ; we shall change it, and we shall give it after six months.' This is the ISI specification which has been developed by this Ministry. Is it possible with these three monopolies to export even a single car at least to Ceylon, if not to Ceylon, at least to Mauritius, if not to Mauritius, at least to South Africa or at least to a very backward country in the world...

AN HON. MEMBER : China.

SHRI RAJARAM : No, not China, because China is highly developed.

So, this matter must be looked into.

Then, I would submit that ours being an agricultural country, we want power-tillers. The land-owners in our country are small land-owners. We have manufactured only 252 numbers. When I was in Japan I saw that tillers had been manufactured at a cost of Rs. 1500 and the farmers there are utilising it in a fine way. Why should we not advise some of the industrialists in the private sector to come forward and manufacture such tillers which are required in such large numbers for the agricultural development of our country, or at least why should the public sector not come forward with such manufacture ?

In the budget speech made by Shri C. N. Annadurai in February this year in the Madras legislature, he said :

> "We understand from the Government of India that a plant for manufacture of polyster fibre in our State involving a capital outlay of about Rs. 10 crores will be shortly licensed in the private sector".

We had requested this Government to sanction a licence for a unit to manufacture polyster fibre involving an investment of Rs. 10 crores. But till now there is no reply from the Ministry. I was told that there is some clique between big monopolists living always in Delhi or operating through liaison officers I staying in Ashoka Hotel or in Ministers' residences or in Cabinet Ministers' places and other places, and the authorities here. This application has come from a Tamilian with Tamilian resources. So I think there is discrimination going on in this country. The north *vs.* south controversy is there.

I am requesting this Ministry to go into this and see that the needful is done expeditiously.

My Chief Minister has also requested that the second unit of Indian Telephone Industries should be established in Madras. This request should also be conceded.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Hon. Members may now move the cut motions to the Demands for Grants of the Ministry of Industrial Development and Company Affairs, subject to their being otherwise admissible.

Cut Motion Nos. 2, 3, 22, 23, 31 to 33

SHRI SRINIBAS MISRA (Cuttack) : I beg to move :—

"That the demand under the head Ministry of Industrial Development and Company Affairs be reduced to Re. 1/-."

[Failure to evolve an effective industrial policy. (2)].

"That the demand under the head Ministry of Industrial Development and Company Affairs be reduced to Re. 1/-"

[Transaction of business by industries in public sector (3)].

"That the demand under the head Industries be reduced by Rs. 100/-."

[Failure to check the imbalance in the setting up of small scale industries. (22)]

"That the demand under the head Industries be reduced by Rs. 100/-."

[Slow progress in organising industrial cooperatives, industries. (23)].

"That the demand under the head Capital Outlay of the Ministry of Industrial Development and Company Affairs be reduced by Rs. 100/-."

[Failure to establish another cement factory near Sambalpur (Orissa) to exploit the high grade lime-stone deposit there. (31)].

"That the demand under the head Capital Outlay of the Ministry of Industrial Development and Company Affairs be reduced by Rs. 100/-"

[The slow progress made in manufacturing tractors. (32)]

"That the demand under the head Capital Outlay of the Ministry of Industrial Development and Company Affairs be reduced by Rs. 100/-"

[Losses suffered by the Hindustan Photo Film Manufacturing Company due to faulty planning and administration. (33)].

MR. DEPUTY-SPEAKER : The cut motions are also now before the House.

SHRI P. K. GHOSH (Ranchi) : The slowing down of the rate of industrial production in the country has become a matter of great concern. As pointed out in the report of the Ministry of Industrial Development and Company Affairs, the increase in the index of industrial production during the first nine months of 1967 was only 1.4 per cent as against 2.6 per cent in 1966. It is stated that one of the major factors influencing the trend in the industrial output was the decline in the general level of demand, particularly demand for investment goods.

To meet the current situation, the right policy would have been to create conditions which would put additional purchasing power in the hands of the masses by encouraging industries to expand their production and to go in for repid development. With the expansion of the industrial sector, avenues of fresh employment would open up which in turn would lead to increased purchasing power in the hands of the people. The fall in the industrial output could to a great extent be attributed to the operation results of the public undertakings. We are losing Rs. 588 crores worth of production apart from other losses in the public undertakings where an investment of Rs. 2500 crores of public money has been made.

What are the reasons for this trend of development in the industrial sector ? First, there is continued labour unrest. We have put inexperienced bureaucratic ICS and IAS officers in charge of these undertakings. These people have no sympathy for Indian labour. They have been trained under the Britishers and do not care for the amenities and aspirations of labour. They are penny-wise and pound-foolish. They adopt policies which deprive labour of their basic amenities. Thereby labour get frustrated and do not con tribute their full to production. The result is that production goes down and there is loss running to hundreds of crores of rupees.

Then there is a lot of isms which we find in public undertakings—groupism, provincialism, favouritism, nepotism...

MR. DEPUTY-SPEAKER : Etcetera, etcetera.

SHRI P. K. GHOSH : Then there is communalism which is the most dangerous. We saw a manifestation of it in Ranchi. The incident in Ranchi where minorities were butchered is a matter of deep shame for every Indian. We should try and find out the persons responsible for this and punish them adequately.

The Heavy Machine Building Plant under the HEC, Ranchi is in the doldrums. In the opinion of the senior engineers HMBP will never be able to keep up the supply schedule for Bokaro. Some one lakh tonnes order for Bokaro is being systematically off-loaded and some are being imported from Russia. HMBP has been paying a heavy amount of compensation to some undertakings for not being able to keep the delivery date. Many equipments which could be manufactured

[Shri P. K. Ghosh]

at HMBP are being ordered from Russia for Bokaro.

The reason for this is that rabid favouritism, Provincialism and nepotism is being practised by the General Manager which has brought about a general discontentment among all sections of the employees. A person who was a draftsman before joining the HMBP has been forklifted to the position of a senior design engineer. Another hot favourite who before joining the HMBP was a chargeman, has got two promotions and awaits the third one.

The technical supervisory staff are in a ferment as they complain that the organisation chart now being introduced is a most arbitrary and a prejudiced one. They point out that some officers who have already a number of promotions without having the corresponding qualifications and experience compared to others will again receive promotions, whereas for others holding key positions, all avenues have been blocked. Administrative personnel rather than the key technical personnel have been favoured in the chart and they are assured of many lifts while discipline at the shop floor seems to be at the lowest ebb.

We connot allow such state of affairs to continue in this key undertaking on which the future of the country depends. I would, therefore, suggest that an enquiry by reputed engineers of other private and public sector concerns be instituted and they may be entrusted with the drawing of the organisational chart besides holding a thorough enquiry in to the working load of engineers, their respective qualifications, experience and competency at all levels. With the present General Manager there is no hope for the HMBP. He openly declares that since he has a lot of influence among the high-ups, nobody can touch him. I would therefore, suggest that this man should be removed.

My last point is this. The small industries are being badly neglected by the Industries Department. The small industries are giving 33 per cent of the total industrial output and are employing 35 per cent of the total industrial labour. But we are giving only six per cent of the industrial raw material, either imported or controlled, to the small industries. Therefore I would suggest that 50 per cent of the industrial raw materials and 50 per cent of the foreign exchange for the raw materials be given to the State Directors of Industries so that the small industries could draw their requirements from them.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Dr. Ranen sen Six minutes.

DR. RANEN SEN (Barasat) : Sir, the present state of affairs in our industrial sector is a sad commentary on the functioning and the activities of the Ministry of Industrial Development. This was anticipated long before by our party, and it was stated in this House also. The whole policy about industrial activity, which was laid down by the Government of India, is founded on a wrong basis. It has been our experience in India that the industries have been dependent on foreign collaboration, foreign knowhow, foreign money, foreign machines and foreign spare-parts. There by, we have allowed ourselves to be bullied and blackmailed by the imperialist countries from the very beginning which was very much apparent and which manifested itself after the Indo-Pakistan war of 1965.

Secondly, our industries were allowed to be gradually grabbed by families of monopolists, the houses of monopolists who have thrived not only on the industry of our country but on the private sector also which tried to gain advantage as much as it could, and also from the public sector. This is quite apparent. The industrial policy resolution has been watered down long before; not only that. the Government allowed the private sector to erode on the industrial policy resolutions of 1948 and 1956. It is a known fact that when the Cement Corporation was established the ostensible purpose was to manufacture cement. But as yet not a grain of cement has been produced by the cement corporation. Its main function is only distribution of cement all over India and that to after our experience of CACO from which the Congress, Swatantra and Jan Sangh received lakhs of rupees.

It is said there is industrial recession,

But what has happened to our wagon building industry and other engineering industries ? For the last few months we see in the newspapers that wagons are being exported to South Korea, South Vietnam and other places. There is also an agreement with Soviet Union, Hungary and Yugoslavia for supply of wagons. The minister should clearly state what is the position of the wagon industry in our country, because several waggon factories have been locked out for months. The Indian Standard wagon Company run by Martin Burn, the owner of which runs firms worth Rs. 175 crores—Mr. Somani also referred to it—has been closed for the last 7 months. Are they getting orders or not ? What is the order placed by the Railway Board on this firm ? What about orders for supplying waggons to Soviet Union, Hungary, etc. ? We find there is a definite attempt here also to blackmail and bully the Government and we find these industries are being kept closed for months and months.

Small-scale industries are suffering on account of two things. Firstly, the supply of raw materials—ferrous and non-ferrous metals—is very meagre. So many small industries in West Bengal and Howrah are suffering. Why is this discrimination being made against the small and medium industries in the supply of raw materials ? The subsidies to them are also very meagre. There are no adequate arrangements for marketing and modernisation, though the report says some attempts have been made to modernise them. Unless we help the small and medium industries and save them from the onslaught of big business, Indian industrial sector cannot develop. Simply on the basis of the State sector and the private sector, which is the big business sector, we cannot nurture the industrial sector of India. Therefore, the present policy has to be changed, but not in the light of the advice given by Mr. Somani. His was the voice of the monopolists. Government must listen to the common people's voice and try to build up the industrial economy, so that the small and middle producers may be able to build a prosperous industrial sector.

श्री रबि राय (पुरी) : उपाध्यक्ष महोदय, इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट एंड कन्ट्रोल एक्ट की जो अनुदानों की मांगें हैं उनका मैं विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसके बारे में जो मेरे सुझाव हैं उनको तो मैं बाद में दूंगा लेकिन सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि औद्योगीकरण की नीति क्या होनी चाहिये, इस का ही इनको पता नहीं है। जिस तरह से वैदेशिक नीति के बारे में निरपेक्षता की नीति का अर्थ सरकार को मालूम नहीं है उसी तरह से औद्योगीकरण किस को कहते हैं, इसका सरकार को पता ही नहीं है। इसकी कुछ सफाई हो जानी चाहिये। औद्योगीकरण की नीति तभी सफल होती है जबकि उसकी सहायक नीतियां जैसे सम्पत्ति सम्बन्धी नीति, भाषा सम्बन्धी नीति, जाति सम्बन्धी नीति और प्रशासन सम्बन्धी नीति इत्यादि नीतियां साथ-साथ चलें। भारी उद्योग जिस हद तक खुलने चाहिये थे नहीं खुले हैं और जो खुले भी हैं उन में जितनी क्षमता है उसके अनुसार वहां उत्पादन नहीं हो रहा है। उत्पादन क्षमता का वहां पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र ने भी निजी क्षेत्र के दोषों को सीख लिया है। दोनों ने एक दूसरे के दोषों को सीख लिया है। दोनों में भ्रष्टाचार भरा हुआ है।

सरकार ने 1948 में इंडस्ट्रियल पालिसी रेजोल्यूशन पास किया। 1956 में उसको दोहराया। इससे सरकार ने यह समझ लिया कि हिन्दुस्तान में समाजवाद आ गया है और हिन्दुस्तान में औद्योगीकरण हो गया है। सरकार ने तीन कमेटियां बिठाई थीं और तीनों की रिपोर्ट सरकार के पास आ गई है। एक तो मौनोपोलीज इनक्वायरी कमीशन बैठा था, दूसरी महालनोबिस कमेटी बैठी थी और तीसरी हजारी रिपोर्ट है। इन तीनों रिपोर्टों को देखने से साफ हो जाता है कि देश में औद्योगीकरण हुआ ही नहीं है। इधर-उधर कुछ उद्योग स्थापित तो हुए हैं लेकिन उन को लेकर ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि औद्योगीकरण हो गया है। औद्योगीकरण का जो मतलब है वह सिद्ध नहीं हुआ है। औद्योगीकरण का मतलब

[श्री रवि राय]

क्या होता है ? इसका मतलब तीन चीजें होती हैं। एक तो देश में आर्थिक वैषम्य जो है, आर्थिक असमानता जो है, वह दूर हो। दूसरे जो आम जनता है, जो करोड़ों की संख्या में है, जो उपभोक्ता हैं, उनको फायदा मिले और तीसरा मतलब यह है कि पब्लिक सैक्टर में जो सरकार है और जो मालिक होती है और प्राइवेट सैक्टर में जो पूंजीपति है और जो मालिक होता है, इन दोनों मालिकों का रिश्ता मजदूरों से अच्छा हो। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये रिश्ते अच्छे हो पाये हैं। मैं समझता हूं कि इन तीनों दृष्टियों से देखा जाय तो यही साबित होता है कि औद्योगीकरण की जो नीति है, वह असफल सिद्ध हुई है।

मौनोपोलीज कमिशन के सदस्य श्री आर० सी दत्त को मैं धन्यवाद देता हूं उसके लिए कि जो मिनट आफ डाइसेंट उन्होंने दिया है। मैनेजिंग एंजेसी सिस्टम के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार कपड़ा और दूसरे उद्योगों में 1970 तक इस सिस्टम को खत्म करे। लेकिन इस सम्बन्ध में मैं श्री आर० सी० दत्त को कोट करना चाहता हूं। उनका कहना है :

> "In any case, the Managing Agency system has always been a potent factor for the concentration of economic power, and it still continues to be so. Its importance even at present as an instrument of concentration can be judged from the fact that in five of the large Groups mentioned in Col. 1 below Managing Agency accounted on 31-3-65 to the extent indicated in Vol. 2 for the link with the other companies in the group.

Col. 1	Col. 2
Tata	74%
Birla	82%
Martin-Burn	91%
Bangur	45%
Thapar	58%

> A consideration of the Managing Agency system is, therefore highly relevant for a study of the problem of concentration".

यह जो मैनेजिंग एजंसी सिस्टम है इसको तत्काल खत्म कर दिया जाना चाहिए। इसको खत्म करने के लिए योजना बननी चाहिए।"

राजनीतिक दलों को कम्पनियों द्वारा चन्दा दिया जाता है उसके बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। सरकार कहती है कि वह अगले सैशन में इसके बारे में एक बिल इंट्रोड्यूस करेगी। लेकिन इस अधिवेशन में ही इस बिल को लाया जाना चाहिए और अभी इसको पास किया जाना चाहिए। मैं नहीं समझता हूं कि सरकार इस बिल को लायेगी। मैं समझता हूं कि एक साजिश चल रही है। श्री एस के पाटिल और श्री सी बी गुप्त चाहते हैं कि इस बिल को न लाया जाये। मैं चाहूंगा कि इसको जल्दी लाया जाना चाहिये।

मैं एक और मांग करना चाहता हूं। एस्टीमेट्स कमेटी ने जो सुझाव दिया था उसी को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उसने अपनी नवीं रिपोर्ट में चौथी लोक सभा को यह सुझाव दिया था कि एक इंडस्ट्रीज कमिशन बनाया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में उसका कहना है :

> "The Committee feel that a crucial stage has been reached in the industrialisation of the country and if the slogan of self-reliance has to be given a content and a meaning it is imperative that the strategy of industrilisation should be reviewed pragmatically by an expert body. The Committee suggest that for this purpose Government may appoint an Industries Commission, with representatives drawn from industry, trade, commerce public sector, financial institutions and economists who should have intimate knowledge of industrial development in the country. The Commission may examine the extent to which the Industrial Policy Resolutions and the

Industries (Development and Regulation) Act, 1951 have been helpful or otherwise in developing and regulation the setting up of industries on the desired lines. In the light of their findings they may indicate broadly the strategy to be followed for bringing about self-reliance in industry at the earliest, keeping firmly in view the resources of the country and the aspirations of the people".

श्री थैंकर का किस्सा अभी हुआ है। आज के ही अखबारों में यह निकला है कि श्री के० टी० चंडी जो कि फूड कारपोरेशन के चेयरमैन हैं और जो कि कुछ प्राइवेट कम्पनीज में डायरेक्टर भी हैं उनको एच० एस० एल० का चेयरमैन बनाया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि यह मंत्रालय स्टील मिनिस्ट्री को इसके बारे में सलाह दे कि ऐसा न किया जाए। आप देखें कि आपने जो सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल आफ इंडस्ट्रीज बनाई है उसके कौन कौन मेम्बर हैं। उसके कम्पोजीशन को आप देखें। उसमें श्री एल० एन० बिरला हैं, सी० पी० पिट्स हैं, रामास्वामी मुदालियर हैं, जे० आर० डी० टाटा हैं। यह क्या बात है कि हिन्दुस्तान के जितने पूंजीपति बड़े-बड़े हैं उनको आपने इसमें रख छोड़ा है। जिस तरह से आपने एग्रिकल्चर कमिशन बनाया था इसी तरह से आप एक इंडस्ट्रीज कमिशन बनायें जोकि देखे कि पिछले बीस साल में जो कंसेंट्रेशन आफ वैल्थ हो गया है उसको कैसे खत्म किया जाए। और जो औद्योगीकरण नहीं हो रहा है, उसको कैसे किया जाए।

हजारी रिपोर्ट पर यहां बहस हुई थी। उस वक्त बिरला परिवार की बहुत चर्चा हुई थी। आपने डालमिया और जैन के मामले को लेकर विवियन बोस कमिशन बिठाया था। मैं माननीय सदस्य, श्री उमानाथ, को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पिछली बार लुई फ़िशर की किताब से गांधी जी के केस को कोट किया था। उस किताब में लुई फ़िशर ने लिखा है कि जी० डी० बिड़ला 1920 में एक ब्रोकर थे। इन तीस चालीस सालों में उन की जायदाद करीब-करीब चार सौ करोड़ रुपये की हो गई है। कई लोग कहते हैं कि उन की दैनिक आय एक लाख रुपये है।

मैं मांग करना चाहता हूँ कि इन सब घोटालों वगैरह की जांच करने के लिए विवियन बोस कमीशन की टाइप का एक कमीशन बिठाया जाये, ताकि लोगों को सही स्थिति का पता चले।

आज देश में जो स्थिति है, उस में समाजवाद का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। आज सिर्फ बड़े-बड़े करोड़पतियों और पूंजीपतियों का बोलबाला है। मैं डा० रानेन सेन की इस बात से सहमत हूं कि हमारे देश में छोटी इंडस्ट्रीज को पनपने का अवसर ही नहीं मिल पा रहा है और सब तरफ बड़े-बड़े पूंजीपति ही छाये हुये हैं।

जैसा कि मैं ने अभी कहा है, एक इंडस्ट्रियल कमीशन बिठाया जाये, जो इस बात की जांच करे कि पिछले बीस सालों में कितना औद्योगीकरण हुआ है और भविष्य में औद्योगीकरण किस प्रकार होना चाहिये, उस का दृष्टिकोण क्या होना चाहिये।

आप जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार के जमाने से ही महाराष्ट्र, पंजाब, मद्रास और बम्बई आदि प्रदेशों को औद्योगीकरण के द्वारा विकास और प्रगति करने के बहुत अवसर दिये गये, क्योंकि उन प्रदेशों से अंग्रेजों का फ़ायदा होता था। लेकिन बिहार, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश आदि प्रदेश पिछड़े हुए रह गए। इन पिछड़े हुए राज्यों की पर-कैपिटा इनकम को बढ़ाने के लिए इन का औद्योगीकरण होना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं इस मंत्रालय की मांगों का विरोध करता हूँ।

श्री भोला नाथ (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस रिपोर्ट के पेज 1 पर कहा गया है कि रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन सम्बन्धी मामलों के कोआर्डिनेशन को इस मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है। यह एक बहुत अच्छा और हैल्दी साइन है।

[श्री भोला नाथ]

आज रिसेशन और कंट्रोल वगैरह की जो बातें चल रही हैं, उन का कारण सिर्फ यह है कि हमारी मिनिस्ट्री ने कलकत्ता, बम्बई जैसे बड़े-बड़े शहरों में ही इंडस्ट्रीज लगाई हैं और रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। मेरा निवेदन है कि अब उद्योगों का डीसेंट्रलाइजेशन होना चाहिये और बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज को शहरों से हटा कर देहात में फैला देना चाहिये। अगर सरकार ने रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन की कोई योजना बनाई है, तो उस को जल्दी कार्यान्वित करना चाहिये।

पहले कम्यूनिटी डेवेलपमेंट प्राजेक्टस में इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन आफिसर रखे गये थे, लेकिन अब उन को एबालिश कर दिया गया है। देहात की तरफ ध्यान न दे कर सरकार ने शहरों में इंडस्ट्रीज कायम करने पर सारा जोर दिया है। अगर हिन्दुस्तान का कुछ भला करना है, तो हमें अपने देहात में उद्योगों को कायम करना होगा।

रिसेशन की बात बिल्कुल गलत है। आखिर किस चीज का रिसेशन है? क्या आज टायर, ट्यूब या एस्बेस्टोज शीटस या सीमेंट मिल रहा है? आज कोई भी चीज नहीं मिल रही है। ट्रैक्टर और आटोमोबाइल्ज के स्पेयर-पार्ट्स के लिये बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। रशा से जो ट्रैक्टर मंगाए गए हैं, उन के स्लीव्ज की वास्तविक कीमत 34 रुपये है, लेकिन ब्लैक में वे 125 रुपए में मिलते हैं। यही स्थिति जेटर और फर्गूसन ट्रेक्टर्ज की है। उन का सामान भी नहीं मिल रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जीप्स का जितना प्राडक्शन होना चाहिए, उससे कम हो रहा है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सीमेंट मिल मशीनरी की इन्स्टाल्ड कैपेसिटी 2300 लाख रुपये की है, लेकिन उस का एक्टीमेटिड प्राडक्शन सिर्फ 650 लाख रुपये का है। इस कारण आज सीमेंट की स्कैरसिटी है। यह क्या तमाशा हो रहा है? कहा जा रहा है कि रिसेशन है, लेकिन खुद ही आवश्यक चीजों का प्राडक्शन नहीं किया जा रहा है। इसी तरह कहा जाता है कि फूड कम पैक्स होने की वजह से इंडस्ट्रीज काम नहीं कर रही हैं, लेकिन रिपोर्ट में बताया गया है कि फूड प्रासेसिंग सम्बन्धी इन्स्टाल्ड केपेसिटी 64 लाख रुपये की है, लेकिन उस की प्राडक्शन 65 लाख रुपये की हुई है। इस से प्रकट है कि यह प्राडक्शन बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है।

यह समझ में नहीं आता है कि रिसेशन किस तरफ है। असली बात यह है कि बड़े-बड़े आदमी अपने माल को रोक कर बैठ जाते हैं। वे उस माल को बनाना नहीं चाहते हैं, जो कि बनाना चाहिये। आज न ट्रेक्टर और जीप मिलते हैं और न टायर ट्यूब मिलते हैं। क्या दिल्ली शहर में टायर ट्यूब मिल सकते हैं? मैं ने एक स्कूटर खरीदा है। उस की स्टेप्नी का रिम तो दे दिया गया है, लेकिन टायर ट्यूब नहीं दिये गये हैं। ट्रेक्टर के बारे में बराबर यही कहा जाता है कि आर्डर बुक कराइये, तो मिल जायेगा; तीन बरस के बाद उस का नम्बर आता है। आज रिसेशन कहां है? जो चीजें बनाई जानी चाहिये, उन को बनाया नहीं जा रहा है।

सरकार ने इंडस्ट्रियल एस्टेट्स का प्रोग्राम शुरू किया था। ओखला में छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज बनाई गईं। एक योजना थी कि अलवर में ओखला का एक्सटेंशन कायम किया जायेगा। न मालूम, वह स्कीम कहां गायब हो गई है। सरकार को उस तरफ ध्यान देना चाहिये।

अलवर, राजस्थान में केमिकल इंडस्ट्रीज बहुत पनप सकती हैं, क्योंकि वहां पर कच्चा माल बहुत उपलब्ध है।

मैं ने राजस्थान के चीफ मिनिस्टर को एक चिट्ठी लिखी थी कि अलवर, राजस्थान में टेली-फोन इंडस्ट्री कायम की जाये। उन्होंने 20 अप्रैल, 1968 के पत्र में मुझे यह उत्तर दिया है:

"आप का पत्र दिनांक 3 अप्रैल 1968 प्राप्त हुआ। अलवर में टेलीफोन उद्योग लगाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने भारत सरकार को अगस्त, 1967 में ही प्रस्ताव भेज दिये थे और इस पर भारत सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है। आशा है शीघ्र ही उपयुक्त निर्णय ले लिया जायेगा।" मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस सम्बन्ध में जल्दी ही निर्णय कर के अलवर, राजस्थान में टेलीफोन इंडस्ट्री स्थापित करने की व्यवस्था करें।

देश के कुछ बड़े-बड़े शहरों में सारे उद्योगों को केन्द्रित करने का ही यह परिणाम है कि रिसेशन, वेराव, कंट्रोल और डीकंट्रोल वगैरह की बातें होती हैं। सारे उद्योग कुछ ही शहरों में सीमित हो गए हैं। इस से उन शहरों में हाउसिंग की प्रावलम क्रीएट होती है, राशनिंग की व्यवस्था करनी पड़ती है, कई और समस्यायें पैदा हो जाती हैं। अगर राजस्थान में उद्योग खोले जायें, तो वहां पर राशनिंग वगैरह नहीं करना पड़ेगा। वहां पर बहुत अनाज होता है। आज राजस्थान से जौ और चना बाहर भेजा जा रहा है।

इण्डस्ट्रियल पालिसी रेजोल्यूशन के अन्तर्गत हम ने अपने यहां मिक्स्ड इकानोमी लागू करने और पब्लिक सेक्टर तथा प्राइवेट सेक्टर दोनों को चलाने का निर्णय किया था। लेकिन अब समय आ गया है कि इण्डस्ट्री को डीसेंट्रलाइज किया जाये और इस बात की व्यवस्था की जाये कि हम अपने उद्योगों को उपयुक्त स्थानों पर ही स्थापित करें।

मैं अपने राजस्थानी भाइयों से कहूंगा कि वे कोरल कलकत्ता छोड़ कर राजस्थान चले आवें। वहां पर उद्योग लगाने की बड़ी गुंजायश है। इसलिए वहां पर ज्यादा से ज्यादा इण्डस्ट्रीज लगानी चाहिए। मैं उन को राजस्थान में उद्योग लगाने के लिये इनवाइट करता हूं। वहां पर उन्हें ज्यादा से ज्यादा सहूलियत दी जायेगी। अब तो वहां पर एटामिक एनर्जी पैदा होने वाली है। कल श्री सोमानी ने कहा कि राजस्थान में एटामिक पावर तो पैदा हो जायेगी, लेकिन उस को कनज्यूम कौन करेगा। मैं उन की इनवाइट करना चाहता हूं कि वह उस एटामिक पावर को कनज्यूम करने के लिए राजस्थान में उद्योग स्थापित करें। जो लोग अपने यहां से भगाना चाहते हैं, राजस्थान में आ कर वह उन से और बेरावों आदि से बच जायेंगे।

कल श्री सोमानी ने छोटी कार की योजना का विरोध किया था, लेकिन मैं चाहता हूं कि छोटी जरूर बननी चाहिये।

श्री रवि राय : यह इन का समाजवाद है! वहां की जनता कारों का बहुत प्रयोग करती है न!

श्री भोला नाथ : अन्त में मैं दोहराना चाहता हूं कि सरकार टायर-ट्यूब और ट्रेक्टर तथा जीप के स्पेयर पार्ट्स को उपलब्ध करने की तरफ ध्यान दे, और अलवर, राजस्थान में टेलीफोन इंडस्ट्री और ओखला एक्सटेंशन कायम की जाये।

SHRI J. AHMED (Dhubri) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on a subject which covers the whole of India and which is the most important subject. I do not I can do justice to my country by speaking only 4 minutes on subject. So, I do not like to discuss the industrial policy the Government but I will just bring to the notice of the hon. Minister the condition of Assam regarding our industrial development in the province.

Last year, I also mentioned that not a single industry in Assam was taken up or any amount was sanctioned by this Government. The hon. Minister who comes from Assam knows the nook and corner and the backwardness of the province of Assam about its Industrial development. I just requested him that we expected many things from the hon. Minister who comes from that province. He could not include anything last year for the province of Assam. But this year, he was very kind enough to include something to which I

[Shri J. Ahmed]

want to draw his attention also that is the Cement Corporation of India Ltd. has taken in hand the work of preparation of a detailed project report for a cement factory at Bokajan in Assam.

This much is done and nothing else has been included in the whole of this. You know very well, Sir, that Assam is very rich in respect of raw materials. Lime stone is abundantly found in every district, in every part of Assam. The Minister knows himself that cement can be produced in Assam and the whole of India can be supplied from only Assam. So much of raw material is there. So also, in the case of newsprint ; Assam is full of forests and full of bamboos ; the whole of Assam is full of these. I have seen that all the raw materials go from Assam to Titagarh Paper Mill, and the Minister cannot take the initiative to start a paper mill in Assam. So is the case with regard to jute mill, Cotton mill and other mills in Assam.

15 hrs.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The Minister also comes from Assam. He knows.

SHRI RABI RAY : That is the allegation now.

SHRI J. AHMED : That is why I am saying. He comes from Assam. We are proud of him. But he was not born in Assam ; I know that...

AN HON. MEMBER : Only for ministership.

SHRI J. AHMED : His forefathers belonged to Assam. I know his father, Col. Jalnur Ali. He was a man of Assam. Therefore, the Assam people hope many things.

The condition of Assam is deteriorating day by day. They must read the writing on the wall. The people of Assam are frustrated. They may go against the whole of India also. They are not having anything... (*Interruptions*)

श्री रवि राय : इन के खिलाफ जाइये, हिन्दुस्तान के खिलाफ नहीं।

SHRI I. AHMED : During the last twenty years of rule, they have not done anything to improve the condition of Assam. The position of Assam is very difficult and precarious. You know the position of Assam. It has a bottleneck. No private industrialist is going to Assam ; they are not taking any risk. After the Gauhati riots, nobody will go, no private industrialist will go there. Therefore, I say, Sir, no private entrepreneur is going there...

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now the hon. Member will have to conclude.

SHRI J. AHMED : When you order, I shall have to conclude.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I am sorry, I am helpless.

SHRI J. AHMED : I know. I will request the hon. Minister to try to start some factories in public sector immediately. Let him speak this out. Otherwise, I do not know which way the fate of Assam will go.

श्री गणपत सहाय (सुलतानपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ कि आपने मुद्दत के बाद आज अपने विचारों को इस सदन में रखने का अवसर दिया। यूं तो मेरी इच्छा थी कि मैं और विषयों पर भी अपने विचारों को रखूं, मगर बदकिस्मती रही कि मुझ को मौका नहीं मिला। इस समय मुझे एक शेर याद आता है —

दस्तूरे जबां बन्दी है कैसा तेरी महफिल में,
यहां तो बात करने को तरसती है जबां मेरी।

या यों कहिए कि मैं यहां सब से बूढ़ा मेम्बर हूं, सब बाल सफेद हो गये हैं। हिन्दी की एक मिसाल है—

उजले-उजले सब भले, उजलो भलो न केस,
न नारी नर्व, न नृप डरे, न आदर करे नरेश।

इसलिये आपने मेरे ऊपर कोई कृपा नहीं की है। चूंकि समय बहुत कम है, इसलिए मैं केवल दो-तीन बातें ही कहना चाहता हूँ।

मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। उत्तर प्रदेश हमारे देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, यहां पर 7 करोड़ की जनसंख्या है, प्राकृतिक जितनी भी सुविधायें हैं, वे सब यहां पर मौजूद हैं। अनेकों नदियां इसकी गोदी में खेलती हैं, कितने बेकार जंगल यहां पर पड़े हुए हैं और कितनी मादनियात यहां पर छिपी हुई है। लेकिन आप ने जो किताब छापी है, स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज के बारे में, उसमें लिखा है—

In spite of many natural advantages, the State did not advance industrially.

उत्तर प्रदेश की यह हालत है कि तीनों प्रधान मंत्री उत्तर प्रदेश के थे, यहां के बड़े-बड़े दिग्गज नेता आपकी केबिनेट में रहे हैं, इस के अलावा आप यह देखेंगे कि इस सदन में उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा मेम्बर हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की आज यह हालत है कि वहां पर कोई भी इण्डस्ट्रीयल एडवांसमेंट नहीं हुआ है। आप सारे उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिये, वहां के पूर्वी जिलों को देखिये—आपकी इस किताब में लिखा है—

Most of the Districts in the Eastern U. P. and Bundelkhand region are untoched by industrial development.

उसी पूर्वी जिले में हमारा जिला सुलतान पुर है, जिसकी आबादी 14 लाख है और सरकार ने माना है कि यह एक डैफिसिट डिस्ट्रिक्ट है। डैफिसिट डिस्ट्रिक्ट के मायने यह हैं कि हम इतना गल्ला पैदा नहीं करते हैं जो वहां की जरूरत को पूरा कर सके। इसका नतीजा यह है कि हमारे यहां के हजारों आदमी अहमदाबाद दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, कानपुर में अपनी आजीविका कमाने के लिए पड़े हुए हैं, क्योंकि वहां पर उनकी आजीविका का कोई प्रबन्ध नहीं है।

आपको आश्चर्य होगा कि स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज की जो वाल्यूम छपी है, उसमें जो यूनिट्स फैक्टरीज एक्ट के अण्डर रजिस्टर हुए हैं, उनकी तादाद दी गई हैं। उसमें लिखा है कि सुलतानपुर में 2, प्रतापगढ़ में 2, बलिया में 1 और जौनपुर में "नदारद"—इनके अलावा कहीं भी कोई फैक्टरी रजिस्टर नहीं हुई। सुलतान पुर एक ऐसी जगह है, जिसकी आबादी 14 लाख के करीब है, लेकिन वहां पर न कोई टैक्सटाइल मिल है, न शुगर मिल है और न कोई आयरन फाउण्ड्री है। इसी चीज को देख कर एक दफा हमारी सरकार ने तजवीज किया था कि वहां पर एक डीजल इन्जिन का कारखाना खोला जाय। अगर डीजल इन्जिन का वह कारखाना खोला गया होता, तो आज हजारों आदमियों को वहां आजीविका मिलती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।

चूंकि मुझे बहुत कम समय मिला है, बातें मैं बहुत सी कहना चाहता था, जहां जनरल पालिसी का सवाल आता है, वहां तो जुबान बन्द है, इसलिए मैं मंत्री जी से केवल यही प्रार्थना करूंगा कि हमारे प्रदेश का, खास कर पूर्वी जिलों का ध्यान करें और वहां पर कुछ इण्डस्ट्रीयल डवेलपमेंट करें।

SHRI UMANATH (Pudukkottai) : Mr. Deputy Speaker, Sir, after the report of the Vivian Bose Commission, with great pomp and tom tom, Mr. T. T. Krishnamachari, brought forward the Company Law Amendment Bill and got it passed into an Act and said that hereafter with this Bill having been passed here, these various tendencies, monopolies and malpractices will be curbed. Let us see what has happened after that Act has come into force. Take the question of Bennett Coleman and Company. The Government applied to the Tribunal for the removal of the Directors and pending the disposal of the petition the tribunal appoint a chairman with Veto power. That veto power was given to the Chairman so that the Jain directors who are still in the majority will not misuse their majority again and continue all sort of bogus things. What is the position today ? The position today is this. Even while the petition for the removal of these directors is pending before the Tribunal, the Chairman has gone in collusion with the Jain Directors. That is the position. They removed the earlier Chairman and put this new Chairman,

[Sbri Umanath]

The new Chairman has also joined in collusion with other Jain directors on the Board. I will give one instance. About 4 or 5 employees were victimised because they were giving evidence before the Tribunal and the Government. As soon as Mr. Kunte became the new Chairman this is what has happened. As soon as he became Chairman they wanted to take up a resolution for appealing against the decision of the Tribunal which did not allow this Board to suspend them. At that time the Chairman opposed the resolution but now the latest position is that when the Jain director moved a resolution about these employees, and they wanted to dismiss those employees as a measure of victimisation, the new director has voted for the resolution and the resolution is passed. What has happened to the new Chairman ? He opposed earlier on the ground that they have not been given opportunities but again he has voted for the resolution. That is why I say Sir, the new Chairman is kept in collusion with the Jain directors there.

Already certain charges against the Chairman have been raised on the floor of the House about his having taken about Rs. 2 lakhs as donations from the company for his election expenses which is denied on the floor of the House. But the Minister assured this House that he will enquire into this allegation. I want to know from the Minister whether such enquiry has been conducted and what the conclusions are. These malpractices are continuing. Earlier they refused to pass the TA and DA bills of the new Chairman for his tour other than for the purposes of the company. But now I understand that the Jain directors are passing the bills for TA and DA which they refused earlier. I demand of this Government that this Government must file a petition before the Tribunal for the removal of the present Chairman also. This is what has happened. This is how the Act is being implemented in practice. This is the first point.

Now, Sir, I would like to go to the second point. This is a most norrible thing, namely, the case of Fedko in Bombay. Fedko are the allied concern of Mafatlal group. They forged certain documents, they forged the signature of the Deputy CCI, Delhi as having recommended granting them certain import licences and those documents were passed on to the JCCI, Bombay who was deceived on the basis of the forged signature of the Deputy CCI, and certain import licenses were granted. They were caught at the instance of the CBI investigations. They were caught ; they were prosecuted and after prosecution they were convicted by the high court. They were found to have entered into a conspiracy to cheat the JCCI, Bombay, and this was proved. They went on appeal to the Supreme court and the supreme court also upheld the conviction, and said, they must immediately surrender the bail and undergo the sentence. What has happened ? For 36 days after the Supreme Court directed that they must surrender bail, they were moving about in Bombay in posh cars and luxurious cars without being arrested. For 36 days the writ of the supreme court does not move beyond its precincts. This is the case of big businessmen being convicted. For 36 days they were not doing anything. As soon as they were arrested what happened ? Four people were arrested ; on the same day all the four people were released. It is said that they were released on grounds of health. It is very strange, all the four big businessmen falling ill on the same day, simultaneously, and then being released simultaneously.

I want to raise a question of propriety here. I want to know from the Central Government also what they have done in this matter. The question of propriety is this. After the topmost court in this land has upheld the sentence and after about Rs. 4 lakhs have been spent by Government by way of lawyer-fees alone for their prosecution and conviction, they are today free without undergoing the sentence. What is the propriety in this ? What did the Central Government do about this ?

The second question that I would like to ask is this. The prosecution was at the instance of the Central Government. So also, they were convicted under a Central Act. But the State Government releases them and nullifies the decision of the Supreme Court. What is the propriety involved in this ? I would like to know whether the Maharashtra Government

applied for any concurrence from the Centre when they decided to release them and nullify the decision of the Supreme Court by misusing their powers. Did they ask for concurrence from the Central Government, especially sinse those persons had been convicted under the Central Act, and they had been prosecuted at the instance of the Centre? This is what I would like to know from the hon. Minister. But I shall give you the secret of how it happened. Those 36 days are relevant for this purpose. For those 36 days they were not taken into jail. They refused to submit themselves to the orders of the Supreme Court. For 36 days they were having some conspiracy to get out of the entire thing. They approached the Maharashtra Chief Minister. Through whom did they approach? They approached him through Shri. A. K. Sen who is also a lawyer appearing to defend the company's fraud and to defend the company's misappropriation. Shri A. K. Sen and one Commander Ghate who is an employee of the Mafatlal Group, these two people approached the Chief Minister and a deal was struck by which they were arrested and released on the same day. You will be surprised to know who this Commander Ghate is, who is an employee of the Mafatlal Group, who has such powers over the Chief Minister. Commander Ghate is no other person than the brother-in-law of Shri V. P. Naik, the Chief Minister of Maharashtra. This is how things are happening here. This is how all these things have happened.

I would like to know what the Central Government did in this matter. When persons have been convicted by the Supreme Court itself, and the conviction has been upheld by the Supreme Court and yet they go scot-free without undergoing even one days' sentence in a jail, I demand that the Central Government must institute an inquiry. The State Government may have their own lame excuses. But a thorough inquiry must be conducted as to how it happened, especially when on the floor of the House I have pointed out how the deal was struck and how the things have happened.

In conclusion, I would like to say something about the provision in the Act that employees who give evidence against these companies will be protected. Prime Minister Jawaharlal Nehru gave in person an assurance to these employees of the Bennet Colemans that he would see to it that they were not victimised. Relying upon Prime Minister Jawaharlal Nehru's assurance, they gave evidence, and after the evidence was given, which was very valuable, some of them must have been on the new board actually. But where are these employees now? They are on the streets now; because they gave evidence against the company, they are in the streets now. When I had asked a question of the hon. Minister here what action had been taken to protect them, the hon. Minister said that one of the employees, one Mrs. Rama Jain had filed a false complaint and therefore, she was proceeded against in the court. The court acquitted that employee. Should the Central Government not immediately intervene and see that she was protected at least after the court's order? But the reply given is that the Maharashtra Government and not Jain has gone in appeal to see that that person is convicted again, and the Central Government are keeping quiet. Why should they not tell the Maharashtra Government that this employee is innocent and they should not proceed with the appeal? But the Central Government have not said so.

That is why I say that in these matters of protecting these monopoly groups and all sorts of offences and atrocities committed by these groups, this Government also have got their own part and share.

SHRI TENNETI VISWANATHAM (Visakhapatnam): Not merely a part, but a major part.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Minister.

श्री प्रेम चन्द वर्मा (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री कार्तिक उरांव को दो मिनट का समय दे दिया जाय ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: I cannot apportion time like this if the Minister is surrendering some time of his. The time is at the disposal of the House, not of the Minister.

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) : I am grateful to hon. Members for the various views expressed in such a short time. I am also in agreement with them that for discussion of such an important matter, there should have been only two hours, 40 minutes of which I am taking for replying. I think it is neither fair to my Ministry nor fair to me nor to the subject we are discussing here.

SHRI M. N. REDDY (Nizamabad) : Nor to the members.

SHRI F. A. AHMED : The House may remember that we took nearly 6-7 hours to discuss only the Hazari Report.

15 22 hrs.

[Shri Manoharan *in the Chair*]

On the other hand, such a Ministry which has to deal not only with the public sector but is also intimately connected with the private sector, is given only two hours. I hope in future it will be possible for us to have more time for discussion on the subjects or of the various departments over which I have the honour to preside. I would particularly like sufficient time to be given to hon. Members for expressing their opinions and also for giving me an opportunity of ciarifying a large number of things connected with public industries. I hope if not during the budget session, on some other occasion sometime is fixed up for a discussion that will be helpful to me and also will be in the interest of the country at large.

I would first of all deal with the general aspect of the question posed here. Some hon. Members have expressed concerned over the decline in the rate of industrial growth. That is certainly a matter with which all of us are concerned and should be concerned. But I would like to consider this matter along with the hon. members. This is a subject on which there should be a national approach, in which there should be such an atmosphere —political atmosphere—which should be able to help industrial growth in our country. Apart from these things, it is also necessary that the labour situation, which has been a source of great anxiety to all of us, should also be such as can help in production and productivity in the various industries in the country.

But more than that, I would like hon. Members to remember that today when there is fast development of science and technology, unless and until we keep pace with that trend, it will not be possible for us to make any head way so far as industrial development is concerned ; because the purpose of industrial development in our country is two fold, one to provide for the establishment of industries for production of goods for consumption in the country which we have been accustomed to import and the other to manufacture in our country products which we should be able to export for earning foreign exchange. This can only be done when we can compete in the international market both in quality and in price.

15.24 hrs.

[Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*]

So my suggestions to the House are these, that apart from the political atmosphere, apart from the national view which we have to take with regard to these matters, we must also find out what other countries are doing in this regard. I would like to point out the two instances which we have before us. One is of the socialist countries and the other is of the other developed countries. We have been accustomed to borrow technical know-how and technology from outside under various collaboration schemes, both under the private sector and the public sector. What has been disturbing me during the past few months is that we have not taken advantage of this colloboration of technical know-how which we have been receiving from a large number of countries.

So far as the socialist economy is concerned, they have depended mostly on their own research work, but there are other developed countries, even countries like the USA and Japan, who borrow to a large extent technology from outside but they back up that borrowed knowledge by further development in their own countries. But what has been the case so far as our country is concerned ? I am very sorry to point out that during these few months

I have had the honour of looking into those things, I find that in more than 30 to 35 per cent of the cases where the foreign collaboration has existed so far as the technical know-how is concerned, even now applications are received by us for the purpose of extending the period of collaboration. That only indicates that there is plenty of room, both for the Government and the private sector, for the purpose of spending or investing money in research which can help us in developing our technical know how and in bringing down the cost of production and in making various other improvements. I was just trying to compare the figures of the amount which is invested by various countries and by us on research and improvement of technology. I find that so far as our country is concerned, it is less than 0.5 per cent of the total production of our country, and in a country like Japan, it is 2.3 percent. Perhaps in the United States it is much more and so on and so forth. Therefore, if we have to compete in the international market for the purpose of increasing the demand in our own country, we have to consider these various aspects, and see how these things can be improved upon. This is one aspect in which I would like hon. Members also to give their suggestions and see how we can improve it. Now we are going to have the fourth Five Year Plan and are going to have a new look. My suggestion is that I would like to have the support of the hon. Members, that at least so far as the industrial development is concerned, we must see that the Planning Commission is giving more money for the purpose of investing and spending on research which can only help in the improvement of the existing position.

There also comes the question of bringing down the cost of production as also the improvement of quality. It is true that this can only be done when a thing is manufactured in a large scale. Therefore, very rightly the point has been raised, that the question of monopoly has to be considered having regard to efficiency and low cost of production. Perhaps no one in this House will grudge if a particular industry has to be of a size which can be developed in our country by one unit or by two units and is of a big size which can give us goods at a cheaper cost and of a better quality.

What we do not agree to is that there are some people who do not confine their activities to one or two industries, but who want to extend it to all kinds of industries all over the country. That has to be resisted. Not only we should provide opportunities to young entrepreneurs from various parts of the country but we should also tackle the unemployment question. Therefore, I would ask hon. members not to have a closed view on this subject. We must try to reach a conclusion where we can allow the existence of a big industry, while at the same time not allowing one or two people to monopolise all goods throughout the country.

On the one side Mr. Somani suggested that there is no case for manufacture of a small car and those already in the industry should be allowed to produce more cars. On the other hand, there was a voice from Jan Sangh that the kind of car being produced now is of worthless quality and soon the country should be spared of having these useless cars.

SHRI N. K. SOMANI : The two statements are not contradictory.

SHRI RAJARAM : It is not possible to have a small car as long as Mr. Birla is alive.

SHRI F. A. AHMED : This is exactly what I was trying to point out and hon. members tried to contradict me.

Now, because of these grievances from the public and MPs, the Pande Committee was set up. They submitted a useful report which is already before the House. I am sure hon. members must have read it. We have practically implemented all those recommendations. I hope as the implementation proceeds, the quality of the car also may improve.

SHRI M. N. REDDY : By what date the quality car would emerge as a result of this implementation ?

SHRI F. A. AHMED : It is a relevant question. We have already issued instructions to them. We shall see that soon every recommendation is implemented and

[Shri F. A. Ahmed]

the manufactured car is supervised before it is given to the consumer. But we have to consider the question of manufacturing cars in a big way, because the demand is such that it cannot be met by the 8 units already in the field. For that, we have had a large number of proposals which are being examined. These have been sent to the Planning Commission.

SHRI PILOO MODY (Godhra) : These are new proposals ?

SHRI F. A. AHMED : No, they are old proposals. As soon as Mr. Venkataraman who is a broad comes back, I shall have an opportunity of discussing this with him.

SHRI TENNETI VISWANATHAM : How many proposals are there ?

SHRI F. A. AHMED : About 17 or 18.

SHRI PILOO MODY : From existing manufacturers or for new cars ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : It would not be of any use to you.

SHRI PILOO MODY : Why do you think, Sir, that I am against this manufacture ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : I only said that it would not be of any use to you.

SHRI LOBO PRABHU (Udipi) : Sir, I rise on a point of clarification. You are mentioning about a small car not suitable for my hon. friend. Apart from that objection, the new car has to establish that it is superior in some respects to existing models for us to have another plant because the overheads of a new plant will be added while extension of existing plants would be cheaper. Therefore, when you are suggesting this to the country you have to ask the Planning Commission to explain what new features this car has and which the existing cars do not possess for us to go in for a fourth plant.

SHRI RAJARAM : You can nationalise all these three plants and have a good public sector undertaking. I am accepting Shri Lobo Prabhu's suggestion.

SHRI LOBO PRABHU : If my hon. friend is so enamoured.....

SHRI RAJARAM : I want a good car in the public sector.

SHRI LOBO PRABHU : If he is so enamoured of a good car, of a public sector car, I would like him to buy one of the cycles made by the Mysore Government which costs Rs. 16,000 without saddle. This is the experience of public sector undertakings in respect of vehicles.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU (Chittoor) : They are only reconditioning cars in the present factories. They are not manufacturing new cars. They are only supplying re-conditioned cars.

SHRI F. A. AHMED : Out of these various suggestions which we have received some of them which we found suitable have been forwarded to the Planning Commission. Certainly the suggestion given by the hon. Member will be kept in view when we take our decision.

I was really amazed when Shri Somani mentioned that we will require about Rs. 32 crores to Rs. 33 crores foreign exchange for the purpose of setting up a unit to manufacture a small car of Rs. 5000 and above. I would not like to give the House all the details but I know that at least two of the proposals, one from Renaults and the other from Mysore State, gave a much smaller amount of investment than what has been indicated by the hon. Member.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU : What about Andhra's proposal ? What about Pande Committee's recommendation to have it in Hyderabad ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now every State would make a claim. We have very limited time and I would like the Minister to continue without any interruptions.

SHRI F. A. AHMED : Now, Sir, I would go to another important question which is also a part and parcel of our industrial policy, and that is about regional imbalance. Many hon. Members, even a Member from my own State, raised the question about discontent in various sector and said that there has been no equitable distribution of industries in a large number of areas. Though by pointing out to the House that I was not born in Assam perhaps he was trying to disown me, he cannot disown me because my roots are there and very deep roots too. May I point out, Sir, that it is our effort to see that so far as all the regions are concerned they should have proper treatment from the Central Government.

But I would like hon. Members to remember that it depends not only on the effort of the Central Government but it also depends on the efforts of the State Government concerned and it also depends on the effort made by the private sector. I will give a very small example.

SHRI J. AHMED : In Assam no private person is going now to set up industries. After the Gauhati riots Assam's position has totally changed.

SHRI F. A. AHMED : For that the Central Government cannot be blamed.

I was going to point out that the prosperity of the people and raising the *per Capita* income through industry does not depend so much on the establishment of a big industry as on the establishment of a small-scale icdustry. I would just quote the instance of the Punjab Government. They are spending over a crore of rupees for small-scale industries while the Rajasthan Government is spending about Rs. 6 lakhs or Rs. 7 lakhs only.

SHRI N. K. SOMANI : Pull them up. Your own party is in power there.

SHRI F. A. AHMED : Here it is not a question of pulling up ; it is a question of their giving priority, to what item and so on and so fourth.

So, the question of development of industries in a particular area will also depend on the investment which the State Government is going to provide in that area and it will also depend on the facilities available in that particular area, for instance transport, power and other things. Also, it will depend on the question of royalty and sales tax on commodities which will be manufactured there. All these things have to be taken into consideration.

Take, for instance, cement. So far as the manufacture of cement is concerned, it is our policy that hence forth we should try to set up cement factories in areas which are deficit, instead of cement being taken from the south to the east or to the west. Maharashtra is also deficit in cement and the eastern region is also deficit in cement. So, it is our desire that subject to the availability of raw material and other facilities we must give preference to areas which are deficit in the matter of cement and so on.

Similarly, we shall try to see to what extent other industries also can be given to areas which have been clamouring for them and which have been neglected in the past. I hope, the Planning Commission will bear this fact in mind and will provide sufficient funds under the Central sector where an effort can be made for the purpose of removing these imbalances.

SHRI N. K. SOMANI : They do it on population basis.

SHRI F. A. AHMED : There I do not agree, namely, that only population is the criterion. We have to take many other factors also into consideration.

It was brought out by some hon. Member and particular reference was made to nuts and bolts that nuts and bolts of all types including screws, which are being produced here, are also being imported. I may inform the House that that is not correct because all imports of such types of nuts and bolts have been banned ; only some special types required by the actual users are allowed if they are not made in the country. Some screws or high tensile bolts required by some industry, like the aircraft industry, typewriter industry, when required in very small quantities are allowed to be imported because they are not made in the country.

SHRI N. K. SOMANI : Wire ropes.

SHRI F. A. AHMED : It is uneconomical to produce these and the imports of these things are very negligible. Prices of standard steel nuts and bolts produced in the country are very competitive. Therefore, I would like to assure the House that where it has been possible for us to manufacture things in our own country (*Shri N K. Somani* : Everything is possible in the country.) and where it is being produced, we see to it that imports are not being allowed. If hon. Members have knowledge of any particular item that is still being imported though it is being manufactured, they have only to let me know and we shall see how we can tighten the belt.

The question has also been raised regarding the manufacture of wagons. So far as we are concerned, we are aware that we have the capacity of manufacturing nearly 30,000 wagons in our country in terms of 4 wheelers, including export orders of nearly 3,000 wagons. Taking the performance of the industry during the last two years, the orders which are already with them will keep them busy. The hon. Members will also be pleased to know that recently a Protocol has been signed with the Soviet Union for manufacture and supply of substantial number of wagons from India to that country. It is expected that, starting with the supply of 2,000 wagons next year, we should be able to raise it progressively to 10,000 wagons a year during the next years. A suitable organisation to prepare for production of the wagons needed for export to the Soviet Union has already been set up.

SHRI M. N. REDDY : Is it linked with the supply of any civil aircraft by the Russians ?

DR. RANEN SEN : If the wagon building firms are getting orders, why are these firms still closed and locked out ? How do you explain this phenomenon ?

SHRI F. A. AHMED : I do not know. Actually, some of these people met me and said that, because of labour trouble, they are locking them out. It is no use blaming one side, finding fault with one side. We have to create a political atmosphere ; we have to consider this problem from national point of view. Then only, the industry can pick up.

SHRI M. N. REDDY : Is the supply of wagons linked with the supply of civil aircraft by USSR ?

SHRI F. A. AHMED : So far as I am concerned, I do not think it is linked with anything. I know that so many orders have been placed. But, naturally, any country would like that there should be a balance of trade, if not in one or two years, in three to four years to come and, I think, we cannot raise any objection to that.

SHRI UMANATH : How can a wagon be linked with an aircraft ?

SHRI F. A. AHMED : Then, some Members raised the question about the spare tyres not being supplied with the scooters. I admit that this was so. This was because of the shortage of tyres. As the hon. Members are aware, one of the factories was closed for a large number of months and only recently it has opened. When we found that there was scarcity of tyres, we allowed the import of tyres also. We are insisting on the manufacturers that, when they supply scooters, they should also supply the spare tyre also. My information is that recently, they have started out doing it. I hope, in future, there will be no complaint because the manufacturers have also undertaken to produce tyres in sufficient number of quantity required in our country.

SHRI N. N. PATEL (Bulsar) : Not only the scooter tyres. The tyres for cars and tractors also are not available. The people have to pay a very high price. What are you going to do about that ?

SHRI F. A. AHMED : That is also true. The Firestone Co. in Bombay was closed for nearly 7 or 8 months and only recently it has opened. On account of that, the whole thing was out of gear. With the result that we had to decide the question of importing tyres from outside for about there months. I hope, in the near future, when all the Companies have also agreed...

SHRI LOBO PRABHU : May I point out to you that far from importing tyres outside, at this moment, we are exporting tyres outside. Not only that, We are

giving an incentive for exporting tyres outside. I would like to raise a simple question: Have you represented to your colleague in the Commerce Ministry that the export of tyres for scooters should be stopped till our production becomes normal ?

SHRI F. A. AHMED : That matter will be taken up by me ; we will discuss and see. But we are also anxious to earn foreign exchange by sending out these tyres. Anyhow, I have had a recent look at these matters and I can assure the House that, in the coming year, it will be possible for us to manufacture tyres in sufficient quantities.

There was also some objection regarding the imports of raw materials so far as small scale industries are concerned. I may inform the House that the total value of import licences given to the small scale units during the years 1966-67 and 1967-68 upto 24-2-1968 was of the order of Rs. 74.9 crores and Rs. 40.85 crores, respectively. These figure will indicate...

SHRI P. K. GHOSH : I wanted to know percentage.

SHRI F. A. AHMED : The percentage is also much higher than before. Progressively we are giving much more.

So far as indigenous raw material is concerned, most of the indigenous raw materials have been decontrolled since 1966-67. At present the allocatian is made only in respect of certain raw materials E.C. Grade Aluminium, Nickel, Electrolytic Zinc and Antimony. During the year 1967-68, the following materials were distributed to the various States : electrolytic zinc 423 M.T. ; Nickel 40 M.T. ; Antimony 90 M.T. ; and E.C. Grade Aluminium 6,800 M.T. Brass tubes, copper and so on have also been given. We have given all these things.

Therefore, the hon. members may please realise that we attach a good deal of importance so far as small scale industries are concerned. The hon. members who had the opportunity of seeing the exhibition of small scale industries must have come back satisfied with the variety of goods and the good quality of goods which are now being manufactured by the small scale industries. May I point out that perhaps in no other developing country this has so much succeeded as in our country... (*Interruptions*). Here nearly 35 per cent of the industrial production is under small scale industries and nearly 30 per cent of the people employed in industries are under the small scale industries.

I personally feel that one of the ways of solving the unemployment problem, particularly of the young engineers and diploma-holders, is to provide training for the purpose of undertaking small scale industries, and, I think, that will help in the solution of the unemployment problem and it will also help in the development of small scale industries and dispersal of the industries all over the country, and this will, to a great extent, remove the regional imbalances.

SHRI P. K. GHOSH : What steps are being taken to encourage the small scale industries ? What about providing finance ? You should provide adequate finance.

SHRI F. A. AHMED : So far as the steps are concerned, a large number of items are being exclusively reserved for the purpose of small scale industries. Then also, I think, preferential treatment is given so far as the purchase of the commodities produced by them is concerned. Also arrangement is being made to provide credit facilities on better terms than what they have been getting in the past.

SHRI N. K. SOMANI : What about the paper industry ?

श्री हरदयाल देवगुण : बैटर टर्म्स क्या हैं ? सरकार उन से हायर-परचेज का रुपया पांच साल में रीकवर करती है। क्या वह उन को बड़ी इंडस्ट्रीज के मुकाबले में खड़ा होने के योग्य बनाने के लिए दस साल में वह रुपया लेने के लिए तैयार है ? क्या वह उनको कोई ऐसी सबस्टेंशल कनसेशन देने के लिए तैयार है, ताकि वे बड़ी इंडस्ट्रीज के मुकाबले में खड़े हो सकें ? आज वे बहुत डिसएडवांटेजस पोज़ीशन में हैं।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यह बात जरूर-गौर है और इस बात पर भी गौर किया जा रहा है कि उनकी और डिफ़ीकल्टीज किस तरह से दूर की जा सकती हैं।

Now with regard to paper industry, I may take the House into confidence that I personally feel that it is necessary for us to have a look into the difficulties of the paper industry because I find that even after the paper industry was delicensed, new people are not coming forward.

SHRI N. K. SOMANI : They won't.

SHRI F. A. AHMED : The matter is being examined by us and I hope it will be possible for us to take an early decision in the matter.

SHRI N. K. SOMANI : You have been saying that for a long time both in the House and outside.

SHRI RAJARAM : What about industrial development in Tamil Nad ? I am interested in that.

SHRI F. A. AHMED : Some questions were raised with regard to power tillers and tractors. I would like to inform the House that we have exempted these two from the licencing provisions of the Industries Act to encourage establishment of more units for the purpose of producing these varieties of tractors. I hope they will now come forward and take up this scheme. The likely places where this can be taken up are Punjab, U.P. as also Madras and my hon. friend from Madras was asking 'Why don't you give something to us ?' Now this industry is delicenced and it is a useful industry not only for one part of the country but for the entire country and let him take this offer so that some people start manufacturing these varieties of tractors and power tillers in every part of the country.

SHRI M. N. REDDY : Any tax concession given for the power tiller industry ?

SHRI F. A. AHMED : So far as this question is concerned, I think the best person to give a reply is the Finance Minister.

SHRI SEZHIYAN (Kumbakonam) : The Deputy Prime Minister.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The hon. Minister's time is up. I am helpless, because the Speaker has announced that we will put the demands to the vote and finish this Ministry by 4 p.m.

SHRI F. A. AHMED : If that is your direction, then I hope next time when we get an opportunity of discussing this matter, we shall have more time so that it may be possible for me to know the views of the hon. Members and also I may place before them a complete picture about the activities of this Ministry. With these few words, I conclude.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I will now put all the cut motions to the vote of the House.

All the cut motions were put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now the question is :

> "That the respective sums not exceeding the amounts shown in the fourth column of the order paper, be granted to the President, *to complete* the sums necessary to defrary the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against Demands Nos. 53 to 56 and 119 relating to the Ministry of Industrial Development and Compay Affairs."

The motion was adopted.

---

16 hrs.

Department of Social Welfare

MR. DEPUTY-SPEAKER : The House will now take up discussion and voting on Demand Nos. 97 and 98 relating to the Department of Social Welfare.

Hon. Members present in the House who are desirous of moving their cut motions may send slips to the Table within 15 minutes indicating the serial numbers of the cut motions they would like to move.

We have got just exactly three hours,

Demand No. 97—Department of Social Welfare.

MR DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :

> "That a sum not exceeding Rs. 15, 51,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Department of Social Welfare'."

Demand No. 98—Other Revenue Expenditure of the Department of Social Welfare.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :

> "That a sum not exceeding Rs. 3,34, 86,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Other Revenue Expenditure of the Department of Social Welfare'."

SHRI D. R. PARMAR (Patan) : Sir, I am very much thankful to the hon. Speaker that discussion has been allowed on the Demands of Social Welfare Ministry even at the last hours. Since 1965 no discussion was held on the Floor of the House on the Demands of this Ministry. It was discussed only in the year 1965 when this Ministry was designated as Social Security Ministry at that time. As this Ministry mainly deals with the so-called welfare of backward and down-trodden classes of the society, I feel the hon. Minister for Parliamentary Affairs might have thought to keep this Ministry backward even in the discussion of its Demands.

16.02 hrs.

[Shri C. K. Bhattacharyya *in the Chair*]

In this Department many items are clubbed together, that is, welfare of scheduled castes and scheduled tribes, welfare for women and children and care of the handicapped and the orphans and running of some non-official organisations.

Now I come to the Demands for Grants for this Ministry for 1968-69 asked for. The first demand is demand No. 97 which amounts to Rs. 18,61,000, for pay and allowances for officers and establishment, for the secretariat of this Ministry, that is, this expenditure comes to 4.43 per cent of the total demand of Rs. 4,20,44,000. Rs. 2 lakhs and Rs. 1 lakh are shown as expenditure to be incurred for other charges and the amount placed at the discretion of the Minister, respectively. The details thereof are neither shown in the Demand nor are they stated elsewhere. That is, no details are given for more than 16 per cent of the amounts to be spent under this head.

Another Demand is Demand No. 98, which amounts to Rs. 4 01,83,000. Under this demand a huge sum of Rs. 2,21,56,000 is shown to be allotted to the Central Social Welfare Board, which comes to 55 per cent of the amount asked for under this Demand. I may bring to the notice of the hon. House that no details for 55% of the total amount under this demand are supplied. It is not understood how and where this 55% amount is to be spent. Will the hon Minister be pleased to clarify whether this hon. House is expected to know the details thereof ? If these details are not to be supplied it is not understood then why the details for 45% amounts are supplied. In scrutinising even these details it is found that much more amount is to be spent over pay and allowances of officers and establishment rather than actual welfare work for socially handicapped and down-trodden people. Will the hon. Minister supply the details and percentage of the amount actually to be spent for the benefit and uplift of these people out of the amount asked for under the head of this demand ?

Over and above this amount of Rs. 2,21,56,000 there is another grant-in-aid amount of Rs. 27,00,000 for the welfare of backward classes and Rs. 1 lakh to All-India Prohibition Council shown in Demand No. 98 for which no details are shown. This Department is doing only the work of a post office. They are simply transferring the amount to the non-official organisations. These amounts are being directly given to the non-official organisations and they use the amounts at their own discretion Why should Government not directly deal with it ? The needy persons are now placed at the mercy of these non-official organisations. The main work

[Shri D. R. Parmar]

of these organisations is to prepare volunteers for the ruling party and to create an impression in the minds of the needy people from the backward classes and the handicapped sections that the ruling party is taking much more care of them.

Looking to the notes on the important schemes under this Ministry, there is a provision of Rs. 1.32 lakhs for homes, infirmaries and outside doles for displaced persons from Pakistan (non-plan); Rs. 11.05 lakhs for grant of loans for the rehabilitation of rehabilitable families in homes, infirmaries etc., Rs. 32,60,000 for pre-vocational training centres, Rs. 3,82,000 for regional training centres, both under the scheme of pre-vocational training centres, and Rs. 15.95 crores for schemes for the welfare of the backward classes are not seen in the Demands of this Ministry. Will the hon. Minister be pleased to clarify from where these amounts are to be met ?

For the welfare of the backward classes Rs. 18 crores were allotted during 1967-68. I would like to know why the amount has been reduced to Rs. 15.95 crores during the current year. As stated in the Demands, there are some training centres being run by the Department in question, such as the Kasturba Niketan, Lajpatnagar, training-*cum*-production centres and refugee handicraft shops, wage centres for Government order work at the training centres, the Central Braille Press, Dehra Dun etc. But no revenue income being realised from these centres has been shown. The hon. Minister may please clarify these points.

Now, I come to the point of the uplift and the welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. We want social stability. But without improvement in the economic conditions of these classes, how could it be possible to have social security and stability ? Unless and until the people have some income for their existence how could there be social stability ? This is the burning question for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people. Unless and until this question is properly tackled, social disabilities arising out of it cannot be removed satisfactorily. In my opinion, to improve the economic conditions of these classes, their home industries should be improved and developed. Government should help these people either in running of their home industries or give them some work which would give them a better existence and better living.

Of the Scheduled Castes and scheduled tribes people, more than 90 per cent are agricultural labourers. The landless people should be provided with land. Agriculturists should be provided with better seeds and monetary help for purchasing bullocks, agricultural implements, machinery for lift irrigation and other facilities for irrigation and fertilisers. The present system of giving such help is not satisfactory. The needy persons do not get real help. To take such help, the people have to request the workers of non-official organisations.

For proper distribution of land to the landless people, land reform legislation should be framed and passed to give benefit to the landless people.

Hand-weaving and training are the main home industries of the Scheduled Castes. Due to introduction of machinery and power, these persons became jobless. The main problem with these people is how to earn their livelihood. Yet Government do not consider the problem seriously except beating the drum that the Government do much more work for the welfare of Harijans and the down-trodden.

MR. CHAIRMAN : Time is up.

SHRI D. R. PARMAR : Sir, we do not get what we demand. But when we request for more time to ventilate our grievances, at least that should be conceded in a generous manner.

Weaving is the main industry of the Scheduled Castes in Gujarat State. Due to introduction of textile machinery and powerlooms, they are deprived of their home industry. Yet Government do not consider it necessary to allot powerlooms to jobless Scheduled Caste people.

I do not want to say anything against the refugees. But Government take keen interest in their rehabilitation and welfare, and industries for them. They are being considerably monetarily helped. They should be helped. But in the same way, the downtrodden who constitute one-fifth

of the total population of the country should also be helped for their social and economic uplift.

In Gujarat, the refugees are being allotted with powerlooms and monetarily helped for purchasing and maintaining powerlooms. But the Scheduled Caste persons whose home industry is hand-weaving and who have become jobless are neither allotted powerlooms nor monetarily helped. Why should there be such discrimination ? We are socially as well as economically backward. What have Government done for the improvement of our economic condition since the last 20 years ? Nothing. We have become more and more poor during this period.

It has been proved beyond doubt by various commissions, reports, speeches and also inquiries made that economically no improvement has been made so far as the backward and scheduled castes and tribes are concerned.

My point is that neither the Central Government nor the State Governments have so far been able to bring before the country any measures which would help to improve the financial and economic conditions of these classes.

Only one minute more.

MR. CHAIRMAN : That is enough. I have given you much more than one minute.

SHRI D. R. PARMAR : In this Panchayat Raj the Harijans are suffering a lot and the Government cannot take any action as they want the support from the persons in the villages. My main point is about the improvement of educational facilities for the Scheduled Caste people. The students belonging to these communities are getting scholarships, but there is a bar of Rs. 6,000, of their parents' income for getting freeship and scholarship. Now, in view of the rise in prices, I request that the rate of scholarships and the bar on their parents' income should be reviewed and revised.

MR. CHAIRMAN : This is being repeated. Kindly conclude.

SHRI D. R. PARMAR : I have concluded.

SHRI P. R. THAKUR *rose—*

MR. CHAIRMAN : He will speak later. I have not called him yet.

SHRI P. R. THAKUR (Nabadwip) : I had requested you to give me time. Will you allow me ?

MR. CHAIRMAN : One on this side and one on the other side. Dr. Saha.

DR. S. K. SAHA (Birbhum) : Mr. Chairman, Sir, I rise to support the demands presented by the Department of Social Welfare for the year 1968-69. This department has mainly two branches—one deals with the welfare and upliftment of the backward classes, and another deals with general welfare. I shall confine myself to the welfare of the backward classes. India is a vast, democratic country with a population of 51 crores of which 56 million belong to the Scheduled Castes. They are the landless people. They have no land for agricultural operations and they have no house to live in. They depend on their daily wages. They live in very unhygienic conditions and environments. Owing to these unhygienic environments and to the malnutrition, they are often subject to infectious diseases like cholera, typhoid, malaria and tuberculosis and so on. It is the bounden duty of the Government to improve their conditions and bring them on a par with the other people by improving their educational and economic condition and improving the working conditions of those Harijans who are engaged in cleaning works. They are backward in education, because they do not get any financial help for this purpose. They get only scholarship in the matric and post-matric classes. They get small amount which is not sufficient to maintain their educational expenses. I suggest that education should be given free for all these people both in the higher and the secondary level.

Untouchability is a most distressing element in the lives of these people. Untouchability, though a crime under the Untouchability Act, 1955 yet it is in practice in one way or the other in the rural areas.

[Dr. S. K. Saha]

The depressed classes are not allowed to go to the well and tanks to collect water; they are not allowed to collect water from them. because those wells or tanks are being used by the so-called higher caste people. After 20 years of Independence, it is a disgrace that such a thing continues. In most of the villages which are inhabited by Scheduled Castes and Scheduled Tribes, there is no drinking water ; for getting drinking water, they have to travel miles together from the villages. Therefore, I ask the Government to see that every village should be supplied with drinking water, especially those villages which are inhabited by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

There are no hostels for scheduled caste and scheduled tribe girls. I am glad that Rs. 9 lakhs and Rs. 11 lakhs had been provided in the third plan for the hostels for the scheduled caste and scheduled tribe girls respectively. They should be given the necessary help for starting domestic industries and small-scale industries. They are backward in society and they do not get any opportunity to develop themselves. Therefore, Government should take steps to provide them with all the facilities so that they can improve their condition.

With these words, I support the demands.

SHRI MUTHU GOUNDER (Tiruppattur) : Sir, only during the British rule of 200 years a beginning was made in the upliftment of the downtrodden and the removal of untouchability, unapproachability and other social inequalities. Then came Mahatma Gandhi who fought for this cause. When the Hindu kings were ruling this country, casteism flourished. According to *Manu Shastra*, there should be four castes—*Brahmins, Vaisyas, Kshatriyas and Sudras*. As long as we accept Hindu philosophy, we have to nourish and maintain the caste system.

Even during the Rama Rajya, there was one Sambugan who unfortunately belonged to the *Sudra* community. He performed tapas to purify himself and attain *moksha*. But according to Manu dharma, a *sudra* is not entitled to pray to God directly. It must be through somebody only. For that offence, Rama ordered him to be called. There is a whole *padalam* called Sambugavadam in the Ramayana. From that time itself, there is casteism. We should have the guts to find out the root where the caste system was born and we should destroy the very system which nourishes it. But we always lack in that. Only somebody from the south has started it.

Periyar E. V. Ramasamy has started this big movement and it is gaining momentum. Even now according to a report by the Research Project on Caste in Educational Institutions sponsored by the National Council of Educational Research in Mysore State it was observed that in a Sanskrit Pathashala in Dharwar only Brahmin students are admitted for the study of Hindu scriptures. While denying entry to Scheduled Caste persons in this institution the Brahmins of the Trust Committee said that in the precincts of personal and sectarian religion and ritual the Brahmins will not mix with others as these rules have been ordained in Vedas and shastras that because of their defiling occupations the Scheduled Castes could not be allowed to mix with the pure in the learning of sacred knowledge and rituals. Therefore, as long as we have our cherished objective—Ramrajya—as long as we try to reach Ramrajya we have to and we are bound to keep this caste system. If only we want to throw away Ramrajya, if only we boldly say that our target is not Ramrajya, we can speak of removing these caste barriers.

SHRI J. B. KRIPALANI (Guna) : Sir, are we representatives of Ramrajya here ?

SHRI MUTHU GOUNDER : Besides these Scheduled Castes and Scheduled Tribes there are many backward communities also which are very backward. In certain areas they are more backward than even the Scheduled Tribes.

The Scheduled Tribes live in geographically isolated pockets. My constituency consists of many Scheduled Tribes. I took personal interest to uplift some people in some villages by giving them jobs. I also impressed it on some social reformers that we are not able to give them any uplift because they are always slaves of superstition. If they get some extra income they spend everything by going to some big temple in

the south. They put up to the last paisa in the hundi and return fully shaved and empty handed. The problem before those who are interested in uplifting these people is how to uplift them. I have tried in some pockets but I have failed miserably. If I give Rs. 50 to a man and ask him to purchase some sarees for his wife and some dhoties for himself, he will take all that money and also another Rs. 50 from a moneylender, go to Tirupathi and put all the money there. I do not want to offend anyone. Let the rich people, wealthy people go and put all their ill-gotten money in the hundi. These bus owners and moneylenders who are interested in duping these poor people manage to spread some stories among these hill tribes that if they put whatever they have earned in the hundi next year they will have a bumper crop and they will earn more. Such stories are printed and circulated among the hill tribes and poor people. They believe them. I have used my entire power and influence but they do not believe me or anyone who has got some rational thinking. They take their entire money and also the money taken from moneylenders and put everything in the hundi. The Central Government some three or four years back asked the State Governments to prevent moneylenders from going and giving money to hill tribes. I do not know why the State Governments are reluctant to pass orders saying that moneylenders should no longer go to the hill tribes. These moneylenders give money to these people, with that money they earn and save something and at the end of the year they spend everything in the temples.

So, there is no way. Unless we root out this superstition in religion, we cannot uplift them. There is no other alternative. Therefore, everyone, who is interested in the uplift of Harijans or the Scheduled Tribes, should find out the real cause and remove the superstition and such follies in religion.

Then, coming to untouchability, we speak much about it. It is still in an acute form, but it is in its most acute form among the Scheduled Castes themselves. Everybody knows it. A cobbler is considered to be the last man, perhaps. A Harijan will not touch him. Others may touch him on occasions, but he will find that a Harijan will not touch a cobbler. But we should not use these things so as not to give them any support. The problem is very acute among themselves and we should educate them thoroughly and fully so that untouchability based on religion is wiped out from our country and society.

Everywhere labour unions are working well, specially in the industrial sector. Where it is very much wanted is among the hill tribes. Almost 50 per cent of the hill tribes are used as labourers by forest contractors. The forest contractors are exploiting them fully. There is no co-operative labour union among these hill tribes. According to statistics, Government seems to have formed already 1,600 co-operative labour unions in many parts of the country, but they are not working effectively.

Everywhere a forest contractor will be making huge amounts of profit, whereas the poor hill tribe labourer working under him will be getting Rs. 1½ or Rs. 2 a day. So, we should make it compulsory that labour unions should be formed and we should give some protection to these hill tribesmen who are working under forest contractors.

The Scheduled Castes people originally were following only Buddhism, according to Ambedkar. I want to quote a Government publication regarding this :—

> "Ambedkar was of the opinion that many of the Scheduled Castes belonged originally to the Buddhist denomination and it was the tyranny of Brahmin priesthood which eventually reduced them to their lowly position. From the experience of numerous social workers one learns that it is easier to reduce the distance between the upper and the lower castes than between sections among the lower castes themselves."

So, the system has got deep roots among the Scheduled Castes themselves.

SHRI R. D. BHANDARE (Bombay Central) : You have mixed up the two statements and put them together as one. They are entirely separate.

SHRI MUTHU GOUNDER : There are two issues but the issues are dealt with here.

[Shri Muthu Gounder]

The root is in religion. If we do not give much importance to religion, the caste system will go away. If we give so much importance to religion and superstition, castes will be there for ever. Therefore I put so much emphasis on the importance to remove this religious basis.

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, may now move the cut motions to Demands for Grants relating to the Department of Social Welfare, subject to their being otherwise admissible.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna) : I beg to move :

That the Demand under the Head Department of Social Welfare be reduced by Rs. 100.

[Need to overhaul the administrative machinery of the Government Lady Noyce School for Deaf and Dumb, Delhi (9)]

That the Demand under the Head Department of Social Welfare be reduced by Rs. 100.

[Need to improve the catering arrangements in hostel attached to Government Lady Noyce School for Deaf and Dumb, Delhi (10)]

That the Demand under the Head Department of Social Welfare be reduced by Rs. 100.

[Need to reduce the boarding charges and improve the quality of food provided to students in the hostel of Government Lady Noyce School for Deaf and Dumb, Delhi (11)]

That the Demand under the Head Department of Social Welfare be reduced by Rs. 100.

[Need to look into the grievances of the staff attached to the Government Lady Noyce School for Deaf and Dumb, Delhi (12)]

That the Demand under the Head Department of Social Welfare be reduced by Rs. 100.

[Behaviour of the officials of the Government Lady Noyce School for Deaf and Dumb, Delhi towards the staff and employees (13)]

That the Demand under the Head Department of Social Welfare be reduced by Rs. 100.

[Need to repair the quarters attached to the Government Lady Noyce School for Deaf and Dumb, Delhi (14)]

That the Demand under the Head Department of Social Welfare be reduced by Rs. 100.

[Irregularities and favouritism in the allotment of quarters attached to the Government Lady Noyce School for Deaf and Dumb, Delhi (15)]

That the Demand under the Head Department of Social Welfare be reduced by Rs. 100.

[Failure to supply summer and winter uniform in time to class IV employees attached to Government Lady Noyce School for Deaf and Dumb and other Homes in Delhi (16)]

That the Demand under the Head Department of Social Welfare be reduced by Rs. 100.

[Failure to confirm temporary employees who have put in more than 10 to 15 years of service in Government. Lady Noyce School and other Homes (17)]

That the Domand under the Head Department of Social Welfare be reduced by Rs. 100.

[Failure to improve the condition of buses and provide new buses for the Government Lady Noyce School for Deaf and Dumb, Delhi (18)]

That the Demand under the Head Department of Social Welfare be reduced by Rs. 100.

[Failure to pay overtime allowance to class IV staff for working beyond regular duty hours (19)]

That the Demand under the Head Department of Social Welfare be reduced by Rs. 100.

[Failure to fix the duty hours of class IV staff of the Government Lady Noyce School for Deaf and Dumb and avoid putting persons in both shifts, morning and evening (20)]

That the Demand under the Head Department of Social Welfare be reduced by Rs. 100.

[Maladministration and irregularities in the Government Lady Noyce School for Deaf and Dumb, Delhi (21)]

That the Demand under the Head Department of Social Welfare be reduced by Rs. 100.

[Need to go by seniority for the purposes of promotion in the Government Lady Noyce School for Deaf and Dumb, Delhi (22)]

MR. CHAIRMAN : The cut motions are also before the House.

श्री ब० मं० काहानडोल (मालेगांव) : सभापति महोदय, में समाजकल्याण मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिये उत्तिष्ठ हूं। साथ ही मन्त्री महोदय का ध्यान आदिवासी यानी शेडयूल्ड ट्राइब्ज की कुछ अड़चनों की तरफ खींचना चाहता हूं।

मैं खासकर महाराष्ट्र के आदिवासियों के विषय में कुछ कहूँगा। हम लोग ज्यादातर जंगलों में रहते हैं। शहरों के साथ हमारा बहुत ही कम सम्पर्क आता है। हमारे इलाके में अच्छी सड़कें नहीं हैं। जो हैं भी, वह बुरी स्थिति में तथा अपर्याप्त हैं। यातायात के अभाव के कारण हम लोगों को केवल आर्थिक ही नहीं, परन्तु शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। बीमारों का इलाज नहीं हो पाता। मामूली रोगों से भी जीवन हानि होती है। अतएव पर्याप्त व अच्छी सड़कें होना आवश्यक है।

आदिवासी बच्चों की पढ़ाई के लिये स्वयंसेवी संस्थायें वसतिगृह चलाती हैं। कुछ बड़ी संस्थायें अच्छा कार्य कर रही हैं। किन्तु ज्यादातर संस्थायें इस क्षेत्र में व्यावसायिक रूप से उतरने लगी हैं। जिस से बच्चों के खाने पीने तथा कपड़ों की व्यवस्था ठीक नहीं रहती है।

अनेकों बसतिगृहों के होने हुए भी शिक्षा का प्रबन्ध अधूरा ही है। केवल हम आदिवासी बच्चों की प्राथमिक शिक्षा की भी समस्या सुलझायें तो भी बहुत काम होगा। इस बिषय में मैं आश्रम शालाओं की सिफारिश करूंगा। महाराष्ट्र में आश्रम शालाओं ने सराहनीय कार्य किया है।

आदिमजातिजनों की प्रगति के लिये सरकार ने उन के इलाकों में खास विकास योजनायें शुरू की हैं। इसमें कृषि को अग्रक्रम दिया गया है। फलस्वरूप जिन गांवों में एक भी कुआं नहीं था वहां कुओं के पानी पर सब्जियां तथा गन्ने की खेती होने लगी है। आदिवासी जनों में नये सिरे से खेती के लिये उत्साह निर्माण हुआ है। आम तौर पर हर गांव में कुएं और तालाबों के कारण पीने का पानी भी प्राप्त होने लगा है।

विकास योजनाओं का काम जिला परिषदों की ओर से चलाया जाता है। जिला परिषदें आदिवासियों की तरफ ज्यादा ध्यान दे कर काम चलाती हैं।

अतएव मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करता हूँ कि खासकर आदिवासी विकास योजनाओं के लिये ज्याद पैसे दिये जायें। इस से जिला परिषदों को और कार्य करना सम्भव होगा।

आदिवासी क्षेत्रों में प्रति 30 हजार संख्या के लिये एक स्वास्थ्य केन्द्र है। इस हेल्थ सेन्टर का भवन होता है लाख-डेढ़ लाख का और औषधियां होती हैं केवल हजार-बारह सौ रुपयों की। प्रार्थना है कि वार्षिक औषधि के खर्च के लिये भी ज्यादा धनराशि दी जाएं।

आदिवासी कई पीढ़ी से गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। औषधि तथा अन्य चिकित्सा का महत्व तक उन को समझाना है। इस लिये इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सम्बन्धी काय सर्व-सुविधा के साथ किया जाना चाहिये।

गिरिजन तथा जंगलों का निकट सम्बन्ध है। 20-25 साल पहले हमारे जंगल घने थे। किन्तु आज वहां एक भी वृक्ष दिखाई नहीं देता। केवल पत्थर बाकी हैं। इस स्थिति में सरकार वन विभाग की जमीनों तथा खानगी जमीनों में वृक्ष लगाने का काम बड़ी मात्रा में नहीं करेगी तो भविष्य में बड़ी बुरी हालत हो सकती हैं।

[श्री ज० मं० काहानडोल]

इस समस्या का हल सरकार शीघ्रतापूर्वक ढूंढे तथा वन महोत्सव सत्य रूप में प्रभावशाली करे ।

भारतीय समाज-परिवार के हरिजन तथा गिरिजन दो ऐसे सदस्य हैं, जो एक तरह से अपंग हैं । उन में भी हरिजन संगठित तथा राजनीतिक दृष्टि से जागृत हैं । गिरिजन न तो शिक्षित हैं और न ही जागृत । राष्ट्र के नेता, नियोजक तथा सरकार के मान्य पदस्थ इस अपने पिछड़े भाई की ओर खास ध्यान दें, यही मेरी प्रार्थना है ।

श्री शिवचरण लाल (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, मैं पहले तो आप के माध्यम से जो इस विभाग के मंत्रिगण हैं, हरिजन और समाजकल्याण की बात करने वाले, छुआछूत को दूर करने के लिये कहने वाले, हरिजनों को उत्थान देने की बात करने वाले, उन से कहूँगा कि उन को चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिये ।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण संक्षेप में दीजिये ।

श्री शिवचरण लाल : मैं बहुत दुखी हूँ । आजादी के बीस सालों में जो कुछ काम किया गया है उस के अनुसार इस समाज-कल्याण विभाग को नहीं रहना चाहिये । इस लिये मैं आप के समक्ष इन मांगों का घोर विरोध करता हूँ । आज हरिजनों को समाज-कल्याण की जगह बेकारी, भुखमरी, अपमान, अमानुषिक छुआछूत, गोली, लाठी और तिरस्कार का गम्भीर सामना करना पड़ रहा है । विशेषकर मेहतर कहलाने वाले अछूत, सफाई का काम करने वाले हरिजन, जो कि ऐसा गन्दा काम करते हैं, जिसे भारत में शायद कोई भी नहीं कर सकता है, आज इस आजादी में भी हर प्रकार की बर्बादी का सामना कर रहे हैं । आज उन्हें महसूस हो रहा है कि कांग्रेस के इस कुराज से तो अंग्रेजी राज अच्छा था । अंग्रेजी राज में कम से कम कानून का तो पालन होता था खुले-आम उन गरीबों को मार दिया जाता है, किन्तु अपराधियों को कुछ भी दंड नहीं मिलता है । सरकार आज तक हरिजनों की देख-रेख करने और सुरक्षा करने में असफल रही है । आज हरिजनों में कितने भूमिहीन हैं, कितने बिना मकान के हैं, कितने कुओं के बिना पानी के लिए तरस रहे हैं, कितने हरिजन बच्चे स्कूलों में प्रवेश नहीं पा रहे हैं, कहां कहां छुआछूत विद्यमान है, यह सारी हालत जानने में सरकार बिल्कुल असमर्थ रही है और अब भी है । दिन-दहाड़े उन गरीबों को मार दिया जाता है । मैं इस के कुछ उदाहरण आप के सामने पेश करूंगा ।

दिनांक 26 फ़रवरी, 1968 को ग्राम वनिठारी, तहसील सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर, थाना ककोड़, उत्तर प्रदेश के निवासी श्री शम्भूनाथ बाल्मीकि के चौदह वर्षीय इकलौते लड़के स्वर्गीय चन्दूराम की निर्मम हत्या उक्त गांव के धनाढ्य, शक्तिशाली तथा प्रभावशाली ब्राह्मण गुट ने अपने नवयुवकों से कराई । उक्त घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराने से अल्पसंख्यक हरिजनों को बलपूर्वक रोका गया तथा 11 मार्च, 1968 तक रिपोर्ट दर्ज नहीं होने दी ।

उस बच्चे की मां की ममता इन मंत्रियों की कुर्सियों से टकरा रही है और रो रो कर कह रही है कि वाह, यह कैसा रामराज्य है; यह कैसा न्याय है कि हमारे निरपराध बच्चे मारे जा रहे हैं !

घाटमपुर क्षेत्र, ग्राम हथिरवा में ठाकुर लाल सिंह ने दो हरिजन बालकों को कुंए में फैंक कर इस लिए निर्मम हत्या कर दी कि वे उस की खाट पर बैठे गए थे ।

आन्ध्र प्रदेश के एक हरिजन बालक को इस लिए तेल छिड़क कर जिन्दा जला दिया गया कि उस ने एक सवर्ण जाती के व्यक्ति के

बर्तन छू लिए थे, लेकिन पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज किया ।

आन्ध्र प्रदेश के एक गांव में हरिजन महिलाओं को नंगा कर के सारे-ग्राम घुमाया गया, क्योंकि उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल अपनी मर्जी से किया था। आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने इस घटना की गलत रिपोर्ट दी, जिस पर केन्द्रीय मंत्री-मंडल संतुष्ट हो गया ।

इसी प्रकार मध्य प्रदेश में तीन हरिजनों को मूंछ पर ताव देने के दोष में सवर्ण जाती का गोली का शिकार होना पड़ा ।

क्या यही राम-राज्य है ? राम के आदर्श बहुत ऊंचे थे । उन्होंने कहा था : "जो अनीति कुछ भांकू भाई, तो मोही बर जो भय बिसराई"। राम-राज्य का आदर्श यह था : "दैविक दैहिक भौतिक तापा, राम-राज्य का हुए नहीं व्यापा ।" मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि चन्द्रशेखर आजाद 27 फ़रवरी, 1931 को इलाहाबाद में अपनी मूंछों पर ताव देते हुए अंग्रेजों की गोली से मारा गया था । हम समझेंगे कि हरिजनों के लिए यह अंग्रेजी राज्य है, जिस में मूंछों पर ताव देने से उन को गोली मार दी जाती है ।

उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं । जिला अलीगढ़ के अनेक ग्रामों की शिकायत राज्य सरकार तथा जिलाधीश को दी जा चुकी है । उसमें एक प्रमुख घटना यह है कि ग्राम शिकरना थाना जोया में एक हरिजन महिला को एक लोधे राजपूत ने घर से बुला कर जगत में उस अकेली को लाठी से बुरी तरह जख्मी कर दिया । इस की सूचना समस्त अधिकारियों को है, परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई ।

लकिन मैं समझता हूं कि इस बारे में दोष मारने वालों का नहीं है, बल्कि दोष तो सरकार का है, जो आज तक ऐसे अपराधों की रोक थाम नहीं कर सकी है । दोषी यह सरकार है, जो ऐसे अपराधों को बढ़ावा देती है और हरिजनों पर अत्याचार करवाती है । हम तो यह चाहते हैं कि हम सवर्णों की गोलियों से न मरें, बल्कि सरकार और समाज-कल्याण मंत्री अपने हाथों से हरिजनों को मारें ।

इसी प्रकार जिला एटा में एक मुसलमान जमींदार ने एक बाल्मीकी हरिजन के खेत पर जबर्दस्ती कब्जा कर रखा है, जिस की सूचना उत्तर प्रदेश की भूतपूर्व मुख्य मन्त्री, श्रीमती सुचेता कृपालानी को दी गई थी, परन्तु खेद है कि आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

16 अप्रैल, 1968 के दैनिक **हिन्दुस्तान**, पृष्ट 6, कालम 1 पर छपा है कि मध्य प्रदेश के टिकरी पीपरिया ग्राम के एक ठाकुर द्वारा लगभग 35 हरिजनों के खलिहान दिन-दहाड़े जला दिये गये ।

आन्ध्र प्रदेश के एक मन्त्री ने कहा है कि हरिजनों को लात मारनी चाहिए तथा जो पत्रकार उनका समर्थन करेगा उसे भी लात मारनी चाहिए । यह समाचार 24 अप्रैल, 1968 के **पेट्रियेट** में छपा है । मेरी मांग है कि उन व्यक्ति को मन्त्री के पद से हटा दिया जाये और उस पर अस्पृश्यता कानून तथा नागरिक कानून के अन्तर्गत मुकदमा चलाया जाये ।

केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें आज तक इस बात का पता नहीं लगा पाई हैं कि सरकारी सेवाओं में कितने हरिजन है, जबकि वह बिलों के चूहों तक का पता लगा लेती है ।

खिदमते मुल्क में जो मर जायेंगे,
अमर नाम दुनिया में कर जायेंगे
यह न पूछो कि मर कर किधर जायेंगे,
जिधर भेज देगा, उधर जायेंगे ।
लो अछूतों को छाती लगा हिन्दुओ,
वर्ना ये लाल गैरों के घर जायेंगे ।
टूट जायें न माला कहीं प्रेम की,
वर्ना अनमोल मोती बिखर जायेंगे ।
लगाते रहे अगर प्रेम का मरहम,
तो जख्म ये सारे भर जायेंगे ।

[श्री शिवचरण लाल]

मानो न मानो खुशी आपकी,
हम मुसाफ़िर हैं, कल अपने घर जायेंगे।
दुख दर्द वही अपना अपना,
इस दुख दर्द का चारा न हुआ,
इस देश का बंटवारा तो हुआ,
दुख दर्द का कुछ बंटवारा न हुआ।
इस देश के खेवनहारों पर अब टूट पड़ा है धन कैसे,
इतने उजले कपड़ों में फिर इतने गन्दे मन कैसे।
जिन को था जगाना देशअभी,
वे ऐश के मारे सोते हैं,
आकाश के तारे हंसते हैं,
धरतीकेसितारे रोते है ।

इस देश में हरिजनों की जनसंख्या 60 प्रतिशत है। क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि क्या हमारी पुलिस में 16 प्रतिशत भी हरिजन थानेदार हैं ?

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त करें।

श्री शिवचरण लाल : मैं एक दो मिनट चाहता हूं।

सभापति महोदय : अभी और बहुत से सदस्यों ने बोलना है।

श्री शिवचरण लाल : सरकार की ओर से हरिजनों का कल्याण करने की बड़ी डींग मारी जाती है, लेकिन मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि आज सरकारी नौकरियों में ऊंचे पदों पर कितने हरिजन हैं, आज हमारे जजों में से कितने हरिजन हैं, कितने हरिजन विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश भेजा गया है।

हम देखते हैं कि हमारे मंत्री लोग हरिजनों से बात करना भी पसन्द नहीं करते हैं। लेकिन माननीय मंत्री, डा० रामसुभग सिंह, हरिजनों के एक हितैषी मंत्री हैं, जो प्यार से उन्हें पास बिठाते हैं ।

सरकार को भंगियों, मेहतरों और हरिजनों की हालत को देखना चाहिए। गांवों में हमारे लिए कोई कूंए नहीं हैं। हमें पानी तक नहीं मिल रहा है। हमारे कल्याण के लिए जो अनुदान दिया जाता है, पता नहीं, उसको कौन खाता है, उसको बर्बाद किया जा रहा है। हम मल और टट्टी उठाते हैं, लेकिन हमारे लिए स्वच्छ मकान नहीं हैं, स्वच्छ वातावरण नहीं है, स्वच्छ कपड़े नहीं हैं। हमारे लिए स्वच्छ नौकरी नहीं है, ताकि हम अच्छी तरह जीवन व्यतीत कर सकें।

इस लिए मैं मन्त्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि एक संसदीय कमेटी बनाई जाये, जो इस बात की जांच करे कि पिछले बीस सालों में हरिजनों का कितना उत्थान हुआ है, सरकारी नौकरियों में उन का प्रतिनिधित्व कितना बढ़ा है आज स्थिति यह है कि बीस साल पहले हरिजनों के साथ जो बर्ताव होता था, आज भी वही बर्ताव उनके साथ हो रहा है, बल्कि उससे भी अधिक खराब बर्ताव हो रहा है।

इन शब्दों के साथ में इस मन्त्रालय की मांगों का घोर विरोध करता हूँ। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि एक कमेटी बना कर इस बात की जांच की जाये कि देश में हरिजनों पर कहां कहां अत्याचार हो रहे हैं और दोषियों को दण्ड देने की व्यवस्था की जाये। वर्ना मैं समझूंगा कि ये अत्याचार यह सरकार करा रही है और वही ज्यादा दोषी तथा अपराधी है। वह कमेटी गांव गांव जाकर हरिजनों की हालत की जांच करे और स्थिति की सही रिपोर्ट सरकार को दे।

SHRI R. D. BHANDARE (Bombay Central) : Mr. Chairman, Sir, hon. Members will speak on the various aspects of the work done by the Social Welfare Department. Some other hon. Members will also speak on the bemoaning tales of sufferings of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

One of the hon. Members who just now spoke was actually bemoaning and telling us agonising stories which are based on facts and they are not factions. Today,

I will take the opportunity to place before this House one specific point. I will not travel over vast ground because I would leave that matter to the other Members to do so. We are dealing with Social Welfare and what is the purpose of Social Welfare ? What work does this Social Welfare Department do ? It is given here at page 7, on the Introductory portion of Chapter I. This Report says that 'the prime concern of the Government has been to bring these less fortunate sections of society at par with the rest of the population'. That is the objective envisaged or placed by this department before itself. The principles enunciated are also given there. It says : 'The high ideals of social, economic and political justice, equality of status and opportunity and the promotion of fraternity among all sections of society were embodied in the preamble to the Constitution itself'. Therefore, Government have taken upon itself the task to bring these less fortunate sections of society on par with the rest of the people.

This Department has also announced to the world that it wants to implement the Directive Principles. I need not tell this House about the importance of education. The late Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru said 'Education is an investment in man'. I do not know whether the Government, and more specially the Social Welfare and Education Departments are insisting that this investment in man should be increased. It is also said that education is an instrument of transforming a man or a person into cultural and cultivated man. Education is also considered to be an instrument to transform the Indian society. Well, these are the high-sounding principles. In actual practice, for the last two years the Government is reducing scholarships and thereby reducing the investment in man. I need not trouble the House in reading the figures of the last 3 years. I would refer to page 60, of the Report of the Social Welfare Department. These figures will disclose that the amount spent on scholarships is being reduced gradually on one pretext or the other. However, even on that point, I should not dwell at length. I have failed to understand as to why this aspect of the programme of the Social Welfare is not extended to the unfortunate sections of the society, which section has embraced Buddhism. Whenever I raise this question it is not understood by the people in general and more especially by the Government. We are not demanding something which is not their constitutional obligation. There are some obligations under which Government must extend the educational facilities in the sense of scholarships and free studentships. Let us answer some of the questions so that we can understand the problem of the new converts to Buddhism. Who are these people who have embraced Buddhism ? In order to understand who these people are, we have to take into consideration who these people were, and what their status, position and habitat was. If we take into consideration their status, position and habitat before their conversion and their status, position and habitat after conversion, we shall find that there is no change in their status, position and habitat whatsoever.

SHRI S. XAVIER (Tirunelveli): Except in religion.

SHRI R. D. BHANDARE : Except in religion. And religion for what purpose ?

SHRI J. B. KRIPALANI : No purpose.

SHRI R D. BHANDARE : No, there is a specific purpose. As education is an investment in man, Buddhism speaks of the changing of the mind of an individual. The Lord Buddha himself had described and defined his religion in the following words:

सर्व पापस्य अकरणम् कुसलस्य उपसम्पदा
सचित् परयोदपनम् एतन् बुद्धान सासनम् ।

The purpose of Buddhism is to change the mind so that a person can transform his life based on the social norms enunciated by the Lord Buddha, namely *Prajna, Sheela* and *Karunaa,* wisdom, moral character and softness of mind and also *Maitree* or friendship.

SHRI J. B. KRIPALANI : Why should he not convert the Treasury Benches ?

SHRI R. D. BHANDARE : I am trying to convert my hon. friend too, because he says that religion is of no use

[Shri R. D. Bhandare]

at all. Therefore, I am saying this. In order that an individual should change himself, we have accepted Buddhism. But then, this aspect has not been appreciated and understood.

Anyway, it is a moral obligation on the basis of which facilities, and more especially educational facilities, should be extended to the Buddhists. But I am not standing merely on moral obligation. On moral obligation basis, Government may or may not act, an individual may or may not act, a Minister may or may not act, an officer or official may or may not fulfil what is expected of him. But every individual who has accepted the Constitution as the basis of society has to fulfil those obligations. We have accepted democracy not only as a form of government under which the Ministry and the Cabinet form of Government is there, but as a way of life. Are we, therefore, to accept only a part of the Constitution and reject the rest of it ?

I would, therefore, draw your attention to article 25, because whenever we raise the question of facilities to the Buddhists, the question is raised that we are no longer Hindus, and we have left the fold of Hinduism. But since we are dealing with social welfare, I am drawing your attention and through you the attention of the Government and more especially of my friends who are occupying positions of power and authority, to this. Article 25 speaks of the right to freedom of religion. But I am not propounding or explaining the basic principles of secularism. So, I would only read clause 2 of article 25 which reads thus :

> "Nothing in this article shall affect the operation of any existing law..."

This means that Government can and the State must fulfil the obligation and nothing should come in the way fulfilling the constitutional obligation. Then the clause goes on to say :

> "or prevent the State from making any law—
>
> (a) regulating or restricting any economic ..

I would now read out clause (2) (b) which reads thus :

> "providing for social welfare..."

Let me emphasise these words "social welfare". Then it goes on to say :

> "...and reform..."

The reform is the reform of the Indian society.

> "...or the throwing open of Hindu religious institutions of a public character to all classes and sections of Hindus".

So, for social welfare and social reform, Government must perform certain obligations enunciated in article 25. But to whom is the application of the programme enunciated under social welfare to be made ? Explanation II says :

> "In sub-clause (b) of clause (2), the reference to Hindus shall be construed as including a reference to persons professing the Sikh, Jaina or Buddhist religion, and the reference to Hindu religious institutions shall be construed accordingly."

17 00 hrs.

So for the purpose of fulfilling the constitutional obligation under art. 25(2) Explanation II, the educational facilities, meaning thereby grant of scholarships and free studentships, must be extended to the Buddhists. What is the difficulty in doing this ? I do not understand. I am told that Government have already accepted the principle. Then why is it that they are not announcing it ? I demand they must make a categorical statement whether they are going to extend the educational facilities to the Buddhists or not. It is already in the air, I have been hearing it for a long time. What is the difficulty in coming out with an announcement ? Whoever joins the post-matric class should be given facilities, which is done by the Maharashtra Government. I was under the impression that the Maharashtra Government was not progressive and the Central Government would be very much more progressive because they subscribe to, and profess to follow certain norms or principles of democratic socialism. But then our Maharashtra Government is far more progressive than I could envisage the Central Government, because it has extended all facilities to the newly converted Buddhists. I do

not know why the Central Government, specially the Social Welfare Department is lagging behind in this matter.

Is it that their socialism is one step forward and two steps backward ? What is it that they are professing, what are those socialistic principles when a large section of the community are denied the basic necessities in the form of education for transforming themselves ? I need not elaborate this point.

I would only make an appeal again that a categorical statement should be made here today because I have been hearing it, I have been praying for it, I have been...

AN HON. MEMBER : Fighting for it.

SHRI R. D. BHANDARE : No, not fighting.

SHRI DEORAO PATIL (Yeotmal) : It is said the matter is under consideration.

SHRI R. D. BHANDARE : I shall start protesting a day after tomorrow if the announcement is not made today. Then we will be free, specially I will be free, to protest and fight. Therefore, my request to the hon. Minister to make a categorical statement so that the Buddhists can be certain that they will get some facilities and consider that our Government are much more progressive.

MR. CHAIRMAN : Time being what it is, it is necessary that Members kindly limit their remarks to 5—7 minutes. Shri A. K. Kisku.

SHRI P. R. THAKUR : I have moved some cut motions and want to speak on them. I may be allowed early as I have an engagement outside.

SHRI A. K. KISKU (Jhargram) : You have very kindly agreed to give me 7 minutes. I would like to have only 3 more because in the entire Budget session I was not given any chance at all. Therefore, I would like to have this chance.

While listening to today's discussion on social welfare, a line from the Negro scripture was ringing in my ears. The Negro is crying out of utter distress and praying : 'Here am I. Hear me and save me from the sufferings that come from man'.

Today my hon. friend over there expressed most emotionally and most reasonably the distress of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

He also expressed the sufferings of humanity at large. When they talk of social welfare, social welfare must have a basis, must have a philosophy, must have a source of inspiration. Our country has a philosophy. We believe in Gandhism. We have a socialist pattern of society. It is declared to be a secular, non-communal, socialist-patterned, welfare State. And there is a declaration of some social welfare schemes for the service of the Harijans and also for the alleviation of the suffering humanity. This is a beautiful philosophy and in order to implement this philosophy we have a beautiful machinery. At the helm of affairs we have a Minister whose name is Ashok. We have Shri Asoka Mehta. We have a beautifully-balanced Constitution, a Parliament, the legislatures. There is a Government with an elaborate machinery and department. There is a Secretariat, a Directorate and a big Publicity Department. And in order to work for social welfare within this framework, money is being asked for from the public treasury.

Today in the early hours we have heard that a Minister of a State had remarked that the Harijans deserve to be kicked. Within this beautiful Constitution, with this most eloquent philosophy, we are getting this kick, and this is not the first time. During the last few days there have been so many unhappy incidents which we read in the newspapers. I think it is high time that we very seriously thought of the whole matter and gave the responsibility to the Social Welfare Department to see that they look into this more seriously.

I would like to point out that this Social Welfare Department is an isolated detached department in the whole Cabinet. What I mean is that the Government should work as a team and it is the responsibility of the Social Welfare Department to baptize the entire Cabinet and inspire them into action. It should not only do what it should through the Government but it should involve the entire nation, the voluntary organisations, so that the whole society

[Shri A. K. Kisku]

becomes social welfare-wise oriented to alleviate the sufferings of the people. I am very sorry to say that in this report I got a list where there were only 21 organisations which are co-operating with the Government. It shows that the Social Welfare Department has failed in its fundamental duty to inspire the whole nation to be involved in these welfare matters.

Secondly, I would like to point out to you and to the House how the constitutional rights and privileges of the people and the office of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes have been reduced. I am tempted to say that it is a sort of petro-chemical evaporation of the functions and the constitutional rights of the Commissioner. Today we find in the report that the regional offices of the Commissioner have been taken over by the Directorate-General of the Welfare of Backward Classes. What does it mean ? It means that the Commissioner has been denied his eyes, his ears and his hands to work with. He has been reduced to the position of a sophisticated police constable. He has eyes ; he cannot see ; he has ears, he cannot hear, and he has hands which are tied. He has been chained in the whole system of bureaucracy. When we get a chance to discuss the recent report of the Commissioner for Scheduled Castes and Tribes, I will show you how it has been a great disappointment to us that we have not got the right type of safeguards and recommendations from the Commissioner.

This social welfare department sometimes looks as though it is not only indifferent and cold, but massively hostile to the scheduled castes and tribes. There is a certain amount of money to be spent for stipends of students. Why is it that during the last 20 years, the machinery is not functioning properly and the stipend does not reach the students in time ? Why are applications for jobs from scheduled castes and tribes suppressed ? Why is it that their promotional records are tampered with ? Why is it that the poor adivasis do not get protection even today from the exploitation of *mahajans* and their lands are taken away ? It is all because the social welfare department is failing terribly in its task.

In yesterday's pepers in West Bengal there was a very sad news. The education department was preparing a plan to feed the primary school children of the rural areas, for which CARE and other philanthropic institutions from Germany and other places had agreed to provide food for the students. But just because the West Bengal Government failed to give only Rs. 45 lakhs, the entire scheme has failed. It is not the direct responsibility of the social welfare department, but they should take it up with the West Bengal Government to see that these boys and girls from the scheduled castes and tribes and other backward classes in the rural areas get food. Otherwise, they cannot read. They must be given food, clothing and education at the same time.

We hear so much about T. D. blocks. But it has created a sort of frustration among the tribals because of the wrong implementation. In Bihar, Orissa and Bengal there is a big belt of scheduled tribes. But the boundary of the States runs in such a way that there is a chunk in West Bengal where there is a small section of tribals. But they are not getting the TD blocks whereas Bihar and Orissa are getting a share. This is great injustice. The tribals should be taken *en bloc* and the geographical barrier should be done away with, so that there is proper integration and proper implementation and the entire tribal community should get the benefit.

Among the lothars in Chargram only a few days back there was inter-tribal trouble. In this inter-tribal trouble the lothars' colony was burnt. I hope a report is coming and we will know what the facts are. This trouble was going on for five days and during these five days, as I said, the lothars' colony was burnt and some people were killed. What was the police doing for so many days ?

17.16 hrs.

[Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*]

If this thing happened in Calcutta the whole country would have been awake. These poor people were quarrelling among themselves because of ignorance or innocence and the police did not take any action.

These are some instances of great distress that these people are suffering. It is the duty, it is the responsibility of the Social Welfare Department to see that justice is done to these people.

श्री कांबले (लातूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समाज कल्याण विभाग के बजट अनुदानों का समर्थन करते हुए संक्षेप में कुछ अपने विचार सदन के सामने रखना चाहता हूँ ।

मांग संख्या 97 जो 8,63,000 रुपये की है और दूसरी मांग संख्या 98 जो 4,01,83,000 रुपये की है । इन दोनों को यदि टोटल किया जाय तो वह कुल मिला कर 4,20,46,000 रुपये होते हैं ।

इस समाज कल्याण विभाग में विशेषतया शोषित वर्ग की उन्नति का कार्य आता है । अब अगर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की रिपोर्ट के अनुसार इन वर्गों की संख्या 1961 की जनगणना के अनुसार कुल 9,42,54,592 है जबकि इस वक्त देश की कुल जनसंख्या 50 करोड़ के करीब है । इस का मतलब यह हुआ कि इस देश के अन्दर अनुमानतः 10 करोड़ आबादी शैडयूल्ड कास्टस और शैडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों की है बल्कि उस से कुछ ज्यादा भी हो सकती है । अब अगर आप हिसाब लगा कर देखें तो मालूम पड़ेगा कि वह करीब 4 करोड़ रुपया 10 करोड़ की जनसंख्या पर खर्च होना है तो उस हिसाब से प्रति आदमी के पीछे कोई 40 पैसे खर्च होगा । मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे हम अपने उस उद्देश्य में इस तरह से कामयाब हो सकते हैं और कैसे हम उन लोगों की उन्नति कर सकेंगे ? यह उन पर खर्च की जाने वाली रकम बहुत कम है और दूसरे इस में आफिस वगैरह का खर्चा भी आ जाता है । इसलिये यह रकम और अधिक बढ़ाये जाने की आवश्यकता है ।

आदिवासियों तथा हरिजनों की समस्या मेरी समझ में एक राष्ट्रीय समस्या है । यह बड़े खेद का विषय है कि भारतवर्ष की आजादी प्राप्ति के 20-21 वर्ष बीत जाने के बाद भी वह समस्या अभी भी हमारे सामने प्रश्नचिन्ह बन कर खड़ी हुई है । राष्ट्रपति जी ने इसी सत्र का उद्घाटन करते हुए अपने अभिभाषण में एक चीज कही है और उसे मैं आप के सामने उद्धृत करना चाहता हूं । उन्होंने इस समस्या का जिक्र करते हुये अपने अभिभाषण के पृष्ठ 8 पर यह कहा है :

"अनुसूचित जातियों, अनुसचित आदिम-जातियों और पिछड़ी जातियों की सामाजिक-आर्थिक उन्नति सरकार के लिये अत्यन्त रुचि और चिन्ता का विषय रहा है । हालांकि उन की उन्नति के लिये बहुत कुछ किया गया हैं, तो भी सरकार यह जानती है कि बहुत करना बाकी है ।

इस से मतलब यह है कि यह समस्या हमारे सामने आज खड़ी है । इस समस्या को कैसे हल किया जाय ? इस के अन्दर सिर्फ एक सामाजिक ही चीज नहीं है बल्कि इस के साथ आर्थिक, सामाजिक शैक्षणिक और राजनैतिक जीवन भी जुड़ गया है । उन सब को हल करना है । इसलिए मैं चाहूंगा कि इस मंत्रालय के लिए बजट अनुदानों की रकम को और ज्यादा बढ़ाया जाय क्योंकि इसके जिम्मे 10 करोड़ से अधिक शोषित वर्गों के आर्थिक जीवन को सुधारने का काम है ।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में एक और उल्लेख आया है जिसका भी मैं जिक्र करना चाहूंगा उन्होंने अपने अभिभाषण के पृष्ठ संख्या 12 के अन्दर यह कहा है :

"हम ने जातीय भेदभाव और दमन की घिनौनी प्रथा समाप्त करने का भी समर्थन किया है। हम दक्षिण रोडेशिया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका और पुर्तगाली उपनिवेशों के दलित लोगों को स्वतन्त्रता और मुक्ति दिलाने के लिए निरन्तर प्रयत्न करते रहेंगे । जो लोग रंगभेद की बर्बर नीति के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं उन्हें हमारा समर्थन बराबर मिलता रहेगा ।"

[श्री कांबले]

एक तरफ तो हम अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने ऊंचे आदर्शों की बात कहते हैं क्योंकि दुनिया के कई देशों में जातिभेद और रंगभेद की नीति बरती जाती है और इस का हम विरोध करते हैं लेकिन जब हम अपनी ओर देखते हैं तो पाते हैं कि एक ही प्रान्त के रहने वाले, एक ही रंग के, एक ही जाति और धर्म को मानने वाले लोग एक दूसरे को मानव समझने के लिये तैयार नहीं हैं। यह विपरीत बातें हमें देखने को मिलती हैं। हमें इस बात का बड़ा दुःख होता है कि हमारे देश में इतने ऊंचे आदर्श होते हुये भी बीस साल की आजादी के बाद शोषित वर्गों की दशा सुधरी नहीं है। बहुत सी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जिन के कारण सदमा पहुँचता है। अभी-अभी हाल में बिलासपुर, मध्य प्रदेश की घटना, आंध्र प्रदेश की घटना तथा दूसरी घटनाओं को मैं गिनाना नहीं चाहता, लेकिन इस से इस बात का पता चलता है कि हमारे देश में किस प्रकार मानवता खत्म हो रही है। आज हम सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में मानव को मानव समझने के लिये भी तैयार नहीं हैं। इस सामाजिक असमानता को दूर करने के लिये हमारी सरकार के प्रयत्न होंगे, वह कर भी रही है, लेकिन किस गति से वह चल रही है? एक तरफ तो मोटर साइकिल है और दूसरी तरफ बिल्कुल बीमार आदमी जो चल नहीं सकता है। इन दोनों की रेस हो रही है। मैं समझता हूं कि जो ऐसा वर्ग है जिन की शिक्षा की अवस्था, सामाजिक अवस्था और राजनीतिक अवस्था पिछड़ी हुई है उन को दूसरे प्रगतिशील लोगों के साथ जोड़ना ठीक नहीं है। आज सभी जगहों पर ऐसा किया जा रहा है। हम देखते हैं कि पब्लिक सर्विस कमिशन और दूसरी नौकरियों के अन्दर हरिजन विद्यार्थियों को दूसरों के साथ जोड़ दिया जाता है। इस तरह से कैसे काम चल सकता है? एक वह विद्यार्थी जो दिया के नीचे बैठ कर अभ्यास करता है, जिस को समय पर खाना नहीं मिलता जिस को सोने का तथा अन्य कार्यों का आराम नहीं है, दूसरे वह विद्यार्थी जिस के लिए लैम्प है, पंखा है, टीचर है, ट्यूशन मिलता है। इन दोनों की तुलना कैसे की जा सकती है? मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि दोनों में कुछ न कुछ फर्क तो उस में रखना ही चाहिये ताकि गरीब हरिजनों और गिरिजनों को उन के साथ न जोड़ा जा सके। आप इन पिछड़े हुए लोगों का आपस में कम्पिटीशन करा सकते हैं ताकि उन के सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन की दशा सुधारने का काम हो सके।

आज बहुत सी सामाजिक असमानतायें हैं जिन के लिये कानून बनाये गये हैं, अम्बेदकर साहब ने कानून की सारी कड़ियों को जोड़ने का प्रयत्न किया, बड़े-बड़े नेताओं ने भी किया, लेकिन आज क्या हुआ है? धार्मिक मन्दिरों में, धार्मिक मेलों में, कुंओं पर पानी भरने से उन को रोका जाता है, जहां इन्सान नहीं जा सकता जानवर जा सकते हैं, कुत्ते, बिल्लियां, गधे भी जा सकते हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसी कौन सी चीज हमारे दिमाग में बैठ गई है, जिस को धर्म के ठेकेदारों और पाखंडियों ने बैठा दी है, कि उस के नाम पर हम इन्सान को इन्सान समझने के लिये तैयार नहीं हैं। एक ऊंचा दूसरा नीचा, इस तरह का भेद-भाव है, झगड़ा होता है मारपीट होती है, मुकदमे चलते हैं। ऐसे जो लोग हैं, मन्दिर के पुजारी, धार्मिक मेलों को कराने वाले, जिन्होंने इस तरह अमानवीय अत्याचार किये हैं, उन को कड़े से कड़ा दण्ड दिया जाये ताकि फिर उन की हिम्मत न हो सके इन कानूनों को तोड़ने की। आज आजादी के बीस साल बाद भी यह कानून कड़े ढंग से लागू नहीं किये जा सकते, यह हमारे लिये अच्छी चीज नहीं है। हमें इसके बारे में सोचना होगा कि क्या बात है, क्यों इतनी निराशा देखी जाती है और क्यों इन लोगों को कड़ी सजा नहीं दी जाती है ताकि अपराध करने वालों की फिर हिम्मत न हो सके?

आज कई मन्दिरों के अन्दर हम ने देखा है

कि पुजारियों को तन्ख्वाह मिलती है, कई मन्दिरों के पास साधन हैं। लेकिन जिन मन्दिरों में हरिजनों का प्रवेश बन्द हो उन को सरकार अपने कब्जे में ले ले, जिन को प्राश्रय दिया गया, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर क्यो न हो, वहां पर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जिस में सब लोग जा सकें। जहां पर ऐसा नहीं होता उन की सम्पत्ति और जमीन सरकार अपने कब्जे में ले सकती है, इस तरह का कानून आप बना सकते हैं।...(व्यवधान)

दक्षिण भारत में भी बहुत सी बातें होती हैं और उत्तर भारत में भी होती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जो मेरी देखी हुई न हो। यह सुनी सुनाई बात नहीं है।

दूसरी चीज मैं मद्य निषेध के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ। गांधीजी ने आदेश दिया था कि इस देश में मद्य सेवन बन्द होना चाहिए। आजादी के बाद देश में मद्य निषेध हुआ। लेकिन बड़े दुख की बात है कि अब बहुत सी सरकारों ने मद्य-निषेध की अपनी कार्रवाई को स्थगित कर दिया है। मद्य निषेध के सम्बन्ध में ढीलापन कर दिया है। कहते हैं कि लोग इसको मान नहीं रहे हैं, इसलिए इसको ढीला किया जाये। मैं प्रार्थना करूंगा कि इसके लिए ऐसी व्यवस्था हो ताकि मद्य निषेध के मामले में कड़ाई हो। हमने सारे संसार में देखा है कि जो पैसे वाले लोग होते हैं वह कानून न रहने पर मद्य सेवन के सम्बन्ध में, भिखारी बन गये है। अगर हमारे देश में इसके लिये छूट दी गई तो हमारे अनुसूचित जाति के लोग और भी गरीब हो जायेंगे।

इस के बाद मैं अस्पृश्यता निवारण के सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। अस्पृश्यता का निवारण कानून के द्वारा ही नहीं हो सकता है। इस के लिए मानसिक तैयारी भी करनी चाहिए। प्रचार के साथ कुछ चीजें और भी की जा सकतीं हैं। नौकरियों के सम्बन्ध में यह किया जा सकता है कि जो जाति-बन्धन तोड़क संस्था को मानते हैं, जो जाति के बन्धन से ऊंचा उठकर अपना विवाह दूसरी जातियों में रचाते हैं उनको प्रमोशन दिया जाये, ऊंची जगहें दी जायें ताकि जाति-पांति के बन्धन तोड़ने में मदद हो सके।

साथ ही सर्वमिश्रित आबादी हो यह न हो कि हरिजनों को गांवों के बाहर बसाया जाये। उन की आबादी गांवों के अन्दर ही बाहर नहीं होनी चाहिये, और जो सवर्ण लोग उनके साथ रहते हैं उनको मदद दी जाये जिसमें वह सब लोगों के साथ मिल कर बैठ सकें।

इसके अलावा जो बसतिगृह हैं, अर्थात होस्टल्स, स्कूलों और कालेजों के, वहां पर इन लोगों को ज्यादा रहने का अवसर देना चाहिए जिस में कि सारे लोग एक साथ मिल कर बैठ सकें। जो भी इस तरह के बसतिगृह हैं उनमें हरिजनों का परसेंटेज निश्चित कर दिया जाना चाहिए।

इसके बाद हरिजनों की घरों की समस्या है। हम देखते हैं कि जगह-जगह हाउसिंग सोसायटियां बनती हैं वे मिल्स हों, हरिजनों के घरों की बुरी अवस्था है। उनकी ओर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। बहुत जगहों पर उनके घर जल जाते हैं, बरसात में गिर जाते हैं और उन के बच्चों को तक्लीफ होती है। मैं समझता हूं कि यह लाजिमी कर दिया जाना चाहिए कि हरिजन मकान खुला नहीं रहेगा। अगर इसके लिए आवश्यकता हो तो कानून बनाया जा सकता है। साथ ही सरकार को मकान बनाकर उनको उनमें बसाना चाहिए।

हमारे देश में जितना भूदान होता हैं या ग्रामदान होता है, उसके सम्बन्ध में हरिजनों की तरफ से पूछना चाहता हूं कि उसका क्या फायदा हरिजनों को होता है? कितने लोगों को जमीनें मिली हैं या घर मिले हैं, इस की छानबीन कर ली जाये। सरकार यह प्रबन्ध कर सकती है यह उनको भूदान से मदद मिले।

आखिर बात यह है कि हमारी प्रगति का मूल्यांकन होना चाहिए और हर साल इस की

[श्री कांबले]

रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए कि कितने लोगों को नौकरियां दिलाई गई, कितनों को जगह मिली है, कितनों को जमीन दी गई और कितनी खाली है, तथा कितनी बची हुई जमीन और दी जा सकती है। यह मूल्यांकन प्रति वर्ष होना चाहिए।

SHRIMATI SUSEELA GOPALAN (Ambalapuzha) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, the Department of Social Welfare deals with two important items. One deals with the backward classes and the other deals with general social welfare.

We are discussing this after twenty years of Indepedence. You all know that there was report in yesterday's press about the Andhra State Minister making a remark about the Harijans. This I think, is not an isolated instance. It is the culmination of what was taking place in Andhra in the last several months. One after another, so many incidents were brought to our notice. But our Central Ministers did not pay heed to them. A boy was murdered to death; one man was burnt and women ware even asked to walk on the street without clothes. I know our Home Minister has contradicted it. He got a report from the State Government that it is not correct. But after reading the Report of the Comissioner of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, I cannot believe the report given by the State Government because in that Report itself it is stated that in 3 or 4 instances, one after another, the report received from the State Government that might be the report they received from the State Department—was proved false. When they went to the State and enquired into that, that report was proved false. The report actually supplied by the State Government was false. So, I cannot believe the report which was given by the Andhra Government.

The Deputy Minister is a lady. It was her duty to go to the spot and enquire into the details of what is taking place. Even after twenty years of Independence, women are asked to walk naked in the street. We cannot even think about it. So many incidents are taking place and, I think, hundreds and thousands of cases are registered against the Harijans and they are talking about armed struggle and all that.

Likewise, you can see in Tripura, in the last so many years, the tribe people evicted from the area where they own their lands. In the name of refugees, they are now in a minority in that area. That is the policy pursued so far. I am sure, if Gandhiji was alive, he would have asked them to take up arms against that policy. That is the policy pursued by them and they all talk big about the backward classes and the welfare of the people.

The Report reveals so many glaring instances in so many parts of the country. In classes, the Harijan students are not allowed to sit with the others. There was an incident in Mysore or Maharashtra State; a lady teacher was beaten by the Head Mistress; that lady was a Harijan. I have read so many such glaring instances. In Panchayat Boards, some Harijan members are not allowed to sit in chairs. When institutions connected with the Government are doing these things, you can take concrete action, but no action is taken. Nearly three thousand incidents have been reported in the report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, But no proper action has been taken in any of these cases.

I think, untouchability is a cogniable offence under the Constisution, but whatever is done against the Harijans and the tribal people is tolerated. If they resist a little, then they talk loudly about armed struggle there. There is no use talking about these things. This is the crux of the problem. I would like to remind the Government that unless and until they give land to the Harijans and the tribal people and to those who have no property rights, there will be no salvation for these people; unless and until that is done, the lot of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes is not going to improve. So, that should be the first step to be taken in this direction, and then, have those welfare programmes and they will have an effect on the people.

Coming to the general welfare, I am very sorry to read in the Report that there

are about 10 million handicapped people in our country. I calculated the amount; I calculated up to Rs. 15 lakhs; it may come to Rs. 20 lakhs at the most. You have no money to spend for the handicapped, but you are giving Rs. 5 crores to Rajas as their Privy Purses. You have no money to spend for these poor people; there are only Rs. 20 lakhs for the 20 million handicapped people.

For so many other items, no money is spent. Even for research work, our Government is saying that no new research institution should be opened because there is no money, and thay have submitted a report to the USA Government and they have to approve it and implement in our country. After 20 years of independence, this is the position. This is a shame to our country.

Coming to the day-to-day work of the Social Welfare Board, in my own State I was a member of the Social Welfare Board for four years. It only helps the upper strata of women; for the lower people, no benefit is done. I had gone to several institutions when I was a member of the Board. If you go, without notice, the institution, you can see the actual position. During those four years, I used to go without notice, and nothing used to be there. If, however, you go with notice, then you can see everything. This is what was actually happening. Lakhs of rupees are sepent on this.

What is the position of the poor employees ? They were turned out; in 1962, there was retrenchment. Even now some of the employees are going to be retrenched. Only when that comes, they come to the State Government. But the State Government have no powers. They have They submitted a concrete proposal to the Central Government, so that they could take it under the State Department.

Now the Central Government say, 'If it is under the State Government, then we are not going to give you the salaries, only the project grant we will give'. Sir, you will understand that if the State Government also co-operate and work, then I think some substantial work can be done in the that field. Now when they say that they can give only the project grant and they are not prepared to give them the salary, I think it is sheer waste of money you are spending on the Social Welfare Board. Unless the entire work of the Social Welfare Board is changed, nothing can be done in our country.

Lastly, I want to point out that there were representations from our State of Kerala that 'Peruvannan', 'Velan' and 'Pullu', a very down-trodden section of the community—they have made a request to you—should be included in the list of Scheduled Castes, but so far nothing has been done by the Central Government. I request the Central Government to look into this matter.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I am glad to point out that several members have sent in slips. They will have a very rare opportunity to speak on the floor of the House because this is the last demand. Therefore I will accommodate some of them but those who have already spoken, not only once but on several occasions, should not take the trouble of speaking.

SHRI A. S. SAIGAL (Bilaspur) : Sir, many of us represent Harijans and Scheduled Castes and it is our moral duty that we should place their grievances before you. I think it is not correct on your part to exclude us.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have not excluded Harijans. These who have not spoken so far should be accommodated as far as possible.

SHRI RAM CHARAN (Khurja) : I request you to extend the time.

MR. DEPUTY-SPEAKER : That is not in my hands. Shrimati Ganga Devi.

श्रीमती गंगा देवी (मोहनलाल गंज) : उपाध्यक्ष महोदय, यह राष्ट्र के लिए और इस सरकार के लिए कितनी बड़ी लज्जा की बात है कि आज बीस साल की आजादी के बाद भी इस सदन में बैठ कर हम हरिजनों की समस्या पर विचार कर रहे हैं। यह समस्या केवल इस लिए पैदा हुई है कि उनका आर्थिक और सामाजिक स्तर इन 20 वर्षों में भी दूसरे उच्च वर्गों के समानान्तर पर नहीं लाया गया। इनको

[श्रीमती गंगा देवी]

पीड़ित किये जाने के समाचार आए दिन अखबारों में आते रहते हैं। आंध्र में, मध्य प्रदेश में, और दिल्ली में भी रोजाना इनको पीड़ित किया जाता है। आंध्र का तो रोजाना कुछ न कुछ समाचार हमारे सामने आ जाती हैं। उन को सभी जगह सताया जा रहा है। इसका विशेष कारण हमारी सरकार की कमजोरी है। अगर हमारी सरकार सख्त कदम उठाये तो किसी भी जगह हरिजनों को मारा न जाए, उनको नाजायज तरीके से सताया न जाए, उन को पीड़ित न किया जाए। अगर सरकार इस तरह के जो अनुचित काम करते हैं उनको यदि सख्त सजा दे तो इस प्रकार की घटनाएं बन्द हो सकती है। लेकिन अपराधियों को सजा नहीं दी जाती है। उन केसों को दबा दिया जाता है। जिन को मारा जाता है उनके साथ सरकार की स्वयं की कोई सहानुभूति नहीं होती है। तालाब में बड़ी मछली छोटी मछली को हमेशा निगल जाया करती है। इसी तरह से कमजोर व्यक्ति मारे जाते हैं, सताये जाते हैं। जिस तरीके से सरकारी मशीनरी चल रही है अगर उसकी यही रफ्तार रही तो कैसे आशा की जा सकती है कि हरिजनों की सामाजिक और आर्थिक रूप से उन्नति हो सकेगी, उनका स्तर ऊंचा उठ सकेगा। इस रफ्तार से तो सौ साल के बाद भी उनका स्तर ऊंचा नहीं उठ सकेगा, उनकी सामाजिक दशा में सुधार नहीं हो सकेगा, उनकी आर्थिक हालत ऊंची नहीं हो सकेगी। बहुत सक्रिय कदम इस सम्बन्ध में उठाने की तत्काल आवश्यकता है।

जहां तक आर्थिक पहलू का सम्बन्ध है हमारे पास सैंकड़ों एकड़ जमीन देश में पड़ी हुई है जो कि हरिजनों को दी जा सकती है लेकिन दी नहीं जा रही है। जमींदारी उन्मूलन के बाद जो जमीनें ली गई थी उनको हरिजनों को दिया जा सकता था। ऐसा अगर किया जाता तो खाद्य समस्या को हल करने में हमें कुछ सहयोग मिल सकता था। इससे गरीबों की गरीबी भी कुछ हद तक दूर होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जमींदारी उन्मूलन के बाद भी बड़े-बड़े फार्म लोगों के पास हैं, चार-चार दस-दस और बीस-बीस हज़ार एकड़ के फार्म लोगों के पास आज भी हैं। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। उनके पास वे जमीनें कहां से आई हैं। आज भूमिहीन किसान, भूमिहीन मजदूर, खेतीहर मजदूर और हरिजन एक-एक इंच भूमि के लिए तरस रहा है, परेशान है। क्या हमारी सरकार जो यहां पर सोशल सिक्योरिटी करती है, जो उनकी सोशल सिक्योरिटी की जिम्मेदार है, कभी इस चीज़ को वहां जा कर देखती है कि देश में क्या हो रहा है हरिजनों का शोषण किस तरीके से हो रहा है—कोई देखने वाला नहीं है। यहां बैठ कर हम स्कीमें बनाते हैं, योजनायें बनाते हैं, बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। यहां बैठकर कर हम बहुत से प्रश्नों का जवाब दे देते हैं, हम लोगों को खुश करने के लिए बड़ी-बड़ी रिपोर्टें आ जाती हैं यह हुआ, वह हुआ, खुश करने वाली सन्तुष्ट करने वाली रिपोर्टें आती हैं, लेकिन ये सब कागजी रिपोर्टें हैं, कोई कहीं जा कर नहीं देखता।

जो सैन्ट्रल गवर्नमेंट है, सैन्टर में हमारे जो लोग बैठे हुए हैं, जिनको हमने वहां बैठाला है, उनको चाहिए कि वे देश के कोने-कोने में जा कर देखें और वास्तविक रिपोर्ट हमारे सामने लायें, हमारे सामने सही रिपोर्ट आनी चाहिए, गलत रिपोर्ट नहीं आनी चाहिए। लेकिन वास्तविकता यह है कि बहुत सी रिपोर्टें हम लोगों को बहलाने के लिए तैयार की जाती हैं।

हरिजनों की आर्थिक समस्या सुधारने के लिए और उनका सामाजिक स्तर ऊंचा करने के लिए करोड़ों रुपये का बजट हम लोग पास करते हैं। क्या कोई यह कह सकता है क्या कोई इस चीज़ को मन्जूर कर सकता है कि वह सारा रुपया उनके वेलफेयर पर खर्च होता है, उनके आर्थिक विकास परे खर्च होता है। उस

में से पचास परसेन्ट से अधिक रुपया डिपार्टमेंट को मेन्टेन करने पर, अफसरों की बड़ी-बड़ी तनख्वाहों, टी० ए० और डी० ए० पर खर्च हो जाता है। मुश्किल से 1 परसेंट या 2 परसेंट उन के पास जाता है। जिनके लिए आज हम स्कीमें बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं, उनको मालूम भी नहीं है कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं।

देश के अन्दर अगर हम इस असमानता को दूर करें तो एक बहुत बड़ी खाई हम लोगों के बीच में पड़ती है—हरिजन और उच्च वर्ण के बीच में जो खाई है, जब तक उसको दूर करने का प्रयत्न हम नहीं करेंगे, जब तक हम उस को नहीं पाटेंगे इस को सिर्फ सरकार ही पाट सकती है, अगर वह इस काम में दिलचस्पी ले अगर ईमानदारी के साथ उसको पाटने का प्रयत्न करें, तो यह समस्या आसानी से हल हो सकती है।

सरकारी नौकरियों में हरिजनों के साथ पक्षपात किया जाता है। जो शेडयूल्ड कास्ट के कैन्डीडेट होते हैं, उन को ज्यादा क्वालीफाइड होने पर भी रिजैक्ट कर दिया जाता है। कोई न कोई बहाना कर के, उन से कम क्वालीफाइड आदमी को उन जगहों पर रख लिया जाता है। दूर जाने की बात नहीं है—मैं आपको देहरादून का उदाहरण देना चाहती हूं। वहां पर हमारे आयल-एण्ड-नैचुरल गैस कमीशन का हैड आफिस है। वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर्ज की 3 रिज़र्व्ड पोस्टें सन1965 में एडवर्टाइज़ हुई थीं, लेकिन आज तक उन पर किसी को नहीं रखा गया हैं। अनेकों चिट्ठियां वहां की यूनियन ने मेहता साहब को लिखीं, लेकिन आज तक उन का सन्तोषजनक उत्तर उन लोगों को नहीं मिला। मुझे सन्देह है कि वे पोस्टें भी इसी तरीके से फिल-अप हो जायेंगी और शेडयूल्ड कास्ट के कैन्डीडेट्स मुंह देखते रह जायेंगे। इस प्रकार की और भी अनेकों बातें हैं।

शिक्षा के सम्बन्ध में मैं खास तौर से कहना चाहती हूं। हमारे लड़के और लड़कियां जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन को सही तरीके से वज़ीफ़ा नहीं मिलता। वे बेचारे एप्लाई करते करते परेशान हो जाते हैं, लेकिन उनको समय पर वज़ीफ़ा नहीं मिलता और अगर मिलता भी है तो साल भर खत्म होने के बाद। इस कारण से जो लड़के और लड़कियां अपने पास से नहीं खर्च कर सकते हैं, वे बीच में ही बैठ जाते हैं। मैं यह चाहती हूं कि यदि उन को देना है, तो ठीक तरह से वज़ीफ़ा दें, समय पर दें, वरना बन्द कर दें। इस प्रकार की भीख हम को नहीं चाहिये। आप हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, हम अपना अधिकार मांगते हैं।

स्कालर शिप बोर्ड आफ शेडयूल्ड कास्ट्स एण्ड शेडयूल्ड ट्राइब्स पहिले सैन्टर में होता था। लेकिन अब इस प्रकार के वजीफों का वितरण स्टेट्स के हाथ में कर देने से वहां पर धांधलीबाजी चल रही है। मैं चाहती हूं कि वह स्कोलरशिप बोर्ड फिर से सेन्टर में आये और बच्चों को ठीक तरह से वज़ीफे दिये जायं। वज़ीफे की धनराशि जो पहले निर्धारित की गई थी उस समय इतनी मंहगाई नहीं थी, अब मंहगाई इतनी ज्यादा हो गई है और एजूकेशन इतनी कौस्टली हो गई है कि उस में पूरा नहीं पड़ता। मैं चाहती हूं कि वज़ीफे की धनराशि को बढ़ाया जाय।

अब मैं कुछ सोशल वेलफेयर बोर्ड के बारे में कहना चाहती हूं। कई लोगों ने यहां पर कहा, हमारी बहन सुशीला गोपालन ने भी कहा और मैं भी इस बोर्ड में दो साल रह कर आई हूं—हम देखते हैं कि इस बोर्ड की जो एक्टीविटीज़ हैं, वह शेडयूल्ड कास्ट्स के बीच में बिलकुल नहीं है। लाखों-करोड़ों रुपया खर्च होता है, लेकिन जितनी भी एक्टीविटीज़ हैं, वे उन लोगों में हो रही हैं जो आलरेडी सोशली-वेल-टु-डु है। सोशल वेलफेअर किस पर होना चाहिये? उन लोगों पर जो कि सोशली बैकवर्ड हैं, जो दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, यदि उन का सोशल अपलिफ्ट नहीं होता है, तो इस विभाग का होना बेकार है। इस में जो पैसा खर्च हो रहा

[श्रीमती गंगा देवी]

है, बिलकुल बेकार है, या तो उन लोगों में काम होना चाहिये, जितने भी कन्डेन्स्ड कोर्स हैं, बाल-वाड़ियां हैं, महिला मंगल योजनायें हैं, कहीं भी हरिजन बस्तियों में नहीं चल रही हैं। कोई भी स्कूल आप हरिजन बस्ती में नहीं दिखा सकते, कोई भी कन्डेन्स्ड कोर्स हरिजनों को नहीं दिया गया है, कोई बाल-वाड़ी हरिजनों के बीच में नहीं चल रही है; उन के बच्चे मुंह ताकते रहते हैं, उन के लिये कोई स्कूल नहीं है, कोई खेलने का स्थान नहीं है। इस प्रकार के सोशल वेलफेअर बोर्ड के लिये हम पैसे की मांग करते हैं। यदि यही हालत रही, तो हम इस चीज का विरोध करेंगे, क्योंकि हम क्षेत्र को देखते हैं, हम आम पब्लिक में घूमते हैं, हम पब्लिक वर्कर हैं और हम देखते हैं कि पब्लिक को कितनी तकलीफ हो रही है। आज हरिजन बहुत तरह से कुचले हुए हैं, जब तक उन के लिये विशेष रूप से कोई काम नहीं किया जायगा, तब तक यह सब बेकार होगा।

गांवों में कर्ज लेने की प्रणाली इस प्रकार चलती आ रही है कि जो आदमी किसी जमीदार से या बड़े किसान से पचास रुपये भी ले लेता है, तो वह हमेशा के लिये उस का गुलाम हो जाता है, हमेशा के लिये वह उस के हाथों में बिक जाता है। क्या आज तक कोई ऐसी अर्थ व्यवस्था आपने कायम की है कि जिससे हमारे हरिजनों को इस प्रकार से लेनदेन में या अपनी आर्थिक समस्या को सुलझाने में मदद मिलती हो। मैं चाहती हूं कि उन के लिये रुपये-पैसे के लेनदेन का इन्तजाम गांव में सरकारी तौर पर अवश्य होना चाहिये।

एक विशेष बात मैं और कहना चाहती हूं। आजतक हरिजनों के लिये जोकि इस देश के सैकड़ों सालों से निवासी हैं, उन के हाउसिंग का कोई इन्तजाम नहीं हुआ। उन के रोजगार का अब तक कोई इन्तजाम नहीं हुआ। सरकार ने, जब हमारे देश में शरणार्थी आये, उन के लिये विशेष महकमा खोला और एक निर्धारित समय के अन्दर उन के लिये मकान बनाये, उन को जमीनें मिलीं, उन को रोजगार मिले, हर चीज उन को मिली मेरा मतलब यह नहीं है कि उन के लिये यह सब न किया जाय, उन के लिये अवश्य किया जाय लेकिन अगर हरिजनों के लिये भी आप इसी तरह से करें, तो निर्धारित समय के अन्दर आप इन की समस्याओं को भी हल कर सकते हैं।

एक बात मुझे और कहनी है सन 1952 में शेडयूल्ड कास्ट कमिश्नर ने यह सिफारिश की थी सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट हर प्रदेश के अन्दर हरिजनों के लिये जो अनुदान हैं, उस को उनकी आबादी के अनुपात से ईयर-मार्क कर दे और उन के वेलफेअर पर उतना पैसा खर्च किया जाय। लेकिन इस प्रकार का कदम अभी तक किसी प्रदेशीय सरकार ने नहीं उठाया है—इस के लिये आप को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये।

अभी तक पीने के पानी का कोई इन्तजाम नहीं हुआ है। छुआछूत उसी तरह से बरकरार है। हम ने अनटचेबिलिटी रिमूवल के लिये कानून बनाया, लेकिन हम कहीं भी नहीं देखते कि उस का पालन हुआ है। आज भी कुओं पर हरिजनों को नहीं चढ़ने दिया जाता, मन्दिर और धर्मशालाओं में हरिजनों को नहीं जाने दिया जाता—इस चीज की ओर आपको विशेष रूप से देखना है। जब आपने उन के लिये कानून बनाया है तो उस का अवश्य पालन होना चाहिये।

SHRI K. HALDAR (Mathurapur) : The high ideals of social, economic and political justice and equality of status were given to all sections of society in the Constitution. It was further emphasised that the State shall promote with special care the educational and economic interest of the weaker sections of people and in particular, the scheduled castes and scheduled tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation.

Now, we are to scrutinise the pious wishes of the Centre and the States, whether these are implemented or not. On the 8th August 1967, the Centre tasted the first defeat after 20 years of administration on a motion regarding the Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. After that setback, two Ministers from the Scheduled Castes and Scheduled Tribes were taken in. To satisfy the members, five zonal offices have come into being with effect from 1 February, 1968.

In the name of reorganisation, some high posts with a large number of staff are functioning in several States, I know some of these officials are against the safeguards for the backward communities. Then how can these oppressed people expect justice from these persons? As a result, year after year, reserved posts are not filled on the flimsy ground that suitable candidates are not available. Only a few white elephants are maintained at the cost of Government.

In the last UF Ministry of West Bengal, the Minister of Tribal Welfare complained that not a single person belonging to these oppressed classes was posted in his department. This state of affairs generally disappoints the people who go for protection from the officers.

I have got innumerable complaints from candidates posted in various departments of Government for being promoted or confirmed in due time. They are even demoted in some cases due to punishment on unknown grounds. I know personally an employee who detected a case of corruption, and the culprit was punished. But the employee was also punished for not reporting the incident to higher authority previously.

Regarding promotions, I quote a circular of the Railway Board which reads :

> "While filling up the post on promotion, however, candidatee of S.C. and S.T. communities should be judged in a sympathic manner and arrangement should be made where necessary, to give to such staff additional training and coaching to bring them up to the standard of others".

But nowhere is the rule followed.

We condemn the South African and American Governments for racialism. But what is happening in our country when we see Harijans burnt alive, when Muslims are butchered here and there in broad daylight. Our Congress Government preaches truth and non-violence but in practice we see that no less a person than a Congress Minister in Andhra implecated in a heinous utterance against Harijans. So to speak of socialist society is only to deceive the people and nothing else.

Baster is a tribal area which is as big as Kerala State. People still live there in a nomadic state ill-fed and unclad, though natural resources are abundant there.

Some factories are established merely to exploit the people as cheap labour. Now they are being retrenched from the factories.

In a capitalist society, it is not possible to ameliorate the grievances of the common people, not to speak of the backward communities. So it is natural that one section will exploit the other sections. Those people are fighting for distribution of land. Land which is not distributed among those people should be immediately distributed.

This will help to improve the economic conditions of these people and place them in civilised society.

The people who work in the fields and factories are mostly Scheduled Caste and Scheduled Tribes. So, if the land if properly distributed and the workers' service conditions are improved, many of the anomalies in society can be removed.

The Government has totally failed in this matter to satisfy only the vested interests. So, if the Government do not come forward in this primary work and try to give some relief, only the people will go forward with their own strength and establish their rights.

SHRI KARTIK ORAON (Lohardaga) : Sir, bats off, to the framers of the Constitution who had framed the Constitution in such a way, that if the provisions of the Constitution had been implemented in the proper way, I think the Scheduled Castes and Scheduled Tribes of India whould have merged in the national life of the country by now, but in the light of the incidents that have recently come to light, the atrocities against the Harijans and of course

[Shri Kartik Oraon]

in different forms against the tribals also, I think that instead of going forward we are going backward. I think that though they should have been things of the past, yet, I am rather shocked and perhaps everybody will be shocked, that this is just a beginning of what is going to happen in India tommorrow. I must say that this is a very sad commentary of the performance of the Social Welfare Department, no matter in what form this has been functioning. It is rather shameful that even after 20 years we are in a state of helplessness and this should shock the conscience of almost every Indian if at all there are Indians in India.

Ours is a secular State in which there is no diserimination made on grounds of caste, creed, religion and belief. But the Government of India have already created a precedent by bringing about a discrimination of religion in the case of Scheduled Castes. Why ? Just to protect a particular community from a more aggressive, vocal and advanced force, i.e., those converted to other religions.

I want to bring to the knowledge of this House that so far as the tribes of India are concerned, the Government have been really very, very hard on them, and I think the Deputy-Speaker will bear with me and he may not be so hard with me today at least. What I am going to say is that there has been a sort of misunderstanding in the minds of the people in this country and perhaps even in the minds of great leaders : they think that the tribes have no religion of their own. In this connection I would like to say that even the British Government were very fair to the tribals because they knew who the tribals were. They knew what the tribals religion was and is. In the Census Report of 1911, there has been a specific mention as to what the tribal religion is and who are the tribes. In that report they have said this : animism has been defined in the Census Report.

> "Animism is the term used to cover the miscellany of superstitions which prevail among primitive tribes in all parts of the world. These tribes are very vague in their religious conceptions but then all agree and believe in the presense on earth of a shadowy crowed of powerful and malevolent beings, who usually have a local habitation in a hill or patch of primeaval forest and who interest themselves in the affairs of men. Illness and misfortune of all kinds are attributed to their influence".

I would like to be very brief. The report further says :

> "There is also a general belief in magic and witchcraft. Wizards are employed to ascertain the cause of troubles and to remove it either by incantation and exorcism or by placating the offended ghostly being by a suitable sacrifice" ; and things of that nature.

> "From that point of view of census, it will suffice to say that animism is used as the name of category to which are relegated, all the pre-Hindu religions of India".

18.00 hrs.

Pre-Hindu religions of India—that is the tribal religion. Many anthropologists, social workers and advocates of tribal welfare say that tribal religions have never been defined. If they are really interested in the tribes, they would have found what tribal religions are. In various parts of the country, the tribes are following the tribal religion.

About the Rengmas, one BDO of Nagaland has written thus :

> "The non-Christains believe—

Importance has been given to the Christians ; that is why, he says "non-Christians"—

> "The non-Christians believe is some other Gods and evil spirits whom they consider inferior to the supreme creator Sunngigu. Special mention can be made of Sungperi—Peri means snake—which is considered to be an evil spirit and harmful to mankind. It is also believed by them that there are some other benevolent spirits (Gods) viz., Byeseginyu, Thokhonyu and Ozurikinyu, who are in charge of crops, hunting and water respectively.

"The Rengmas who follow the traditional religion have belief in superstitions and they believe in evil spirits. If a person falls sick after returning from forest, field or a tour, the family members offer eggs or a chicken on the path by which he or she returned to appease the evil spirit. If the persons is still not cured, the elderly persons sit around his bed, pray for him and advise the family members to sacrifice pigs or Mithun to save the life of the patient. Such beliefs in evil spirits is fast dying away with the conversion to Christianity".

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have to accommodate some more hon. members. He should try to conclude now.

SHRI KARTIK ORAON : The Thangul Nagas of Manipur also profess a traditional religion.

I will just read one passage from a letter written by Mr. Barkataki, the Deputy Commissioner of Kohima, to the noted anthropologist, Dr. Verrier Elwin. It is published in this book *Kamapura* at page 26 :

"The Angami Nagas are now having their big *Sacreni Puja* and I have been thoroughly enjoying myself taking part in their feasts and drinking bouts. It pains me deeply to think that all this colour and vitality are fast disappearing with the conversion of the Nagas to Christianity. I am writing to you about this, because I understood from Harper that you hold similar views. I had the the opportunity of studying the effect of conversion on the Lushais at close quarters. Apart from the denationalising influence of conversion, I feel that it is striking at the roots of a way of life which is no way inferior to any other. I feel that the foreign missionaries in the hills districts are committing a crime against humanity. If I had the authority, I would have sent them away lock, stock and barrel within 24 hours".

What is happening today in Bihar ? We have got in each village big groves of trees. There we have got Sarna Devi. In Madhya Pradesh we have Kher Mai. In Gujarat we have Devi Matha. In Orissa also we have Devi Matha. We worship this Devi Matha yearly and it is, called Sarnah Pooja in Bihar. This worship is done every year Chait, Shukla Paksh 3. What is happening today in Chotta Nagpur. It is here that where the Christains dominate these places of Sarnah places of worship of the adivasis heve been converted into graveyards, The trees in these groves have been cut to build churches. If they did believe in co-existence and religious tolerance they would not have done anything of this nature.

Of late the married tribes after conversion are made to marry, again no matter whether they are 50 years or 60 years old. That means the previous marriage is null and viod. On the one hand they feign to believe in the tribal culture and tradition and on the other they make the converted Christians to marry again. Very recently there was a Sarhul Pooja at the residence of Shri Jaipal Singh. What I want to point out is that this fake religious tolerance should not be a instrument of exploitation. The tribals in India constitute 90 per cent of total tribal population. Those who are converted are 10%, we accept them as our brothers but they should have religious tolerance. Whatever we the tribe get from the Government, 90 per cent of that is being by the christians and we get 10 per cent. We are trying to remove this disparity. Never in the history of India can this disparity be cut down.

I also want that there should be uniformity. There should be no discrimination when you have made a discrimination in the case of Scheduled Castes ; please do it in the case of Schedule Tribes also. If you cannot do that, let there be no Scheduled Castes and no Scheduled Tribes, let there be only one class of Indians. When they get converted,—you pay more attention—you are helping the Christians and not the tribal people. Even IAS officers get converted. That way the whole tribal people will be converted and there would be a big Nagaland. You are worried about 2.5 lakhs in the Nagaland, but this will become a Nagaland of 2,70,00,000. You are putting the tribal people along with that class, that section of people who are not only emotionally linked with the Christians of India but who are

[Shri Kartik Oraon]

connected with the rest of the Christian world. Why do you put a dwarf with a giant and say that you are serving the tribals ? This position has to be removed. I am not saying this because I am against Christianity. I only want to say that we will not be able to help the tribals and to develop them until we introduce equity. Let these people get there due share of help.

श्री शिवचंडिका प्रसाद (जमशेदपुर) : अभी माननीय सदस्य सरहुल पर्व की बात यहां पर कर रहे थे । यह पर्व छोटा नागपुर के आदि-वासी मानते हैं.....

MR. DEPUTY-SPEAKER : No controversy, please.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Why are you not calling Shri Onkar Lal Berwa to speak ?

SHRI SHEO NARAIN : He was called but he was not in the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER : He will get his time, I assure you.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : It is all right that he will get the time ; but every time you change the order.

MR. DEPUTY-SPEAKER : You are not aware that he was not here when he was called... (*Interruption*)

SHRI SHIV CHANDIKA PRASAD : On a point of information, Sir.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please resume your seat. On that issue you cannot raise a controversy. He expressed certain thoughts, sentiments, emotion or whatever it is. Try to understand him.

18.11 hrs.

[Mr. Speaker *in the Chair*]

SHRI BAIDHAR BEHERA (Jajpur) : **Mr. Speaker, Sir, the discussion on the Social Welfare going on today has been going on for the last twenty years of Congress rule. The discussion is confined only to speeches and no action is taken thereon. Although the main object of this department is to remove untouchability, this department has itself become untouchable amongst other departments, instead of being able to remove untouchability. Nobody takes the decisions of this department into consideration and no other department cares for this department. No department complies with the directions and promises of this department. The conditions prevalent in the State level is worse. Crores of rupees have been granted to this department since its inception, but in effect it has not been able to do anything for those who are meant to be benefitted thereby.

So far no effective economic, social and cultural improvement could be effected for the Harijans and the Adivasis. They still grope in the same darkness as before.

Untouchability, the removal of which is the main constitutional responsibility of this Ministry, is still strong. The Harijans and Adivasis even now continue to be untouchable as in the days past—rather the intensity has become deeper. These neglected classes are still deprived of equal privileges and rights in matters of temple-entry, service in hotels, use of wells etc. A responsible Congress Minister of Andhra Pradesh has loudly proclaimed the treatment that should be meted out to the Harijans. The incident of burning a Harijan boy alive in the same State has often been discussed in this House. I do not want to repeat it. If this be the attitude of the higher classes, the dark future of these oppressed classes and the consequential effect on the social condition of the society as a whole can very well be imagined.

These classes have been suffering in the mater of education. Many pupils of these classes have been deprived of education for want of funds and are now unemployed. The facility of financial help extended to them has been discontinued since the Chinese aggression ; the reason advanced is want of funds due to increase in the expenses on military operations. As a result lakhs of pupils have had to discontinue their edu-

**Translation of speech delivered in Oriya.

cation. The same policy is being followed even now. Those who had received some education have also been deprived of their rightful place in society. This is evidenced by the report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the year 1966-67. The Home Department of the Union Government had notified in their notification No. 1/4/60 R.P.S. dated 5.3.1960 that the scheduled castes and scheduled tribles would be entitled to reservation of 12% and 5% respectively of posts on all-India basis and to departmental promotion at the rate of 16.2/3% and 5% respectively on the same basis. This quota is not being fulfilled on various pretexts. One of the reasons advanced for this is that the Harijan and Adivasi candidates are unable to compete in all India examinations. Sir, please consider how a Harijan or an Adivasi boy educated in the Ashram or Sevashram School can be a fair competitor against another boy educated in public schools and nurtured by private tutors ? How can both be compared on the same level and from the same standard ? Hence to remove this discrimination either the Ashram or Sevashram schools meant for the Harijan and Adivasi pupils be converted to public schools, or all the other schools be converted to Ashram or Sevashram schools. The justification for such a proposal will be evident from an examination of the standard of education imparted in the Ashram and Sevashram schools in Orissa.

Nothing has been done to improve the economic codition of these classes. Although these classes are mostly engaged in agricultural productions, most of them are landless. It is reported that the extent of surplus land has been determined in the States, but there has been no distribution of such land as yet. In many places the Adivasis have been deprived of their land for accommodating other organisations and colonies. The Adivasis who have been evicted for the resettlement scheme at Dandakaranya have not yet been resettled. The local Adivasis have not been given equal advantage along with the refugees from the scheme.

There have been some paper plans for improving the economic condition of the Harijans and the Adivasis, but instead of any improvement in their conditions, their real income has gone down. They have been neglected in industrial employment and have been forced to work as agricultural labour as before. The condition is in no way an improvement on their condition in the middle ages.

Therefore I oppose the demands of this Ministry.

कुमारी कमला कुजूर (पालामऊ) : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आप को धन्यावाद देती हूं कि आप ने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैंने प्रयास तो बहुत दफे किया लेकिन समय नहीं मिल सका। आज थोड़ा समय मिला है, इस लिए मैं आप की आभारी हूं।

आज आजादी मिले हुए बीस साल हुए, लेकिन बहुत अफसोस होता है कि आज हमारी दशा वही की वही बनी हुई है। मैं सोचती हूं कि बीस साल में जितनी प्रगति होनी चाहिये थी वह हो नहीं पाई। बीस सालों में न तो आर्थिक उन्नति की बात हुई, न राजनीतिक और न ही सामाजिक जब हम सामाजिक स्तर पर जाते हैं, तो देखते हैं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदि जातियों की अवस्था वही है जो पहले थी बल्कि पहले जो थी उससे और भी गिर गई है।

आप आन्ध्र की हालत को देखें। वहां पर महिलाओं की क्या हालत हुई है ? उन्हें नंगा करके घुमाया गया है। बच्चे को जिन्दा जलाया गया है और तरह तरह के अत्याचार हरिजनों पर किये जा रहे हैं। उनकी हत्यायें की जा रही हैं। इन सब बातों को देख कर यही लगता है कि हम आगे बढ़ने के बजाय पीछे जा रहे हैं। सरकार पैसा खर्च तो जरूर करती है लेकिन पता नहीं किस तरह से वह खर्च होता है, क्या उसका सदुपयोग भी होता है या नहीं होता है ? इस तरह की जो घटनायें हो रही हैं इनको आपको सख्ती से रोकना चाहिये।

शिक्षा को आप लें। इन जातियों के लोगों के लिए स्थान सुरक्षित हैं लेकिन जब ये एडमिशन लेने के लिये जाते हैं तो कह दिया जाता

[कुमारी कमला कुमारी]

है कि सीट नहीं है। मैं आपको इतनी ही मिसाल बतलाती हूँ। यह आज की तो नहीं लेकिन काफी पहले की बात है। मैं डबल एम ए करना चाहती थी और मैं इसके लिए एडमिशन लेने गई। मुझे रांची विश्वविद्यालय के डिप्टी रजिस्ट्रार ने कहा कि आप ही क्यों डबल एम ए करना चाहती हैं किसी और को भी मौका दें। अब आप देखें कि रांची डिस्ट्रिक्ट में कोई भी हरिजन छात्रा एम ए पढ़ रही हो, शायद ही आप को यह चीज देखने के लिए मिले। और तब तो कोई थी ही नहीं। लेकिन एक छात्रा जो पढ़ना चाहती भी थी उसको इस तरह की बातें कह कर रोका गया। बाकी जो दूसरे विद्यार्थी हैं उनकी तो बात ही क्या की जा सकती है।

हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब है। जो खेतीहर मजदूर हैं उनको भूमि तो अवश्य दी गई है लेकिन ऐसी भूमि दे दी गई है जोकि बंजर है, जिस में न तो जुताई हो सकती है और न ही खुदाई हो सकती है। नाम के लिए उनको जमीन दे दी गई है लेकिन वास्तव में उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। इस तरह की जो बातें हैं इनको कोई देखता ही नहीं है।

संविधान तो बन गया है और उस में अस्पृश्यता को मिटाने के लिए प्रावधान भी कर दिया गया है लेकिन वह सिर्फ किताबों तक ही सीमित हो कर रह गया है। जितना उसे सफलीभूत होना चाहिए था उतना नहीं हो सका है। अगर इन लोगों के साथ अस्पृश्यता बरती जाती है और मामला अदालत में जाता है तो इसको साबित करने के लिए गवाह ही नहीं मिलते हैं। अगर कोई उच्च जाती का व्यक्ति इनके साथ दुर्व्यवहार करता है तो इनको न तो इसको साबित करने के लिए गवाह मिलते हैं और न ही इनके पास इतना पैसा होता है, इतने साधन होते हैं कि ये अदालतों में जा कर केस कर सकें। इनकी कहीं कोई सुनवाई ही नहीं होती है। विधान किताबों तक ही सीमित हो कर रह गया है। उसे विकसित होने का मौका ही नहीं मिल सका है। उस पर अमल ही नहीं आज तक किया जा सका है।

और भी बहुत सी बातें हैं छोटी मोटी जिन की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। आप देखें किस तरह से इनके साथ अत्याचार होते हैं। कल ही हमारे यहां एक व्यक्ति पालामऊ जिले का आया था। उन के चाचा चौकीदारी का कार्य करते थे। वहीं के एक सम्भ्रान्त व्यक्ति की लड़की ने आत्म-हत्या कर ली। उन्होंने चुपचाप उसे जलाने की कोशिश की। इस चौकीदार ने न्याय प्राप्त करने के लिए थाने में जा कर इसकी रिपोर्ट की। अब आप देखें कि उसको इसका किस तरह से फल भुगतना पड़ा। पन्द्रह दिन के बाद डकैती का केस बना कर उसको उसमें फंसा लिया गया और उसे दस साल की सजा कर दी गई। इस तरह के बहुत से अत्याचार इन पर हो रहे हैं जिनकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है।

आप रुपया तो देते हैं लेकिन वह रुपया किस मद में खर्च होता है, किधर जाता है यह पता ही नहीं चलता है। अब सरकार सैपेरेट कोलोनीज हरिजनों के लिए या आदिवासियों के लिए बनाने जा रही है। क्या आप समझते हैं इस तरह से अस्पृश्यता मिट सकती है। इससे तो आप अस्पृश्यता को बढ़ावा ही देंगे। अगर आप को अस्पृश्यता को मिटाना है तो आप ऐसा करें कि एक ही कालोनी में पांच प्रतिशत उच्च वर्ग के लोगों को, पांच प्रतिशत निम्न वर्ग के लोगों, पांच प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोगों को, पांच प्रतिशत अनुसूचित आदिम जाति के लोगों को रखें ताकि वे आपस में मिलें और उन में सदभाव पैदा हो, उन में मेलजोल पैदा हो।

आदिम जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की महिलाओं को कितनी तकलीफ है, इसको भी आपको देखना चाहिये। वे मजदूरी कर सकती हैं, उनके पास शारीरिक शक्ति है लेकिन वे बेरोजगार हैं। उनको कहीं मजदूरी

नहीं मिलती है। वे पिसती जा रही हैं। कई केसेज में तो ऐसा भी हुआ है कि वे गलत रास्ते पर पड़ गई मजबूर हो कर और वे समाज की नजरों में गिर गई। ऐसे काम भी वे कर बैठती हैं जिन के कारण उन पर लांछन लगाये जाने लगते हैं और ये महिलायें अपना जीवन इधर उधर व्यतीत कर रही हैं। अन्त में उन्हें वैश्यालयों की तरफ भी जाना पड़ जाता है। इस वास्ते आपको महिलाओं को रोजगार देने का प्रबन्ध करना चाहिये। आपको ऐसा कुछ करना चाहिये कि वे अपनी मर्यादा को बचाये रख कर काम कर सकें और कोढ़ का टीका उनके सिर पर न लगे।

हरिजनों के लिए नौकरियों में सीट्स तो रिजर्व आपने कर दी हैं लेकिन उन को जगहें मिलती नहीं हैं। पढ़े लिखे भी होते हैं, क्वालिफाइड भी होते हैं, डिजर्व भी करते हैं लेकिन फिर भी उनको नहीं लिया जाता है। उनके लिए साढ़े बारह प्रतिशत सीटें रिजर्व हैं लेकिन कह दिया जाता है कि कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिलता है। जब इसकी रिपोर्ट शैड्यूल्ड कास्ट कमिशनर के पास जाती है और बताया जाता है कि कितनी पोस्ट्स भरी गई हैं और कितनी नहीं भरी गई हैं तो वहां इसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। मैं आपको दिल्ली के ही एक व्यक्ति की मिसाल देती हूं। एक यहां शैड्यूल्ड कास्ट का लड़का है। वह सैकेंडरी पास है। वह चपरासी के पद पर था। एक आफिस में काम करता था। अफसर उससे घरेलू काम लेना चाहता था। वह चाहता था कि वह कभी कभी सब्जी बब्जी ला दिया करे, कभी कभी बीबी की साड़ियां धो कर दिया करे, पालिस कर दिया करे। बाद में ऐसा हुआ कि इसको तो रिट्रेंच कर दिया गया और एक दूसरे बैकवर्ड क्लासिस के आदमी को रख लिया गया जो उनके घर का काम इत्यादि कर दिया करता था। यह व्यक्ति टाइप भी जानता था लेकिन इसको रिट्रेंच कर दिया गया। सात महीने से यह व्यक्ति यहां दिल्ली में न्याय प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है लेकिन इसको न्याय नहीं मिल रहा है। यह दिल्ली की सड़कों की खाक छानता फिर रहा है। लेकिन इसको नौकरी नहीं मिल रही है। यह जब हालत है तो मैं कैसे कहूं कि सामाजिक तौर पर इनको ऊपर उठाया जा रहा है या कोई ऐसा विभाग या संस्था भी है जो हमारी उन्नति करना चाहती है और हमें आगे बढ़ाना चाहती है। रिपोर्ट तो बड़ी बड़ी छाप दी जाती हैं, दिखावे के लिए तो बहुत कुछ कर दिया जाता है, आश्वासन तो दे दिये जाते हैं लेकिन वास्तव में कुछ होता नहीं है। जितने भी अनुसूचित जातियों के लोग हैं या आदिम जातियों के लोग हैं वे तो इसी आशा में दिन गुजार रहे हैं :

यहि आशा लटकयो रहयो अली गुलाब के मूल
आई है बहुरी बसन्त ऋतु
खिलिहैं इन डारन में फूल

यही हिसाब यहां है। पता नहीं जिन्दगी कब तक है और कब तक चलेगी। कुछ गुजर गई है और कुछ बाकी है। आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसकी हालत क्या होगी कुछ पता नहीं। जो पीढ़ी गुजर गई है उसकी हालत थोड़ी अच्छी थी। आने वाली पीढ़ी की हालत क्या होगी, यह कहना बड़ा मुश्किल है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस सब की अच्छी तरह से छानबीन होनी चाहिए। एक अलग से कोई समिति बननी चाहिए। फ्री एजुकेशन का प्रबन्ध होना चाहिए। साथ ही साथ ऐसी कालोनी बननी चाहिए जिसमें उच्च वर्ग के निम्न वर्ग के, आदिम जातियों के, अनुसूचित आदिम जातियों के लोग हों। तभी अस्पृश्यता मिट सकती है। अन्यथा यह कभी नहीं हो सकता है कि इन जातियों के लोगों को आप उन्नति के पथ पर ला सकें।

श्री ओंकार लाल बेरवा (कोटा) : हमने इस अनुसूचित और अनुसूचित आदिम जाति मंत्रालय को ऐसा बना दिया कि जैसे कोई अनाथ बच्चा हो। कभी तो इसको गृह मंत्रालय की गोद में डाल दिया जाता है, कभी प्लानिंग

[श्री ओंकार लाल बेरवा]

मंत्रालय की गोद में और कभी खाद्य मंत्रालय की गोद में। इसको हम किसी न किसी के साथ चेटे रखते हैं। मैं चाहता हूं कि इसका एक अलग मंत्रालय होना चाहिए ताकि इन लोगों की सुनवाई हो सके, कोई इनकी पूछ ही सके। सतरह करोड़ आबादी शैडयूल्ड कास्ट और शैडयूल्ड ट्राइब्ज के लोगों की है। क्यों नहीं इनके लिए अलग से मंत्रालय होता है। मैं चाहता हूं कि इनके लिए अलग से मंत्रालय बनाया जाए।

दूसरी बात यह है कि संविधान के जो निर्माता कहे जाते हैं यह कितनी शर्म की बात है कि उनका सैंट्रल हाल में फोटो तक नहीं है। यह गवर्नमेंट के लिए बहुत लज्जाजनक बात है। उनका फोटो सैंट्रल हाल में होना चाहिए।

आपने इनके लिए 1959 से लेकर 1966 तक एक अरब रुपया खर्च किया है। लेकिन 1966-67 में आ कर आपने 33 प्रतिशत और 1967-68 में 35 प्रतिशत की कटौती कर दी है। यह क्यों की गई है? क्या इनका उत्थान हो गया है? रोजाना हम अखबारों में पढ़ते हैं और कानों से सुनते हैं कि इनकी उन्नति नहीं हुई है।

जहां तक रिजर्वेशन का सम्बन्ध है, सीटें भर ली जाती हैं और कह दिया जाता है कि अब कोई जगह खाली नहीं है। ऐसी रिजर्वेशन का क्या फायदा। दो सौ सीटें हुई और उन को आपने भर लिया और इनको इनका कोटा नहीं दिया तो उस रिजर्वेशन का क्यों फायदा। आप देखें कि कितनी जगहें इनको मिली हैं। 1-1-59 से आप देखें कि ए क्लास की 10403 पोस्ट्स हुई। उनमें से 123 अनुसूचित जातियों के और 118 अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को मिलनी चाहिये थीं लेकिन मिली केवल क्रमशः 17 और 16 प्रतिशत। कहा जाता है कि लायक लड़के नहीं मिलते। अच्छे-अच्छे लायक लड़के हैं लेकिन कह दिया जाता है कि वे नालायक हैं, ठोकरें खाते फिर रहे हैं लेकिन कहा जाता है कि क्वालिफाइड नहीं मिलते हैं। इंटरव्यू होती है तो कह दिया जाता है कि ये अयोग्य हैं, लायक नहीं हैं। जिन्होंने यूनिवर्सिटीज से सर्टिफिकेट प्राप्त किये हैं या जिन्होंने आई. ए. एस. किया है क्या वे नालायक थे कि उन्होंने ऐसा कर लिया, कैसे उन्होंने सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिये। इतनी मुश्किलें से वे अपनी पढ़ाई खत्म करते हैं लेकिन जब नौकरी की बात होती है तो कह दिया जाता है कि उनके लिए नौकरी नहीं है।

जब सैकन्ड क्लास अफसरों को देखिये, 20,501 और 488 जिसमें हुए 238 और अनुसूचित आदिम जाति के 97 और लिये 47। यह सैकेन्ड क्लास अफसरों की हालत है, सैकेन्ड क्लास अफसरों में भी योग्यता नहीं मिलती है। कहा यह जाता है कि चौथी और पांचवीं क्लास के कर्मचारियों का कोटा पूरा कर दिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या किसी मेहतर की जगह पर किसी ब्राह्मण को भेजोगे झाड़ू निकालने के लिये? उनका कोटा तो पूरा हो ही जायेगा क्योंकि झाड़ू निकालने वाले दूसरे मिलते नहीं हैं। इसी लिए उनका जो प्रतिशत है वह तो पूरा हो ही जायेगा।

मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक अरब से उपर रुपया खर्च करके बीस साल में आपने कुछ नहीं किया। स्वतंत्रता के बाद नारा लगा था कि राजाओं के राज से छूटकारा पाये और अब कांग्रेस राज्य में हमें उत्थान के रास्ते पर ले जायेगा। लेकिन बड़े शर्म की बात है, इस मंत्री-मंडल को इस्तीफा दे देना चाहिए, 20 वर्ष के बाद भी कुछ भी हालत नहीं सुधरी है। राजस्थान के अन्दर करौली में उदयराम नामक लड़के को जो कि खनिज मंत्रालय में क्लर्क की जगह पर काम करता था, उसे घर से बुला कर ड्यूटी पर ही मार दिया। खुद मेरी कांस्टीचूएंसी में सात आदमियों को घर से बुलाकर हमला कर दिया और एक धोबी को मार दिया। आंध्र

प्रदेश जैसे वाक्ये रोज हम सुनते हैं लेकिन इस सरकार को कोई शर्म नहीं आती। आज इन बातों का नाजायज फायदा ईसाई उठा रहे हैं। जैसा कि एक भाई ने बुद्धिस्ट का नाम लिया और कहा कि धर्म से जाति का सम्बन्ध अलग होता है। क्या बौद्ध होने से उनका उत्थान हो जायेगा ? कभी नही होगा। शिक्षा के आधार पर और दूसरे प्रकार से अगर सरकार उनकी सहायता करे तो उनका उत्थान अपने आप हो जाएगा। किसी का धर्म के परिवर्तन से उत्थान नहीं होता है और न कभी होगा। मैं इसका डटकर विरोध करता हूँ। जितने ईसाई कैथोलिक वगैरह जो आज बढ़ते जा रहे हैं यह सारे शेड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं क्योंकि वे बेचारे पैसे के लालच से, जमीन के लालच से या नौकरी के लालच से धर्म परिवर्तन के लिए तैयार हो जाते हैं। आप संख्या देख लीजिये उनकी लाखों की संख्या आज करोड़ों पर पहुँच गई है।

होस्टल्ज की हालत देखिये। 20 साल पहले जो रेट था जबकि चार पैसे में दाल, तीन पैसे में तेल, और 6 पैसे में साबुन मिलता था, उसी रेट से साढ़े चार आने आज भी खर्च किये जाते हैं। क्या आज 20 साल पहले के ही भाव हैं ? पहले रुपये का 20 सेर अनाज मिलता था, जबकि आज एक रुपये का अनाज जेब में आ जाता है। कितनी बुरी चीज है कि 20 साल पहले के शैडयूल्ड को आज भी होस्टल्ज में चलाया जा रहा है। आज वहाँ लड़के साबुन नहीं लगा पाते। अच्छी तरह से नहीं रह पाते। होस्टल्ज की आज बहुत ही खराब हालत हो गई है। इसी तरह से आई० टी० आई० के लड़कों को भारत सरकार ने 45 रुपये देने का वायदा किया था लेकिन आप राज्य सरकार से पूछिये कि उसमें से 20 रुपये कहां चले गये, सिर्फ 25 रुपये ही क्यों दिये जाते हैं ? 45 रुपये क्यों नहीं दिये जाते ? 25 रुपये में आज किसी भी लड़के की गुजर नहीं हो सकती है।

मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आप गांव में पीने के पानी की हालत देखिये। वहां के कूओं की हालत देखिये। मैंने राजस्थान के रेगिस्तान का दौरा किया है, वहां पर जानवरों के लिए जो पानी होता है वह हरिजनों को पिलाया जाता है। क्योंकि गांवों में ज्यादातर सवर्ण ही रहते हैं, शैड्यूल्ड कास्ट के एक दो आदमी होते हैं। इसी लिए उन को वह पानी जो जानवर पीते हैं, पिलाया जाता है यह कितने शर्म की बात है। आप एक-एक आइटम को लेकर चलते, जैसे कि पानी पीने की व्यवस्था करना, शिक्षा की व्यवस्था करना, इत्यादि। जो लड़के वजीफे के लिए या छात्रवृत्ति के लिए फार्म भरते हैं उनको टाइम से फार्म नहीं मिलते हैं, पूरी संख्या में फार्म छपाये नही जाते हैं जिस से विलम्ब हो जाता है। लड़के साल भर पढ़ते हैं, उनको कितनी छात्रवृत्ति मिल पाती है ? शहरों में तो कुछ मिल भी जाती है लेकिन गांवों में या तो सरपंच खा जाये या प्रधान खा जाये और अगर उनसे छूटे तो हैडमास्टर खा जाये। कितनी बुरी चीज है। इन सब बातों के रहते हुए भी आपने रिजर्वेशन भी बन्द कर दिया फर्स्ट-सेकेन्ड क्लास का। थर्ड और फोर्थ क्लास में दिया है लेकिन उसमें उनका रिजर्वेशन प्रमोशन में भी होना चाहिए।

इसके अलावा उनके लिये मकान और जमीन का इन्तजाम होना चाहिये। कम से कम 500 रुपये से नीचे के जो शैड्यूल्ड कास्ट हैं उनके लिये मकान और जमीन का एलाटमेंट होना चाहिये क्योंकि उसमें उनकी गुजर चल ही नहीं सकती है। मकान के लिये उनको किस्तों पर रुपया मिलना चाहिये। आपने 750 रु० एक शेड्यूल्ड कास्ट को सहायता के रूप में देना स्वीकार किया है। 750 रुपये में तो आज एक कोल्हू भी नहीं आता है, डंडे और बल्लियां अलग हैं। 750 रुपये बीस साल पहले चलते थे, आज तो वे किसी काम के नहीं हैं। इसलिये इस रकम को बढ़ाना चाहिये। 750 की जगह पर कम से कम दो हजार रुपया जरूर कर देना

[श्री ओंकार लाल बेरवा]

चाहिये । इतनी खराब हालत के होते हुये उनका रिजर्वेशन भी हरएक चीज में बन्द है । अभी अभी निर्माण आवास में 223 सीट्स भरी हैं जिसमें 10 शेड्यूल्ड कास्ट के लिये हैं । मानिक सेवा संस्था में 33 ग्रेजुएट गजटेड आफिसर लिये हैं लेकिन उसमें एक भी शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्ज का नहीं है । जब केन्द्रीय सरकार की यह हालत है तो राज्य सरकारों को क्या परवाह हो सकती है ।

जहां तक अस्पृश्यता निवारण की बात है, मैं ने आयुक्त की रिपोर्ट देखी है, उसमें 27 मुकदमे साल भर में दिखाये गये हैं । पेपर देखने से मालूम होता है कि 37 आदमियों की मृत्यु हो गई साल भर में और हरिजनों के 27 मुकदमे लिये हैं । 19 का निपटारा अभी पेंडिंग है, 8 को सजा दी गई है । बंगलों में बैठकर हरिजनों की योजना पूरी की जाती है । इसलिये मेरी निवेदन है कि जो इनका रिजर्वेशन है वह प्रमोशन के मामले में भी होना चाहिये । डाइरेक्ट भरती अगर होती है तो उसमें भी होना चाहिये । इसके अलावा जैसे कि अनेक मुहकमे हैं रेलवे इत्यादि, उनमें इनका कोटा पूरा होना चाहिये । यहां पर डा० राम सुभग सिंह जी ने कहा था कि कोटे से भी ज्यादा वह पूरा करेंगे लेकिन अभी तक तो कोटा ही खाली पड़ा हुआ है, पहले उसको तो पूरा कर लीजिये । मेरा निवेदन है कि शेडयूल्ड कास्ट के बच्चों के लिये शिक्षा का, उनकी नौकरी का, राजस्थान के अन्दर पीने के पानी का, उनके मकानों का और उनके लिये जमीन का इन्तजाम किया जाय ।

श्री भा० सुन्दरलाल (बस्तर) : अध्यक्ष महोदय, आदिवासी और शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में सरकार ने जो कुछ किया है, जैसा कि सभी सदस्यों ने कहा है कि अगर एक अरब रुपया ठीक ढंग से लगाया जाता तो आदिवासियों और शेडयूल्ड कास्ट की उन्नति जरूर हो जाती । किन्तु सरकार की जो कार्य-प्रणाली है पैसा खर्च करने की वह बहुत गलत है । मैं अपने बस्तर के बारे में कुछ नमूने रखना चाहता हूँ कि वहां पर उनके साथ कितना अन्याय होता है । बस्तर में 12 लाख आदिवासी रहते हैं, वे किस प्रकार रहते हैं, कहां रहते हैं, किस प्रकार से अपने को जंगली जानवरों से बचाते हैं, क्या खाते हैं, वह केन्द्रीय सरकार को कुछ भी नहीं मालूम है और न उनकी तरफ सरकार का कभी ध्यान ही गया है । प्रान्तीय सरकार ने भी उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है । वहां पर हजारों एकड़ जमीन बेकार पड़ी हुई है जिसमें लाखों मन अनाज पैदा किया जा सकता है । वहां के आदिवासी हमेशा सरकार से यह मांग करते रहते हैं कि हमको वह जमीन दे दी जाये ताकि हम उसमें पूरा अनाज पैदा कर सकें और ठीक से रह सकें, अपने बच्चों का पालन-पोषण कर सकें लेकिन उनकी दरख्वास्त पर कोई सुनवाई नहीं की जाती है । दूसरी ओर वहां पर जो रेफ्यूजी आये हैं उनकी और सरकार ध्यान दे रही है । आदिवासी कहते हैं कि हमको बैल नहीं मिलते हैं और कोई दूसरी सहायता नहीं मिलती है जबकि बाहर से आये हुए लोगों को बांटा जा रहा है । यह कहां का न्याय है ? सरकार को चाहिये कि जो हमारे बच्चे नवीं, दस्वीं, मैट्रिक पास हो गये हैं उनको नौकरी दिलाये लेकिन सरकार आदिवासियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है । हमारे यहां आदिवासी बहुमत में हैं । सरकार को चाहिये कि छोटे-छोटे बच्चों की पढ़ाई का ठीक ढंग से इन्तजाम करे लेकिन उनको मास्टर की नौकरी भी नहीं मिलती है । उस पर बाहर के लोग आ गये हैं जो कि वहां की बोली भी नहीं समझते हैं फिर किस प्रकार से पढ़ा सकते हैं ? इस तरह से कैसे उनका विकास हो सकता है ? इसलिये मेरा सरकार से कहना है कि कम से कम वहां की प्राथमिक पाठशालाओं में वहां के लड़कों को रखें ताकि जल्दी शिक्षा के मामले में लड़के आगे बढ़ सकें । न वहां आने जाने का साधन है । सरकार ने आज तक उधर उपेक्षा दिख-

लाई है और वहां विकास कार्य नहीं किया है। अगर वहां बिजली पैदा की जाय तो बस्तर, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बहुत से इलाकों में बिजली फैला कर वहां का विकास किया जा सकता है। बिजली से सिंचाई भी किसान आसानी से कर सकते हैं। लोग 2000-4000 रुपये में मोटरपम्प खरीद सकते हैं और सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं। इस के अलावा वह छोटे-छोटे कुंओं से भी अपनी खेती की सिंचाई कर सकते हैं लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सरकार का उधर ख्याल ही नहीं गया है। निराश और हताश होकर वहां के लोग यह भी कहते हैं कि इस अपनी भारतीय सरकार से तो वह ब्रिटिश सरकार ही अच्छी थी जिसके कि जमाने में 1 रुपये का 32 सेर नाज मिला करता था लेकिन आज इस सरकार के जमाने में तो हम को पेट भर खाने तक को नसीब नहीं हो पाता है। उन पिछड़े व अविकसित इलाकों की दशा बड़ी ही दयनीय है और इस साल भी 13 आदमी भूख से मर गये।

ईसाई मिशनरीज उन की खराब हालत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं और दो, दो चार, चार रुपये देकर, बहला, फुसला कर उन गरीब हरिजन लोगों को और आदिवासियों को ईसाई बनाया जा रहा है। अनेकों गरीब आदिवासियों का इन ईसाई पादरियों द्वारा इस तरह से धर्म परिवर्तन कराया गया है। ईसाई पादरियों की यह हरकतें एकदम नाजायज व गलत हैं और यह आदिवासियों पर एक बड़ा भारी अन्याय है। समय रहते सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिएं ताकि इस तरह की बेजा कार्यवाहियां बंद हों वरना एक दिन ऐसा आने वाला है कि बस्तर में तमाम आदिवासी इस चीज को खत्म करने के लिए और इसे सदा के लिए रोकने के लिए सरकार से लड़ेंगे। मेरे पास इस किस्म की अनेकों शिकायतें आई हैं कि यह ईसाई पादरी लोग हमारी जाति वालों को पैसा आदि देकर फुसला कर अपने धर्म में मिला लेते हैं और इस तरीके से हमारी बहू, बेटियों की इज्जत लूटते हैं। सरकार से मेरा आग्रह है कि वह इसे जल्द से जल्द रोकने की व्यवस्था करें। बस इतना कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री रामजी राम (अकबरपुर) : अध्यक्ष महोदय,

इस मुल्क के रहनुमा बहुत शाद हुए,
अमीर और अमीर, गरीब बरबाद हुए।
किस फिक्र से आजाद हुए,
अहले वतन कै साल हुए मुल्क को आजाद हुए ? ।।

इस मन्त्रालय की बजट डिमांड्स का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं लेकिन मुझे अफसोस है कि मौजूदा रकम बहुत ही कम और नाकाफी है। मेरी समझ में यह रकम चौगुनी होनी चाहिए थी। आप गांवों से लेकर शहरों तक देखें तो आप यह अंदाज लगायेंगे कि आज 20 साल की आजादी के बाद भी शैडयूल्ड ट्राइब्स और शैडयूल्ड कास्ट्स वालों का कोई उत्थान नहीं हुआ है। आज भी हर जगह उन का उसी तरह से शोषण किया जा रहा है। गांवों में थानेदारों, पुलिस स्टेशंस, तहसीलदारों, कचहरी और ब्लाक्स से हरिजनों को किसी किस्म की सहायता और न्याय नहीं मिलता है। यह ठीक है कि छुआछूत को दूर करने के लिए कानून बना हुआ है लेकिन जब वह रिपोर्ट करने जाते हैं तो उन की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। इसी तरह से तहसीलों में जो इन के रेकार्ड्स दर्ज होने चाहिएं, खेत वगैरह जो थोड़े बहुत इन के पास होते भी हैं वह भी दर्ज नहीं किये जाते हैं। इनके खेत दूसरों के कब्जे में लिखे जाते हैं। हालत यह है कि लेखपाल से लेकर तहसीलदार तक सब इन शेडयूल्ड कास्ट्स आदिवासियों के खिलाफ होते हैं और उन के पक्ष में जमीन दर्ज नहीं करते हैं। कचहरी में इंसाफ़ टके पर बिकता है और इन गरीब अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को इंसाफ़ नहीं मिलता है। आज गांवों में उन को रहने के लिए स्थान नहीं है, काम करने के अनुसार उन की मजदूरी नहीं है और खेती करने

[श्री रामजी राम]

के लिए उन को जमीन नहीं है। इसलिए बुनियादी तौर पर जब तक उन की समस्याओं को हल नहीं किया जायगा तब तक सही तौर पर हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा और वह अपने उस भूतकाल के गौरव को प्राप्त नहीं कर सकेगा। इसलिए मैं आप के माध्यम से चाहूंगा कि इस के ऊपर खास तौर से ध्यान दिया जाय।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि यह जो भंगी, मेहतर और डोम आदि हैं इन की जगह गजैटैड की जाय और उन लोगों की 300 रुपये मासिक से कम तनख्वाह नहीं होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था होने से अन्य लोग भी जैसे ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य और अन्य शूद्र लोग भी इस पेशे को स्वाभिमान की दृष्टि से देखेंगे और वह भी इस में आयेंगे।

It may be your interest to be our masters but how it is ours to be your slaves ? यह नहीं हो सकता कि हम हमेशा के लिए आप के गुलाम बने रहें। एक वक्त ऐसा आने वाला है कि हमें मजबूर होकर अपने लिए अलग राज्य की मांग करनी पड़ेगी क्योंकि न आप हमें गांवों में रहने देते हैं और न शहरों में रहने देते हैं।

जहां तक इन झुग्गी झोंपड़ियों का सवाल है उन में रहने वाले शेडयूल्ड कास्ट्स और मजदूरों का सवाल है आप उन को वहां से उजाड़ कर शहर से 15-20 मील की दूरी पर ले जाकर बैठा देते हैं जहां न रोजगार होता है, न बच्चों की पढ़ाई आदि की व्यवस्था होती है और न ही बीमार बच्चों की दवादारू की व्यवस्था होती है। अगर आप वाकई में उन की तरक्की चाहते हैं और उन की सहायता करना चाहते हैं तो उन्हें आप शहरी इलाके में ही कहीं पर ले जाकर बसायें जहां कि उन्हें रोजगार व अन्य आवश्यक सुविधाएं सुलभ हो सकें। उन्हें वहीं पर दो, तीन मंजिले मकान बना कर किराये पर दें और वह किराया तब तक काटते रहें जब तक कि मकान की कौस्ट पूरी न हो जाय। अगर ऐसा नहीं किया जायगा तो जैसा मैंने कहा उन्हें मजबूर होकर अपने लिए एक अलग राज्य की मांग करनी पड़ेगी। आज भले ही उन की मांग के पीछे आवश्यक बल न हो लेकिन अगर ऐसी ही दयनीय हालत उन की चलती रही और उन में असन्तोष बढ़ता रहा तो एक वक्त जल्द ही ऐसा आयेगा कि उन की उस मांग के पीछे आवश्यक बल हो जायेगा और आप को उसे मानना पड़ेगा।

अगर वाकई सही तौर पर आप इन की समस्याओं को हल करना चाहते हैं तो इन की समस्याओं को सही तौर पर आप को समझना पड़ेगा और मुस्तैदी से उन्हें हल करना पड़ेगा। आज स्थिति यह है कि समाज कल्याण विभाग से उन को जो सहायता मिलती है उस रकम का आधे से ज्यादा पैसा अफसरों के जरिए खा लिया जाता है और वह उन तक सही तौर पर नहीं पहुंच पाता है। यह बात साफ है कि छात्रवृत्ति जो मिलती है वह बहुत कम है और उस को ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए। लड़कों की संख्या के मुकाबले वह छात्रवृत्ति बहुत कम है। 700-800 लड़के हैं और छात्रवृत्ति केवल 6-7 हैं। अब कैसे 6-7 छात्रवृत्ति को 700-800 लड़कों में तकसीम किया जा सकता है ? यह तो वही ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात हो गयी।

देश की आबादी बढ़ती जा रही है। सरकार द्वारा आवाज पर आवाज लगाई जा रही है कि आबादी घटाई जाय, आबादी बढ़ने के ऊपर अंकुश लगाया जाय। इस के लिए लोगों में फैमिली प्लानिंग का प्रचार किया जा रहा है। आबादी पर रोक लगाने के लिए यह बाल विवाह को अनिवार्य रूप से रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। चाइल्ड मैरिज रैस्ट्रेंट ऐक्ट 1929 में बना था लेकिन वह अभी कौग्निजेबुल औफैंस नहीं है। उसे कौग्निजेबुल औफैंस किया जाय।

हरिजन बच्चों को स्कूल, कालिजों और युनिवरसिटीज में दाखिला नहीं मिलता है। इस

बारे में मैं ने दो, तीन महीने पहले शिकायत की थी कि हरिजन लड़कों को स्कूल से लेकर युनिवरसिटी तक दाखिला नहीं मिलता है और उनके दाखिले के लिए कोई सरकार द्वारा पक्की व्यवस्था की जाय। उन की फीस भी माफ नहीं होती है। हर जगह पर उन की फ़ीस माफ़ हो इस का भी सरकार को इंतजाम करना चाहिए।

इलाहाबाद के कोचिंग क्लास में आई० ए० एस० के प्रेपरेशन के लिए जो एक साल के लिए लड़कों को वहां रहना पड़ता है तो वहां का भी इंतजाम बहुत खराब है और उस की जांच होनी चाहिए। वहां पर बड़ी गड़बड़ी चलती है। सब पैसा खा लेते हैं और सही तौर पर उस का इंतजाम नहीं कर पाते हैं। उस की जांच कराई जाय।

हरिजनों के विकास कार्यों आदि के लिए जो रुपया दिया जाता है वह एक तो नाकाफ़ी होता है और दूसरे वह पूरा खर्च भी नहीं किया जाता है और अक्सर पैसा लैप्स भी हो जाया करता है। इस सिलसिले में मैं उत्तर प्रदेश की एक मिसाल आप के सामने रखना चाहता हूं कि पिछले वर्ष उत्तरप्रदेश में डेढ़ करोड़ रुपया हरिजनों के काम में लैप्स हो गया। इस का मतलब आखिर क्या है महज़ इस के कि उन की तरक्की में कोई दिलचस्पी नहीं लेना चाहता है।

थोड़ा सा आखिर में मैं हथकरघा उद्योग के बारे में कहना चाहता हूं। यहां उत्तर प्रदेश में और दिल्ली के आसपास में हैण्डलूम सोसाइटियां काम कर रही हैं लेकिन उन की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। उन की तरक्की के लिए कोई खयाल नहीं किया जाता है। यहां की इन शैडयूल्ड कास्ट्स सोसाइटियों को रिबेट नहीं मिला। यह रिबेट का पैसा यहां पर एक माननीय सदस्य हैं, उन का नाम इत्तिफाक से मुझे इस समय याद नही आ रहा हैं, वह माननीय सदस्य उन के रिबेट का पैसा खा लेते हैं और वह पैसा उन सोसाइटियों तक नहीं जाने पाता है जबकि उन की सोसाइटियां रजिस्टर्ड हैं। इस के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए।

शैडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिए राज्य सभा, विधान परिषदों राज्यपालों, राजदूतों, कोटा परमिट लाइसेंस, इम्पोर्ट और ऐक्सपोर्ट इन सब में रिजरवेशन अर्थात् भाषा आरक्षण होना चाहिए। इसी तरह से फौज और पुलिस विभाग में भी हरिजनों के लिए आरक्षण होना चाहिए।

चूंकि स्पीच समाप्त कराने के लिए कई बार घंटी बज चुकी है इसलिए मैं और ज्यादा न कहते हुए श्री भण्डारे द्वारा कही हुई बातों का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी जगह लेता हूं।

شری رامجی رام (اکبرپور) :- ادھیکش مہودئے اس ملک
کے رہنما بہت شاد ہوتے امیر اور امیر۔ غریب برباد ہوئے۔ کس فکر سے
آزاد ہوتے۔ اہلِ وطن کے سال ہوتے ملک کو آزاد ہوئے۔

اس منترالئے کی بجٹ ڈیمانڈس کا سمرتھن کرنے کے لئے میں کھڑا ہوا ہوں لیکن مجھے افسوس ہے کہ موجودہ رقم بہت ہی کم اور ناکافی ہے میری سمجھ میں یہ رقم چوگنی ہونی چاہیئے تھی۔ آج آپ گاؤں سے لے کر شہروں تک دیکھیں تو آپ یہ اندازہ لگائیں گے کہ آج ۲۰ سال کی آزادی کے بعد بھی شڈیولڈ ٹرائبس اور شڈیولڈ کاسٹس والوں کا کوئی اتھان نہیں ہوا ہے۔ آج بھی ہر جگہ ان کا اسی طرح سے شوشن کیا جارہا ہے۔ گاؤں میں تھانے داروں۔ پولس اسٹیشنس تحصیل داروں۔ کچہری اور بلاکس سے ہریجنوں کو کس قسم کی سہائیتا اور نیائے نہیں ملتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ چھوا چھوت کو دور کرنے کے لئے قانون بنا ہوا ہے لیکن جب وہ رپورٹ کرنے جاتے ہیں تو ان کی رپورٹ نہیں لکھی جاتی ہے۔ اس طرح سے تحصیلوں میں جو ان کے ریکارڈس درج ہونے چاہئیں۔ کھیت وغیرہ جو تھوڑے بہت ان کے پاس ہوتے بھی ہیں وہ بھی درج نہیں کئے جاتے ہیں۔ ان کے کھیت دوسروں کے قبضہ میں لکھے جاتے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ لیکھپال سے لیکر تحصیل دار تک سب ان شیڈولڈ کاسٹ آدیواسیوں کے خلاف ہوتے ہیں اور ان کے پکش میں زمین درج نہیں کرتے ہیں۔ کچہری میں انصاف ٹکے پر بکتا ہے اور ان غریب انوسوچت جاتیوں تتھا انوسوچت آدم جاتیوں کو انصاف نہیں ملتا ہے۔ آج گاؤں میں انکو رہنے کے لئے استھان نہیں ہے۔ کام کرنے کے انوسار ان کی مزدوری نہیں ہے اور کھیتی کرنے لئے ان کو زمین نہیں ہے۔ اس لئے بنیادی طور پر جب تک ان کی سمسیاؤں کو حل نہیں کیا جائے گا تب تک صحیح طور پر ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکے گا اور وہ اپنے اس بھوت کال کے گورو کو پراپت نہیں کر سکے گا۔ اس لئے میں آپ کے مادھیم سے چاہوں گا کہ اس کے اوپر خاص طور سے دھیان دیا جائے۔

دوسری بات مجھے یہ کہنی ہے کہ یہ جو بھنگی۔ مہتر اور ڈوم آدمی ہیں ان کی جگہ گلیفیڈ کی جائے اور ان لوگوں کی ۳۰۰ روپئے ملسکھ سے کم تنخواہ نہیں ہونی چاہیئے۔ ایسی ویوستھا ہونے سے انیئے لوگ بھی جیسے براہمن۔ چھتری۔ ویشئے اور انیئے شودر لوگ بھی اس پیشے کو سوابھمان کی درشٹی سے دیکھیں گے اور وہ بھی اس میں آئیں گے۔

It may be your interest to be our masters but how it is ours to be your slaves ?

یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ہمیشہ کے لئے آپ کے غلام بنے رہیں۔ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ ہمیں مجبور ہو کر اپنے لئے الگ راجیہ کی مانگ کرنی پڑے گی۔ کیونکہ نہ آپ ہمیں گاؤں میں رہنے دیتے ہیں۔ اور نہ شہروں میں رہنے دیتے ہیں۔

جہاں تک ان گندی جھونپڑیاں کا سوال ہے ان میں رہنے والے شیڈولڈ کاسٹ اور مزدوروں کا سوال ہے آپ ان کو وہاں سے اجاڑ کر شہر سے ۲۰-۱۵ میل کی دوری پر لے کر بیٹھا دیتے ہیں جہاں نہ روزگار ہوتا ہے نہ بچوں کی پڑھائی آدی کی ویوستھا ہوتی ہے۔ اگر آپ واقعی میں ان کی ترقی چاہتے ہیں اور ان کی سہایتا کرنا چاہتے ہیں تو انہیں آپ شہری علاقہ میں ہی کہیں پہلے جاکر بسائیں جہاں کہ انہیں روزگار و انیئے آوشیک سوویدھائیں سلبھ ہو سکیں۔ انہیں وہیں پر دو۔تین منزلے مکان بناکر کرائے پر دیں اور وہ کرایہ تب تک کاٹتے رہیں جب تک کہ مکان کی کاسٹ پوری نہ ہو جائے۔ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو جیسا میں نے کہا انہیں مجبور ہو کر اپنے لئے ایک الگ راجیہ کی مانگ کرنی پڑے گی۔ آج بھلے ہی ان کی مانگ کے پیچھے آوشیک بل نہ ہو لیکن اگر ایسی ہی دینیہ حالت ان کی چلتی رہی اور ان میں اسنتوش بڑھتا رہا تو ایک وقت جلدی ایسا آئے گا کہ ان کی اس مانگ کے پیچھے آوشیک بل ہو جائے گا اور آپ کو اسے ماننا پڑے گا۔

اگر واقعی صحیح طور پر آپ ان کی سمسیاؤں کو حل کرنا چاہتے ہیں تو ان کی سمسیاؤں کو صحیح طور پر آپ کو سمجھنا پڑے گا اور مستعدی سے انہیں حل کرنا پڑے گا۔ آج استھتی یہ ہے کہ سماج کلیان وبھاگ سے ان کو جو سہایتا ملتی ہے اس رقم کا آدھے سے زیادہ پیسہ افسروں کے ذریعہ کھا لیا جاتا ہے اور وہ ان تک صحیح طور پر نہیں پہنچ پاتا ہے۔ یہ بات صاف ہے کہ چھاتر ورتی جو ملتی ہے وہ بہت کم ہے اور اس کو زیادہ بڑھایا جانا چاہیئے۔ لڑکوں کی سنکھیا کے مقابلے وہ چھاتر ورتی بہت کم ہے ۱۰،۰۰۰ لڑکے ہیں اور چھاتر ورتی کیول ۶-۷ ہیں۔ اب کیسے ۶-۷ چھاتر ورتی کو ۷۰۰۰-۸۰۰۰ لڑکوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو وہی اونٹ کے منہ میں زیرہ والی بات ہو گئی۔

دیش کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے۔ سرکار دوارا آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ آبادی گھٹائی جائے۔ آبادی بڑھنے کے اوپر انکش لگایا جائے اس کے لئے لوگوں میں فیملی پلاننگ کا پرچار کیا جا رہا ہے۔ آبادی پر روک لگانے کے لئے یہ بال ویواہ کو انواریہ روپ سے روکنے کے لئے کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے۔ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ ۱۹۲۹ میں بنا تھا لیکن وہ ابھی کوگنیزیبل آفنس نہیں ہے۔ اسے کوگنیزیبل کیا جائے۔

ہریجن بچوں کو اسکول۔ کالجوں اور یونیورسٹیز میں داخلہ نہیں ملتا ہے اس بارے میں میں نے دو تین مہینے پہلے شکایت کی تھی کہ ہریجن لڑکوں کو اسکول سے لیکر یونیورسٹی تک داخلہ نہیں ملتا ہے اور ان کے داخلے کے لئے کوئی سرکار دوارا ٹھیک ویوستھا کی جائے۔ ان کی فیس بھی معاف نہیں ہوتی ہے۔ ہر جگہ پر ان کی فیس معاف ہو اس کا بھی سرکار کو انتظام کرنا چاہیئے۔

الہ آباد کے کوچنگ کلاس میں آئی۔ اے۔ ایس کے پریپریشن کے لئے جو ایک سال کے لئے لڑکوں کو وہاں رہنا پڑتا ہے تو وہاں کا بھی انتظام بہت خراب ہے اور اس کی جانچ ہونی چاہیئے۔ وہاں پر بڑی گڑبڑی چلتی ہے۔ سب پیسہ کھا لیتے ہیں اور صحیح طور پر اس کا انتظام نہیں کر پاتے ہیں۔ اس کی جانچ کرائی جائے۔

ہریجنوں کے وکاس کاریوں آدی کے لئے جو روپیہ دیا جاتا ہے وہ ایک تو ناکافی ہوتا ہے اور دوسرے وہ پورا خرچ بھی نہیں کیا جاتا ہے اور اکثر پیسہ لیپس ہو جایا کرتا ہے۔ اس سلسلے میں میں اتر پردیش کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پچھلے ورش اتر پردیش میں ڈیڑھ کروڑ روپیہ ہریجنوں کے کام میں لیپس ہو گیا۔ اس کا مطلب آخر کیا ہے محض اس کے کہ ان کی ترقی میں کوئی دلچسپی نہیں لینا چاہتا ہے۔

تھوڑا سا آخر میں میں ہینڈ کرگھا ادیوگ کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں۔ یہاں اتر پردیش میں اور دلی کے آس پاس میں ہینڈلوم سوسائٹیاں کام کر رہی ہیں لیکن ان کی اور کوئی دھیان نہیں دیا جاتا ہے۔ انکی ترقی کے لئے کوئی خیال نہیں کیا جاتا ہے۔ یہاں کی ان شیڈولڈ کاسٹس سوسائٹیوں کو ریبیٹ نہیں ملا۔ یہ ریبیٹ کا پیسہ یہاں پر ایک مانیہ سدسیے ہیں ان کا نام اتفاق سے مجھے اس سمے یاد نہیں آرہا ہے وہ مانیہ سدسیے انکے ریبیٹ کا کھا لیتے ہیں اور وہ پیسہ ان سوسائٹیوں تک نہیں جانے پاتا ہے جب ان کی سوسائٹیوں رجسٹرڈ ہیں۔ اس کے اوپر دھیان دیا جانا چاہیئے۔

شڈیولڈ کاسٹس اور شڈیولڈ ٹرائبس کے لوگوں کے لئے راجیہ سبھا سویدھان پریشدوں راجیہ پالوں۔ راجیہ وتوں۔ کوٹا پرمٹ لائسنس امپورٹ اور ایکسپورٹ ان سب میں ریزرویشن ارتھات آرکچھن ہونا چاہیے۔ اس طرح سے فوج اور پولس ویبھاگ میں بھی ہریجنوں کیلئے آرکچھن ہونا چاہیے۔

چونکہ اسپیچ سماپت کرانے کے لئے کئی بار گھنٹی بج چکی ہے اس لئے میں اور زیادہ نہ کہتے ہوئے شری بھنڈارے دوارا رکھی ہوئی باتوں کا پر زور سمرتھن کرتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں۔

THE MINISTER OF PLANNING, PETROLEUM AND CHEMICALS AND SOCIAL WELFARE (SHRI ASOKA MEHTA) : Mr. Speaker, Sir, I am grateful to the sixteen hon. Members who have participated in the debate. Eloquent and indignant speeches have been made, and I think the problem is such that it inevitably evokes both eloquence and indignation. I feel I have great sense of humility because many of the hon. Members who have spoken have expressed such high expectations from this department. One hon. Member suggested that this department should be able to mobilise the efforts of the entire community in getting rid of the evils that have existed for a long time. Another hon. Member suggested that this department should be able to co-ordinate and mobilise the resources of the Government as a whole. All that I can say is that it will be our endeavour to do the utmost that we can. It will also be the endeavour of this Government to see that as far as co-ordination inside the Government is concerned that will be fully and adequately carried out.

One of the most important questions asked was what was being done with the money that was being spent ? A number of hon. Members said that the money was either being misused or not properly used. May I point out that Rs. 20 crores will be spent during this year—about Rs. 15 crores at the Centre and Rs. 5 crores in the States—on this particular activity. Of this the distribution is like this.

As far as the Scheduled Castes are concerned, 45 per cent of all the money that the States will be spending will be earmarked for education and 99 per cent of the Central expenditure will be on education ; 40 per cent of what the State will be spending will be on economic development and 15 per cent on other schemes. The Centre spends practically its entire amount on education.

As far as the Scheduled Tribes are concerned, the corresponding figures are—60 per cent on education and 30 per cent on economic development in the States, while the Centre will be spending 17 per cent on education and 80 per cent on economic development.

I have underlined this point as the main emphasis so far has been on educational facilities. 6 lakhs of students belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes are receiving scholarships at the pre-matric level and 1,32,000 students belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes will be receiving scholarships at the post-matric level in the current year. Whether this educational effort is bringing about any transformation or not is for the hon. Members to tell me. I believe, however, that this is a massive effort and we have deliberately selected this sector because it is through education that this transformation can be most quickly achieved.

The other area where an equally significant effort is being made is in the tribal development blocks. There are at the moment 489 tribal development blocks. We would like to set up more blocks, but because of lack of resources we have not been able to move forward. This is again an area where we want to move forward. However, economic development has to be carried out on the basis of the allocations that are made in the different sectors.

I realise, partly because of my experience in the Planning Commission as well as from what I have seen here in the Department, that these expectations have not been fulfilled. Therefore, when the new Fourth Plan is being drawn up, even in finelising the approach to the Plan that is being discussed and evolved just now, it has been agreed that built-in provisions will be made to ensure that from the sectoral allocations, either for agriculture or any other economic activity, a proportionate share is made available to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. What is sought to be done from whatever money is made available under this department is

[Shri Asoka Mehta]

to be considered of a supplementary character.

The most important criticism, I realise, is about employment and promotions. This is a matter which has been engaging our attention very seriously. I would like to assure the hon, House that the Home Minister has been giving his personal attention to this matter. He and some of his colleagues in the Cabinet will soon be coming up with proposals whereby this matter will be thoroughly gone into and the unsatisfactory state of affairs that exists today will be sought to be corrected as early and as efficiently as possible. As to what should be the mechanism for it, various suggestions are being made These suggestions are being gone into and I would be very happy to receive the maximum co-operation from all my colleagues. But the Government is not happy with the state of affairs as far as employment and promotion are concerned. In the presence of the Prime Minister and the Deputy Prime Minister and most of my colleagues, I am authorised to say that we will not leave any stone unturned to see that in the matter of employment and promotion this state of affairs is remedied..... (*Interruption*).

The last point which I would like to refer to, because time is running out, is that there have been many gruesome stories and many unfortunate incidents have been reported. I share with the whole House the feeling of shame and of deep anger about it. But may I beg of hon. Members that as it is the situation is bad enough ; need we talk about stories which have no foundation in fact at all ? I am referring to one particular incident which has been referred to here at least three or four times. My hon. friend, Shri Muthyal Rao comes from Andhra Pradesh and his constituency is Mahbubnagar. This particular incident is supposed to have occurred in this constituency, where certain Scheduled Caste sisters of ours were supposed to have been stripped naked and paraded in the streets.

My distinguished colleague immediately went to his constituency and also to other districts wherever such stories had come up—it is his own constituency ; he knows the area and he knows all the friends—and he enquired and found there was no basis in that story. It is completely baseless ; nothing like that has happened. Bad incidents are happening ; gruesome stories have occurred. We are looking into them and, with the co-operation of the hon. Members, we hope, we will be able to put a stop to them. But need we go on repeating stories which have no basis at all ? That only creates a feeling of avoidable anger of course. We need indignation, but the indignation should be behind those issues which should have a basis in fact.

That is all I have to say. I would like to assure the hon. Members that I am deeply grateful for the valuable comments and encouragement they have given today. We fully realise the importance of the situation and the importance of the problem that we are dealing with. We are fully aware of the indignation that not only the hon. Members belonging to scheduled castes and tribes feel, but everyone of us also feels, as you, Sir, yourself have given expression to it. With the co-operation of the hon. Members, the Government would like to do the utmost possible to see that these blots on our civilised life are quickly removed.

SHRI SONAVANE (Pandharpur): May I know in what period of time his sincerity will be displayed into action. All lip-sympathy and good expressions are used. Will the evidence of that be available by the time we, next time, discuss the Report of the Scheduled Castes and Tribes Commissioner ?

MR. SPEAKER : Let us hope so.

श्री देवराव पाटिल : बौद्धजनों को आदिम-जातियों को मिलने वाली सहूलियतें देने का सवाल उठाया गया था...

SHRI BAL RAJ MADHOK : Is it the sincerity of man or Government ?

MR. SPEAKER : Now, I put all the cut motions together.

All the cut motions were put and negatived

MR. SPEAKER : The question is :

"That the respective sum not exceeding the amounts shown in the fourth column of the order paper, be granted to the President, *to complete* the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against Demands Nos. 97 and 98 relating to the Department of Social Welfare."

The motion was adopted.

19.00 hrs.

Ministry of Finance, Health, Law, etc., and other Departments

MR. SPEAKER : Now, I put all the outstanding Demands.

SHRI BAL RAJ MADHOK : I would like to put only one question to the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development. Sir, nobody is here from that Ministry.

MR. SPEAKER : Nobody is here.

Now, I put all the outstanding Demands to the vote of the House.

The question is :

"That the respective sums not exceeding the amounts shown in the fourth column of the order paper, be granted to the President, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against—

(i) Demands Nos. 15 to 29 and 106 to 113 relating to the Ministry of Finance ;

(ii) Demands Nos. 35 to 37 and 116 relating to the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development ;

(iii) Demand Nos. 68 and 69 relating to the Ministry of Law ;

(iv) Demand No. 96 relating to the Department of Parliamentary Affairs ;

(v) Demand No. 99 relating to the Planning Commission ;

(vi) Demand No. 100 relating to Lok Sabha ;

(vii) Demand No. 101 relating to Rajya Sabha ; and

(viii) Demand No. 102 relating to the Secretariat of the Vice-President."

The motion was adopted.

[The Motions for Demands for Grants which were adopted by the Lok Sabha, are reproduced below—Ed.]

Demand No. 15—Ministry of Finance

"That a sum not exceeding Rs. 2,32,18,000 be granted to the President *to complete the sum necessary to defray* the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March 1969, in respect of 'Ministry of Finance'."

Demand No. 16—Customs

"That a sum not exceeding Rs. 5,76,67,000 be granted to the President *to complete the sum necessary to defray* the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Customs'."

Demand No. 17—Union Excise Duties

"That a sum not exceeding Rs. 13,48,24,000 be granted to the President *to complete the sum necessary to defray* the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Union Excise Duties'."

Demand No. 18—Taxes on Income including Corporation tax, etc.

"That a sum not exceeding Rs. 10,78,97,000 be granted to the President *to complete the sum necessary to defray* the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Taxes on Income including Corporation tax, etc.'."

Demand No. 19 – Stamps

"That a sum not exceeding Rs. 4,48,56,000 be granted to the President

to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Stamps'."

Demand No. 20—Audit

"That a sum not exceeding Rs. 18,79,17,000 be granted to the President *to complete the sum necessary to defray* the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Audit'."

Demand No. 21—Currency and Coinage

"That a sum not exceeding Rs. 12,69,82,000 be granted to the President *to complete the sum necessary to defray* the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Currency and Coinage'."

Demand No. 22 –Mint

"That a sum not exceeding Rs. 3,29,54,000 be granted to the President *to complete the sum necessary to defray* the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969. in respect of 'Mint'."

Demand No. 23—Kolar Gold Mines

"That a sum not exceeding Rs. 4,54,68,000 be granted to the President *to complete the sum necessary to defray* the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Kolar Gold Mines'."

Demand No. 24—Pensions and other Retirement Benefits

"That a sum not exceeding Rs. 4,97,26,000 be granted to the President *to complete the sum necessary to defray* the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Pensions and other Retirement Benefits'."

Demand No. 25—Opium

"That a sum not exceeding Rs. 85,00,000 be granted to the President *to complete the sum necessary to defray* the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Opium'."

Demand No. 26—Other Revenue Expenditure of the Ministry of Finance

"That a sum not exceeding Rs. 34,04,16,000 be granted to the President *to complete the sum necessary to defray* the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Other Revenue Expenditure of the Ministry of Finance'."

Demand No. 27—Grants-in-aid to State and Union Territory Governments

"That a sum not exceeding Rs. 2,79,82,39,000 be granted to the President *to complete the sum necessary to defray* the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Grant-in-aid to State and Union Territory Governments'."

Demand No. 28—Miscellaneous Adjustment between the Central, State and Union Territory Governments

"That a sum not exceeding Rs. 23,50,000 be granted to the President *to complete the sum necessary to defray* the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Miscellaneous Adjustments between the Central, State and Union Territory Governments'."

Demand No. 29—Pre-partition payments

"That a sum not exceeding Rs. 2,21,000 be granted to the President *to complete the sum necessary to defray* the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Pre-partition payments'."

Demand No. 106—Capital outlay on the India Security-Press

"That a sum not exceeding Rs. 39,37,000 be granted to the President *to complete the sum necessary to defray* the charges which will come in course of payment during the year ending the

31st day of March, 1969, in respect of 'Capital Outlay on the India Security Press'."

Demand No. 107—Capital Outlay on Currency and Coinage

"That a sum not exceeding Rs. 16,32,95,000 be granted to the President *to complete the sum necessary to defray* the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Capital outlay on Currency and Coinage'."

Demand No. 108—Capital Outlay on Mints.

"That a sum not exceeding Rs. 65,73,000 be granted to the President *to complete the sum necessary to defray* the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Capital Outlay on Mints'."

Demand No 109—Capital Outlay on Kolar Gold Mines

"That a sum not exceeding Rs. 95,22,000 be granted to the President *to complete the sum necessary to defray* the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Capital Outlay on Kolar Gold Mines'."

Demand No. 110—Commuted Value of Pensions

"That a sum not exceeding Rs. 4,00,41,000 be granted to the President *to complete the sum necessary to defray* the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Commuted value of Pensions'."

Demand No. 111—Other Capital Outlay of the Ministry of Finance

"That a sum not exceeding Rs. 2,20,83,000 be granted to the President *to complete the sum necessary to defray* the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Other Capital Outlay of the Ministry of Finance'."

Demand No. 112—Capital Outlay on Grants to State Governments for Development

"That a sum not exceeding Rs. 43,13,19,000 be granted to the President *to complete the sum necessary to defray* the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Capital Outlay on Grants to State Governments for Development'."

Demand No. 113—Loans and Advances by the Central Government

"That a sum not exceeding Rs. 4,02,67,86,000 be granted to the President *to complete the sum necessary to defray* the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Loans and Advances by the Central Government'."

Demand No. 35—Ministry of Health, Family Planning and Urban Development

"That a sum not exceeding Rs. 34,12,000 be granted to the President *to complete the sum necessary to defray* the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Ministry of Health, Family Planning and Urban Development'."

Demand No .36—Medical and Public Health

"That a sum not exceeding Rs. 19,20,68,000 be granted to the President *to complete the sum necessary to defray* the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Medical and Public Health'."

Demand No. 37—Other Revenue Expenditure of the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development

"That a sum not exceeding Rs. 82,35,000 be granted to the President *to complete the sum necessary to defray* the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Other Revenue Expenditure of the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development'."

Demand No. 116—Capital Outlay of the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development

"That a sum not exceeding Rs. 13,17,12,000 be granted to the President *to complete the sum necessary to defray* the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Capital Outlay of the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development'."

Demand No 68 - Ministry of Law

"That a sum not exceeding Rs. 57,35,000 be granted to the President *to complete the sum necessary to defray* the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Ministry of Law'."

Demand No. 69—Other Revenue Expenditure of the Ministry of Law

"That a sum not exceeding Rs. 1,36,08,000 be granted to the President *to complete the sum necessary to defray* the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Other Revenue Expenditure of the Ministry of Law'."

Demand No. 96—Department of Parliamentary Affairs

"That a sum not exceeding Rs. 5,51,000 be granted to the President *to complete the sum necessary to defray* the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Department of Parliamentary Affairs'."

Demand No. 99—Planning Commission

"That a sum not exceeding Rs. 1,32,49,000 be granted to the President *to complete the sum necessary to defray* the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Planning Commission'."

Demand No. 100—Lok Sabha

"That a sum not exceeding Rs. 1,29,55,000 be granted to the President *to complete the sum necessary to defray* the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Lok Sabha'."

Demand No. 101—Rajya Sabha

"That a sum not exceeding Rs. 49,01,000 be granted to the President *to complete the sum necessary to defray* the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Rajya Sabha'."

Demand No. 102—Secretariat of the Vice President

"That a sum not exceeding Rs. 2,44,000 be granted to the President *to complete the sum necessary to defray* the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Secretariat of the Vice-President'."

Appropriation (No. 2) Bill*, 1968

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the service of the financial year 1968-69.

MR. SPEAKER : The question is :

"That leave is granted to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1968-69".

The motion was adopted.

SHRI MORARJI DESAI : I introduce† the Bill.

---

*Published in Gazette of India Extraordinary Part, II, section 2, dated 25.4.68.

†Introduced/moved with the recommendation of the President.

Sir, I beg to move :

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1968-69, be taken into consideration".

MR. SPEAKER : The question is :

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1968-69, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. SPEAKER : We shall now take up the clause-by-clause consideration of the Bill.

The question is :

"That clauses 2 and 3 and the Schedule with Annexure stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 and the Schedule with Annexure were added to the Bill.

MR. SPEAKER : The question is :

"That clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI MORARJI DESAI : Sir, I beg to move :

"That the Bill be passed."

MR. SPEAKER : The question is :

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

MR. SPEAKER : The Bill is passed. The House stands adjourned to meet again tomorrow at 11 A.M.

19.02 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, April 26, 1968/ Vaisakha 6, 1890 (Saka)

Printed at Akashdeep Printers 20, Darvaganj, Delhi-6.